हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक मंगलवार दिनांक, 17 फरवरी, 2026 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर 171004-शिमला, में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरंभ हुई ।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

17.02.2026/1100/बी.एस./ए.एस.-1

व्यवस्था का प्रश्न

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ महत्वपूर्ण विषय के ऊपर अपनी बात रखनी है, कृपया मुझे बोलने का समय दीजिए

अध्यक्ष : ठाकुर साहब, सबसे पहले प्रश्न काल होगा उसके बाद आपको उचित समय दिया जाएगा।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न, प्रश्न काल से ही संबंधित है। कृपया, मुझे बोलने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष : ठाकुर साहब, bear with me. पहले प्रश्न काल होने दीजिए, क्योंकि प्रश्न काल बहुत महत्वपूर्ण होता है अन्यथा यह फिर नयी प्रथा बन जाएगी कि प्रश्न काल से पहले ही व्यवस्था का प्रश्न शुरू हो जाएगा। आपका विषय प्रश्न काल से कैसे जुड़ा हुआ है? आप इस पर सप्लिमेंटरी पूछ सकते हैं। आज यहां पर बहुत ज्यादा स्थगित प्रश्न लगे हुए हैं जिनके बारे में आप बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं और आपका कहना था कि स्थगित प्रश्न बार-बार स्थगित नहीं होने चाहिए। आज सबसे पहला प्रश्न आदरणीय विनोद कुमार जी का लगा है। आप इन्हें बोलने का मौका दीजिए। ...(Interruption) No, I am not allowing anybody. I am just starting the Question Hour.

17.02.2026/1100/बी.एस./ए.एस.-2

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, यह तो गलत बात है, आप बोलने के लिए समय नहीं दे रहे हैं।

Speaker : Please, Shri Vinod Kumar ji, after Question Hour I will allow you.

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, आपकी NeVA प्रणाली काम नहीं कर रही है।

अध्यक्ष : NeVA हमारी प्रणाली नहीं है। NeVA यूनियन ऑफ इंडिया की है और हम भी इससे परेशान है। इस बात को मैंने लोक सभा में भी बोल दिया है और केन्द्र सरकार को भी इस बारे में अवगत करवा दिया गया है। अब हमारा अपना पोर्टल स्टार्ट हो रहा है। (...व्यवधान...) कृपया, बैठ जाइए। ऐसा है कि पिछले कल भी मेरे चैंबर में आदरणीय ठाकुर साहब ने यह विषय उठाया था। यह सत्र तीन दिन का है और इसमें जो 15 दिन का समय है उसको भी मैंने अपने क्षेत्राधिकार के अनुसार कम किया है।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

16.02.2026/1105/DT/AS-1

अध्यक्ष जारी...

माननीय सदस्यों को यह पता नहीं लग रहा कि उन्होंने प्रश्न या नोटिस देने हैं या नहीं। यह सत्र एक दिन, दो दिन या 3 दिन के लिए हो रहा है लेकिन मैंने कल भी आपसे यह कहा था कि सत्र की नोटिफिकेशन 3 दिन के लिए की गई है। 3 दिन में हमने पहले राज्यपाल महोदय का अभिभाषण और उसके बाद लेजिसलेटिव बिजनैस को ट्रांजैक्ट कर लिया है। इसके अगले दिन प्रश्नकाल प्रारंभ होता है। सभी माननीय सदस्यों को यह अधिकार है कि वे अपने प्रश्न, अपने सारे नोटिसिज जिन-जिन नियमों के तहत देना चाहते हैं, वे दें। जब

सेशन नोटिफाई हो गया और पोर्टल नहीं चल रहा है तो आप अपने प्रश्न/नोटिसिज रिटन में दे दें। पोर्टल नहीं चलने का कारण यह है कि हम अभी 'नेवा' के ऊपर शिफ्ट हुए हैं। वैसे हमारा ई- विधान मॉडल बहुत एडवांस था जिसको सारी कंट्रीज ने अडॉप्ट किया है। हमें भी लोकसभा या केंद्रीय मंत्रालय द्वारा यह कहा गया कि आप 'नेवा' पर शिफ्ट हो जाएं और अब हम इस टेक्नोलोजी पर काम कर रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में जहां पहुंच चुके थे, शिफ्ट होने के बाद नेवा हमारे मॉड्यूल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इस संदर्भ में मैंने बार-बार दिल्ली में आयोजित सम्मेलनों में केंद्रीय मंत्री जी से यह बात कही है और वह भी इस बात को मान रहे हैं। देश की अन्य विधान सभाओं ने भी अपने मॉड्यूल के साथ-साथ नेवा पर कार्य किया है। Likewise we are also reviving our own e-Vidhan application. साथ में हम नेवा पर भी काम करेंगे। आप सभी माननीय सदस्य अपने नोटिसिज दे सकते हैं। डायरेक्ट, एन0आई0सी, गवर्नमेंट आफ इंडिया ने कहा है कि पोर्टल पर सभी जानकारियां मिल रही हैं और माननीय सदस्यों के प्रश्न आ रहे हैं। लगभग 125 प्रश्न पहले ही आ चुके हैं जिनमें 111 ओरली और 14 के करीब रिटन प्रश्न हैं। हमने इन प्रश्नों को लिस्ट करना शुरू कर दिया है। हमने आज स्थगित प्रश्न लिस्ट किए हैं। जो इस बार माननीय सदस्यों ने दिए प्रश्न दिए हैं उन्हें लिस्ट किया गया है। इसलिए आप और प्रश्न दीजिए क्योंकि यह सत्र लम्बा चलना है। अभी इस सत्र के 15-20 दिन और हैं इसलिए आपके प्रश्न भी लगेंगे शून्यकाल भी आरंभ होगा। जो भी नोटिसिज आएंगे उन पर चर्चा होगी। This, I can assure to all the Hon'ble Members of this Hous

16.02.2026/1105/DT/AS-2

स्थगित **प्रश्न संख्याः 3055**

श्री विनोद कुमार : मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है 'जी हां।' विभिन्न विभागों में पदोन्नति एवं सेवानिवृत्ति होने के कारण पद रिक्त हुए हैं जिनका रिक्त होने का कारण पात्र उम्मीदवारों का न मिलना है। आपने इस प्रश्न के उत्तर में कहा है कि विभाग

को पात्र उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। दूसरी ओर आपने देखा होगा कि हमारे दिव्यांगजन आज से नहीं बल्कि गत तीन वर्षों से राज्य सचिवालय के बाहर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने यह भी देखा होगा कि वह इस ठंड के मौसम में भी वहीं बैठे थे। सरकार ने उनके पास जाकर उनकी कोई बात नहीं सुनी। सरकार ने उनके विषयों को लेकर कोई चिंता नहीं की बल्कि सरकारी अधिकारी उन्हें जरूर डराने-धमकाने का कार्य कर रहे हैं। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि जो दिव्यांगजन धरने में बैठे हैं क्या उनके पास जाकर सरकार उनकी बात सुनना सुनिश्चित करेगी? इन्होंने कहा है कि इन्हें पात्र उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। अगर आपको पात्र व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं तो दिव्यांगजनों की जितनी भी भर्ती होनी है उसमें रिलैक्सेशन दें।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी

17.02.2026/1110/डी.सी.-एन.जी./1

प्रश्न संख्या - 3055.........जारी श्री विनोद कुमार.......... जारी

ताकि उन लोगों को नौकरी मिल सके।

तीसरा मैंने यह भी पूछा था कि सरकार ने दो वर्षों में कितनी भर्तियां की हैं? मैं प्रश्न के उत्तर में देख रहा था कि दिव्यांगजनों के 1459 पद रिक्त पड़े हुए हैं और प्रदेश सरकार ने केवल 101 पदों को ही भरा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इन रिक्त पदों को जल्दी-से-जल्दी कब तक भर दिया जाएगा, इस बात को माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अपने उत्तर में अवश्य कहें?

इसके अलावा उत्तर में कहा गया है कि दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित, बैकलॉग के सभी पदों को भरने हेतु दिनांक 12 नवम्बर, 2025 को मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता

में हुई बैठक में सभी विभागों को प्राथमिकता के आधार पर भरने बारे निर्देश दे दिए गए हैं और वर्ष में दो बार दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित पदों को भरने के लिए निश्चित समय-सारणी भी निर्धारित की गई है। मेरा माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से निवेदन रहेगा कि बैकलॉग के तहत होने वाली भर्तियों के लिए इतना लम्बा समय क्यों लिया जा रहा है? मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जितनी भी बैकलॉग के तहत भर्तियां होनी हैं, उसके लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें और उसी समय सीमा में इन भर्तियों को जल्दी किया जाए।

17.02.2026/1110/डी.सी.-एन.जी./2

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिंता से भली-भांति अवगत हूं। सचिवालय के बाहर जो लोग धरने पर बैठे हुए हैं, मैं स्वयं उनसे मिला हूं। मैं जानता हूं कि उनकी कुछ समस्याएं काफी जटिल हैं और राजनीति के कारण भी उन्हें प्रेरित कर दिया जाता है। हमारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस परिस्थिति पर लगातार नज़र बनाए हुए है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को अवगत करवाना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री ने इस दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। यदि माननीय सदस्य कभी मुख्य मंत्री सुखाश्रय योजना के तहत लूथान नामक स्थान जोकि ज्वालामुखी विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है...(व्यवधान) यह विषय इसी से संबंधित है क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि वह कितना बड़ा फोकस है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर दिव्यांगजनों के लिए बहुत बड़ा संस्थान बन रहा है। हालही में कण्डाघाट (सोलन) के नजदीक क्वारग नामक स्थान पर लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से दिव्यांगजनों के लिए संस्थान बनाया जा रहा है और उस संस्थान में सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के आज के मूल प्रश्न के संदर्भ में बताना चाहता हूं कि उम्मीदवारों का न मिलना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। पात्र व्यक्ति न होने के कारण कुछ व्यक्ति धरने पर बैठ जाते हैं और कुछ माननीय उच्च न्यायालय में चले जाते हैं। इस प्रकार के कुछ तकनीकी कारण होते हैं और यदि हम अपात्र व्यक्ति को चुन लेते हैं तो फिर से एक धरना शुरू हो जाएगा। माननीय सदस्य ने जैसा कहा है कि दिनांक 12 नवम्बर, 2025 को मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो बैठक ली थी, उसमें हरेक विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं कि दिव्यांगजनों के 1459 रिक्त पड़े पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी जाए। **मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अभी तो केवल 101 पदों को ही भरा गया है लेकिन शेष पदों को चरणबद्ध तरीके से भर दिया जाएगा।**

17.02.2026/1110/डी.सी.-एन.जी./3

श्री सतपाल सिंह सत्ती : अध्यक्ष महोदय, मैंने व माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार ने दिव्यांगजनों की नौकरी शीघ्र लगने के संदर्भ में प्रश्न किया है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री से आग्रह रहेगा कि आप इस मामले में स्वयं इंटरवीन कीजिए क्योंकि दिव्यांगजन बहुत लम्बे समय से सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। अनेकों बार ऐसी खबरें भी आई हैं कि उन दिव्यांगजनों के साथ धक्का-मुक्की हुई, कोई नाली में गिर गया, किसी के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ और किसी की टांग भी टूट गई थी। जिन लोगों को परमात्मा की ओर से पहले ही कष्ट मिला है या उनके शरीर में कोई दिक्कत है तो उन व्यक्तियों के संदर्भ में सरकार को विशेष रूचि रखनी चाहिए। मेरा आग्रह है कि बैकलॉग के जो 1459 पद रिक्त पड़े हैं, उन पदों को प्राथमिकता के आधार पर जल्दी-से-जल्दी भरना चाहिए या जहां पर भी इन्हें समायोजित कर सकते हैं, उसे करने के लिए एक समय-सीमा निर्धारित करनी चाहिए और दिव्यांगजनों को नौकरी देनी चाहिए। मेरा आग्रह है कि सरकार की ओर से इस विषय पर पूरा आश्वासन दिया जाए और इन पदों को समय-सीमा के तहत भरा

जाए। ताकि दिव्यांगजनों को आंदोलन से भी राहत मिले और इस ठंड भरे मौसम से भी उनका बचाव किया जा सके तथा वे सभी अपने-अपने घरों की ओर जा सकें।

स्वास्थ्य मंत्री.....श्री ए0पी0 द्वारा......जारी

17.02.2026/1115/डी.सी./ए.पी/01

प्रश्न संख्या 3055 जारी.....

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, there is a formula. जो हमारी भर्तीयां है उसमें 4 प्रतिशत का फार्मूला है और उन्हें भरने का तरीका क्या है? अध्यक्ष महोदय मैं बताना चाहता हूं कि यह blind, low vision, deaf and hard of hearing, locomotor disability and multiple disabilities वालो से संबंधित हैं, उनके लिए एक-एक प्रतिशत बांटा हुआ है तो चार प्रतिशत देने के बाद जो अन्य पद बच भी जाते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सितंबर और अप्रैल साल में दो बार यह प्रक्रिया होती है। लेकिन हमने एक चार्ट बनाया है जिससे हर महीने इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। **उस चार्ट के अनुसार, जैसा दोनों माननीय सदस्यों ने कहा उनकी इस बात पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। इसे मन्थवाईज मॉनिटर किया जा रहा है और रिक्त पदों को भरा जाएगा।**

17.02.2026/1115/डी.सी./ए.पी/02

स्थगित **प्रश्न संख्या : 3538**

श्री सतपाल सिंह सत्ती : अध्यक्ष महोदय, जो मैंने प्रश्न किया है कि सरकार के कितने सरकारी भवन खाली हैं। मुझे लगता है कि उसका रिकॉर्ड तो सरकार को सीधे जिला मुख्यालय से मिल जाना चाहिए था। लेकिन इसमें भी, जैसा कि ज्यादातर प्रश्नों के उत्तरों में होता है, सूचना एकत्रित की जा रही है। यह तो सरकार के पक्ष का प्रश्न है कि कौन-सी बिल्डिंग खाली है और कई जगहों पर आज भी हमारे सरकारी दफ्तर किराए की बिल्डिंगों में चल रहे हैं। जबकि हमारे अपने भवन खाली पड़े हैं। पैसे बचाने के चक्कर में हम लोग अपने भवन खाली छोड़ रहे हैं और प्राइवेट लोगों को किराए का पैसा दे रहे हैं। इसी से संबंधित मैंने प्रश्न किया था। अगर इसकी सूचना जिला मुख्यालय या तहसील मुख्यालय स्तर पर एकत्रित नहीं की जा रही है तो आप लोग स्वयं इस पर ध्यान दें। मुझे लगता है कि अगर मुख्य मंत्री जी आग्रह करेंगे, आदेश देंगे तो आपके पास भी रिकॉर्ड आएगा और आप वहां पर दफ्तर शिफ्ट कर सकते हैं और अपना पैसा बचा सकते हैं, इसी से संबंधित यह प्रश्न था।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा बहुत महत्वपूर्ण सूचना दी गई है। अभी तक हमारे पास करीब 600 खाली भावनों का रिकॉर्ड आया है। तो मैं बताना चाहता हूं कि 600 के करीब खाली भवन है और अभी कई अन्य डिपार्टमेंट हैं जिनमें 29 से 40 के करीब डिपार्टमेंट हैं। इसके अलावा कॉरपोरेशन बोर्ड है। इस सदन में मैं कोशिश करूंगा की अंतिम सप्ताह तक पूरी सूचना एकत्रित कर ली जाए। **अभी तक हमारे पास 600 के करीब खाली भवनों का रिकॉर्ड आया है। जैसे ही पूरा रिकॉर्ड आएगा आपको सूचना उपलब्ध करवा दी जाएगी।**

अध्यक्ष : इसी सत्र के अंत तक सूचना उपलब्ध करवाई जाए।

17.02.2026/1115/डी.सी./ए.पी/03

स्थगित **प्रश्न संख्या : 3583**

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय,मेरा बहुत सिंपल का प्रश्न था कि प्रदेश में कितनी सहकारी सभाएं पंजीकृत है और कितने अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है। वन टाइम सेटलमेंट कितनी सभाओं में हुई है। इतना सिंपल प्रश्न है और इस प्रश्न के बीच में कौन-सा ऐसा विषय है जिसके कारण से सूचना को एकत्रित करने की बात कही जा रही है। माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि कृपया बताएं कि यह मामला क्यों लटक रहा है। कई बार अखबारों में भी आ रहा है कि इसको दण्ड मिला, इसको दण्ड मिला, यहां पर ये डिफॉल्टर है, तो सदन के अंदर भी इस तरह के विषय आने चाहिए।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो हमारे मित्र और माननीय सदस्य ने जो यह सवाल पूछा है यह बहुत लेंथी सवाल है जैसा यह प्रेजेंट कर रहे हैं, वैसा नहीं है। इस प्रश्न पर लाखों रुपये का खर्चा है और इसकी सूचना एकत्रित करते-करते कागजों के बहुत भंडार भर जायेंगे। क्योंकि बहुत-सी कोऑपरेटिव सोसाइटी में घपले हुए हैं। मैं तो चाहूंगा कि आप इस सवाल को विदड्रॉ कर ले। किसी पार्टिकुलर मैटर में अगर आपका इंटरेस्ट है तो मैं आपको वह सूचना उपलब्ध करवा देता हूं। अन्यथा इसमें थोड़ा समय लग सकता है।

अध्यक्ष : उप-मुख्य मंत्री जी कोशिश करें कि इसी सत्र में सूचना दी जाए।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

17/02/2026/1120/AT/HK/01

प्रश्न संख्या 3583 जारी.....

श्री बि**क्रम सिंह** : माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न विदड्रॉ नहीं किया जायेगा। यदि इसके लिए अधिक समय चाहिए तो वह भी लिया जाए, लेकिन यह अवश्य पता लगना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, कहां-कहां गड़बड़ी है और कहां-कहां

लाखों रुपये के घोटाले हुए हैं। यदि इस सत्र में उत्तर देना संभव नहीं है तो अगले सत्र में दें, और यदि उसमें भी नहीं तो उसके अगले सत्र में दें, लेकिन जब तक हम यहां बैठे हैं, तब तक इसका उत्तर अवश्य दिया जाए।

उप मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, सूचना छिपाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। यह सदन इसलिए बना है कि सूचना रखी जाए। **लेकिन इसकी सूचना काफी विस्तृत है फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि इसे जितनी जल्दी संभव हो सके इसकी सूचना आपको उपलब्ध करवाई जाए।**

17/02/2026/1120/AT/HK/02

प्रश्न संख्या 3834

श्री सुधीर शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सभा पटल पर जो सूचना रखी गई है उसमें 59 सड़कें दर्शाई गई हैं। इसमें एफ0आर0ए0 स्वीकृत हुआ है। क्या यह सत्य है कि सड़क निर्माण के लिए एफ0आर0ए0 लेना आवश्यक होता है और इसके लिए कोई बजटरी प्रावधान रखा जाता है? यदि हां, तो जिन सड़कों का एफ0आर0ए0 हो चुका है वे किस-किस हेड में निर्मित हो रही हैं?

लोक निर्माण मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सुधीर जी द्वारा पूछा गया प्रश्न self-explanatory है। उन्हें समस्त जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। जिला कांगड़ा में 59 सड़कें विभिन्न हेड्स में स्वीकृत हुई हैं कुछ Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana के अंतर्गत, कुछ नाबार्ड के तहत तथा कुछ राज्य हेड में, इनमें टोकन अमाउंट कोड के माध्यम से स्वीकृत करवाया जाता है और उसके अनुसार बजट में उल्लेख किया जाता है। जब बजट की किस्त आती है, then the work proceeds. Because the FRA is only limited to a span of one hectares, इससे अधिक होने पर एफ0सी0ए0 का मामला बनता है। एक हेक्टेयर में 75 से अधिक पेड़ नहीं काटे जा सकते। इसलिए संबंधित हेड के तहत टोकन बजट का प्रावधान किया जाता है।

श्री सुधीर शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से जानना चाहता हूं कि इन सड़कों के लिए एफ0आर0ए0 हेतु जो टोकन अमाउंट दिया गया है वह किस-किस हेड से आया है? यदि एफ0आर0ए0 हो गया है तो क्या सरकार इन सड़कों के निर्माण के लिए नियमित बजटरी प्रावधान किस हेड में करेगी?

17/02/2026/1120/AT/HK/03

लोक निर्माण मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, as far as I know टोकन अमाउंट राज्य हेड से भी दिया जाता है। कुछ मामलों में विधायक निधि से भी यह राशि दी जाती है। कई स्थानों पर डी0सी0 के माध्यम से भी प्रावधान किया गया है। जहां-जहां से भी यह संभव हो सके क्योंकि यह एक nominal amount है for the initiation of the case so that has been done. जब एक बार सैंक्शन हो जाता है और बजट स्वीकृत हो जाता है तो संबंधित हेड से ही आगे की राशि जारी की जाती है।

Speaker : Hon'ble Chief Minister wants to supplement the Hon'ble Minister.

मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इस मामले में एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि विधायक निधि से भी एफ0आर0ए0 के लिए राशि दी जा सके।

Speaker : This is already there.

मुख्य मंत्रीः जो नोटिफिकेशन अभी वापस (withdraw) हूई है उसे पुनः जारी कर दिया जाएगा।

17/02/2026/1120/AT/HK/04

प्रश्न संख्या 3835

श्री राकेश कालिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यद्यपि प्रश्न का उत्तर 400 पृष्ठों में दिया गया है। मेरी चिंता यह है कि कुछ लोग

दिल्ली में बैठकर योजनाओं का अध्ययन कर लेते हैं और उन्होंने वहां गग्गल एयरपोर्ट के अंदर लैंड बैंक बना रखा है।

एम0डी0द्वारा जारी ……

17-02-2026/1125/HK/MD/1

श्री राकेश कालिया---जारी प्रश्न संख्या : 3835--जारी

और सैंकडों गरीब लोगों की जमीन आधे-पोने दामों में खरीदी गई है। पहले वह हमारे कांग्रेस के एडवाइजर बने थे और आजकल बी0जे0पी0 के एडवाइजर बने हैं। जोकि रिटार्यड अधिकारी हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन गरीब लोगों के आधे-पोने दामों पर इन लोगों ने जमीन खरीदी हैं क्या सरकार उनके ऊपर कोई कार्रवाई करेगी? जो जमीन हाल ही में, पिछले डेढ़ साल या दो साल के अंदर खरीदी या बेची गई है, या जिनके बेनामी सौदे हुए हैं, क्या आप उन पर कार्रवाई करेंगे? मैं बताना चाहता हूं कि हमने तो उन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए हैं, क्योंकि इन्होंने वहां पैसे इकट्ठा करने का दूसरा कल्चर लाया था ठेकेदारों से परसेंटेज लेने का। हमने आठ लाख रुपये का एक मुकदमा उनके ऊपर दर्ज कर रखा है। उत्तराखंड के लोग पैसा ले गए हैं। यही दलाल अब गग्गल एयरपोर्ट में दखलअंदाजी कर रहे हैं। उस केस में भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि शिमला से कुछ हो नहीं पा रहा। आप लोग कुछ कर नहीं रहे। केस वैसे का वैसा पड़ा है। एस0पी0 ने फाइल वैसे ही रखी हुई है। इन लोगों के खिलाफ दलाली खिलाई गई है और उत्तराखंड के लोगों के खातों में पैसा ट्रांसफर हुआ है। दो नंबर का पैसा एक नंबर में कन्वर्ट हुआ है। इसी तरह गग्गल एयरपोर्ट पर भी हेरा-फेरी हो रही है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि ऐसी जमीन लोगों को वापिस दिलाई जाएगी या उन्हें उनका हक दिलाया जाएगा। मैं यह जानना चाहता हूं।

17-02-2026/1125/HK/MD/2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री राकेश कालिया जी ने जो बात ध्यान में लाई है, वैसे आउटसाइडर को अगर जमीन खरीदनी हो तो धारा 118 के तहत परमिशन लेनी पड़ती है। अगर 118 की परमिशन ली गई है और उसके बाद एयरपोर्ट के लिए उस

समय जगह खरीदी गई है, तो उस बात की जानकारी अभी हमारे पास स्वीकृत रूप में नहीं है पर जो बात माननीय सदस्य ने उठाई है कि उत्तराखंड का एक व्यक्ति है, जिस पर केस है, उसने बाहर की जगह ली और पैसे खाए उस मामले की हम इंक्वायरी करवाएंगे। इंक्वायरी में जो भी तथ्य सामने आएंगे सरकार कानून के अनुसार जो कार्रवाई बनती होगी वह करेगी। अगर कोई भी व्यक्ति दलाली के रूप में जगह का बयाना देकर आगे बढ़ा है, तो उसमें कानून क्या कहता है, उसी आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि प्रोजेक्ट आते रहेंगे और बनते भी रहेंगे। अब सवाल यह है कि आउटसाइडर जमीन कैसे खरीदेगा, क्योंकि हिमाचली के अलावा किसी और के लिए कानून है। आउटसाइडर को 118 के तहत सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। **अगर किसी ने बेनामी ट्रांजैक्शन की है और 118 की परमिशन नहीं है, तो ऐसी जगह को हम जब्त करेंगे और उसका मुआवजा भी नहीं देंगे। अगर वह सरकारी जमीन होगी तो वह सरकार की ही रहेगी। ऐसे जो केस सदन के ध्यान में आते हैं कि किसी गरीब आदमी की जगह किसी ने बेनामी ट्रांजैक्शन से ले ली और बाद में जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है और हम लैंड एक्विजिशन करते हैं, तो ऐसे मामलों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।**

17-02-2026/1125/HK/MD/3

श्री राकेश कालिया : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि आप उस व्यक्ति को जानते भी हैं। वह उत्तराखंड का रिटायर्ड अधिकारी है और उसके बेटे पर दलाली खाने का आरोप लगा है। पहले वह दलाल बना हुआ था और आजकल वह ‘शुगर डैडी’ बना हुआ है। इलाके के बहुत से लोगों को इस तरह से एक्सप्लॉइट किया गया है। मुख्य मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है, लेकिन मैं पक्के तौर पर आश्वासन चाहता हूं कि जिन उत्तराखंड के लोगों के खातों में पैसा गया है, उन्हें पकड़कर यहां लाया जाएगा? हमने मुकदमा दर्ज कराए हुए एक साल हो गया है। क्या उनका इन्वेस्टिगेशन जॉइन करवाया जाएगा? क्योंकि वह केस आगे बढ़ ही नहीं रहा है। एक और मामला मैं मुख्य मंत्री महोदय के ध्यान में लाया था कि फिश फार्म के जो मोटरसाइकिल हैं वे अजीब तरीके से बांटे गए हैं अपने लोगों को, अपने वर्कर्स को बांटे गए हैं। उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह पूरा एक क्लब है अनियमितताओं का। मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहता हूं कि गगरेट विधान सभा क्षेत्र में उस समय जो इतनी अव्यवस्था फैली

थी, उसकी पूरी इंक्वायरी कराई जाएगी। एक ही व्यक्ति है, जिसका हर जगह हाथ रहा है यहां तक कि हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार तोड़ने में भी उसका हाथ बताया जाता है। आज वह दिल्ली में बैठकर हेरा-फेरी कर रहा है, पहले गगरेट में बैठकर कर रहा था। ऐसे व्यक्ति के ऊपर कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन बढ़ाई जानी चाहिए, जिसने यू0पी0 कल्चर यहां हिमाचल प्रदेश में लाने की कोशिश की है। मैं मुख्य मंत्री जी से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बड़ा और महत्वपूर्ण मसला उठाया है और जो केसिज से संबंधित बातें सामने आई हैं उनकी पूरी इंक्वायरी करवाई जाएगी। इसका मैं आश्वासन देता हूं। मैं पुलिस की एक एस0आई0टी0 गठित करूंगा जो इस मामले की जांच करेगी। माननीय सदस्य श्री राकेश कालिया जी के पास जो भी प्रूफ हैं वे माननीय डी0जी0पी0 को दें और उसकी एक कॉपी मुख्य मंत्री जी को भी दें। **उसके खिलाफ जो भी एफ0आई0आर0 दर्ज हुई है और उस एफ0आई0आर0 पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है इसकी भी जांच करवाई जाएगी। हमारी सरकार इस प्रकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी।**

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी---
17.02.2026/1130/केएस/वाईके/1

प्रश्न संख्या 3836

श्री दीप राज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो 31 मार्च तक बचे हुए पैंडिंग सब्सिडी के केसिज़ हैं, क्या उन सभी को सब्सिडी दी जाएगी?

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो पैंडिंग सब्सिडीज़ हैं, जो धनराशि उपलब्ध होगी, यह उसके ऊपर निर्भर करता है।

श्री दीप राज : अध्यक्ष महोदय, जो ऑलरेडी पिछले बजट में मैंशन किया गया था, मैं उसके बारे में पूछ रहा हूं यानी 31 मार्च तक के बारे में जानना चाहता हूं। मैं उसके बाद की बात नहीं कर रहा हूं। 31 मार्च तक के जितने इस वर्ष के पैंडिंग केसिज़ हैं, मैं उनकी बात

कर रहा हूं। आर0डी0जी0 तो चलो आगे की बात है लेकिन 31 मार्च तक बता दें क्योंकि मेरे चुनाव क्षेत्र में कुल 1,89,460 रुपये ही सब्सिडी दी है।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य का मूल प्रश्न है वह कीटनाशक और फंफूदनाशक के ऊपर कितनी सब्सिडी दी गई है, उसके बारे में है। उसका जवाब मैंने दे दिया है बाकी जो ये पैंडिंग के बारे में पूछ रहे हैं, अगर ये दूसरा प्रश्न करेंगे तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। इस प्रश्न से उसका ताल्लुक नहीं है। अगर ये अलग से प्रश्न करेंगे तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : दीप राज जी, मंत्री जी ने कह दिया है कि जो पैंडिंग है as per the availability of funds दे देंगे। मंत्री जी, माननीय सदस्य जानना चाह रहे हैं कि उनको क्या इसी फाइनेंशियल ईयर में यह सब्सिडी मिल जाएगी या नहीं?

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह वर्तमान बजट के ऊपर निर्भर करेगा। यह कोई पिछले साल की पैंडेंसी नहीं है। उससे पहले से भी पैंडिंग है और हम हर साल कुछ न कुछ देते हुए इस पैंडेंसी को कम कर रहे हैं। **इस बार भी हमसे जितना हो सकेगा हम पूरा प्रयास करेंगे।**

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इनको लिखित में डिटेल दे दें।

17.02.2026/1130/केएस/वाईके/2

प्रश्न संख्या : 3837

श्री कुलदीप सिंह राठौर : (अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या : 3838

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल : अध्यक्ष महोदय, अंडर ग्राउंड यूटिलिटी डक्ट जो कि छोटा शिमला से लेकर विल्ली पार्क चौड़ा मैदान तक बिछाई जा रही है, मैं इसके लिए सरकार का धन्यवाद भी करना चाहूंगा क्योंकि काफी लम्बे समय से इस डक्ट को बनाने की

आवश्यकता थी लेकिन बाजार के व्यापारी लोगों को एक अंदेशा है कि कहीं इसकी वजह से उनको भविष्य में कोई परेशानी ना आए क्योंकि जब पीछे भी 10-15 वर्ष पहले पानी की लाइन बिछाई गई थी, आपको याद होगा कि वह स्कैंडल प्वाइंट के पास फट गई थी। एक-दो जगह आकाशवाणी से आगे बालूगंज रोड में भी फट गई थी जिसकी वजह से भारी नुकसान हुआ था। शिमला शहर का जियोलोजिकल स्ट्रेटा कहीं पर हार्ड है और कहीं पर नरम है। जो लूज़ स्ट्रेटा है, कल को उसमें कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए इसमें जो एस्टिमेट बने हैं, पूरी गुणवत्ता के साथ क्या उसके ऊपर पूरा अध्ययन किया गया है? ऐसा ना हो कि आने वाले समय में यह जी का जंजाल बन जाए। मालरोड और लोअर बाजार के व्यापारियों को अंदेशा है कि कहीं उसमें सीपेज ना हो जिसकी वजह से मालरोड और लोअर बाजार ध्वस्त ना हो जाए। कृपया हमारे शिमला शहर के लोगों का जो अंदेशा है,उनको जो खतरा महसूस हो रहा है, उनके साथ बैठकर चर्चा की जाए और उन्हें भरोसा दिया जाए कि इस डक्ट के बनने से भविष्य में कोई नुकसान नहीं होगा। यह एक अच्छी योजना बनी है लेकिन

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ...

17.02.2026/1135/av/yk/1

प्रश्न संख्या : 3838 ----- क्रमागत

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल------- जारी

इसके साथ-साथ उनकी परिसम्पत्तियों का ठीक रहना भी जरूरी है। कृपया उन व्यापारियों के साथ बैठक करके उनको यह बता दिया जाए कि इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, शिमला को सुन्दर बनाने के लिए छोटा शिमला से लेकर पूरे शिमला में डकट बिछाने का एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। पूरे शिमला में ओवरहैड बिजली की तारों का जाल बिछा हुआ है। उसके बाद टेलीकॉम कम्पनियां भी पेड़ों पर तारों का जाल बिछाती चली गईं। इस बारे में एक स्टडी करवाई गई और उस स्टडी के बाद मेरी माननीय मंत्री और अन्य अधिकारियों के साथ कई बार वार्तालाप हुई हैं। शिमला

हमारे प्रदेश की राजधानी है इसलिए यहां डकट बनाने का फैसला लिया गया। उस डकट की स्टडी करने के लिए हमारी टीम जयपुर और देश के दूसरे स्थानों पर गई। इसकी क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाईज नहीं किया जा रहा है। शिमला में बिजली या टेलीकॉम इत्यादि की तारों और पानी की पाइप्स के लिए अब सड़कों को बार-बार नहीं खोदा जाएगा। यह योजना लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जा रही है। एक बार तो मैंने, माननीय मंत्री, विधायक श्री हरीश जनारथा और सचिव महोदय ने इसका विज़िट भी किया है। जिस प्रकार से अण्डर ग्राउंड कॉम्प्लैक्स बनता है उसी प्रकार की यह डकट बनाई जा रही है। अगर पानी के लिकेज की बात की जाए तो इसके लिए पानी की एक मेन सप्लाई लाइन जा रही है। इसके अलावा अगर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स डालनी होंगी तो उसके लिए हमने चैनल बनाकर रखे हैं कि वहां से डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स को निकाला जाएगा। आने वाले समय में अगर बिजली की तारें डालनी होंगी तो प्रत्येक सौ मीटर या 50 मीटर पर डकट्स बनाई गई हैं। माननीय विधायक की जो चिंता है कि शेरे पंजाब से लोअर बाजार, सब्जी मण्डी इत्यादि एरियाज में क्या करना है क्योंकि वहां पर तो बहुत बड़ी डकट नहीं बन सकती। छोटा शिमला, लिफ्ट, स्कैण्डल प्वाइंट और चौड़ा मैदान के एरिया में तो सभी प्रकार की ओवरहैड तारों को अण्डर ग्राउंड करने के लिए डकट बनाई जाएगी। लेकिन लोअर बाजार की डकट्स में पानी की पाइप्स डाली जाए या नहीं; इस बारे में

17.02.2026/1135/av/yk/2

अभी अध्ययन किया जा रहा है। आप लोअर बाजार में तारों का जाल देखेंगे तो पाएंगे कि अगर अपने घर पर ही किसी छोटे बच्चे या व्यक्ति का गलती से बिजली की तार में हाथ लग जाए तो उसको कंरट लग जाएगा। इसलिए इस बारे में अभी स्टडी कर रहे हैं। शेरे पंजाब से सी0टी0ओ0 तक पूरी स्टडी करने के बाद ही सरकार आगे बढ़ेगी। निचली तरफ जो सब्जी मण्डी का कॉम्प्लैक्स है उसमें सरकार ने 500 करोड़ रुपये की लागत से एक प्रोजैक्ट बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। शिमला को सुन्दर बनाने के दृष्टिगत पूरी सब्जी मण्डी, मीट मार्किट और ग्राउंड को ठीक करने का काम किया जाएगा। शिमला हमारे प्रदेश की एक पहचान है और पर्यटकों के लिए एक रमणीक स्थल भी है। इसलिए

हम यह चाहते हैं कि यहां आने वाले पर्यटकों को यह न लगे कि यहां पर चारों तरफ तारें-ही-तारें हैं। इससे एक फायदा यह भी होगा कि आपकी पानी और बिजली की सप्लाई 24X7 रहेगी। हमने धन के सही उपयोग की दिशा में आगे बढ़ना है।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, यह जो अण्डर ग्राउंड यूटिलिटी डकट का जिक्र हो रहा है; इस बारे में पहले भी विचार किया गया था परंतु किसी कारण से यह प्रोजैक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। यहां पर जैसे मुख्य मंत्री जी ने जिक्र किया कि इनकी टीम ने देश के दूसरे राज्यों में जाकर इस बारे में अध्ययन किया है तो मैं कहना चाहता हूं कि हिली टैरेन और फ्रैज़ाइल स्ट्रैटा होने के कारण उस वक्त भी बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए थे जिसके कारण हमें उस समय रुकना पड़ा था। शिमला में रिज जब चारों तरफ से धंस रहा था तो उसको रिस्टोर करने के लिए हमने बहुत सारी स्टडी की थी। उस समय आई0आई0टी रुड़की की ओर से एक प्लान किया गया जिसमें हम लोग आगे बढ़े थे। लेकिन इस काम में हमें रुकना पड़ा।

टी सी द्वारा जारी

17.02.2026/1140/टी0सी0वी0/ए0जी0-1
प्रश्न संख्या : .3838… क्रमागत् श्री जय राम ठाकुर .. जारी

हम इस बात से सहमत हैं कि स्टेट कैपिटल है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यह अच्छी और सुंदर होनी चाहिए। लेकिन इसी बात को लेकर बहुत-बड़ी आशंकाएं हैं कि शिमला में यदि थोड़ी-सी भी कहीं खुदाई की जाती है तो यहां मिट्टी ऐसी है कि उसको ठिकाना मुश्किल हो जाता है। सचिवालय से लेकर जहां तक यह डक्ट खोदा गया है वहां तक स्ट्रेटा ठीक है, लेकिन जो आगे वाला पोर्शन है, वहां बहुत-सी जगह इस बात को लेकर प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि क्या इसका अध्ययन ठीक तरह से हुआ है या नहीं। आप सड़क के नीचे जो कटिंग करवा रहे हैं उस कटिंग के बाद वहां जो स्थिति बन रही है, वह ऐसी बन रही है जिसके कारण सड़क टूटने की संभावना हो सकती है और इससे शिमला शहर को खतरा उत्पन्न होने की स्थिति बन सकती है ।

दूसरी बात, मैं इस विषय को लेकर मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इन सारी चीजों को लेकर स्टडी हुई है क्योंकि अल्टीमेटली जब स्ट्रेटा एक बार थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है तो बरसात के मौसम में शिमला और हमारे हिमाचल जैसे प्रदेश में उसको ठिकाना मुश्किल हो जाता है।

तीसरा, अध्यक्ष महोदय, जो पोर्शन आपने बनाकर तैयार कर दिया, जहां आपने डक्ट में तार या पाइपें बिछा दी है उसको शीघ्र चलने लायक बनाया जाए क्योंकि वहां बहुत-बड़ी दुर्घटना हो सकती है। सचिवालय से लेकर आपके निवास तक डक्ट के ढक्कन खुले पड़े हुए हैं। आपने वहां से गाड़ी चलाना शुरू कर दिया है लेकिन वहां संकेत या कोन लगाए जाने चाहिए ताकि दूर से मालूम पड़े कि यहां कुछ कार्य चल रहा है। आज भी मैं वहां से होकर आया, आपके मुख्य मंत्री निवास के पीछे भी गड्ढे खुले पड़े हुए हैं। वहां डक्ट पर कवर नहीं लगे हैं लेकिन उसके बावजूद भी कार्य जारी है।

अंत में, जितनी भी चीजें की जा रही हैं उनको युद्ध-स्तर पर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। इस प्रोजैक्ट को कई-वर्षों तक चलाए रखना उचित नहीं है। शिमला को

17.02.2026/1140/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

पूरी तरह से उखाड़ कर रखना उचित नहीं है। इसके कारण कुछेक एरिया में तो एंबुलेंस के लिए भी कठिनाई हो रही है। वहां पर यातायात की सुविधा ठीक प्रकार से हो यह भी सुनिश्तिच किया जाना चाहिए। इसके लिए सेफ्टी मेयर्स लेने की आवश्यकता है लेकिन उसको अभी तक भी खुला ही रखा गया है। इसके कारण पूरा शहर बदसूरत हो गया है।

मुख्य मंत्री : अध्य महोदय, आपने नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी को पूरे 4 मिनट का समय दिया और इन्होंने इसमें पूरा राजनीतिक विवेचन किया। मैं आपको याद दिला रहा हूं कि आप क्या-क्या बोल रहे थे...(व्यवधान)

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। स्टेट कैपिटल सबका है। मैंने कहा कि वहां गहरी खुदाई की गई है और उससे न जाने कितने लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, ये मुख्य मंत्री है तो इसका मतलब यह

कदाचित नहीं है कि ये कुछ भी बोलते रहे। ...(व्यवधान) मुझे इनकी टिप्पणी पर ऐतराज है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको इनकी बात के बारे में ही बता रहा हूं। आप गुस्सा मत करें। आप मेरी टिप्पणी पर ऐतराज तब करते यदि मैं कोई ऐसी बात बोल रहा होता जो आपने नहीं कही है। आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं।

श्रीमती एन0ए0 द्वारा जारी ...

17-2-2026/1145/एन0एस0-ए0जी0/1

प्रश्न संख्या : 3838-----क्रमागत मुख्य मंत्री -----जारी

आप तो स्वभाव से गुस्से वाले नहीं हैं। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपने चार मिनट का समय लिया है और मुझे दो मिनट तो बोलने दीजिए। ...(व्यवधान) इन्होंने कहा कि हम विचार कर रहे थे। ...(व्यवधान) आप गुस्से में न बोलें। मैंने उस पर कोई गलत टिप्पणी नहीं की। आप विचार करते रहे। पहले ही पूरे शिमला शहर में कंकरीट का जंगल खड़ा कर दिया है। इन्होंने कहा मैं तब कह रहा हूं। इन्होंने कहा कि आपने पहले इसकी स्टडी करवाई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने स्टडी करवाई है और दो प्रदेशों जम्मू-कश्मीर व जयपुर में इसके लिए गए। तीसरी, इन्होंने बात कही कि इसका स्ट्रेटा यह है। मैंने कहा कि वे सारा हमने देखा है। मेरे जीवन के 55 साल शिमला में ही बीते हैं। यहां पर क्या स्ट्रेटा है और कितना हार्ड है, उसको हमने देखा है। मैंने उस डक्ट को 50 बार व्यक्तिगत तौर पर खुद जाकर देखा है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर कोई खोद कर काम करने की तकनीक नहीं है। वहां पर हम हरेक चीज़ के लिए 50 मीटर या 30 मीटर का स्लैब डाल रहे हैं ताकि उसमें किसी प्रकार की कोई कमी न रहे, इसलिए काम स्लो चला हुआ है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को मैं बताना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहें और इससे किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। यह कार्य अच्छा हुआ है क्योंकि पहले इस कार्य को करने के लिए बार-बार शिमला की सड़कों की खुदाई होती थी तो अब वह बंद हो जाएगी और पेड़ों के ऊपर कील गाढ़ कर जो तारें लटकाई गई हैं वे भी

लटकना बंद हो जाएंगी तथा इसकी क्वालिटी को हर लैवल पर हर मीटिंग में एंश्योर किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी हमेशा इसके लिए मीटिंग लेते हैं और उसको एंश्योर करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत जरूरी था और हम धीरे-धीरे इसमें आगे बढ़ रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपका वहां से रास्ता है और जब खुदाई होती है तो स्वाभाविक रूप से समस्या आती है। आपने यहां पर सेफ्टी मेजर्स की बात की है कि टूटा हुआ है। उसके लिए हमने वहां पर इंस्ट्रक्शन्स दे रखी हैं और ये धीरे-धीरे पीछे से बंद होते जा रहे हैं। इसी सत्र से पहले इस सड़का का पहला पैच ओक ओवर से लेकर छोटा शिमला तक आपको आने वाले समय में नज़र आएगा कि किस प्रकार का बदलाव शिमला में होने वाला है।

17-2-2026/1145/एन0एस0-ए0जी0/2

प्रश्न संख्या : 3839

डॉ0 हंस राज : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने पिछली बार भी पूछा था और उसमें माननीय मंत्री जी ने उत्तर भी दिया था। मेरी चिंता यह है कि भारी बरसात के दौरान बादल फटने से मेरे क्षेत्र के कंगेला नाले का ब्रिज बह गया है और पूरी सड़क डैमेज हो गई है। यह पुल चार पंचायतों बघेईगढ़, चरड़ा, चांजू व देहरा को जोड़ता है। हम अगर चम्बा से चलें तो चांजू नाला, शरेला, डूडली के पास यह पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। वहां पर चांजू माता का बड़ा भव्य मंदिर है और बहुत श्रद्धालु जाते हैं। प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि पुल के पुनर्निर्माण के लिए मु0 2.00 करोड़ रुपये की धनराशि की आवश्यकता है। बजट की उपलब्धता के अनुसार पुल का पुनर्निर्माण किया जाएगा। चांजू-3 और चांजू-4 दो हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट वहां लगे हुए हैं। उसमें लाडा का बहुत सारा पैसा लगा है और कई बार 2-4 करोड़ रुपये वेस्ट भी हुए हैं। अगर हम बैकवर्ड सब-प्लान से पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो हम वहां पर डी0सी0 के माध्यम से इसको बना सकते हैं। बघेईगढ़ में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और कठवाल से और साथ लगती पंचायतों से बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं।

17.02.2026/1150/RKS/As-1

प्रश्न संख्याः 3839... जारी डॉ0 हंस राज ... जारी

पिछली बार भी बरसात के समय इस नाले को क्रॉस करने में लोगों को काफी दिक्कत आई थी। यह महत्वपूर्ण पुल है इसलिए क्या माननीय मंत्री जी आश्वस्त करेंगे कि आप इसके लिए 2 करोड़ रुपये जारी करेंगे?

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यहां पर बहुत ही संवेदनशील विषय रखा है। हमारा जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों के साथ बहुत प्यार है। हालांकि हमारी जिम्मेवारी पूरे प्रदेश के लिए है लेकिन मैं बार-बार इस सदन मे यह जिक्र करता हूं कि हमारी सरकार और मेरी व्यक्तिगत सोच हमेशा जनजातीय, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र के लोगों को केटर करने के लिए रही है। हमें जो केंद्र सरकार से लेटेस्ट सैंक्शन प्राप्त हुई है उसमें अधिकतर शेयर कांगड़ा जोन के भरमौर और चुराह विधान सभा क्षेत्र के लिए गया है। यह इस बात को दर्शाता है कि हमने कभी भी सड़कों की डी0पी0आर0 और रोडमैप बनाने में कोई कोताही नहीं बरती है। माननीय सदस्य ने टिक्करीगढ़-बघेईगढ़ सड़क 13/340 पर 35.50 मीटर्ज स्पैन पर ब्रीज स्थापित करने की बात की है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर यह ब्रिज बजट की कमी के कारण स्थापित नहीं हो पाया है। हालांकि इस सड़क को यातायात के लिए अस्थाई रूप से बहाल कर दिया गया है। मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं कि यह पुल स्थापित होना चाहिए। हम आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे कि विभागीय बजट के माध्यम से इस पुल की आपूर्ति हो। यदि इसके कार्य में कोई कमी रहती है तो हम सारे एवेन्यूज खोलने पर आपको सहयोग देंगे। चाहे वह डी0सी0पी0, लाडा या किसी भी रूप में फंड जारी करने की बात हो क्योंकि हमें यह भी देखना है कि पी0डब्ल्यू0डी0 एक एक्जिक्यूटिव एजेंसी है और इसमें

बहुत-से कार्य डिपोजिट वर्क के माध्यम से भी करवाए जाते हैं। **हम विभागीय बजट से इस कार्य को करवाने की कोशिश करेंगे। यदि इस कार्य में कोई कमी रहती है तो हम दूसरे एवेन्यूज को एक्सप्लोर करने में भी कोई कमी नहीं रखेंगे।**

17.02.2026/1150/RKS/As-2

डॉ0 हंस राज : मैं माननीय मंत्री की बात से पूरी तरह सहमत हूं। अगर आप नगरोट-कफाड़ी से आगे चलें तो इस सड़क के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत वाइडनिंग के लिए पैसा आया था। यह एक अच्छी सड़क बनी थी। मैं लाडा का इसलिए जिक्र कर रहा था क्योंकि प्रोजैक्ट बनने की वजह से इस सड़क का सत्यानाश हो गया है। प्रोजैक्ट लगने से इस सड़क में भारी यातायात की आवाजाही होती है। क्या आप इस बात को आश्वस्त करेंगे कि जो लाडा का पैसा इस रोड की मैंटिनेंस व वाइडनिंग के लगना था उसे यहीं यूज किया जाएगा?

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपने डॉ0 हंस राज जी को डॉक्टर की उपाधि दी है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये किस चीज के डॉक्टर हैं?

अध्यक्ष : यह उपाधि मैंने माननीय सदस्य को नहीं दी है। इन्होंने खुद डॉक्टरेट की है और ये हिन्दी के डॉक्टर हैं। ये पी0एच0डी0 होल्डर हैं।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारे लिए सारे सोर्सिज ओपन हैं और जो इन्होंने सुझाव दिए हैं उन्हें हम स्वीकार करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि अब भारत के रिश्ते सभी देशों के साथ अच्छे हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो हमारे रिश्ते (***) के साथ भी बहुत अच्छे बन रहे हैं। मैं आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर हमें वहां से भी पैसा लाना होगा तो हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।

Speaker: (***) shall not to be a part of the record.

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

प्रश्न संख्याः 3840 श्री बी0एस0द्वारा जारी

17.02.2026/1155/बी.एस./ए.एस.-1

प्रश्न संख्याः 3840

श्री सुधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पासू सब्जी मंडी के भवन का निर्माण कार्य कब पूरा हो गया था; और जो उत्तर में आया है कि कैंटीन और शौचालय का वहां पर निर्माण चल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि यह कार्य कब शुरू हुआ? दूसरा क्या मंत्री जी विभाग से यह जानकारी मंगवाएंगे कि जो सब्जी मंडी का भवन बना है उसकी वस्तु स्थिति क्या है? क्या उसको भी दोबारा रिपेयर की जरूरत पड़ गई है; या उस भवन को रंग रोगन होना है? यह भवन कुछ वर्ष पहले बन करके तैयार हो गया था परंतु शौचालय और कैंटीन न बन पाने के कारण यह भवन बंद पड़ा है। मैं जानना चाहता हूं कि इसकी वस्तु स्थिति क्या है? इसकी रिपोर्ट विभाग से तलब करेंगे?

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह जो मंडी है इसके ऊपर 2,37,77,439 रुपये व्यय किए गए हैं और शौचालय और कैंटीन का निर्माण कार्य प्रगति पर है और माह फरवरी के अंत तक इसको पूरा कर लिया जाएगा।

17.02.2026/1155/बी.एस./ए.एस.-2

प्रश्न संख्याः 3841

श्री राकेश कालियाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आशीर्वाद से मंत्री जी ने तो नहीं परंतु मुख्य मंत्री जी ने पिछली बार भी इसी क्वेश्चन का जिक्र आया था तो मुख्य मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था इस पी0एच0सी0 के लिए जल्दी जमीन देख लेंगे लेकिन अभी तक

अधिकारियों ने ढुलमुल रवैया अपनाया हुआ है, इसके लिए सरकार से पैसा जा चुका है। लेकिन मैं अधिकारियों के बारे में क्या बताऊं? कुछ अधिकारी तो फोन भी नहीं उठाते हैं। मैं चाहता हूं कि जिन अधिकारियों को अलाउंसिज दिए जा रहे हैं उनके अलाउंसिज बंद किए जाएं जब वे लोग विधायकों के फोन ही नहीं उठाएंगे तो हम कैसे आगे काम चलाएंगे? इसलिए ऐसे अधिकारियों को भी चैताया जाए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऐसे सभी अधिकारियों के बारे में आप विधान सभा सचिवालय को लिखित में दें। We will take action.

श्री राकेश कालियाः यदि ये इस कार्य से बाज नहीं आए तो हम खुद इनका घेराव करेंगे। जो मेरी आदत है, मैं उसके खिलाफ काम कर रहा हूं। जिस दिन मेरा दिमाग में कुछ आ गया तो मैं गांव से 200 लोग ला करके इनके खिलाफ धरना दे दूंगा।

अध्यक्ष : नहीं, आपने शांति से काम लेना है।

श्री राकेश कालियाः सर, विधायकों के तो अपने काम होते नहीं है, हमने लोगों के काम ही करवाने होते हैं। क्योंकि पिछले साल मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हम जमीन देख लेंगे और जमीन अभी तक नहीं देखी जा रही है। इसलिए मुख्य मंत्री जी, आप अधिकारियों को जरा डांट लगाइए ताकि हमारे काम हो सके और वे हमारे फोन उठाएं और कभी-कभी हमारी बात सुन लें और पिछली बार का जो आपका इस प्रश्न के बारे में विधान सभा का आश्वासन है उस पर कार्रवाई करने के लिए आदेश करें, धन्यवाद।

प्रश्न काल समाप्त

17.02.2026/1155/बी.एस./ए.एस.-3

अध्यक्ष : जो माननीय सदस्य राकेश कालिया जी ने कंसर्न वेंटिलेट किया है against certain officers/officials कि जो अधिकारी माननीय विधायकों के फोन नहीं सुनते हैं या उस वक्त वे फोन नहीं सुन पाते तो बाद में उन्हें रिस्पोंड नहीं करते this is a very serious aspersion on the Officers also and very serious questions so far the Hon'ble Members of the Vidhan Sabha are concerned. I am taking a

---

cognizance of it. You please give in a writing against those Officers, we will proceed against them. Thank you very much.

मैं तो प्रयास कर रहा था कि आज प्रश्न काल भी समाप्त हो जाए और प्रश्न भी समाप्त हो जाए परंतु फिर भी दो प्रश्न बच गए हैं। इससे पहले कि शून्य काल आरंभ हो क्या नेता प्रतिपक्ष व्यवस्था के बारे में कुछ बोलना चाह रहे हैं? यदि कुछ विषय है तो आप बोल सकते हैं, ऐसे तो आपने कल अपनी बात रख दी है। बोलने की अनुमति देने से पहले मुझे कुछ पता तो चलना चाहिए कि आप किस विषय पर बोलना चाह रहे हैं।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

17.02.2026/1200/डी0टी0/डी0सी0 -1

अध्यक्ष जारी...

कल तो आपने एक घंटा भाषण दे दिया है। ...(व्यवधान) किस पर? आप कौन से इश्यू पर बोलना चाहा रहे हैं? ...(व्यवधान) I should know कि कौन सा इश्यू है? ...(व्यवधान) नहीं, पर अलाउ करने से पहले मुझे इश्यू का तो पता होना चाहिए कि आप बोलना क्या चाहा रहे हैं या क्या आप Point of Order लेना चाहा रहे हैं? किसी भी प्वाइंट में Point of Order तो बन नहीं रहा पर चलो What you want to say?

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, आप हमें इतना भी मत रोकिए।

अध्यक्ष : नहीं-नहीं, मैं तो आपको पूरा समय दे रहा हूं।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहा रहा था कि जो प्रश्न से संबंधित विषय था यह विषय सभी माननीय विधायकों के बीच में कंन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। मेरा कहने का अर्थ है कि प्रश्न कब तक लिए जाएंगे? जो प्रश्न से संबंधित 15 दिन पूर्व नोटिस देने की व्यवस्था है वह कायम है क्या? हमें मालूम नहीं की आगे सत्र कब तक होगा? इसलिए प्रश्न के संबंध में जो नोटिस हम नेवा के माध्यम से दे रहे थे वे नोटिस नेवा के माध्यम से सबमिट नहीं हो पा रहे हैं। इसके संबंध में विधान सभा सचिवालय की ओर से जानकारी तुरंत माननीय सदस्यों को दी जानी चाहिए थी कि आपके प्रश्न नेवा के माध्यम से नहीं बल्कि आप व्यक्तिगत तौर से लिखित रूप में प्रश्न

सबमिट करें। अगर यह जानकारी हमें विधान सभा सचिवालय की ओर से प्राप्त हो जाती तो मुझे लगता है कि हमें सुविधा होती।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हम प्रश्न कब तक दें? व्यवस्था तो यह है कि सत्र से 15 दिन पूर्व किसी भी सदस्य को प्रश्न के संबंध में नोटिस देना होता है और हम तो प्रश्न विधान सभा सचिवालय में भेजते रहेंगे और उम्मीद भी करते हैं कि जो प्रश्न हम देंगे वे लगेंगे भी। इसके अतिरिक्त जो बात मैं बोलना चाहता हूं वह यह है कि हम जब कोई भी स्पीच या कोई प्रश्न इस माननीय सदन में उठाते हैं, जो भी हम बोलते हैं वह विधान सभा के रिकार्ड में भी जाता है, उसका रिकार्ड मिलने में विलंब हो रहा है और पूरा रिकार्ड भी नहीं मिल पा रहा है। मैंने कल लगभग एक घंटा बोला है लकिन हमें जो विधान सचिवालय की ओर जो रिकार्डिंग उपलब्ध करवाई

17.02.2026/1200/डी0टी0/डी0सी0 -2

गई है वह मुश्किल से 15 मिनट की है और वह चार क्लिप्स में मुझे दी गई और वे भी रात के नौ-दस बजे मिली है। जो हम बोल रहे हैं वह स्पीच हमको उपलब्ध होनी चाहिए ताकि उसमें से क्या छांटना है क्या काटना है, कौन सा भाग हमने सोशल मीडिया में डालना है, वह हम देख लें क्येांकि एक घंटे की स्पीच तो हम सोशल मीडिया में नहीं डाल सकते। इसलिए मेरा कहने का अर्थ की जो स्पीच हम इस सदन में देते हैं वह हमें तुरन्त मिल जाए। ताकि वह व्यक्ति जो माननीय विधायकों का आई0टी0 का कार्य देखते हैं वह उसमें जो पोर्शन काटना है उसे काट कर उसे सोशल मीडिया में डाल दे। क्योंकि लोग यह जानना चाहते हैं कि विधान सभा में हमारे विधायक ने क्या बोला या कुछ बोला भी या नहीं बोला और अगर बोला तो क्या बोला? मुझे लगता है कि इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। मैं समझ सकता हूं कि शायद आपने डायरैक्शंज दी हैं कि उस स्पीच को आपको भी एक बार देखना है या चेक करना है। लेकिन जब आपके सामने सारी कार्यवाही हो रही है और उस कार्यवाही में कोई क्वश्चनेबल या कोई इस तरह का शब्द हो तो उसे आप पहले ही एक्सपंज कर देते हैं। जब ऑब्जैक्शन नहीं होता तो वह कार्यवाही जानकारी के रूप में हमें उपलब्ध होनी चाहिए। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी स्पीच हमें समय पर मिले और पूरी मिले ताकि उसमें से रेलेवेंट पॉर्शन निकाल कर हम सोशल मीडिया में डाल सके। मैंने अपनी स्पीच में जो मुद्दे उठाये थे और जो चार क्लिप मुझे

दिए गये हैं उसमें से वे मुद्दे गायब हैं। उसमें केवल रोटीन की बातें हैं जो हमनें डिस्कस की हैं। लेकिन विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जो प्वाइंट हमनें रेज किये थे वह सारे प्वाइंट उसमें नहीं आए। इसलिए मैं चाहा रहा हूं कि हमारी जो स्पीच है वह पूरी की पूरी हमें उपलब्ध होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक और सबमिशन करना चाहता हूं कि विधायक क्षेत्र विकास निधि- इसमें हम आपका भी सहयोग चाहेंगे क्योंकि आपने भी वह निधि अपने क्षेत्र में देनी है। हमें अभी तक केवल दो इंस्टॉलमेंटस मिली हैं। हम आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जाकर घोषणा कर चुके हैं। यदि कोई पुल टूट गया तो उसके लिए हम विधायक निधि का दो लाख रुपये, पांच लाख रुपये या दस लाख रुपये देने की घोषणा करते हैं और कई जगह हम ऐसी घोषणाएं करके आ गये हैं। अब हमारी स्थिति यह हो गई कि विधायिका का यह इंस्टीटयूशन ऐसी चीजों के लिए बदनाम हो

17.02.2026/1200/डी0टी0/डी0सी0 -3

रहा है। लोग कहते हैं कि विधायक आया था और झूठ बोल कर चला गया क्योंकि पैसा तो आया ही नहीं।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

17.02.2026/1205/डी.सी.-एन.जी./1

श्री जय राम ठाकुर जारी.......... जारी

अध्यक्ष महोदय, कई जगह ऐसी स्थिति हो गई है कि हमने लोगों को चिट्ठी भेज दी है लेकिन उसका पैसा अभी तक जारी ही नहीं हो पा रहा है। हम चाहते हैं कि मुख्य मंत्री जी, आगे का फैसला क्या करना है, आप उसे करें। हमें मालूम है कि प्रदेश आर्थिक संकट के दौर में है और हम इस बात को मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत मिलने वाली धनराशि के लिए आपने इसी माननीय सदन में बजट पारित करवाकर एक व्यवस्था की है और उसके लिए बजट का प्रावधान भी किया है। मेरा आग्रह

है कि इस धनराशि को मत काटिए। इसके अलावा ऐच्छिक निधि भी नहीं मिल रही है। मेरा आग्रह है कि इन दोनों निधियों को तुरन्त प्रभाव से जारी किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, अभी बजट सत्र चल रहा है और इसके बाद नया वित्तीय वर्ष आरम्भ हो जाएगा जिस कारण वर्तमान वित्तीय वर्ष का पैसा लैप्स हो जाएगा। ऐसे में हम चाहते हैं कि मुख्य मंत्री जी तुरंत प्रभाव से विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना और ऐच्छिक निधि का पैसा जारी करें। हम विधायकों के पास काम करने का एकमात्र साधन विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना का पैसा है क्योंकि सरकार की ओर से अन्य योजनाओं में पैसा तो मिल नहीं रहा है। सत्तापक्ष के माननीय विधायकों को पैसा मिल रहा होगा तो उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है लेकिन विपक्ष के माननीय विधायकों को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि आप प्रदेश सरकार को जल्दी-से-जल्दी उचित निर्देश जारी करें। धन्यवाद।

17.02.2026/1205/डी.सी.-एन.जी./2

अध्यक्ष : अभी नेता प्रतिपक्ष जी ने तीन विषयों को उठाया है और उनमें से दो विषय विधान सभा से मुतल्लिक हैं। नेता प्रतिपक्ष जी ने कल भी कहा था कि हम लोग प्रश्नों को कब तक दे सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि आमतौर पर बजट सत्र की 15 से 18 बैठकें होती हैं। अभी हमारा बजट सत्र शुरू हो चुका है और यदि इसके बीच में कोई ब्रेक आती है तब भी वह बजट सत्र का पार्ट ही होगा। जब बजट सत्र की अंतिम तिथि नोटिफाई होती है तो उसके सात दिन पहले तक प्रश्न दिए जा सकते हैं। अभी हमारा पोर्टल ओपन हो चुका है और माननीय विधायकों की ओर से जितने भी नोटिस व प्रश्न आएंगे, हम विधान सभा में उन सभी को प्राथमिकता के आधर पर व नियमों के तहत लगाएंगे इसलिए माननीय विधायक प्रश्न व नोटिस देते जाइए।

दूसरा, जो नेवा नहीं चल रहा है उसके लिए मैंने पहले भी कहा है कि इसके संदर्भ में मैंने लोकसभा व माननीय केन्द्रीय मंत्री के समक्ष बात को रखा है। निदेशक, एन0आई0सी0 (हि0प्र0 विधान सभा) भी कह रहे हैं, हमें भी लग रहा है और इस माननीय सदन के सदस्यों की भी यही भावनाएं हैं कि नेवा उस प्रकार से काम नहीं कर रहा है जिस प्रकार से हमारा ई-विधान मॉड्यूल काम करता था। हम नेवा पर भी काम करते रहेंगे और vis-à-vis हम ई-विधान मॉड्यूल को भी रिवाइव करने की बात कर रहे हैं। इसके संदर्भ में हमने सरकार व लोकसभा से पत्राचार भी किया है। We are thinking to revive our own module also. फिलहाल मुझे जो सूचना दी गई है और निदेशक, एन0आई0सी0 (हि0प्र0 विधान सभा) भी कह रहे हैं कि अभी नेवा का पोर्टल चल रहा है। मैं भी सदन की सारी कार्यवाही नेवा पोर्टल पर ही देख रहा हूं। हो सकता है कि कुछ माननीय सदस्यों को समस्याएं आ रही हों तो मैं विधान सभा के आई0टी0 सैल के अधिकारी/कर्मचारियों को निर्देश देता हूं कि जिन-जिन माननीय सदस्यों को समस्याएं आ रही हैं, उनके इश्यूज़ को एड्रैस करें।

17.02.2026/1205/डी.सी.-एन.जी./3

नेता प्रतिपक्ष जी ने रिकॉर्डिंग से संबंधित बात कही है तो मेरे पास सूचना आई है कि नेता प्रतिपक्ष जी को पिछले कल 07:30 बजे रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवा दी गई थी जबकि आप (नेता प्रतिपक्ष को कहा) रात्रि 10:30 बजे कह रहे थे। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष जी का पूरा-का-पूरा भाषण रिकॉर्डिड है और अन्य माननीय सदस्यों का भी पूरा भाषण रिकॉर्डिड है। यदि हमने (चेयर ने) किसी माननीय सदस्य द्वारा माननीय सदन में दिए गए भाषण के किसी भाग को विलोप नहीं किया है या उसके ऊपर कोई रूलिंग नहीं दी है तो उस माननीय सदस्य को उनका पूरा भाषण मिलता है। यह व्यवस्था पहले भी थी, अब भी है और आगे भी जारी रहेगी। नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि माननीय सदस्य को उसी वक्त भाषण की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवा दी जाए तो यह थोड़ा मुश्किल है। जैसे पिछले कल

एक इश्यू हो गया था और अभी मैं उसे रैफर नहीं करना चाहता हूं। यहां पर अनेक बार कोई माननीय सदस्य भाव में बहकर बहुत सारी बातें कह देता है और बाद में उसी माननीय सदस्य को लगता है कि भाव में बहकर मैंने कुछ ऐसा कह दिया है जो पब्लिक नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने इस प्रकार की व्यवस्था दी थी कि हम माननीय सदस्य के भाषण की रिकॉर्डिंग को 5-6 बजे तक या जब तक सत्र की कार्यवाही चलेगी, उसके बाद ही माननीय सदस्य के भाषण/वक्तव्य की रिकॉर्डिंग को दिया जाएगा। उसमें कुछ सुधार करने की जरूरत होगी तो उसे हम देखेंगे।

जहां तक विधायक निधि का ताल्लुक है तो

श्री ए0पी0 द्वारा......जारी

17.02.2026/1210/HK/AP/01

अध्यक्ष जारी .....

उसमें कुछ सुधार करने की जरूरत होगी तो उसको भी हम देखेंगे। जहां तक विधायक निधि का ताल्लुक है, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह स्थिति को स्पष्ट करें। विधायक निधि के बारे में जो शंकाएं नेता प्रतिपक्ष महोदय को हैं उसके बारे में सरकार का क्या विचार है, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे मैं प्रतिपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी से हमेशा कहता हूं कि सच बोलिए। आज फिर से आपका झूठ पकड़ा गया। आपने 10:30 की जगह 07:30 कहा। मेरा कहने का मतलब है कि जब आदमी तनाव में होता है तो इस प्रकार की बातें हो जाती हैं। आप तनावमुक्त रहिये, ध्यान लगाइये, आराम से अपनी बात कहिये तो अच्छा रहेगा। लेकिन मैं विधायक निधि क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। मैंने पहले भी कहा था। अध्यक्ष महोदय, विधायक क्षेत्र निधि पर हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं। जब बिक्रम जी और विपिन परमार जी आए थे, तब मैंने सभी विधायकों से कहा था कि आपने आर0डी0जी0 के मुद्दे पर सरकार के वित्त सचिव द्वारा जो प्रेजेंटेशन दी थी, उसमें आना है।

उस स्थिति में हम सब मिलकर बैठते और और आकलन करते कि कैसे विधायक निधि को देना है। मैं सभी सदस्यों से चाहता हूं कि सभी लोग इस पर आकलन करें। आर0डी0जी0 का मुद्दा जब खत्म होगा और वोटिंग के बाद हम बैठेंगे, तब तय करेंगे कि कितनी विधायक निधि हम दें सकते हैं और कितना नहीं। उसी आधार पर हम काम कर सकते है। आप अचानक ही इतनी चिट्ठियां न बांटे। हम एक लिमिट तय करेंगे और स्थिति स्पष्ट करेंगे कि कितना हम विधायक निधि में दे सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं। मैं वही कह रहा हूं कि माननीय जय राम ठाकुर जी और अन्य सदस्यों के बैठक कर हम तय करेंगे और चीज़े इसके ध्यान में लाएगे।

अध्यक्ष : अब शून्य काल आरम्भ होगा और उसमें लगभग 15 मिनट बचे है। माननीय ठाकुर साहब अगर आप बोलोंगे तो शून्य काल समाप्त हो जाएगा। अब इन्होंने बता दिया है कि in view of the limitations जब से आर0डी0जी0 का जो निर्णय आया है अभी सरकार इस तरह की परिस्थितियों पर पुनर्विचार कर रही है और विपक्ष के साथ बैठक कर सरकार बातचीत करेगी और उस पर निर्णय लेंगे। मेरे ख्याल मैं अभी जब तक यह सारा चीज़े हम

17.02.2026/1210/HK/AP/02

डिस्कस नहीं कर लेते। माननीय श्री केवल सिंह पठानिया शून्य काल में अपना इश्यू रखेंगे। केवल जी एक मिनट रुकिये।

अभी मेरे पास अगला बिजनेस जो लिस्ट है उसमें बीजेपी की तरफ से तो लिस्ट आ गई है लगभग 12-सदस्यों की रिवाइज लिस्ट आई है। कांग्रेस की तरफ से अभी लिस्ट नहीं आई है और अभी माननीय उप-मुख्य मंत्री महोदय मुझे चेंबर में मिले हैं और he wants to express his views on the Resolution of Revenue Deficit Grant. The moment we initiate that debate, Hon'ble Deputy Chief Minister will have the priority in the speech. शून्य काल। माननीय नेता प्रतिपक्ष।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षेप में बात करूंगा। ठीक है टाइम को लेकर के कुछ आगे-पीछे बात हुई होगी। लेकिन मैं जो कह रहा हूं मैं ठीक कह रहा हूं। कल आपने कहा कि आपने गडकरी जी को चिट्ठी नहीं लिखा। यह चिट्ठी में यहां पर ले देता हूं।

उसके बाद जिसमें उन्होंने लिखा है कि प्रिय जय राम ठाकुर जी कृपया अपने पत्र क्रमांक अशा.पत्र, संख्या : नि.स./पू.मु.म./-194 का संदर्भ लें। जिसके माध्यम से अपने हिमाचल प्रदेश पर मंडी-गाागल- चैलचौक-जंजैहली एम0डी0आर0 जिसकी लंबाई 83 किलोमीटर है। सड़क के पुनर्निर्माण। यह तो चिट्ठी हमने उनको भेजी है। उसके बाद अध्यक्ष महोदय जिसमें उन्होंने कहा कि ...(व्यवधान) मैं चिट्ठी ले कर दूंगा माननीय सदन में। आप कह रहे थें कि हमने चिट्टी नहीं लिखी है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : ठाकुर साहब छोटी-छोटी बातों में न उलझा करें।

श्री जय राम ठाकुर : आगे है कि आपको बड़ी प्रसन्नता के साथ सूचित करना चाहता हूं कि मंत्रालय ने केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि सी0आर0आई0एफ0 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में मंडी-गागल- चैलचौक-जंजैहली के लिए एम0डी0आर0 जिसकी लंबाई 83 किलोमीटर है।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

17/02/2026/1215/AT/HK/01

श्री जय राम ठाकुर जारी :

उसके निर्माण एवं चौड़ीकरण के लिए मु0 137.40 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद करने हेतु बुके देखकर आया हूं।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, सी0पी0एस0 के मामले में... (व्यवधान) इन्होंने कहा कि चिट्ठी नहीं लिखी इस बात का उल्लेख कर रहे थे। एक और बात इन्होंने सी0पी0एस0 के संबंध में कही। मैंने कहा कि आपने डेढ़ करोड़ रुपये दिए, तो आप मुकर गए और कहा कि बिल्कुल पैसे नहीं दिए। मैंने कहा कि 10 करोड़ over all का दिया है और एक हियरिंग का डेढ़ करोड़ रुपये दिया है। इस बात पर मुख्यमंत्री जी मुकर गए। This is part of the record और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को यह बता रहा हूं... (व्यवधान) कृपया जरा सुनिए यह विवेक कृष्ण टांका, सीनियर एडवोकेट को 50 लाख रुपये और दुष्यंत दुबे, सीनियर एडवोकेट को 93 लाख 50 हजार रुपये दिए गए। कुल 1 करोड़ 43 लाख 50

हजार रुपये है। मैं यह भी सदन में रख देता हूं कि यह एक पेशी का भुगतान है... (व्यवधान)। आप गलत मत बोलिए... (व्यवधान)। अन्यथा संकट ही आएगा।

(नेता प्रतिपक्ष ने पत्र सदन के पटल पर ले किया)

Speaker : This is to the information of this Hon'ble House ये जो टॉप लॉयर्ज़ हैं, यह इनकी फीस है। They take it in the shape of a bank transfers. They pay the income tax. So, why we discussing all these issues. We engage those peoples as per our requirement. माननीय मुख्य मंत्री महोदय।

मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी का शुभचिंतक हूं। आपकी पार्टी के लोग आपके शुभचिंतक नहीं हैं इसलिए आप तनाव में रहते हैं। यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइए। स्टेट प्रायोरिटी में हमने अन्य सभी सड़कें छोड़कर माननीय पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री से चर्चा के बाद इस सड़क को प्रथम प्राथमिकता में डाला। उसके बाद इसकी स्वीकृति हुई। मैंने कहा था कि शायद इन्होंने चिट्ठी नहीं लिखी होगी

17/02/2026/1215/AT/HK/02

यदि लिखी है तो अच्छी बात है। कल आपने राजनीतिक तनाव की बात कही थी। राजनीतिक तनाव बहुत बुरा होता है। हम इस तनाव से निपट चुके हैं और अब आप निपट रहे हैं। आपकी पार्टी के गुटों का इतना दबाव है जिस कारण आप स्वयं तनाव में हैं।

मैं फिर कह रहा हूं 7:30 की जगह 10:30 बोलना, 10 करोड़ की जगह डेढ़ करोड़ बोलना, कल आपने जो कहा है आप रिकॉर्ड मंगवाकर देख लें। आपने कहा कि सी0पी0एस0 को बचाने के लिए 10 करोड़ रुपये दिए गए। मैंने सी0पी0एस0 को बचाने के लिए पैसे नहीं दिए। जो भी फीस दी गई वह इन्हीं दो वकीलों को दी गई और यह राशि लोकतंत्र को बचाने के लिए दी गई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सच कह रहा हूं आपने कल 10 करोड़ कहा। लंच के बाद रिकॉर्ड देखकर मुझे बता दीजिए। मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता क्योंकि फिर झूठ का आरोप

आप पर लगेगा। कृपया रिकॉर्ड देख लें और मुझे चेंबर में बता दें कि आपने 10 करोड़ कहा या नहीं कहा। यही सच्चाई है। धन्यवाद।

शून्य काल

Speaker : Hon'ble Member Shri Kewal Singh Pathania be very brief on your proposition please. तीन मुद्दे हैं और मैं इन तीनों मुद्दों को अलाउ करूंगा if I have to go beyond the time also.

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने शून्य काल में बोलने का अवसर दिया। हिमाचल प्रदेश में लगभग 20 महाविद्यालयों में बी0वोक0 के कोर्स चल रहे हैं। पिछले लगभग 10 वर्षों से इन 20 महाविद्यालयों में स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से ये कोर्स संचालित हो रहे हैं। लंबे समय से माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं यह चाहता हूं कि

एम0डी0द्वारा जारी ......

17-02-2026/1220/YK/MD/1

श्री केवल सिंह पठानिया---जारी

लंबे समय से हमारे खासकर जिला मुख्यालय के बड़े कॉलेजिज में ही ये बी-वॉक के कोर्स चल रहे हैं। मैंने इस संदर्भ में पिछले 10 वर्षों के बारे में प्रश्न किया था, जिसके अनुसार लगभग 70 प्रतिशत प्लेसमैंट बी-वॉक बच्चों की हो रही है। वह चाहे ताज हो या ओबरॉय, हयात, मैरिट, रेडिसन, लेमन ट्री, रिलायंस या फिर टाटा हो, इन सारे होटल्ज में हमारे जगह-जगह से बी-वॉक के बच्चों की प्लेसमैंट हो रही हैं। यह मसला मैंने जीरो आवर में इसलिए उठाया क्योंकि अब स्किल डवलपमैंट के कई कोर्सिज बंद हो चुके हैं। ग्रामीण प्रवेश के बच्चों को महाविद्यालय के अंदर शिक्षा विभाग ने बी-वॉक की एक बहुत अच्छी सुविधा दी थी। मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों में सिम्पल बी0ए0 की बजाय ऐसे कोर्सिज चलाए जाएं जिससे कि अनइंप्लॉयमैंट कम हो। इसलिए मीनिंगफुल एजुकेशन और जॉब ओरिएंटेड कोर्सिज चलाए जाएं और मेन स्ट्रीम में बी-वॉक को लाया जाए। आपने बहुत

सारे महाविद्यालय खोले हैं और जगह-जगह पर ये कोर्सिज चले हैं। सेल्फ फाइनेंस के अंतर्गत जहां तक मैं धर्मशाला, मण्डी, शिमला इत्यादि पांच-छः कॉलेज की बात करूं तो 20-22 करोड़ रुपए में ये कोर्सिज हर कॉलेज में सेल्फ फाइनेंस पर स्किल डवलपमैंट व कोलैबोरेशन के साथ चल रहे थे। शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए माननीय शिक्षा मंत्री ने जो कदम उठाए हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। आपने पिछले तीन वर्षों के अंदर जो कदम उठाए हैं, उसी के अंतर्गत मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर कोई स्थाई नीति बनाई जाए। वह चाहे बी-वॉक को लंबे समय से टीचर पढ़ा रहे हैं यानी फैकेल्टी के साथ-साथ तमाम स्टाफ के लिए प्रावधान किया जाए। मैं चाहता हूं कि उन्हीं 20 महाविद्यालयों में मेन सट्रीम में इस कोर्स को आरंभ किया जाए जिससे कि हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार के अवसर मिलते रहे। मैं इसमें शिक्षा मंत्री जी का इंटरवेशन चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

17-02-2026/1220/YK/MD/2

शिक्षा मंत्री : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया जी ने यहां बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। जहां तक बी-वॉक कोर्सेज की बात आती है, यदि हम इसकी पृष्ठभूमि में जाएं तो वर्ष 2017 में ए0डी0बी0 के सहयोग से शिक्षा विभाग ने प्रथम चरण में लगभग 12 कॉलेजिज़ में बी-वॉक कोर्स प्रारंभ किए थे। विशेष रूप से रिटेल मैनेजमेंट तथा टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टर इसमें शामिल थे। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि हमारी जो रेगुलर स्ट्रीम्स हैं, उनके साथ जॉब-बेस्ड और स्किल-बेस्ड एजुकेशन को एक तरह से एंप्लॉयमेंट और रोजगार के अवसरों से जोड़ा जाए। वर्तमान में लगभग 20 कॉलेजिज़ इस योजना के अंतर्गत लाए गए हैं। ए0डी0बी0 के सहयोग से वर्ष 2017 से लेकर 2023 तक इसका वित्त पोषण होता रहा। वर्ष 2023 के बाद हमारी सरकार और हमारा विभाग इसकी फंडिंग कर रहा है। आने वाले समय में यदि हम जॉब-बेस्ड एजुकेशन के साथ अपनी शिक्षा को और अधिक जोड़ना चाहते हैं तो इस दिशा में हमें और कार्य करना होगा। यह हमारी सरकार और हमारे विभाग की प्राथमिकता रहेगी। माननीय सदस्य श्री केवल सिंह जी ने यहां कहा कि इसकी संख्या बढ़ाई जाए और इसे शिक्षा

विभाग का एक रेगुलर फीचर बनाया जाए। माननीय सदस्य श्री केवल सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा कि इसके परिणाम, विशेषकर प्लेसमेंट के बहुत अच्छे रहे हैं। लगभग 72-80 प्रतिशत छात्र-छात्राओं को जो इन कोर्सेज में शिक्षा ले रहे हैं उनको रोजगार मिल रहा है। निश्चित रूप से यह बहुत अच्छा सुझाव है। It is suggestion for action और विभाग इसमें सीरयसली एक्ट करेगा।

अध्यक्ष : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी भाग लेंगे।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूं, वह विषय माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय ने यहां उठाया था। परंतु माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस मुद्दे को लेकर सदन और हिमाचल प्रदेश की जनता को भी (***) करने की कोशिश की है। विषय विधायक क्षेत्र विकास निधि का है। पिछले साल बजट में इसकी राशि बढ़ाकर 2 करोड़ 20 लाख रुपये की गई थी।

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी---

17.02.2026/1225/केएस/वाईके/1

अध्यक्ष : (***) ठीक नहीं है अभी क्योंकि this amounts to a contempt of the House.

श्री रणधीर शर्मा : सर, (***) कहां से गलत है?

अध्यक्ष : आप यह बोल सकते हैं कि जो फीगर्ज़ दी है या जो भी स्टेटमैंट दी है, वह तथ्यों से परे है। (***) this is a very serious allegation then you have prove it on record.

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री रणधीर शर्मा : सर, वह तो मैं कर ही रहा हूं। मैं आगे जो बोल रहा हूं, प्रूव ही कर रहा हूं। सर, पिछले साल पारित बजट में विधायक क्षेत्र विकास निधि का प्रावधान था। वह राशि

बढ़ाकर 2.20 करोड़ रुपए की गई थी और उस बजट में से हमें चार किस्तें 55-55 लाख रुपये की आनी थीं। दो किस्तें अप्रैल में और जुलाई में आईं। हालांकि जो जुलाई की किस्त 55 लाख रुपये की आई, उसकी भी जो हमने सैंक्शंस भेजी हैं, उसकी धनराशि जारी नहीं हुई। कुछ हो गई कुछ रह गई परंतु जो अक्तूबर और जनवरी महीने में 55-55 लाख रुपये की किस्ते आनी थीं वे तो जारी ही नहीं हुईं और आज जब हम विधायक क्षेत्र विकास निधि की बात करते हैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी उसको आर0डी0जी0 के साथ जोड़ रहे हैं। आर0डी0जी0 बंद होने का इंपैक्ट तो 1 अप्रैल 2026 के बाद शुरू होना है। विधायक क्षेत्र विकास निधि तो बजट 2025-26 की स्वीकृत धनराशि है। इसलिए आर0डी0जी0 के इंपैक्ट के साथ इसको जोड़ने पर मैंने कहा गुमराह कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह विधायक क्षेत्र विकास निधि हर विधायक के लिए और हर विधान सभा क्षेत्र की जनता के लिए महत्वपूर्ण है। इससे छोटे छोटे विकास कार्य होते हैं। हमने आपदा के दौरान वायदे किए हैं। आपने प्रावधान किया कि घरों के आगे और पीछे डंगे लगने हैं तो आप लगा सकते हैं। हमने लोगों से एस्टीमेट ले लिए थे।

अध्यक्ष : यह आ गया था ।

17.02.2026/1225/**केएस/वाईके**/2

श्री रणधीर शर्मा : अब पैसा ही नहीं है तो कैसे लगेंगे? अध्यक्ष महोदय, सभी विधायक चाहे वे पक्ष से हों या विपक्ष से हों, सभी के मन में पीड़ा है और सत्ता पक्ष के विधायक भी हमसे बात करते हैं कि आप इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाएं परंतु मुख्य मंत्री महोदय जिस तरह से इस मुद्दे को टालते हैं, यह सही नहीं है

अध्यक्ष : ज़ीरो आवर में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। No politics in Zero Hour.

श्री रणधीर शर्मा : सर, राजनीति की बात नहीं है। यह बजट की और सदन की गरिमा है। बजट इस सदन में प्रस्तुत हुआ पारित हुआ। अगर साल में उस बजट के प्रावधान लागू नहीं होंगे तो बजट की क्या सेंक्टिटी रह जाती है और इस हाउस की क्या गरिमा रह जाती है? अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह है कि यह विधायक

क्षेत्र विकास निधि की जो दो किस्तें बची हैं, इनको तुरंत जारी किया जाए ताकि हमने जो जनता से वायदे किए हैं, उनको हम पूरा कर सके। आर0डी0जी0 की मीटिंग के बाद आपने अगर कोई बैठक करनी है, उसमें 1 अप्रैल के बाद क्या हो सकता है, उस पर विचार हो। परंतु जो हमारी पिछली विधायक निधि सेंक्शंड हैं, उसको इससे न जोड़ा जाए, यह मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह है।

अध्यक्ष : रणधीर शर्मा जी, अध्यक्ष के माध्यम से नहीं ज़ीरो आवर के माध्यम से आग्रह बोलिए। Again a very important issue has been raised by the Hon'ble MLA. Since the Hon'ble Chief Minister is not here in the House, he may reply to this issue later as and when he will be available. But as you all know, I am very liberal in allowing issues which pertains to the public at large, which pertains to the State of Himachal Pradesh and this is also one of the issues in the Zero Hour. Though, there was no written notice, yet I have allowed you. The limitation the Government has that they will explain it. What you say is causing aspersions and that is not a proper thing. So, I will request all the Hon'ble Members since the Hon'ble Chief Minister as time and again apprise this

17.02.2026/1225/केएस/वाईके/3

House that these are the limitations so we must understand those limitations also instead alleging something, which you have to prove later on the record also. The next issue Dr. Janak Rajji.

डॉ0 जनक राज : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

Speaker : This is again your issue which is pertaining to Village Salon where a great damage has been caused by the Monsoon. Already you have questioned on these issues also. Let us be very specific for the issue and don't politicize it.

डॉ0 जनक राज : जी, सर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी के ध्यान में एक विषय लाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के होली क्षेत्र में साह पंचायत का एक सलून गांव है जिसका मानसून के दौरान बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। वहां के लिए रास्ता भी खत्म हो गया। अभी तो रावी नदी में पानी कम था जिस वजह से लोग नदी से भी आर पार जा रहे हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

17.02.2026/1230/av/AG/1

डॉ जनक राज ------- जारी

मैंने उस समय भी माननीय मंत्री से आग्रह किया था कि वहां 200 मीटर पैदल रास्ते की मांग है जोकि ऊपर पहाड़ी से निकलना है। उसके लिए हमने बहुत बार प्रयास किए परंतु वह मामला लोक निर्माण विभाग और पंचायतों के बीच में उलझ कर रह जाता है। मैं इस बारे में माननीय राजस्व मंत्री से आश्वासन चाहता हूं कि यह जो 200 मीटर पैदल रास्ते की मांग हमने आपके समक्ष वहां पर भी रखी थी; कृपा करके उसको बनाया जाए। अभी गर्मी का मौसम आने वाला है और उसके कारण नदी में पानी का स्तर बढ़ेगा जिससे लोगों को आने-जाने में फिर से समस्या होगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री से इस कार्य को जल्दी-से-जल्दी करवाने का आश्वासन चाहता हूं।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस जगह का जिक्र किया है, हम दोनों स्वयं पिछली बरसात के वक्त वहां पर गए थे और उस बारे में वहां पर लोक निर्माण विभाग को जरूरी निर्देश भी दिए थे। **मैं इस बारे में अद्यतन स्थिति पता करके उसके अनुसार कार्रवाई करूंगा।**

अध्यक्ष : आज केवल तीन ही विषय थे और तीनों पूरे हो गए हैं।

17.02.2026/1230/av/AG/2

स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब सचिव, विधान सभा सदन द्वारा पारित उस विधेयक की प्रति सभा पटल पर रखेंगे जिस पर राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

सचिव, विधान सभा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का अधिनियम संख्यांक 3) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जिसे सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरांत राज्यपाल महोदय से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

17.02.2026/1230/av/AG/3

कागजात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब माननीय राजस्व मंत्री कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 की धारा 45(4) के अंतर्गत डॉ0 वाई0एस0 परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन की वार्षिक लेखा रिपोर्ट, वर्ष 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित), की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

17.02.2026/1230/av/AG/4

नियम- 102 के अंतर्गत सरकारी संकल्प पर आगे चर्चा

अध्यक्ष : अब आगे दिनांक 16 फरवरी, 2026 को माननीय संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री) द्वारा नियम-102 के अंतर्गत प्रस्तुत सरकारी संकल्प पर चर्चा होगी। मेरे पास दोनों दलों से आज की रिवाइज्ड लिस्ट आ चुकी है जिसमें 12 माननीय सदस्य भारतीय जनता पार्टी और 10 काँग्रेस पार्टी से इस सरकारी संकल्प की चर्चा में हिस्सा लेंगे। कुल मिलाकर 22 सदस्य बोलने वाले हैं और अगर प्रत्येक सदस्य को 10-15 मिनट्स का समय भी दिया जाए तो भी मुझे लगता है कि हाउस का समय बढ़ाना पड़ेगा। अगर यह विषय खत्म हो गया तो हमारे पास इसके आगे भी बिजनैस है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण भी होना है। इसलिए मेरा यह आग्रह है कि यह मुद्दा बहुत स्पेसिफिक और लिमिटेड है। मेरे ख्याल से राजनैतिक उद्‌बोधन के लिए अभी राज्यपाल महोदय का अभिभाषण और बजट पर चर्चा है। इसलिए आर्टिकल 275 और आर्टिकल 280 के तहत जो मेन्डेट है; सभी माननीय सदस्य उसी पर चर्चा करेंगे तो मेरे ख्याल से हम यह चर्चा समय पर समाप्त करके अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे।

रिवाइज्ड लिस्ट के अनुसार मैं माननीय उप-मुख्य मंत्री से शुरू कर रहा हूं। माननीय उप-मुख्य मंत्री, आप नियम-102 के अंतर्गत चर्चा शुरू कीजिए।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपने चेयर से ही यह स्पष्ट कर दिया कि संविधान की जिन धाराओं के तहत राज्य को जो अधिकार मिलते हैं; केवल उसी के बारे में बात की जाए।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर लगातार बात हो रही है कि आर0डी0जी0 यानी जो राजस्व घाटा अनुदान है; वह आपको क्यों मिले और इस पर आपका क्या राइट है। यह भारत का संविधान है (संविधान की कॉपी हाथ में पकड़कर दिखाई गई।) और इस संविधान के अनुसार हमारा अधिकार है कि हमें यह आर0डी0जी0 मिले। भारत का फैडरल स्ट्रक्चर है और हमारे संविधान में भी फैडरल स्ट्रक्चर की बात है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में **टी सी द्वारा जारी**

17.02.2026/1235/टी0सी0वी0/ए0जी0-1
उप-मुख्य मंत्री ... जारी

संघीय ढांचे की बात आती है लेकिन पिछले कुछ वर्षों से लगातार ऐसा चल रहा है कि राज्यों के टैक्स में कटौती की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, श्री रणधीर शर्मा जी भी उस दिन प्लानिंग कमेटी में थे। वे हमारे सीनियर कलीग हैं और हमारे साथी हैं। उन्होंने उस दिन जोर देकर यह कहा कि यह कांस्टीट्यूशनल नहीं है और यह राज्य का अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा स्पष्ट तौर पर लिखा है कि "संसद द्वारा विधिवत निर्धारित की गई ऐसी धनराशि भारत की संचित निधि से प्रत्येक वर्ष उन राज्यों के राजस्व की सहायता के रूप में आबंटित की जाएगी जिन्हें संसद सहायता की आवश्यकता वाला समझे और विभिन्न राज्यों के लिए अलग-अलग धनराशि निर्धारित की जा सकती है।"

अध्यक्ष महोदय, यह संविधान की धारा-275 में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि केंद्र को राज्य की मदद करनी है। इसमें यह भी स्पष्ट है कि कितनी राशि देनी है। ...(व्यवधान)

Speaker: Please, order in the House. Please don't disturb the Hon'ble Deputy Chief Minister. He is explaining everything.

उप मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर उनसे कहना चाहता हूं कि आज आप जो हाउस में कहेंगे, उसकी गूंज लंबे समय तक रहेगी। जो आप बोल रहे हैं, वह रिकॉर्ड में रहेगा। आपने कहा था 'स्टेटहुड मारो ठुड'। जब हिमाचल बन रहा था, तब आप हिमाचल बनने के खिलाफ थे इसलिए आज तक उसकी चर्चा होती है कि आप हिमाचल बनने के पक्षधर नहीं थे। यह बात हमेशा होती रहेगी कि आपका स्टैंड ठीक नहीं था।

आज जब हिमाचल के भविष्य का सवाल है, मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हिमाचल का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है और आप उसमें साथ नहीं देंगे तो यह भी रिकॉर्ड हो जाएगा कि जब हिमाचल संकट में था तब आप उस समय क्या बोल रहे थे। हम बाबा साहब अंबेडकर जी को याद करते हैं और उनकी टीम को याद करते हैं जिन्होंने

17.02.2026/1235/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

यह संविधान बनाया। उन्होंने दूरदर्शिता के साथ यह व्यवस्था की थी कि राज्यों की मदद होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, अभी इन्होंने संविधान की धारा-280 का उल्लेख किया। ...(व्यवधान)

Speaker: Thakur Sahib, please let him explain now. He will explain in his own manner.

उप मुख्य मंत्री : श्री जयराम ठाकुर जी मुख्य मंत्री रहे हैं, उन्हें मुझसे ज्यादा जानकारी है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि एक फाइनेंस कमीशन बनेगा। इसमें पंचायत और नगर पंचायत को अधिकार दिए जाने का भी प्रावधान है। इसके साथ-साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि संघ और राज्यों के बीच विभाजित किए जाने वाले करों की शुद्ध आय का वितरण तथा राज्यों के बीच ऐसी आय का संबंधित हिस्सों का आबंटन किया जाएगा। जो पैसा कर के रूप में केंद्र के पास जाएगा, वह धन राज्यों में बांटा जाएगा। यह व्यवस्था संविधान के निर्माताओं ने पहले ही कर दी थी।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन की धारा- 282 में कहा गया है कि केंद्र किसी भी राज्य को अनुदान दे सकता है और राज्य को भी यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी को भी अनुदान दे सकता है। मुख्य मंत्री जी, आप लोग जो निर्णय लेते हैं कि किस जिले को पैसा देना है, यह भी संविधान में

श्रीमती एन0ए0 द्वारा जारी ...

17-2-2026/1240/एन0एस0-ए0एस0/1

उप-मुख्य मंत्री -----जारी

पहले ही उल्लेख किया गया था कि केंद्र भी दे सकता है और राज्य भी दे सकता है। अध्यक्ष महोदय, यह ताकत हमें भारत के संविधान ने दी है जो हमारा अधिकार है और हमारा हक है तथा उसकी लड़ाई शुरू हुई है। मैं नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी के बयान सुनता

हूं। ये वरिष्ठ नेता हैं और मैं पूरे अदब के साथ इनसे बात कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जब यहां पर ऑपरेशन लोटस हुआ तो जय राम जी ने यहां पर कहा कि अब तो भगवान भी इस सरकार को नहीं बचा सकता। सरकार तो बची है और चल रही है। ...(व्यवधान) मैं तो आपसे सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि आप इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं, आपको क्या जल्दबाजी है और आप विपक्ष की कुर्सी में क्यों नहीं बैठ सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, यहां पर अभी आर0डी0जी0 का मुद्दा आया। जब आर0डी0जी0 बंद हुई तो श्री जय राम ठाकुर जी ने एक बार भी अफ़सोस जाहिर नहीं किया कि यह प्रदेश के साथ गलत हो गया। ...(व्यवधान)

Speaker : Shri Jai Ram Thakur Ji, please no interruption. ...(Interruption) Please take your seats. बोलने दो, उप-मुख्य मंत्री जी को बोलने दो। Nothing is going on record. ...(Interruption) माननीय सतपाल सिंह सत्ती जी व माननीय हंस राज जी बैठ जाइये।

उप-मुख्य मंत्री : माननीय सत्ती जी अगर आर0डी0जी0 के मुद्दे पर माहौल बिगड़ता भी है तो मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आर0डी0जी0 पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? ...(व्यवधान) जो आप बोल रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं? माननीय जय राम ठाकुर जी जनता के बीच गए और कहा कि चुनाव की तैयारी कीजिए क्योंकि आर0डी0जी0 बंद हो गई है। आपका यह स्टैंड है। ...(व्यवधान) आपने कहा कि नहीं कहा। ...(व्यवधान) हम आपको वीडियो देंगे।

Speaker : No interruption please. I am not allowing anybody except the Hon'ble Deputy Chief Minister. ...(Interruption) अगर आपने कुछ बोलना होगा तो इनकी स्पीच के बाद कोरैक्शन के लिए बोल देना। आपने उसके बाद बोल देना जैसे कल मुख्य मंत्री जी को अंत में समय दिया गया था और अंत में वैसा ही समय मैं इनकी स्पीच के

17-2-2026/1240/एन0एस0-ए0एस0/2

बाद आपको भी दूंगा। आप सुनते जाओ क्योंकि सुनना बहुत जरूरी है। कड़वाहट ज्यादा है इसलिए सुनना जरूरी है। राजनीति में कड़वाहट ज्यादा है सुनना जरूरी है जिससे ज्यादा ताकतवर होते हैं।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह इनका कसूर नहीं है, इस कुर्सी में ही स्प्रिंग लगे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, राज्यों को कमजोर करने की लगातार एक कोशिश चल रही है। पहले जी0एस0टी0 बंद कर दिया गया। जी0एस0टी0 का कंपनसेशन राज्यों को मिलता था। माननीय जय राम ठाकुर जी को जी0एस0टी0 कंपनसेशन बहुत ज्यादा मिला है। इसमें एक बात थी कि जी0एस0टी0 का कंपनसेशन बंद करते समय बड़े समय से केंद्र राज्यों को सूचित कर रहा था कि हम जी0एस0टी0 का कंपनसेशन बंद कर रहे हैं। वे बार-बार कह रहे थे कि हम बंद कर रहे हैं इसलिए राज्य उसके लिए तैयार हो रहे थे कि जी0एस0टी0 का कंपनसेशन बंद हो जाएगा। हालांकि, जी0एस0टी0 कंपनसेशन बंद होने से हिमाचल जैसे राज्य को बहुत भारी नुकसान हुआ है क्योंकि हिमाचल में तो मार्किट नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुंभ का मेला होता है और उनको 20,000 करोड़ रुपये का जी0एस0टी0 इकट्ठा हो जाता है

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

17.02.2026/1245/RKS/As-1

उप-मुख्य मंत्री ... जारी

जिसका आधा भाग उत्तर प्रदेश सरकार को और आधा हिस्सा केंद्र सरकार को जी0एस0टी0 के रूप में मिला। लेकिन हमारे यहां ऐसी कोई मार्किट नहीं है। हम यहां ऐसी कोई चीज नहीं बनाते जो बाहर जाकर बिके। जो चीजें बेचते हैं उन्हें तो पैसा मिल रहा है लेकिन हम यहां देशभक्ति और देश सेवा ही कर रहे हैं। जी0एस0टी0 से हिमाचल प्रदेश को काफी नुकसान हुआ है। ...(व्यवधान) यह प्रदेश हित का मसला है और आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अध्यक्ष महोदय, जी0एस0टी0 न मिलने से हिमाचल प्रदेश को भारी-भरकम नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश ने इस नुकसान को जैसे-तैसे बर्दाश्त कर लिया है। श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार को 16 हजार करोड़ रुपये मिले थे लेकिन

सुक्खू जी की सरकार को यह राशि प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष 2022 से यह राशि मिलना बंद हो गई है। ...(व्यवधान) जय राम जी की सरकार, सुक्खू जी की सरकार और हो सकता है जीवन में कभी आपकी (डॉ0 हंस राज की) सरकार भी बने। सरकार बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। ...(व्यवधान) चलो कांग्रेस की सरकार, भाजपा की सरकार, आप जो समझते हैं, वह ठीक है। वर्ष 2022 में जी0एस0टी0 बंद होने के कारण हमारे राज्य को भारी नुकसान हुआ। आर0डी0जी0 पर श्री जय राम ठाकुर जी ने एकदम बयान दिया कि यह एक नीतिगत फैसला है। इन्होंने कहा कि आर0डी0जी0 17 राज्यों की बंद हुई है और यदि हिमाचल प्रदेश की भी हुई है तो क्या हो गया? अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के प्रति हमारा भावनात्मक लगाव भी होना चाहिए। यह केवल कुर्सी प्राप्त करने का प्रश्न नहीं है बल्कि राज्यों के हितों और उनके भविष्य से जुड़ा विषय है। यह कहा गया कि 17 राज्यों की आर0डी0जी0 बंद कर दी गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आर0डी0जी0 पर सर्वाधिक निर्भरता किन राज्यों की रही है? आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश की लगभग 13 प्रतिशत निर्भरता आर0डी0जी0 पर रही है और हमसे भी अधिक निर्भरता नागालैंड राज्य की है। उत्तराखंड की निर्भरता लगभग 5 प्रतिशत रही है। 12 ऐसे राज्य थे जिन्हें आर0डी0जी0 प्राप्त होती थी किंतु उनके लिए यह राशि फालतू थी। यदि उनकी आर0डी0जी0 बंद हुई है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी राज्य को 1 प्रतिशत और किसी को 2 प्रतिशत आर0डी0जी0 की सहायता मिलती थी। किन्तु जो शीर्ष के पांच राज्यों की आर0डी0जी0 बंद हुई है उनकी स्थिति पर गंभीरतापूर्वक

17.02.2026/1245/RKS/As-2

विचार किया जाना चाहिए। जहां तक जम्मू-कश्मीर का प्रश्न है, यदि उसे आर0डी0जी0 नहीं मिलेगी तो संभव है कि उसे अन्य माध्यमों से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी क्योंकि उसकी परिस्थितियां अलग हैं। जम्मू-कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है तथा सीमावर्ती क्षेत्र होने और पाकिस्तान के साथ संबधों के कारण उसे विभिन्न मदों में सहायता मिलती रहेगी। नॉर्थ-इस्ट राज्यों को भी विभिन्न मदों में पैसा मिलता रहेगा क्योंकि उनकी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। उत्तराखंड राज्य को 5 प्रतिशत आर0डी0जी0 मिल रही है।

उत्तराखंड राज्य का आधा क्षेत्र पहाड़ी और आधा मैदानी है और उन्हें ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य की आर0डी0जी0 बंद हो जाए तो यह चिंता का विषय है। हमारे 68 विधायकों में से जो आर0डी0जी0 के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करने के पक्ष में नहीं होंगे उनका रुख प्रदेश के इतिहास में अवश्य लिखा जाएगा। ...(व्यवधान) मैं गार्डेड लैंग्वेज इस्तेमाल करना चाहता हूं। श्री जय राम ठाकुर जी वरिष्ठ नेता हैं लेकिन पता नहीं ये क्यों डायरेक्शन लैस हो गए हैं? जब हम किसी प्रस्ताव को केंद्र सरकार की सहमति के लिए भेजते हैं तो जय राम ठाकुर जी इसके विरुद्ध हो जाते हैं। ...(व्यवधान) हमने आपदा के समय भी इस सदन से प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार की सहमति हेतु भेजा था लेकिन आप उस समय भी बाहर चले गए थे जबकि सबसे ज्यादा पैसा आपके चुनाव क्षेत्र को ही दिया जा रहा है। आप हमें बताएं कि किस सरकार ने एक मकान के निर्माण कार्य के लिए 7-7, 8-8 लाख रुपये दिए हैं? मैं मुख्य मंत्री जी के दो फंक्शन देख चुका हूं। मंडी के दो फंक्शनों में मुख्य मंत्री जी ने 142 करोड़ रुपये दिए हैं। ...(व्यवधान) श्री रणधीर शर्मा जी यह हकीकत बात है। ...(व्यवधान)

श्री बी0एस0द्वारा जारी

17.02.2026/1250/बी.एस./डी.सी.-1

उप-मुख्य मंत्री जारी...

Speaker: Hon'ble Members, order in the House. Don't interrupt the Hon'ble Deputy Chief Minister.

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये बाहरी तौर पर जो मर्जी कहें लेकिन इनका दिल जरूर मानता है कि हम गलत कर रहे हैं, हम प्रदेश के साथ गलत कर रहे हैं। आज आर0डी0जी0 पर मुख्य मंत्री जी ने क्या कहा; कि आ जाओ सारे इकट्ठे हो जाओ इकट्ठे बैठकर देखते हैं क्या सॉल्यूशन है?

श्री रणधीर शर्मा: हम आए तो हैं।

उप-मुख्य मंत्री : आप आए हैं, परंतु जब संकल्प पास होगा तब तक बरकरार रहें, उसकी बात हो रही है। हम मेजोरिटी में है सरकारी संकल्प को हम पास करेंगे ही। अध्यक्ष महोदय आदरणीय जय राम जी को 54 हजार करोड़ रुपये की आर0डी0जी0 मिली थी। उसके बाद 16 हजार करोड़ रुपये की इनको जी0एस0टी0 मिली। इन्हे 70 हजार करोड़ रूपया मिलने के बाद भी इन्होंने कर्मचारियों के एरियर नहीं दिए।

श्री जय राम ठाकुर : नहीं, हमने एरियर दिया है।

उप-मुख्य मंत्री : आप हिमाचल प्रदेश पर 76 हजार करोड़ रुपये का कर्ज छोड़ गए आज आप बार-बार बयान देते हैं कि सरकार कर्ज पर चल रही है, आप कौन सा गैस पर चल रहे थे? आप भी तो कर्ज पर चल रहे थे और साथ में आपको तो जो पैसा मिला वह न भूतों न भविष्यति और अध्यक्ष महोदय जब आर0डी0जी0 बंद करने की बात आई, यह ठीक है आर0डी0जी0 टेपरिंग में आ रही थी, कभी 12 हजार करोड़ रुपये आई, कभी 10 हजार करोड़ रुपये, कभी 6 हजार करोड़ रुपये, कभी 5 हजार करोड़ रुपये आई अंत में इनको 3 हजार करोड़ रुपये मिली। परंतु उस वक्त एक भी पत्र केंद्र सरकार का अध्यक्ष महोदय दिखा दें जिसमें उन्होंने हिमाचल को लिखा हो कि आपकी आर0डी0जी0 बंद कर दी जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र से यही बोला गया था।

17.02.2026/1250/बी.एस./डी.सी.-2

उप-मुख्य मंत्री : यह आपके मन में है। देखो जय राम जी, आपकी मंशा साफ होती जा रही है कि आप आर0डी0जी0 के खिलाफ हो। आप अब तर्क नहीं दे रहे हो, आप अब कुतर्क दे रहे हो, यह कुतर्क चल रहे हैं। अब आर0डी0जी0 को लेकर केन्द्र ने एक पत्र भी हिमाचल को लिखा होता 5 साल पहले 3 साल पहले एक साल पहले लिखा होता कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, राज्य अपने आपको तैयार करता वन फाइन मॉर्निंग आप कह देते हैं कि आपको पैसा नहीं मिलेगा। इस बारे में कोई एनालिसिस नहीं किया गया और स्टेट कैसे

मीट करेगा कोई गाइडेंस नहीं दी गई। फाइनेंस कमीशन यहां पर आया उन्होंने कोई भी बात ऐसी नहीं रखी कि आपको आने वाले समय में पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपको यह बंद करनी थी तो तैयारी करने के लिए कोई समय देते वैसे मैं एक बात कह देता हूं यह सारा प्रदेश जानता है कि मौजूदा सरकार ने रिसोर्सिज पैदा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। यह आप सब जानते हैं कि हम किस ढंग से अपनी आय का बढ़ा रहे हैं हालांकि लोग नाराज हो रहे हैं क्योंकि उस पर आग आप डाल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमने 3-4 हजार करोड़ रुपये का रेवेन्यू अर्जित किया है। आप मंत्री रहे हैं वरिष्ठ सदस्य हैं आप राय दे रहे हैं कि खर्चों में कटौती करो, हम करेंगे जितना और कर पाएंगे हम कोशिश करेंगे लेकिन आपका जो सुझाव है उसका हम हमेशा सम्मान करते हैं लेकिन हम यहां पर प्रिंसिपल स्टैंड की बात कर रहे हैं कि हमें करना क्या है? अध्यक्ष महोदय मैं तो बड़ा हैरान हुआ, जब मैं सारे कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी कर रहा था और अंग्रेजो ने जाते समय मेंशन किया है, अंग्रेजों ने कहा कि हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है इसको मैनेज करना में दिक्कत होगी इसलिए इनको कोई-न-कोई अपने राज्यों को पैसा देने के लिए सिस्टम निकालना पड़ेगा उसमें यह भी अंकित है, अगर वे 1947 से पहले यह बात करते थे

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

16.02.2026/1255/डीटी/डीसी-1

उप-मुख्य मंत्री जारी......

अगर 1947 से पहले यह बात करते थे तो आज की तारीख में तो हमारी अपनी सरकार है, हमारी अपनी सल्तनत है। अगर गौरे भी ऐसा बोलते थे तो आप सोचो कि क्या बात है? श्री रणधीर शर्मा जी उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसकी बहस के सारे अंश अभी भी विद्यमान है कि किसने क्या कहा और क्या पक्ष रखा। असम के लिए और जनजातिया एलोको के लिए उन्होंने विशेष मदद के लिए कहा। ...(व्यवधान) My dear friend ...(interruption) don't jump to the conclusion. ...(Interruption)

Speaker: We are discussing Article 275 not 271.

उप मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जय राम ठाकुर जी को यह कहना चाहता हूं कि उस समय हिमाचल नहीं बना था। अगर हिमाचल बना होता तो निश्चित तौर पर यह लिखा जाता है कि हिमाचल को भी विशेष सहायता दी जाए। हमारा देश स्वतंत्र होने के बाद हिमाचल बहुत बाद में बना। अगर उस समय असम और अन्य राज्यों के बारे में लिखा गया तो यदि हिमाचल अस्तित्व में होता तो हिमाचल के बारे में भी जरूर लिखा जाता। ...(व्यवधान) अभी क्या दिक्कत है, अभी भी तो कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकती है। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इनकी बहस से एक ही बात निकाल कर बाहर आ रही है। ...(व्यवधान) मैं मुख्य मंत्री जी को पहले से बोलता था और मैंने यह बात कैबिनेट में पहले से बोली है। ...(व्यवधान) जय राम जी नाराज हो जाएंगे। मैं इनको पहले से बोलता था कि जय राम जी दिल्ली पैसा रुकवाने के लिए जाते हैं। यह किसी पॉलिटिकल काम को करवाने के लिए नहीं जाते हैं। ये हिमाचल का पैसा रुकवाने जाते हैं। ...(व्यवधान) यह मैं नहीं कह रहा हूं। ...(व्यवधान)

Speaker: Hon'ble Member Shri Bikram Singh ji, I have not allowed you to speak. ...(Interruption). Please take your seats. ...(Interruption).

16.02.2026/1255/डीटी/डीसी-2

उप मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, (***)...(व्यवधान) चलो, इसे निकाल दे।

Speaker : He has withdrawn his words, so that will not make part of the record.

उप मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन का 1227 करोड़ रुपये नहीं दिया जा रहा है। 1227 करोड़ रुपया घोषित पैसा है जिनमें से 5-6 सौ0 करोड़ तो जय राम जी खर्च

करके चले गए। आप मेरी बात सुनो। जल जीवन मिशन के तहत 5100 करोड़ रुपये आपके समय तक आ चुका था। उसके बाद 1227 करोड रुपए आना था लेकिन वह पैसा कभी नहीं आया। हम मंत्री जी से भी मिले, हमकी जहां-जहां तक पहुंच थी हम मिले लेकिन वह पैसा नहीं आया। आप बताओ कि जहां पर आप 600 करोड़ रुपए के टेंडर कर गए थे ...(व्यवधान) यह तो जो पेट्रोल में सैस आता है उसमें हमारा शेयर है। ...(व्यवधान) ऐसा है न आपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में काम न करवाया होता तो आप यहां न बैठे होते। आपने काम करवाया है। आपने दूसरों से हटके करवाया है।

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी

17.02.2026/1300/एच.के.-एन.जी./1

उप-मुख्य मंत्री.......... जारी

...(व्यवधान) मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अब श्री जय राम ठाकुर जी ने अपने समय में 15 हैलिपैड्स व 10 रेस्ट हाऊसिस का निर्माण अपने विधान सभा क्षेत्र में करवाया था तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कह रहा हूं। ठीक है, ये मुख्य मंत्री थे और इन्होंने जो किया सो किया।...(व्यवधान)

Speaker : Shri Bikram Singh ji, please no interruption. You are a very senior member.

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि बहुत सारे राज्यों की लॉबी हमारे ख़िलाफ है। आर0डी0जी0 की भी एक लॉबी...(व्यवधान) ऐसा है कि कर्नाटक राज्य को आर0डी0जी0 से एक प्रतिशत मिलता था तो उन्हें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उनका टैक्स बेस बहुत ज्यादा है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष : उनके जो रिसोर्सिस हैं, they control their resources themselves whereas in Himachal Pradesh the resources are controlled by the Centre.

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जब हिमाचल प्रदेश बना था तब हमारे व केन्द्र के नेताओं को पता था कि इस राज्य के पास टैक्स बेस नहीं है। इसके पास आय के संसाधन नहीं हैं और इस राज्य को केन्द्र की मदद पर ही चलाना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश के लोगों की पॉलिटिकल एस्प्रेशन को पूरा करने के लिए इसका गठन किया गया था। उस समय भी पता था कि हिमाचल प्रदेश के पास पैसा नहीं होगा और केन्द्र सरकार से ही पैसा देना होगा।

अध्यक्ष : उप-मुख्य मंत्री जी, हमारे रिसोर्सिस पर कंट्रोल भी केन्द्र सरकार का होगा।

17.02.2026/1300/एच.के.-एन.जी./2

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारे रिसोर्सिस पर पूरा कंट्रोल कर लिया गया है। आज की स्थिति में आपको (हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में कहा) जी0एस0टी0 नहीं मिलेगी, आर0डी0जी0 आपको देंगे नहीं, आप जो कर्जा लेंगे उस पर कैप लगा देंगे, आप 10 हज़ार करोड़ रुपये से ज्यादा कर्जा नहीं ले पाएंगे, आपकी फोरेन फंडिग पर कैप लगा दी गई है, यदि आप अपने कर्मचारियों को ओ0पी0एस0 देंगे तो उसकी एवज में आपका 1800 करोड़ रुपये काट लिया जाएगा, इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश पर पूरी तरह से शिकंजा कसा गया है। मेरा आग्रह है कि इसके लिए तो हम सभी को कंसर्न होना चाहिए कि किस प्रकार से यह सारा मामला चल रहा है।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, भारत देश राज्यों का देश है

और केन्द्र सरकार की किट्टी में से 41 प्रतिशत पैसा सभी राज्यों को दिया जा रहा है ताथ 59 प्रतिशत पैसा केन्द्र सरकार स्वयं रख रही है। इसके अलावा राज्यों को जो पैसा आएगा वह भी राज्यों को सीधा न आकर स्कीम के तहत आएगा। राज्यों को पैसे की कोई लिबरेज़ नहीं दी जा रही है।...(व्यवधान) हिमाचल प्रदेश का टैक्स बेस लगभग 18 हज़ार करोड़ रुपये है।...(व्यवधान) सुन लीजिए।...(व्यवधान) अरे, हिमाचल प्रदेश का टैक्स शेयर कितना है? ...(व्यवधान)

Speaker : Shri Randhir Sharma Ji, please ...(Interruption) Let him say in his own manner. आपके (विपक्ष की ओर देख कर कहा) माननीय सदस्य जब बोलेंगे, तब जवाब दे देना।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश का टैक्स शेयर दूसरे राज्यों के मुकाबले कितना है? श्री रणधीर शर्मा जी, इसे भी स्टडी कर लेना। अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश की आय लगभग 18 हज़ार करोड़ रुपये है जबकि हमारी फिक्स लायबिलिटिज़ 42 हज़ार करोड़ रुपये की हैं जिसमें कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और कर्ज का ब्याज आदि शामिल है।...(व्यवधान) यह सब तथ्यों पर है और आपने (माननीय सदस्य, श्री रणधीर शर्मा को कहा) इसको कंट्राडिक्ट कर लेना।...(व्यवधान)

17.02.2026/1300/एच.के.-एन.जी./3

Speaker : No interruption please.

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बड़े राज्यों की लॉबी प्रिवेल कर गई और हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य का गला घोंट दिया गया। बड़े राज्य चाहते थे कि आर0डी0जी0 नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि इससे सबसे ज्यादा फायदा छोटे राज्यों को हो रहा था। अध्यक्ष

महोदय, फण्ड ऐलोकेशन करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी के पास भी किट्टी होती है। हमने कहा है कि माननीय प्रधान मंत्री जी इसमें दखल दें क्योंकि वे हिमाचल प्रदेश में रहे भी हैं। अभी भी समय है और माननीय प्रधान मंत्री जी स्वयं दखल देकर हिमाचल प्रदेश को उसका हक दिलवाएं।

श्री ए0पी0 द्वारा......जारी

17.02.2026/1305/एच.के./ए.पी/01

नियम-102 पर चर्चा जारी ....

उप-मुख्य मंत्री जारी .....

मैं देख रहा था कि हिमाचल के एक सांसद कह रहे थे कि आओ हम आपको सिखाते हैं कि financial management कैसे की जाती है। वह हमें कह रहे है, वह जय राम जी को ही सिखा देते। सुनिये ...(व्यवधान) सुनिये। नहीं ...(व्यवधान) प्रोब्लम आपको भी होगी। ऐसा नहीं है। ...(व्यवधान) देखेंगे नहीं। आपको यह लगता है कि कहीं सीगों को हाथ न पड़ जाए। आप सिर्फ यही देख रहे हो। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य कह रहे है कि बड़े कर्जो को कम ब्याज से कैसे करना है। क्या हम नहीं जानते इन बात को। कह रहे थे कि दिल्ली आओ, आपकी मदद करवाएंगे और कह रहे थे कि कर्जों को कैसे सीमित करना है। ...(व्यवधान) वह तो हमें आता है। वह तो हम खुद रोटेट कर रहे है, इसे आप क्या सिखाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में फिर से कह रहा हूं कि हिमाचल को मझदार में जिस तरह से छोड़ा जा रहा है, यह सही नहीं है। माननीय सदस्य जो यहां पर बात कर रहे है उनसे मैं स्पष्टतौर से यह आग्रह करना चाहूंगा कि आर0डी0जी0 के मुद्दे पर डिस्कशन कर लो, विधायक दल की मीटिंग ढंग से बुला लो, ढंग से विधायक दल की मीटिंग में फैसला कर लो, यह हमारे हिमाचल और हमारी हिमाचलियत का सवाल है, ऐसा मत करो। आप सभी बहुत जिम्मेवार लोग है जो यहां पर चुनकर आए है। एक-एक लाख लोगों ने आपको वोट दिया है तब जाकर आप यहां आए हैं। ...(व्यवधान) ऐसा है राकेश जी आप गलत स्टैज पर चल पड़े हो। आज भी मौका है, आप उठकर माननीय जय राम जी से कह

दो की आप गलत कर रहे हैं (उप-मुख्य मंत्री जी विपक्ष के सभी साथियों को कहते हुए) सब लोग कह दो कि यह गलत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं यहीं कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व किसी के मिटाए नहीं मिटेगा। हिमाचल रहेगा, हिमाचल है और हिमाचलियत हमेशा कायम रहेगी। हमें तो छोटी-छोटी चीजों से नुकसान हो रहा है। आप देख सकते है सेब के मुद्दे को लेकर हमें इम्पोर्ट ड्यूटी से कितना नुकसान हो रहा है। हमारी आय के संसाधन किस तरह से चौक किये जा रहे हैं। हर क्षेत्र में ऐसा ही है। इसलिए हम सब लोग हिमाचल के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। (पक्ष के सभी साथी उप-मुख्य मंत्री की बात पर हामी भरते हुए।) हिमाचल की लड़ाई लड़ने के लिए हम सब लोग

17.02.2026/1305/एच.के./ए.पी/02

तैयार हैं। मैं चाहता हूं कि इस सदन के माध्यम से हम सभी इस लड़ाई को लड़े। क्योंकि लोग हम सब की बात करेंगे। श्री जय राम ठाकुर जी 55,000 करोड़ रुपये प्रदेश का छीना जा रहा है, आपके दिल में जरा सी भी टीस नहीं हो रही? आपको तो हमें लीड करना चाहिए था कि यह गलत हो गया। ऐसा है कि राजनिति एक तरफ, सराकरें तो आती जाती रहेंगी। कभी आप पक्ष में थे तो हम विपक्ष में थे। यह सरकारों का नहीं बल्कि प्रदेश का सवाल है। प्रदेश के स्वाभिमान की लड़ाई है, हमारे डॉ0 वाई0एस0 परमार जैसे नेता जिन्होंने हिमाचल के लिए लड़ाई लड़कर हमें यह प्रदेश दिया और इस माननीय सदन में बैठने लायक बनाया। उनकी आत्मा भी आपको कोस रही होगी कि यह प्रदेश में क्या हो रहा है। ...(व्यवधान) चलो आप हमें भी कोस लें। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया। लेकिन यह कोई नीतिगत मसला नहीं है कि आर0डी0जी0 ग्रांट 17 राज्यों की बंद हुई तो हिमाचल की भी बंद होनी चाहिए। इसे बंद करने से पहले स्टेट का आंकलन होना चाहिए था। स्टेट के पास रिसोर्सेस नहीं हैं। हम आज भी कह रहे हैं और डंके की चोट पर कह रहे हैं कि ओ0पी0एस0 जारी रखेंगे। हम तनख्वाह और पेंशन भी देंगे। आगे की सरकारें आएगी। ...(व्यवधान) माननीय रणधीर जी आपकी भी वरिष्ठता इतनी हो गई है कि आने वाले समय में आप मंत्री होंगे।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

17/02/2026/1310/AT/YK/01

उप मुख्यमंत्री जारी :

लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यदि आज सही स्टैंड ले लेंगे तो हमारी जो ...(व्यवधान)

Speaker : Please no interruption.

उप मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हालात पता क्या हैं आज जय राम जी के नेतृत्व में ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, एक तरफ प्रदेश के भविष्य का सवाल है और दूसरी तरफ एक सदस्य बेली राम की बात कर रहा है ...(व्यवधान) आप देखिए, प्रदेश का अस्तित्व दांव पर लगा हुआ है ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान) तभी मिलेगा जब आर0डी0जी0 आएगी ...(व्यवधान)

Speaker : Hon'ble Member Shri Bikram Thakurji, please take your seat. ...(Interruption)

उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ 55 हजार करोड़ रुपये का मसला खड़ा हो गया है ...(व्यवधान)

Speaker : Please no interruption.

उप मुख्यमंत्री : पहली किस्त 13 हजार करोड़ रुपये आई थी। अध्यक्ष महोदय, हर साल 10 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। आज हम केवल 10 हजार करोड़ रुपये की बात नहीं कर रहे हैं न ही आर0डी0जी0 की बात कर रहे हैं। यह कह रहे है कि विधायक निधि दे दी जाए। विधायक निधि तो हल हो जाएगी लेकिन आज हिमाचल के सामने एक बड़ा लार्जर और मिलियन डॉलर सवाल खड़ा है, क्या हम हिमाचल की आर0डी0जी0 ऐसे ही बंद होने देंगे? सबकी जरूरत है, सबके साथ की जरूरत है। मैं आप सब से आग्रह करना चाहता हूं और आपके सामने दोनों हाथ जोड़ता हूं कि हिमाचल के हित को सामने रखकर आर0डी0जी0 के पक्ष में एकजुट होकर माननीय प्रधानमंत्री जी से आर0डी0जी0

को बहाल करवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। **एम0डी0द्वारा जारी ......**

17-02-2026/1315/YK/MD/1

अध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए 2:15 बजे तक स्थगित की जाती है।

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी---

17.02.2026/1415/केएस/एजी/1

दोपहर के भोजनोपरांत सदन की बैठक अपराह्न 14.15 बजे पुनः आरम्भ हुई।

अध्यक्ष : अभी मेरे पास 21 माननीय सदस्यों की लिस्ट है और आज तो मुझे लगता है कि सदन का समय बढ़ाना ही पड़ेगा। यह 12.00 बजे तक भी चल सकता है। मेरा आग्रह है कि क्योंकि अब बहुत सारे मुद्दों के ऊपर डेलिबरेशन्ज़ कॉमन हो गईं हैं इसलिए स्पैसिफिकली अपने आप को मोशन पर ही कन्फाइंड करते हुए अपने-अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें तो बेहतर रहेगा and that will also save the time of the House और आपकी एनर्जी भी। With these observations, I will now call upon Shri Vinod Kumar ji to take in the deliberations.

श्री विनोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, नियम-102 के अंतर्गत हमारे वरिष्ठ सदस्य आदरणीय हर्षवर्धन चौहान जी जो सरकारी संकल्प ले कर आए हैं, मैं भी उसमें अपने आप को शामिल करता हूं। आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

17.02.2026/1420/av/AG/1

श्री विनोद कुमार------- जारी

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात अवश्य कहना चाहता हूं। अभी यहां पर उप-मुख्य मंत्री जी ने अपनी बात काफी विस्तार से रखी है। परंतु इन्होंने

इस हाउस को गुमराह किया है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय उप-मुख्य मंत्री के माध्यम से इस हाउस के साथ-साथ प्रदेश की जनता को भी गुमराह करने का काम किया गया। हमने यह सुना तो था कि नालायक बच्चों का बस्ता भारी होता है परंतु आज हमने यहां पर अपनी आंखों से देख भी लिया। मैं यहां पर इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा ने कल कहा था कि आर्टिकल 275 के तहत यदि आर0डी0जी0 के लिए कोई एक बात भी कही गई हो तो आप उस बात को स्पष्ट कीजिए। परंतु यहां पर पूरे-का-पूरा संविधान लाने के बावजूद भी ये उस बात का जिक्र नहीं कर पाए। इसलिए आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार इस विषय को लेकर कितनी गंभीर है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कई बार हम होस्पिटल जाते हैं। वहां डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं। जब डॉक्टर ऑपरेशन करने के उपरांत बाहर आता है तो खुश होता है। परंतु जब उसको पूछा जाता है कि हमारे मरीज की स्थिति कैसी है यानी ऑपरेशन कैसा हुआ तो डॉक्टर का जवाब होता है कि 'Operation success and patient dead'; मेरे कहने का मतलब वर्तमान सरकार की भी यही पोजिशन है।

केंद्र सरकार ने दिनांक 1 फरवरी, 2026 को अपना बजट प्रस्तुत किया। मैं कहना चाहता हूं कि यह एन0डी0ए0 सरकार में माननीय श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 13वां बजट प्रस्तुत हुआ है और देश की अर्थव्यवस्था स्वाभाविक रूप से तेज गति व मजबूती से आगे बढ़ी है। मैं आपको इसका उदाहरण देना चाहता हूं। वर्ष 2014 में भारत विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। परंतु श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व व उनके अच्छे तथा कड़े फैसलों के कारण आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं। ...(व्यवधान) इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि

टी सी द्वारा जारी

17.02.2026/1425/टी0सी0वी0/ए0एस0-1
श्री विनोद कुमार.. जारी

जहां मोदी जी की सरकार ने अपना 13वां बजट प्रस्तुत किया है उसके साथ-साथ श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने भी लगातार अपना 9वां बजट पेश किया है। मैं समझता हूं कि एक महिला वित्त मंत्री होने के नाते यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है।

अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा था कि जब केंद्र सरकार ने बजट प्रस्तुत किया तो पूरा देश, देश के प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद कर रहा था ...(व्यवधान) सर, उसी बात पर आ रहा हूं लेकिन हम देख रहे थे कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री जी और हिमाचल प्रदेश के हमारे कांग्रेस के सभी विधायक साथी कह रहे थे कि हिमाचल को कुछ नहीं मिला और हिमाचल का हक छीन लिया गया। जहां तक रिवेन्यू डिफिसिट ग्रांट को लेकर मैं बात करूं तो मैं कहना चाहता हूं कि यह अस्थाई व्यवस्था थी, कोई स्थाई व्यवस्था नहीं थी। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि यह ग्रांट केवल हिमाचल प्रदेश सरकार की ही बंद हुई होती तो भी हम इस बात को मानते लेकिन यह तो 17 राज्यों की बंद हुई है।

अध्यक्ष महोदय, यह जो रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट को लेकर यहां पर बात की जा रही है, मैं इन्हीं की सरकार के प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर कुछ कहना चाहता हूं। छठ्ठा वित्तायोग वर्ष 1974 में आया और 5 वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश को 161 करोड़ रुपये दिए गए। यह मैं नहीं बल्कि सरकार के आंकड़े कहते हैं। इसके बाद सातवें वित्तायोग में 207 करोड़ रुपये, आठवें वित्तायोग में 223 करोड़ रुपये, 9वें वित्तायोग में 523 करोड़ रुपये दिए गए। यदि हम दसवें फाइनेंस कमीशन की बात करें तो 772 करोड़ रुपये हिमाचल को दिए गए, 11वें फाइनेंस कमीशन में 1979 करोड़ रुपये, 12वें फाइनेंस कमीशन में 10202 करोड़ रुपये और 13वें फाइनेंस कमीशन में 7879 करोड़ रुपये हिमाचल को दिए गए। मैं यह कहना चाहता हूं कि हर बार राशि बढ़ी है, हर बार पैसा इंक्रीज हुआ है। लेकिन वर्ष 2010 से वर्ष 2014-15 के बीच ऐसा क्या हो गया कि राशि कम कर दी गई। जब राशि कम की गई तब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी।

17.02.2026/1425/टी0सी0वी0/ए0एस0-2

जब हमारी ओर से यह कहा गया कि हिमाचल का हक छीना जा रहा है तब यह लोग कहां थे इनकी पार्टी कहां थी। आज मैं इनसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं। रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट को लेकर मैं आज इस हाउस के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि वर्ष 1974 से लेकर जब से रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट शुरू हुआ तब से लेकर वर्ष 2014 तक यदि हम देखें तो इन 40 वर्षों में हिमाचल को 20956 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। यह जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं दिया लेकिन ये मैं सरकार के आंकड़ों के आधार पर ही कह रहा हूं। 40 वर्षों में यदि हमें 20956 करोड़ रुपये मिले हैं तो जो आज कहा जा रहा है कि मोदी जी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पक्षपात किया है, जहां 40 सालों में

एन0एस0 द्वारा जारी ...

17-2-2026/1430/एन0एस0-ए0एस0/1

श्री विनोद कुमार ----जारी

20,956 करोड़ रुपये कांग्रेस की केंद्र सरकार ने दिये हैं जबकि लम्बे समय तक देश में कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही हैं। मोदी जी की सरकार ने 14वें वित्तायोग में हिमाचल प्रदेश को 40,624 करोड़ रुपये दिए हैं। 15वें वित्तायोग में 11,431 करोड़ रुपये और कुल मिला करके 37,189 करोड़ रुपये मिले हैं। अगर हम मोदी जी के 12 वर्षों के कार्यकाल की बात करें तो 89,254 करोड़ रुपये हिमाचल प्रदेश को दिए गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जहां 40 वर्षों में 20,956 करोड़ रुपये कांग्रेस पार्टी की केंद्र सरकार ने दिए और मोदी जी ने 12 वर्षों में 89,254 करोड़ रुपये हिमाचल प्रदेश को दिए हैं। फिर भी आप कहते हैं कि हिमाचल के साथ भेदभाव हुआ है। आपकी सरकार ने इतना पैसा 40 वर्षों में दिया और मोदी जी ने 12 वर्षों में आपकी सरकार की अपेक्षा साढ़े चार गुणा से ज्यादा पैसा दिया है। आप कहते हैं कि हिमाचल के साथ भेदभाव हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको थोड़ा और याद दिलाना चाहता हूं। जैसा कि कहा गया कि हिमाचल के साथ भेदभाव हो रहा है। मैं इस बात को आज दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जब-जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई हैं तब-तब जितना हक हिमाचल का था उससे भी अधिक पैसा केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है। क्या आप इस बात को भूल गए हैं? आप भूले होंगे लेकिन प्रदेश की भोली-

भाली जनता नहीं भूली है। जब देश में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो उस समय अटल जी हमेशा कहते थे कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है। जब दूसरे घर की बात आई तो हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा भारतीय जनता पार्टी की श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने दिया है। अगर हिमाचल प्रदेश को विशेष औद्योगिक पैकेज दिया गया है तो भारतीय जनता पार्टी की श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने दिया है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, ये जो आज बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब केंद्र व प्रदेश में आपकी सरकार थी तो उस समय आपकी सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा हिमाचल से वापिस ले लिया था जिसको श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने दिया था, तब आप कहां सोए थे? जब औद्योगिक पैकेज वापिस

17-2-2026/1430/एन0एस0-ए0एस0/2

लिया तो उसकी समयसीमा भी समाप्त नहीं हुई थी। तब ये कांग्रेस के मित्र कहां थे जो आज बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। जैसे ही वे देश के प्रधानमंत्री बने उसी समय हिमाचल प्रदेश को फिर से विशेष राज्य का दर्जा दिया गया जिसके कारण आज हिमाचल प्रदेश में विकास के कार्य चल रहे हैं। मैं अभी माननीय मुकेश जी को सुन रहा था और उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को नहीं बल्कि देश के जितने भी प्रदेश हैं उनको 41 प्रतिशत और केंद्र को 59 प्रतिशत शेयर मिलता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर प्रदेशों को 41 प्रतिशत शेयर दिया जा रहा है तो यह भी तभी मिला है जब नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो उस समय प्रदेशों को 32 प्रतिशत शेयर ही दिया जाता था और 68 प्रतिशत केंद्र के पास ही रहता था

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

17.02.2026/1435/RKS/DC-1

श्री विनोद कुमार जारी....

हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। यहां पर एक बात कही गई कि श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार के समय क्या किया गया? श्री हर्षवर्धन चौहान जी पूछ रहे थे कि श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार ने क्या किया? मैं कहना चाहता हूं कि श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार के कार्यकाल में जो काम हुए उन कामों की तो आप कल्पना करना ही छोड़ दीजिए। ऐसे काम आप कभी कर ही नहीं सकते हैं। आपने कहा कि हमारी सरकार ने क्या किया? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार के समय हमें जो पैसा मिला उससे हमने हिमकेयर जैसी योजना शुरू की। जो गरीब व्यक्ति होस्पिटल जाने से डरता था अगर उसका फ्री उपचार करने का काम किसी ने किया तो वह श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार ने किया है। श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार सहारा योजना लेकर आई। जिन व्यक्तियों का कोई सहारा नहीं था उनका सहारा श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार बनी। ...(व्यवधान) श्री संजय रत्न जी जो बातें आपकी ओर से आई हैं, मैं उन्हीं का उत्तर दे रहा हूं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आर0डी0जी0 पर भी आ रहा हूं। श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार जो 'मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना' लेकर आई उससे गरीब बेटियों की शादी के समय पैसा देकर उनकी आर्थिक मदद की गई। इसके अलावा और बहुत सी चीजें हैं जिन पर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। यहां पर कहा गया कि हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। स्वभाविक है कि जब से यह सरकार बनी है तब से हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। प्रदेश की जनता इस बात को जानना चाहती है कि जब हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट से गुजर रहा है तो इस सरकार ने प्रदेश को संकट से उबारने के लिए क्या कदम उठाए? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट से गुजर रहा था तो वर्तमान सरकार ने हिमाचल प्रदेश में मुख्य संसदीय सचिवों की एक लंबी फौज खड़ी कर दी जिस पर इन्होंने करोड़ों रुपये खर्च करने का काम किया। आपने इस दौर में

17.02.2026/1435/RKS/DC-2

ओ0एस0डी0 और सलाहकारों की भी एक लंबी फौज खड़ी कर दी। अगर उन सलाहकारों ने हिमाचल के हितों के लिए सलाह दी होती तो अच्छा होता लेकिन उन्होंने ऐसी कोई सलाह नहीं दी जिससे हिमाचल प्रदेश को आर्थिक संकट से उबारा जाए। यह इनकी सरकार की स्थिति है। आपने चेयरमैनों की भी काफी लम्बी फौज खड़ी कर दी है। आपने हर जिला से कई चेयरमैन बना दिए हैं और अब आपके कार्यकर्ताओं को वहां खड़ा होना मुश्किल हो गया है। हर जगह चेयरमैन दनदना रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि चेयरमैनों की इतनी लम्बी फौज खड़ी करने की क्या आवश्यकता थी? चेयरमैनों की लम्बी फौज खड़ी करने से सरकार को हर महीने काफी नुकसान हो रहा है जो विचारणीय है। आपने एडवोकेट जनरल की भी लम्बी फौज खड़ी कर दी है। आप कहते हैं कि अगर लम्बी फौज खड़ी कर दी है तो क्या हो गया? आपने बहुत सारे वकील एडवोकेट जनरल बना दिये। आपने प्रदेश से बाहर पंजाब राज्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के बेटे को भी यहां एडवोकेट जनरल बना दिया। यहां पर पिछले कल वाइल्ड फ्लावर हॉल का जिक्र किया गया। आपने कहा कि एडवोकेट जनरल की जो लम्बी फौज खड़ी की है, इन्होंने लम्बे समय से न्यायालय में चल रहे वाइल्ड फ्लावर हॉल के केस को जीत लिया है।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

17.02.2026/1440/बी.एस./डी.सी-1

श्री विनोद कुमार जारी...

वाइल्ड फ्लावर हॉल का जो कल मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया है उस केस को आपके एडवोकेट जनरल ने नहीं लड़ा है क्योंकि अभी पीछे हमारी समिति का मौखिक साक्ष्य था उसमें वित्त सचिव, आदरणीय देवेश जी आए थे और उन्होंने उस बैठक में भी इस बात का जिक्र किया था कि हमने इस केस को जीता है। मैंने उनसे जानकारी चाही कि आपने कैसे-

कैसे जीता जरा हमें भी बताइए? तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो वाइल्ड फ्लावर हॉल का केस था उसके लिए हमने अलग से वकील हायर किये थे जिसके कारण हमने इस केस को जीता है लेकिन पिछले कल भी इस हाउस को गुमराह करने की कोशिश की गई। मैं समझता हूं कि एक नहीं अनेकों बातों को ले करके यहां पर सरकार की ओर से प्रदेश की जनता को गुमराह किया जा रहा है और उसके साथ-साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि यहां पर बात आई कि हिमाचल प्रदेश को क्या मिला? मैं कहना चाहता हूं कि यह तो केंद्र का बजट था उसमें कोई हिमाचल का नाम अलग से तो नहीं आना था लेकिन मैं इतना जरुर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश को पिछली बार लगभग केंद्र सरकार से 21 हजार करोड़ रुपये पिछले बजट में केंद्र सरकार की ओर से मिले और इस बार भी जो बजट प्रस्तुत किया गया है उस बजट के मुताबिक 24,26,21,000 रुपये जो है वह हिमाचल प्रदेश को मिलने का अनुमान है और आप कह रहे थे कुछ नहीं मिला?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री विनोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं यहां पर केंद्र सरकार की ओर से अनेकों योजनाएं इस बार इस बजट में चलाई जा रही है और जिनमें केंद्र सरकार ने कहा कि 50 नए पर्यटन केंद्र चैलेंजिंग आधार पर विकसित करवाए जाएंगे इसकी घोषणा सरकार ने की और मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार की ओर से यहां से अच्छे प्रोजैक्ट बना करके भेजे जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमें बजट का बहुत बड़ा हिस्सा हिमाचल प्रदेश के विकास कार्य के लिए मिल सकता है। मैं इसके अलावा भी यह कहना चाहता हूं कि यहां पर मनरेगा को ले करके बात आई। यहां पर बड़ी-बड़ी बातें मनरेगा को लेकर भी की जा रही थी परंतु मैं कहना चाहता हूं कि अब विकसित भारत " जी राम जी" जो हमारी सरकार ने शुरू की है इसके तहत भी

17.02.2026/1440/बी.एस./डी.सी-2

95 हजार करोड़ रुपये का बजट केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत रखा है, यह भी मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष : आदरणीय विनोद जी, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री विनोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी 10 हजार करोड़ रुपये की योजना हमारी केंद्र की सरकार ले करके आई है और मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश में इस योजना के माध्यम से भी हम बहुत बड़ा लाभ उठा सकते हैं। ज्यादा लंबी चर्चा ना करते हुए मैं इतना कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को चाहे बजट की बात हो, चाहे रेवेन्यू डैफिसिट ग्रांड की बात हो, जो यहां पर जिक्र किया गया है कि हमारी सरकार ने हिमाचल प्रदेश के साथ पक्षपात किया है, भेदभाव किया है तो मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हिमाचल के हित की रक्षा की है और जितना भी सहयोग केंद्र से हिमाचल का हो सकता था वह निश्चित तौर पर केंद्र सरकार ने उस सहयोग को करने का पूरा प्रयास किया है। इतनी बात करने के लिए मैंने इस चर्चा में हिस्सा लिया था। आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ कहना है। मुख्य मंत्री जी और उप-मुख्य मंत्री जी हाउस में नहीं बैठे हैं।

अध्यक्ष : ठाकुर साहब, मुख्य मंत्री और उप-मुख्य मंत्री जी किसी जरूरी मीटिंग में हैं और वे मुझ से अनुमति ले करके गए हैं। उनकी नीचे जरूरी मीटिंग चली हुई है।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, ये फिर से हाउस में आएंगे या नहीं आएंगे इस बात का पता नही हैं।

अध्यक्ष : वे हाउस में बहुत जल्द आएंगे। ठाकुर साहब, आप स्वयं मुख्य मंत्री रहे हैं आपको पता है कि सरकार की एक्सिजेंसिज होती हैं। जरूरी बैठकें भी करनी पड़ती है, वे यहीं तो नहीं बैठे रहेंगे।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

17.02.2026/1445/डीटी/एच0के0-1

अध्यक्ष जारी...

ठाकुर साहब आप मुख्य मंत्री रहे हैं आप को तो पता है कि सरकार की एक्सीजेंसीज होती हैं कई बार मीटिंग्ज भी करनी पड़ती है। हाउस भी चलाना पडता है। कोरम पूरा है। ...(व्यवधान) आप बोल लेना, अभी भवानी सिंह जी को बोलने दो as and when he comes I will give you a chance to rebut. जब आएंगे तो आप उनके सामने बोल लेना। जब मुख्य मंत्री जी आएंगे तो मैं उनके सामने आपको बोलने का चांस दे दूंगा। ...(व्यवधान) उनके चैम्बर में कोई आवश्यक मीटिंग है। ...(व्यवधान) They are all in meeting they have conveyed to the Speaker's office. Please, Thakur Sahib. Shri Bhawani Singh Pathania please start your deliberations.

श्री भवानी सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, नियम-102 की चर्चा में मैं अपने आपको शामिल करता हूं। मैं आपका और नेता प्रतिपक्ष का धन्यवाद करता हूं क्योंकि मुझे आपने बोलने का मौका दिया।

आर0डी0जी0 क्यों शुरू हुई, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था या क्या औचित्य था, इसको समझना बहुत जरूरी है। एक लोकोक्ति है कि "अधजल गगरी छलकत जाए" मतलब जिस गागर में जितना कम पानी होता है वह ज्यादा छलकती है। इसमें आपने बड़े-बड़े तर्क सुने होंगे मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की ओर से। वर्ष 1948-49 में जब संविधान की संरचना हो रही थी उस समय लगभग पांच सौ से सवा पांच सौ जो प्रिंसली स्टेटस थीं इनको मिलाकर यूनियन ऑफ इंडिया बनी और इसमें चार पार्टस की स्टेट बनाई गई। जिसमें पार्ट ए, बी और सी थे। हिमाचल प्रदेश व बिलासपुर को पार्ट सी स्टेट में रखा गया। उस समय संविधान निर्माताओं को जो विचार था और मैं उनकी सोच को सलाम करता हूं-उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति समान नहीं है। कुछ राज्य बहुत बड़े बन गये जैसे बम्बई का राज्य था क्योंकि उस समय बम्बई एक राज्य का नाम था, असम था

17.02.2026/1445/डीटी/एच0के0-2

उसी तरह से राजस्थान था पंजाब था यानी कुछ राज्य बड़े थे और उन राज्यों के पास अपने संसाधन थे। कई राज्यों के पास कोयला था,कई राज्यों के पास अपने प्राकृतिक संसाधन थे और कई राज्यों के पास वाटर बेस थे। लेकिन कई राज्य ऐसे थे जिनके पास प्राकृतिक संसाधन के नाम पर कुछ भी नहीं था। उसके बाद सवाल यह उठा कि एक व्यक्ति जो भारत गणतंत्र के एक छोटे राज्य में रहता है क्या उसका अधिकार बड़े राज्य में रहने वाले व्यक्ति से कम है या ज्यादा है? तो समानता के नियम के ऊपर ये नियम बनाए गये कि फर्क नहीं पड़ता कि मैं हिमाचल में रहता हूं या बिहार में रहता हूं या उत्तराखंड में रहता हूं या देश के किसी अन्य स्थान में रहता हूं। लेकिन जो उस स्थान का नागरिक है उसके अधिकार समान है और वह समानता प्रोवाइड करने के लिए संविधान का सैक्शन 280 बनाया गया। इस सैक्शन में सिम्पल सी चीज यह थी कि जो आपके खर्चे हैं वह आपको खुद वहन करने पड़ेंगे। आप खर्चा किस पर कर रहे हैं आप खर्चा कर रहे हैं विकास पर, आप खर्चा कर रहे हैं सोशल वेलफेयर के ऊपर, आप खर्चा कर रहे हैं अपने प्रदेश के लोगों के ऊपर। लेकिन हो सकता है कि आपकी आय आपके पड़ोसी की आय के जितनी नहीं है। यह खर्चे जो आप जनहित में कर रहे हैं और उससे जो आपकी आय में गेप आ रहा है। यानी जो आपकी लिमिटेशन है उसके बीच का जो गेप है उस गेप को पूरा किया जायेगा। अब उसको आप आर0डी0जी0 बोलिए, स्पैशल ग्रांट बोलिए या ग्रांट-इन-एड बोलिए लेकिन कंसोलिडेटिड फंड ऑफ इण्डिया में प्रावधान किया गया था कि इसमें से पैसा दिया जायेगा। अब यह बात कहां से उठती है कि आर0डी0जी0 कहा पर लिखा है? आर0डी0जी0 की बात नहीं है बात है यह है कि कंसोलिडेटिड फंड ऑफ इण्डिया में से जो ग्रांट-इन-एड है that grant-in-aid has come to the states. यहां पर जो रेवन्यू जो है रेवन्यू एक्सपेंडिचर से कम है। बात बस इतनी सी है।

दूसरी बात यह कि उस समय यानी 1974 में प्रदेश को सौ करोड़ मिला फिर दो सौ करोड़ मिला या फिर तीन सौ करोड़ मिला, लेकिन समझने की बात यह है कि अर्थव्यवस्था का साइज जैसे-जैसे बढ़ता है आप का गेप भी उसी तरीके से बढ़ता है। वर्ष 1980 में हिमाचल

प्रदेश की जी0एस0डी0पी0 333 करोड़ थी और आज वो 2 लाख 33 हजार करोड़ है। यानी 333 करोड़ और 2 लाख 33 हजार करोड़ में स्पष्ट तौर पर आज हमारा खर्चा ज्यादा है और अगर मेरा खर्चा ज्यादा है तो मेरी इंकम उस

17.02.2026/1445/डीटी/एच0के0-3

हिसाब से नहीं बढ़ी और मेरी इंकम का गेप भी ज्यादा है। इसलिए आर0डी0जी0 की मात्रा जो बढ़ी वो इसीलिए बढ़ी और यही हमारा मेन प्वाइंट है जो आपने साबित कर दिया कि जब खर्चा ज्यादा है और आय कम है तो आर0डी0जी0 को बढ़ना चाहिए था। इसको पूर्णतः समाप्त नहीं करना चाहिए था। यही हमारा प्वाइंट है। This is the exact point that we are making. यह पैसा मेरी जेब से नहीं जा रहा है यह पैसा हर उस हिमाचली के जेब जा रहा है जिसका भविष्य आज हमनें अंधकार में डाल दिया है। जनहित के कार्य मैं आपको गिनवाता हूं। पार्ट-I मेरा यह था कि इसकी जरूरत क्या है? एक व्यक्ति है जिसके चार बेटे हैं। उन चार बेटों में से एक बेटा छः फुट का है, दूसरा बेटा 5 फुट 8 इंच का है, तीसरे बेटे को पोलियो हो गया है। लेकिन पिता की संपत्ति पर चारों बेटों का समान अधिकार है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता किस बेटे की शारिरिक क्षमता कैसी है। उसी को पूरा करने के लिए आर0डी0जी0 जैसी ग्रांट को बनाया गया। यह मेरा पार्ट-I था।

अब मैं पार्ट-II पर आता हूं। पोलियो वाली स्थिति है। आर0डी0जी0 शुरू किसने किया? आर0डी0जी0 देना स्टार्ट किया पंडित जवाहर लाल नेहरू ने आर0डी0जी0 को

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

17.02.2026/1450/एच.के.-एन.जी./1

श्री भवानी सिंह पठानिया.......... जारी

आर0डी0जी0 शुरू किसने किया? आर0डी0जी0 पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने शुरू की थी। उसके बाद इस आर0डी0जी0 को श्रीमती इन्दिरा गांधी जी, श्री राजीव गांधी जी, श्री पी0वी0 नरसिम्हा राव जी, श्री अटल बिहारी वाजपयी जी और श्री मनमोहन सिंह जी द्वारा जारी रखा गया। आज हमारे हिमाचल प्रदेश की पंचायतों व गांवों में एक मैसेज जा रहा है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू जी द्वारा जो आर0डी0जी0 शुरू की गई थी उसे विश्व गुरू श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा बंद कर दिया गया है।...(व्यवधान) नहीं बढ़ा है। मैं बताता हूं। I will prove it. आपने (विपक्ष के सदस्यों को देखते हुए कहा) पंचायतों को समाप्त कर दिया है।...(व्यवधान) मैं उस पर भी आ रहा हूं। मैं एक-एक करके सभी परतों को उधेड़ूंगा, आप सभी चिंता मत कीजिए क्योंकि मेरा काम ही यही है।

अध्यक्ष महोदय, हम मानते हैं कि आर0डी0जी0 को शुरू करके वर्ष 1952 में हिमाचल प्रदेश व अन्य छोटे राज्यों के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखा गया था। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के इतिहास में दिनांक 01 फरवरी, 2026 को एक काला दिन माना जाएगा क्योंकि आर0डी0जी0 के रूप में मिलने वाले लगभग 10 हज़ार करोड़ रुपये प्रति वर्ष और पांच साल के 50 हज़ार करोड़ रुपयों को आप लोगों ने (विपक्ष के माननीय सदस्यों के लिए कहा) सदैव के लिए बंद करवा दिया है। यह क्यों करवाया गया है, इसके बारे में केवल विपक्ष के माननीय विधायक ही जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2017 से लेकर वर्ष 2022 तक का लेखा-जोखा बताना चाहता हूं। इसके बारे में बहुत बार बोला जा चुका है कि इस अवधि में लगभग 54 हज़ार करोड़ रुपये आर0डी0जी0 और लगभग 16 हज़ार करोड़ रुपये जी0एस0टी0 कम्पंसेशन के रूप में आया। इस प्रकार से कुल मिलाकर लगभग 70 हज़ार करोड़ रुपये हिमाचल प्रदेश को मिले हैं।

17.02.2026/1450/एच.के.-एन.जी./2

माननीय सदस्य, श्री राकेश जम्वाल जी जनहित के काम के बारे में बोल रहे थे तो मैं इसके बारे में भी बताना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में लगभग 20 हज़ार गांव, 3600 ग्राम पंचायतें और 68 डवलपमैंट ब्लॉक्स हैं। यदि पूर्व सरकार ने विकास पर पैसा खर्च किया होता तो एक सिविल अस्पताल के भवन का निर्माण लगभग 25 करोड़ रुपये में हो जाता है और 70 हज़ार करोड़ रुपयों से 2800 सिविल अस्पताल बनाए जा सकते थे जिससे हर विधान सभा क्षेत्र में 41-41 सिविल अस्पताल होते। आज वे कहां पर हैं? इसी प्रकार एक सिटी स्कैन की मशीन लगभग 2 करोड़ रुपये की आती है और 70 हज़ार करोड़ रुपयों से 35000 मशीनें आ सकती हैं जिससे हर गांव में 2-2 मशीनें लगाई जा सकती थीं। आज वे मशीनें कहां पर हैं? इसी प्रकार एक जोनल अस्पताल लगभग 200 करोड़ रुपये का बन जाता है और 70 हज़ार करोड़ रुपयों से हर डवलपमैंट ब्लॉक में 2-2 जोनल अस्पताल बनाए जा सकते थे, यदि इन 70 हज़ार करोड़ रुपयों का सदुप्योग हुआ होता। वर्ष 2017 में प्रदेश पर लगभग 48 हज़ार करोड़ रुपये का लोन था और पूर्व सरकार इस लोन को बढ़ाने के बजाये इसे शून्य कर सकती थी, यदि इन 70 हज़ार करोड़ रुपयों का सदुप्योग किया होता। विपक्ष के माननीय विधायक कह रहे थे कि हमारी सरकार ने 2000 करोड़ रुपयों की सड़कों का निर्माण करवाया था तो मैं बताना चाहता हूं कि वे सड़कें आर0डी0जी0 के पैसे से नहीं बल्कि केन्द्र सरकार की फंडिंग से बनी थीं। मैं बताना चाहता हूं कि सड़क बनाने में यदि 2 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर का खर्च आता है तो 70 हज़ार करोड़ रुपये से 35000 किलोमीटर सड़क बन सकती थी। यह इतनी लम्बी होती कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक दो बार चक्कर लगा सकते हैं। आज वे सड़कें कहां पर हैं? मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष के माननीय विधायकों के पास 70 हज़ार करोड़ रुपयों का सदुप्योग और कोई जनहित का काम दिखाने के लिए नहीं है। आप (विपक्ष के माननीय विधायाकों के लिए कहा) एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बता दीजिए। पूर्व सरकार के समय में टाण्डा, चमियाना व अन्य मेडिकल कॉलिजिस की दयनीय स्थिति हम सब के सामने है।

17.02.2026/1450/एच.के.-एन.जी./3

यदि इन पैसों का सदुप्योग हुआ होता तो यह पैसा इन संस्थानों में खर्च क्यों नहीं हुआ? वह पैसा कहां पर गया? आज यदि उन 70 हज़ार करोड़ रुपये का हिसाब मांगें तो विपक्ष के माननीय विधायकों के पास कोई हिसाब नहीं है। There is nothing on the ground to show about the development of 70,000/- crores.

आज ये (विपक्ष के माननीय विधायक) लोग हमारी सरकार में मिले केवल 17 हज़ार करोड़ रुपये की आर0डी0जी0 से तुलना कर रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि हमारी सरकार को जो 17 हज़ार करोड़ रुपये मिले, उसका हमने क्या किया? मैं उसके बारे में भी बताना चाहता हूं। पिछले तीन साल में हमारी सरकार को लगभग 17 हज़ार करोड़ रुपये आर0डी0जी0 के रूप में मिले हैं। मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि हमें मालूम है कि आगे का समय कठिन होने वाला है और हमें इस प्रकार के निर्णय लेने पड़ेंगे जोकि सभी को चुभेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जनता की नज़र एक जनप्रतिनिधि पर सदैव बनी रहती है। हम जो भी करें उस पर हमेशा हो-हल्ला होता है। मुख्य मंत्री जी ने सबसे पहले एक काम किया कि हिमाचल भवन व हिमाचल सदन में हम माननीय विधायकों को जो कमरा 100/- रुपये का मिलता था वह अब 1200/- रुपये का मिलता है। इसी प्रकार रैस्ट हाऊसिस, खाने व अन्य सभी चीजों के संदर्भ में मितव्ययता का कदम उठाया गया है। इसके अलावा हमारे प्रदेश के वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग व अन्य विभागों के रैस्ट हाऊसिस की बुकिंग्स को ऑनलाइन कर दिया गया है। इससे आम जनता को रैस्ट हाऊस बुक करने की सुविधा मिली है और इसे मोनिटाइज़ किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद तीसरा काम यह किया गया है कि आज भी एक कबिना मंत्री, एक मुख्य सचेतक और एक डिप्टी स्पीकर का पद रिक्त पड़ा हुआ है।...(व्यवधान) यह लड़ाई नहीं है। पूर्व सरकार के समय में 55 चेयरमैन बनाए गए थे। माननीय सदस्य, श्री सतपाल सिंह सत्ती जी पूर्व सरकार के समय में कैबिनेट रैंक के साथ वित्तायोग के चेयरमैन थे। ...(व्यवधान) 55 चेयरमैन थे।...(व्यवधान) नहीं-नहीं, सर

श्री ए0पी0 द्वारा......जारी

17.02.2026/1455/वाई.के./ए.पी/01

श्री भवानी सिंह पठानिया जारी .....

रेमेडी करते हैं सर, इसका रेमेडी भी करते हैं। बात यह नहीं है कि हमारे पास था तो किया। हमारा प्वाईंट सिर्फ इतना है कि तू इधर-उधर की बात मत कर, बस यह बता कि आर0डी0जी0 क्यों लूटा। क्या आप आर0डी0जी0 बंद होने के समर्थन में हैं या विरोध में हैं? यह एक सीधा सवाल है। इतना ज्ञान बांटने की जरूरत ही नहीं है। क्या आप खुश हैं कि आर0डी0जी0 हिमाचल प्रदेश के लिए बंद हुआ? क्या आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? आप बोल नहीं सकते, क्योंकि जिसने बोला उसकी टिकट काट दी जाएगी या खुड्डे लाईन लगा दिया जाएगा। यह केंद्र सरकार का निर्णय है। हम आपकी विडंबना समझते हैं। जिसने आर0डी0जी0 के खिलाफ बोला कि केंद्र सरकार ने ये गलत किया, उसकी टिकट काट दी जाएगी। क्योंकि पिछली बार 40 में से 17 की टिकट काटी गई थीं, इस बार तो आप 28 हो, अगर 28 में से 17 की टिकट काट दी गई, तो बचेगा कौन? मैं जानता हूं कि आप आर0डी0जी0 बंद होने के विरोध में नहीं बोल सकते। लेकिन कम-से-कम समर्थन तो कर दीजिए। कम-से-कम हमारे साथ दिल्ली तो चल पढ़ो, अंदर मत जाना, बाहर तक तो आप हमारे साथ आ जाइए। केन्द्र सरकार द्वारा जो प्रदेश सरकार की आर0डी0जी बंद की गई है यह एक ऐतिहासिक अन्याय है और इस अन्याय के पीछे हिमाचल प्रदेश के प्रति दुर्भावना है और वह दुर्भावना क्या है? कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की कोशिश कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की कोशिश की। जब वह नहीं हुआ तो कहा कांग्रेस मुक्त उत्तर भारत और उत्तर भारत में एक आंख का कांटा हिमाचल प्रदेश था। उस आंख के कांटे को हटाने के लिए ऑपरेशन लोटस किया गया। लेकिन ऑपरेशन लोटस ओन्धें मुह गिर गया। फूल मर्झा गया और कीचड़ में समा गया। जब ऑपरेशन लोटस भी नहीं पूरा हुआ तो दुर्भावना किस तरह सामने आई, एक-एक प्वाईंट में आपको बताता हूं। I will just take five minutes on this one. इसके बाद बदले की भावना जो हिमाचल प्रदेश के साथ शुरू हुई, वह आज दिन तक चली आ रही है और आर0डी0जी0 उसी का जीता जागता एक परिणाम है। पहली चीज़ मनरेगा में व्यापक

बदलाव किए गए। मैं आपको मनरेगा के बारे में एक छोटी बात बताता हूं। सर, हिमाचल प्रदेश का 91 प्रतिशत ग्रामीण है और हम मनरेगा

17.02.2026/1455/वाई.के./ए.पी/02

पर निर्भर हैं। पहले हमें केंद्र सरकार से मनरेगाा के लिए 1200 करोड़ रुपये सालाना मिलता था। यह "राइट टू वर्क" मनमोहन सिंह जी की सरकार द्वारा दिया गया था वह ऑन डिमाण्ड दिया गया था। हमें 6,000 करोड़ रुपये फ्री ऑफ कॉस्ट आता था। अब हम 90:10 स्टेट बना दिया गया है। जिससे विपक्ष बोल रहा है कि बहुत अच्छी बात हुई। अच्छी बात तो यह हुई कि अब हमें मनरेगा का 6000 करोड़ रुपये पाने के लिए हमें अपनी जेब से 600 करोड़ रुपये डालने पड़ेंगे। यह पैसा हम कहां से लाएंगे? यह क्या अच्छा किया आपने हमारे लिए? आपने पंचायतों को मार दिया। अब जो प्रधान बनेगे मई के महीने में इससे हमारी पंचायत व्यवस्था कमजोर हो गई और गरीब का गला घोट दिया गया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का गला घोट दिया गया। इस तरह आपने 600 करोड़ रुपये की चोट आपने हिमाचल प्रदेश को यह पहुंचाई।

दूसरी बात, हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की ताकि हमारे कर्मचारी डिग्नीफाइड तरीके से अपना बुढ़ापा जी सकें। लेकिन केंद्र सरकार ने हमारी बोरोइंग लिमिट का 1800 करोड़ रुपये प्रति वर्ष काट दिया। यह भी आपने दुर्भावना से हमारे साथ काम किया।

तीसरी बात, जो सबसे बड़ी है, एक ऐतिहासिक ट्रेड डील की गई। जिसमें भारत को कुछ नहीं मिलेगा। अमेरिका, न्यूजीलैंड और यूरोप को फायदा होगा और उनका सेब हिमाचल प्रदेश के सेब को फ्लड कर देंगा। आपने न केवल टैरिफ हटाया बल्कि आपने नॉन टैरिफ बैरियर भी हटा दिये। 22 विधान सभा क्षेत्र के हमारे किसान भाई जो एप्ल बैल्ट के है, उनके भविष्य को आपने सड़क पर लगा दिया। हमारे हिमाचल प्रदेश की लगभग 5,000 करोड़ रुपये की सेब की अर्थव्यवस्था थी, आपने उसको मिट्टी में मिला दिया। अगर वाशिंगटन एप्पल 70 रुपये में हमारी मंडी में बिकेगा तो हमारे बागवान जो कोटगढ़, कुल्लू, मण्डी के है उनका सेब कौन खरीदेगा? और आप केन्द्र सरकार के इस फैसले का

भी समर्थन कर रहे हैं। एक विपक्ष के विधायक जो उस बैल्ट से है वे केन्द्र सरकार के इस फैसले का समर्थन कर रहे है कि यह तो भारत के लिए बहुत अच्छा हुआ।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

17/02/2026/1500/AT/YK /01

श्री भवानी सिंह पठानिया जारी......

(***)है। यह जो ट्रेड डील है इसमें फर्क किसको पड़ना है? फर्क पड़ेगा हिमाचल प्रदेश की एप्पल बेल्ट को, हमारी जैसी बेल्टों को जहां पर हमारा सोना उग रहा है और जो बाकी हमारी क्रॉप्स उग रही हैं। कल को जेनेटिक मॉडिफाइड सीड आ जाएंगे तब हम बुरी तरीके से (***)यह दुर्भावना का तीसरा प्वाईंट है। चौथा प्वाईंट आर0डी0जी0 बंद कर दी। आर0डी0जी0 बंद क्यों की? ...(Interruption) You have financially strangulate Himachal Pradesh. आप वैसे तो हमको हरा नहीं सकते। सर, आप देखिए यह हिमाचल प्रदेश की वह कॉम है कि देश में जितने शहीद हुए हैं,अगर हम अपनी जनसंख्या के अनुपात देखें तो सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश के हैं। तो यह समझ गए कि वैसे तो उनको मार नहीं सकते तो उनका गला फाइनेंशली घोंटो दो। तो इन्होंने क्या किया? आर0डी0जी0 बंद कर दी, 50,000 करोड़ रुपया अगले 5 साल का खत्म कर दिया।

पांचवीं और सबसे बड़ी बात इस देश का सबसे बड़ा व्यक्ति, माननीय राष्ट्रपति के बाद, हमारे परम आदरणीय, विश्व गुरु, यशस्वी नरेंद्र मोदी जी हैं। सर, हमारे यहां फ्लड आया, बहुत बड़ी त्रासदी आई, डिजास्टर आया। वह यहां आए, लेकिन प्रधान मंत्री जी कहीं नहीं गए। ऊपर से हवाई सर्वेक्षण किया एक हवाई अड्डे में बैठे और जाते-जाते बोल गए तुमको 1500 करोड़ दे रहा हूं। उस बात को सात महीने हो गए हैं, उस 1500 करोड़ का एक रुपया भी आज तक आप हमारे पास नहीं पहुंचा पाये। आप बताइए यह दुर्भावना नहीं है तो क्या है? खुद बोला हुआ पैसा अब दे नहीं रहे। 1800 करोड़ रुपये की आपने हमारी बोरिंग लिमिट बंद कर दी, हमारा आर.डी.जी. बंद कर दिया, मनरेगा के अंदर 600 करोड़

की लायबिलिटी हमारे ऊपर डाल दी और उसके ऊपर से आपने ऑपरेशन लोटस करने की कोशिश की, तो उसमें आप औंधे मुंह गिरे। सर, बेसिकली क्या है ...(व्यवधान) इस बार आपका पैसा नहीं चलेगा। पिछले साल 14 फरवरी को पहलगाम के अंदर एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, टेररिस्ट अटैक हुआ था उससे पहले ताज होटल में भी टेररिस्ट अटैक हुआ था, पुलवामा में हुआ, उसके बाद अक्षरधाम मंदिर के ऊपर टेररिस्ट अटैक हुए। मतलब टेररिस्ट की मंशा क्या होती है? टेररिस्ट की मंशा लोगों को डराना होती है। लेकिन यह वह भारत है जो सालों-साल आक्रांताओं से लड़ता आया है। जब भी

17/02/2026/1500/AT/YK /02

ऐसी कोई घटना होती है तो लोग कंसोलिडेट होकर और जो पावर में होता है उसका साथ देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा कर रहे हो। Sir, what is happening to Himachal Pradesh at this point of time - this is nothing but a financial terrorism. हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं। पांच चीजें मैं आपको गिना चुका हूं। इसमें टोटल चोट हमको लगभग 15,000 करोड़ रुपये पर एनम की है। आप मनरेगा गिन लीजिए, 1800 करोड़ रुपये का डेफिसिट गिन लीजिए, इसके बाद आर0डी0जी0 की ग्रांट गिन लीजिए, ट्रेड डील के ऊपर हमारा कितना नुकसान होगा वह मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, लेकिन 15,000 करोड़ रुपये के आसपास का आपने हमको इस टाइम पर (***)लगा दिया है। तो यह राजनीतिक द्वेष और राजनीतिक दुर्भावना नहीं है तो और क्या है?

सर, आखिरी चीज जो मैं बोलना चाहूंगा वह यह है कि जब हम यहां बोल रहे हैं जब यह संकट हमारे आगे आया हुआ है, इसमें न कोई कांग्रेस का है न कोई भारतीय जनता पार्टी का। आपकी जो विडंबना है, हम समझ सकते हैं। हमें भी पता है कि अब भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी नहीं रही जो एक जमाने में थी। अब इसका टोटल ध्रुवीकरण हो चुका है और सत्ता की पावर बिल्कुल कंसंट्रेट हो गई है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आज आप खामोश रहे तो आप हिमाचल प्रदेश की जनता के हितों को कंप्रोमाइज कर रहे हैं। आप उनका दिवालिया पिटवा रहे हैं। आपकी यह खामोशी हिमाचल की जनता माफ नहीं करेगी। आपसे रिक्वेस्ट इतनी है और हम जानते हैं आप ओपन नहीं बोल सकते।

हम जानते हैं भय का माहौल इधर नहीं उधर है। शायद इसी भय के माहौल में आप खुलकर हमारा समर्थन नहीं कर सकते। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोल चुके हैं, उप मुख्यमंत्री जी भी बोल चुके हैं कि आइए हम सब चलकर एक बार प्रधान मंत्री जी से मिलते हैं। अभी भी आर0डी0जी0 की फाइल क्लोज नहीं हुई है। आर0डी0जी0 का फायदा न मुझे होना है, न आपको होना है। आर0डी0जी0 का फायदा उस पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति को होना है, जो हिमाचल प्रदेश के किसी गांव में बैठा है।

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

17/02/2026/1500/AT/YK /03

सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य प्रकाश राणा जी।

एम0डी0द्वारा जारी ......

17-02-2026/1505/AG/MD/1

श्री प्रकाश राणा : अध्यक्ष महोदय, नियम-102 के अंतर्गत रेवेन्यू डैफिशिएंट ग्रांट पर जो चर्चा माननीय सदन में चल रही है, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस वक्त जो समस्या इस प्रदेश में खड़ी है वह सबसे बड़ी समस्या है। इसके लिए जो तीन-चार दिन का सत्र बुलाया गया उसे तो बजट सत्र कहा गया लेकिन मुझे लगता है कि यह चर्चा तीन दिन के लिए विशेष रूप से इसी विषय के लिए बुलाई गई। मैं नहीं समझता कि इसके लिए इतनी आवश्यकता थी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे माननीय सदस्य कह रहे हैं कि यह संविधान में लिखा गया

है, आर्टिकल में है। अगर है तो उसमें चर्चा की क्या जरूरत है? चर्चा की जरूरत नहीं है। अगर है और आपका हक नहीं मिलता है तो आप कोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट बैठा है, हाई कोर्ट बैठा है। यानी इसका मतलब यह है कि समय व्यर्थ करना है। अपनी नाकामी और अपनी असफलता का कारण दूसरे पर थोपना मैं नहीं समझता कि यह ठीक है। इसकी जरूरत ही नहीं है इसकी आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन आपको यह दिखाना है कि ये लोग हमारे साथ तैयार ही नहीं हैं। रेवेन्यू डैफिशिएंट ग्रांट का मतलब क्या है? सही है, यह तो यहां समझाकर चले गए। रेवेन्यू डैफिशिएंट ग्रांट इसलिए दी जाती है कि जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है जो देने हैं जैसे सैलरी और पेंशन, जो सरकार के अपने पर्सनल पर खर्च होते हैं उसमें विकास का हिस्सा आता ही नहीं है। उतना रेवेन्यू तो आपके पास है। आप यह कहें कि हम रेवेन्यू डैफिशिएंट ग्रांट लेकर केंद्र से कर्ज लेते जाएं और उसे भरते जाएं, तो यह नहीं चलने वाला है। अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। सीधी बात है यह आपकी फाइनेंस की रिपोर्ट है कोई मेरी तो नहीं है। आप कह रहे हैं कि हमारा रेवेन्यू 18,000 करोड़ रुपये है और केंद्र से जो आपको मिल रहा है, वह भी 13,900 करोड़ रुपये है तो इसका मतलब है कि 31 से 32 करोड़ रुपये तो हो ही रहा है। अगर आपकी सैलरी और पेंशन पर पैसा जा रहा है, तो जो ग्रांट होती है वह इनकम सोर्सिज बढ़ाकर देनी है। इसमें केवल ग्रांट का प्रश्न नहीं है, इसमें इनकम का प्रश्न है। आप इसे दोबारा स्टडी करें।---(व्यवधान) मान लो पुराना होता है, तो आप लोगों ने क्या किया? तीन वर्ष का अपना तो बताओ। मैं तो 2-3 वर्षों से कह रहा था कि भाई, आप देखो इस प्रदेश के साथ आप क्या कर रहे हैं। जो लोन लिया है, उसके बारे में मुख्य मंत्री को यहां जवाब देना पड़ेगा। जनता सब जानती है। जनता चाहती है कि जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि

17-02-2026/1505/AG/MD/2

सरकार आप चला रहे हैं। आप इसको समझो। यह सच नहीं है कि वर्तमान मुख्य मंत्री ही हिमाचल प्रदेश के ऐसे मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कर्ज लिया है। इसमें कोई जवाब दे सकता है? भाई, अगर उसने लिया तो वही तो बात है। आपके फाइनेंस के ऑफिसर यहां पर बैठे हैं, दो मिनट नहीं लगते प्रिंट निकालने में।

Speaker: Rana ji, you address the Chair. आप इस तरफ से बोलिए। Don't pay attention to them?

श्री प्रकाश राणा : मैं यह बोल रहा हूं कि सत्र बुलाने की क्या जरूरत पड़ी? मैं और क्या बोल रहा हूं? जो फालतू बातें कर गए, उनसे आपने पूछा नहीं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई? इसका मतलब है कि आप सरकार चलाने में असफल हैं। आपके पास विकल्प है, आप छोड़ दो। आपके पास इतना रेवेन्यू है तो फिर आप क्या कर रहे हैं भाई? यह सच नहीं है कि आप कहते हैं कि वह कर्ज ले गया, वे ले गया। कभी बोलते हैं कि श्री जय राम ठाकुर जी ने 72 हजार करोड़ कर्ज ले लिया। कर्ज की हिस्ट्री आप देखना नहीं चाहते हैं। देखते तो हैं लेकिन आप सबको बेवकूफ बना रहे हैं पूरी हिमाचल की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। सबसे ज्यादा कर्ज किसने लिया? अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1993-94 से कर्ज की शुरुआत हुई और उस वक्त सरकार किसकी थी कांग्रेस की थी।

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी---

17.02.2026/1510/केएस/एजी/1

श्री प्रकाश राणा जारी ---

उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। मैं तो शांता कुमार जी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कम से कम इसको ज़ीरो किया था। हम लगभग 32-33 सालों से कर्ज ले रहे हैं। जिसमें 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और 16-17 साल कांग्रेस की सरकार रही। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में 30 से 40 हजार करोड़ रुपये के लगभग कर्ज लिया और कांग्रेस पार्टी ने 60-70 हजार करोड़ रुपये के लगभग कर्ज लिया। ...(व्यवधान) आप उसके प्रिंट निकालो। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ...(व्यवधान) आप फिर आर0डी0जी0 के ऊपर आ गए। आप पहले कर्ज की बात कीजिए। ...(व्यवधान) अध्यक्ष जी, यह गलत है। इनका काम बीच में बोलना ही है। मैं पूछना चाहता हूं कि आर0डी0जी0 की ज़रूरत क्यों पड़ी? आपने कर्ज ले लिया। ...(व्यवधान) फिर वह पैसा गया कहां और क्यों लिया? 1 लाख करोड़ ...

Speaker: Order in the House, please. अवस्थी जी, कृपया बैठे-बैठे ना बोलें। Don't interrupt him?

श्री प्रकाश राणा : अध्यक्ष महोदय, इनको बीच में बोलने की ज़रूरत ही नहीं है।

अध्यक्ष : राणा जी, मैं इनको टोक रहा हूं। आप चेयर की तरफ देखकर बालें। ...(Interruption) I am looking after that. ...(Interruption) Please, be calm.

श्री प्रकाश राणा : ठीक है, सर। ये मुझे डिस्टर्ब ना करें। इन्होंने अपने कार्यकाल में 16 से 17 सालों में 60-70 हजार करोड़ रुपये का कर्ज ले लिया। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में 30-40 हजार करोड़ के लगभग कर्ज लिया। आप डबल कर्ज ले गए। क्या आर0डी0जी0 मिलने से आपका गुज़ारा हो जाएगा? ...(व्यवधान) क्यों आप यहां पर फालतू में बहस कर रहे हैं? अगर आर0डी0जी0 मिलने से आपका काम चलता है तो हमें बता दो। क्या आप कर्ज नहीं लेंगे? इस तरह से हिमाचल प्रदेश की जनता को या हमें गुमराह मत कीजिए और ना ही हमारा समय बर्बाद करो। तीन दिन तक सत्र चलेगा लेकिन इससे कुछ भी नहीं होगा। बस आपने लोगों को दिखाना है और अपनी नाकामी का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ना है। यह आपकी सोच है जो गलत है। आप अपनी सोच को बदलो और हिमाचल को कैसे ऊपर उठाना है, इस बारे में सोचो। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऑप्शन्ज़ नहीं हैं। आप झूठ के ऊपर झूठ बोलते हैं। कभी मुख्य

17.02.2026/1510/केएस/एजी/2

मंत्री जी कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश वर्ष 2027 में आत्मनिर्भर बनेगा और 2032 में सबसे अमीर राज्य बनेगा। दूसरे दिन मुख्य मंत्री जी मीडिया को स्टेटमैंट देते हैं कि हिमाचल प्रदेश रेवन्यू प्लस स्टेट बन ही नहीं सकता। आप झूठ के ऊपर झूठ बोलते हैं।

अध्यक्ष : धन्यवाद राणा जी।

श्री प्रकाश राणा : धन्यवाद क्या अध्यक्ष जी, अभी तो मुझे बोलते हुए आठ ही मिनट हुए हैं।

अध्यक्ष : लेकिन आपका सारा व्यू प्वाइंट तो आ गया है।

श्री प्रकाश राणा : नहीं, सर। अभी कहां, अभी तो मुझे बोलते हुए आठ ही मिनट हुए हैं। हमें भी आधे घंटे का समय दीजिए। ये कभी बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, कभी बोलते हैं कि हम वो कर देंगे। अब आप कह रहे हैं कि चांस ही नहीं है कि हिमाचल रेवन्यू प्लस स्टेट हो जाए। मैं यह पूछना चाहता हूं कि अब सैलरी के लिए हमारे पास पैसा ही कितना बच रहा है? अगर 31 या 32 हजार करोड़ रुपये हमारे पास आ रहे हैं तो 13 हजार करोड़ रुपये की तो हमने उसमें से बैंक की रीपेमेंट्स करनी हैं। हमारे पास बड़ी मुश्किल से साढ़े 18 हजार 900 करोड़ रुपये बच रहे हैं। अब उसको अगर हम मंथली देखते हैं तो बड़ी मुश्किल से 1570 करोड़ है। 1570 करोड़ से आप सैलरी देंगे, पैंशन देंगे या इस प्रदेश को चलाएंगे? अगर कल को कर्ज भी बंद हो जाता है, आप ओवर लिमिट जा रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप लोगों को झूठे सपने क्यों दिखा रहे हो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे? फाइनेंस वाले कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। वे कहते हैं कि हमारे पास कर्ज भरने को पैसा ही नहीं है। आप बोलते हैं कि 10 हजार का कर्ज हम हर महीना लेंगे तो आप पांच साल में फिर 50 हजार ले लेंगे। अभी हमारे को 13 हजार करोड़ सिर्फ बैंक का भरने को है। आगे पांच सालों में हम 20 हजार करोड़ रुपये कहां से लाएंगे उतना तो हमारा रेवन्यू ही नहीं है। क्या कर रहे हैं आप इस प्रदेश का? आप कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश सर प्लस स्टेट हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता? यह वही प्रदेश है जिसमें आज 14 हजार मैगावाट की बिजली उत्पन्न हो रही है और यह मुख्य मंत्री जी खुद कहते हैं। अध्यक्ष जी, 100 मैगावाट का प्रोजैक्ट जो चलता है,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

17.02.2026/1515/av/As/1

श्री प्रकाश राणा-------- जारी

अध्यक्ष महोदय, 100 मैगावाट के प्रोजैक्ट का एक दिन का राजस्व 75 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये का होता है। फिर 14 हजार करोड़ रुपये के प्रोजैक्ट हिमाचल से बाहर क्यों चले गए, आप कहां सोये थे? अगर हम एक वर्ष का हिसाब लगाएं तो 14,000 मेगावाट बिजली का 50,000 करोड़ रुपये राजस्व आना चाहिए। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि

आप लोग कहां थे? आप बोलते हैं कि इससे राजस्व आ ही नहीं सकता। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि कैसे नहीं आ सकता, आप मुझे बताइए? हमारे पास इतने जंगल और दूसरी चीजें हैं; लेकिन उनके बारे में कौन सोचेगा? आपको कर्ज लेने का शौक है, तो लीजिए। इस प्रदेश का बेड़ा गर्क कैसे हुआ, आप उसको देखिए। परंतु आप लोग इस बारे में अभी भी नहीं सोच रहे हैं। आप लोग कहते हैं कि हम आपके साथ आर0डी0जी0 के लिए केंद्र सरकार के पास चलें। लेकिन हम आपके साथ क्यों चलें, आप हमें बताइए? कर्ज लेकर घी आप पी रहे हैं और हम आपके साथ चलें, क्यों चलें? फिर आप हमें डरा रहे हैं कि आपका नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों लिखा जाएगा, क्या हमने कोई गुनाह किया है? ...(व्यवधान) यहां पर मुख्य मंत्री बोल कर गए हैं कि अगर आप लोग साथ नहीं चलेंगे तो आपका नाम हिमाचल की हिस्ट्री में लिखा जाएगा। आपने जो इस प्रदेश को लूट कर खत्म किया, तो क्या आपका नाम हिस्ट्री में नहीं आएगा?

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आर0डी0जी0 की प्रोब्लम नहीं है। यहां पर सबसे बड़ी प्रोब्लम यह है कि इस प्रदेश के ऊपर 13,000 करोड़ रुपये का कर्ज ओवर हो गया है, आप इसको कहां से भरेंगे? आप एक वर्ष में यह कर्ज कहां से लौटाएंगे जबकि हमारे पास उतना राजस्व नहीं है। हमारे पास तो 15,000 करोड़ रुपये बड़ी मुश्किल से बच रहे हैं। इसलिए मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप इस कर्ज को कहां से भरेंगे? यहां पर सबसे पहले इस बात की चर्चा होनी चाहिए थी कि हम इन्कम के संसाधन कैसे जनरेट करें। क्या आपने अपने खर्चे कम किए हैं, आप मुझे इस बारे में बताइए? आप खर्चे तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मुख्य मंत्री जी जहां जाते हैं घोषणाएं करके आ रहे हैं। प्रदेश का वित्त विभाग बोल रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है। उसके बावजूद मुख्य मंत्री जी अपने कार्यक्रमों के दौरान 30 करोड़ रुपये, 50 करोड़ रुपये और एक लाख करोड़ रुपये की घोषणाएं कर रहे हैं। परंतु मैं यह पूछना चाहता हूं कि

17.02.2026/1515/av/As/2

यह पैसा कहां से आएगा? आप प्रदेश की जनता को क्यों ठग रहे हैं? अगर आपके पास पैसा नहीं है तो प्रदेश की जनता को इस प्रकार से मत ठगिए। मैं सचिव(वित्त), हिमाचल

प्रदेश सरकार की प्रशंसा करता हूं क्योंकि इन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। इन्होंने बिल्कुल सही बोला और जनता के सामने सही बात आई है। परंतु बावजूद उसके आप उसी बात को फिर से घुमा-फिरा कर बोल रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर सत्र बुलाया है तो यहां पर इस बारे में विचार-विमर्श किया जाना चाहिए कि हम अपनी स्टेट का राजस्व कैसे बढ़ाएं। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसके लिए कोई कमेटी बनाइए। मैं तो आपको इस बारे में दो वर्षों से बोल रहा था। मैंने आपदा के दौरान हो रही चर्चा में भी कहा था। आप कहते थे कि आपदा के कारण हम खत्म हो गए। लेकिन मैंने उस समय भी कहा था कि सबसे बड़ी आपदा तो आगे आने वाली है परंतु उस समय तो आप लोग हंस रहे थे। अब क्या हो गया? अब आप कम-से-कम इस बात को मान तो जाइए कि हम इस स्टेट को चलाने के काबिल नहीं है, यह सीधी बात है।

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल की जनता मुख्य मंत्री से सुनना चाहती है क्योंकि इनके पास निर्णय लेने की पावर और अधिकार है। आप जब गलत करते हैं तब तो आप हमें अपने से मिलाते हैं। ...(व्यवधान) मुख्य मंत्री जी नहीं हैं परंतु आप (कृषि मंत्री) तो यहां पर बैठे हैं। वर्तमान सरकार ने तो विधायकों को भी जीरो कर दिया है, आपने उनकी निधि भी छीन ली है। मुख्य मंत्री जहां भी जाते हैं घोषणाएं करके आ जाते हैं। मुख्य मंत्री जी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी गए थे और वहां पर 7-8 महिला मण्डलों को 20-20 हजार रुपये बांट दिए। इससे अच्छा अगर आप हमें विधायक निधि देते तो ठीक रहता। हम विधायक क्यों बने हैं? क्या हमें इस तरह से रिजाईन नहीं कर देना चाहिए, आपने क्या यहां पर विधायक केवल सैलरी लेने के लिए रखे हैं? क्या आप यह चाहते हैं कि हम सारे रिजाईन कर दें? आपने विधायकों को जीरो बनाकर इस प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया है। विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में क्या करने जाएगा? हमारे पास तो एक लाख रुपये देने को नहीं होता। हम अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं तो वहां की जनता को आस होती है कि मेरा रास्ता बना दो या कुहल, डंगा इत्यादि लगा दो। वहां पर युवक मण्डल और महिला मण्डल हैं, परंतु आपने तो हमें जीरो कर दिया है। आप लोग (सत्ता पक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा।) भी विधायक हैं। आपने निधि क्यों खत्म की

17.02.2026/1515/av/As/3

और जब आपको जरूरत है तो बोलते हैं कि हमारे साथ आ जाओ। मैं तो अपने साथियों को यह पूछता हूं कि हम यहां पर क्या करने आ रहे हैं। यह वर्तमान सरकार की नाकामी है क्योंकि ये सरकार को नहीं चला पा रहे हैं। इन्होंने हिमाचल प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया है और अब हमें ढूंढ रहे हैं कि आप लोग हमारे साथ दिल्ली चलिए। हम आपके साथ नहीं जाएंगे। अगर आपने अपने खर्चे कम किए होते तो हम अवश्य जाते। ...(व्यवधान) चाचा, आप (कृषि मंत्री) भी बोलिए। पहले

टी सी द्वारा जारी

17.02.2026/1520/टी0सी0वी0/ए0एस0-1
श्री प्रकाश राणा...... जारी

माननीय कृषि मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं इनकी बात भी सुन लेते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : कंक्लूड प्लीज, आपको बोलते हुए 15 मिनट हो गए हैं।

श्री प्रकाश राणा : अध्यक्ष महोदय, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब मेरी बात सुनने की कृपा करें। एक-दूसरे पर इल्जाम न लगाएं। यह प्रदेश बहुत संकट से गुजर रहा है। यह देवी-देवताओं का प्रदेश है और हम सब मिलकर इस प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाएं, इस पर विचार करें। आर0डी0जी0 से हमारा गुजारा नहीं होने वाला और न ही इससे समस्या का समाधान होगा। यही मैं कहना चाहता हूं। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री भवानी सिंह जी 15 मिनट बोले और पिछले कल श्री आशीष बुटेल जी ने 10 मिनट में अपनी बात रखी। 15 minutes is enough time to speak. अब श्री राजेश धर्मानी, माननीय नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री जी चर्चा में भाग लेंगे।

नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। हमारे संसदीय कार्य मामलों के मंत्री श्री

हर्षवर्धन चौहान जी ने नियम 102 के अंतर्गत यहां सरकारी संकल्प प्रस्तुत किया है। इसका उद्देश्य यह है कि दिनांक 01 फरवरी, 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट में हिमाचल प्रदेश की जो अपेक्षाएं थीं, उनकी पूर्ति के संबंध में चर्चा की जाए। इसके लिए फाइनेंस कमीशन के समक्ष मुख्य मंत्री जी ने भी अपना पक्ष रखा था और हम आशा करते हैं कि जब फाइनेंस कमीशन हिमाचल आया था तब आपने (विपक्ष) भी अपना पक्ष रखा होगा। हमारी अपेक्षा थी कि 15वें वित्तायोग द्वारा जिस प्रकार घटते क्रम में टेपरिंग फॉर्म में आर0डी0जी0 स्वीकृत की गई थी उसके स्थान पर सरकार की ओर से यह पक्ष रखा गया था कि 5 वर्ष का औसत निकालकर 16वें वित्तायोग में आर0डी0जी0 की ग्रांट दी जाए।

17.02.2026/1520/टी0सी0वी0/ए0एस0-2

हम इस संकल्प के माध्यम से केंद्रीय बजट में जो कमी रह गई थी उसकी भरपाई के लिए भारत सरकार से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। हम चाहते हैं कि पक्ष और विपक्ष मिलकर इस संकल्प को सर्वसम्मति से पारित करें ताकि भारत सरकार को यह संदेश जाए कि हिमाचल के हितों के मामले में सभी दल एकजुट हैं और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर प्रदेश के हित में अपना पक्ष रखते हैं। अभी भी आपके पास समय है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिन वक्ताओं ने अपने विचार रखे उन्हें सुनकर ऐसा लगा कि उनके द्वारा आर0डी0जी0 पर लगाए गए कट को उचित ठहराने का प्रयास किया गया। इस प्रस्ताव में कहीं भी अन्य सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत राज्यों को मिलने वाली राशि का उल्लेख नहीं है। यह प्रस्ताव केवल राजस्व घाटा पूर्ति से संबंधित आर0डी0जी0 पर केंद्रित है। दुर्भाग्य से आपकी ओर से अपेक्षित सहयोग इसमें नहीं दिखाई दिया।

(सभापति श्री संजय रत्न पदासीन हुए)

अब तक आपके सदस्यों द्वारा सार्वजनिक रूप से और विधान सभा के इस सदन में भी यह कहा गया कि वर्तमान सरकार की मिस मैनेजमैंट के कारण आर0डी0जी0 में कटौती हुई है।

श्रीमती एन0एस0 द्वारा जारी ...

17-2-2026/1525/एन0एस0-डी0सी0/1

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री ----जारी

सभापति महोदय, मैं इनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि भाजपा के समय 54,000 करोड़ रुपये आर0डी0जी0 के तौर पर मिले और 16,000 करोड़ रुपये जी0एस0टी0 कंपनसेशन के तौर पर मिले यानी कुल मिला करके 70,000 करोड़ रुपये अनटाइड फंड भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 वर्षों में मिला। कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में पिछले तीन वर्षों में हमें आर0डी0जी0 के तौर पर अनटाइड फंड सिर्फ 17,000 करोड़ रुपये मिला है क्योंकि जी0एस0टी0 कंपनसेशन बंद हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में 70,000 करोड़ रुपये की जो पैसे की वैल्यू है अगर आज के हिसाब से उसकी वैल्यू लगाएं तो ज्यादा आंकी जाएगी क्योंकि इन्फलेशन के साथ पैसे की वैल्यू कम होती है। हिमाचल सरकार ने जब यहां पर ओ0पी0एस0 लागू किया तो उस वजह से 1600 करोड़ रुपये का और कट यानी बॉरोइंग लिमिट कम की गई। हमें कुल मिला करके 17,000 करोड़ रुपये मिले और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 17,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष मिलता था। अगर इन सारे फैक्टर्ज को जोड़ा जाए तो हमारी एक्सटर्नल बॉरोइंग लिमिट कम की गई। आपको एवरेज टाइम पर जो अनटाइड फंड मिला अगर उसको आज की प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से देखें तो लगभग 17,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष बनते हैं। हमें तो तीन वर्षों में 17,000 करोड़ रुपये मिले। भारतीय जनता पार्टी के समय इतना ज्यादा पैसा अनटाइड फंड के तौर पर मिला। मुझे लगता है कि 14वें व 15वें वित्तायोग ने आपसे भी यह अपेक्षा की होगी कि आप इस पैसे को कहीं पर इन्वैस्ट करेंगे, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, कोई ऐसे प्रोजैक्टस लाएंगे जिससे भविष्य की पीढ़ियों के लिए आमदनी का परमानैंट सोर्स डवलप हो। जैसा माननीय भवानी सिंह पठानिया जी ने कहा कि ऐसी कोई विजिबल इन्वैस्टमैंट आपकी सरकार के समय में नहीं हुई है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अनप्रिसीडेंटली बहुत हाइक मिला तो यह भारतीय जनता पार्टी के समय में मिला है। विपक्ष की फ्रंट रो में श्री विपिन सिंह परमार जी, श्री बिक्रम सिंह और श्री सुख राम चौधरी जी बैठे हैं और तीनों मंत्रिमण्डल के सदस्य थे तथा आपकी सरकार के समय चुनावों से मात्र 2-3 महीने पहले ऐसे निर्णय लिए गए जिसकी

वजह से हिमाचल प्रदेश सरकार का फाइनैंशियल सिस्टम पूरी तरह से गड़बड़ा गया। यहां पर फ्रीबीज की बात माननीय जय राम ठाकुर जी कह रहे थे। हमारी गारंटियों का

17-2-2026/1525/एन0एस0-डी0सी0/2

इम्पैक्ट अभी तक उतना नहीं आया है जितना कि आपकी सरकार के समय में आखिरी तीन महीनों में लिए गए निर्णयों का इम्पैक्ट वर्तमान सरकार पर आया है। उसको जब इवैल्यूएट किया तो यह उसका ही परिणाम है अगर आपकी बात को ही माना जाए। हम आपसे यह उम्मीद करते हैं कि अभी भी समय है कि आप सरकार का साथ दें क्योंकि सरकार का साथ देने का मतलब है कि हिमाचल का साथ देना। यह कांग्रेस की बात नहीं है। अगर एक बार यह ग्रांट बंद हो जाएगी तो दोबारा इस मद में यह ग्रांट नहीं मिलेगी। यह ग्रांट अनटाइड नहीं मिलेगी, किसी और रूप में मिले तो यह अलग बात है। यहां पर रणधीर शर्मा जी कह रहे थे और अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि हमारा सेंट्रल टैक्सिज मे जो शेयर है उसको 41 प्रतिशत किया जाए। उसका मतलब है कि स्टेट से जो टोटल टैक्स कोलैक्शन होती है तो उसमें से हर 100 रुपये में से 59 रुपये भारत सरकार के पास रहता है और 41 रुपये राज्य सरकारों को दिया जाता है लेकिन इसमें भी एक कैच है। पूरी तरह से 41 प्रतिशत या 59 प्रतिशत नहीं मिलता है क्योंकि भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे सैस और सरचार्ज लगा रखे हैं।

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

17.02.2026/1530/RKS/डीसी-1

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री ... जारी

क्योंकि भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार के सैस और सरचार्ज लगाए हुए हैं। मैं आगामी वित्तीय वर्ष का केंद्रीय बजट देख रहा था जिसमें लगभग 5.91 लाख करोड़ रुपये सैस और सरचार्ज के रूप में केंद्र सरकार की किटी में आने का अनुमान है लेकिन सैस और सरचार्ज की राशि राज्यों के साथ शेयर नहीं की जाती है। इसलिए यह परसेंटेज 41 प्रतिशत से भी नीचे रहती है। माननीय उप-मुख्य मंत्री जी ने संविधान का उल्लेख करते हुए कहा कि

इसमें 'रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट' का उल्लेख नहीं है किंतु उसमें 'रेवेन्यू ग्रांट' लिखा है। मूल उद्देश्य तो राज्यों की वित्तीय सहायता करना है फिर प्रश्न उठता है कि उन्होंने इस पर एकदम क्यों कट लगा दिया? अगर आर0डी0जी0 बंद करनी थी तो इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए थे। जैसा श्री जय राम ठाकुर जी कह रहे थे कि यह 15वें वित्तायोग के समय ही तय हो गया था कि आर0डी0जी0 बंद हो सकती है। 15वें वित्तायोग की अनुशंसाएं तो आपके समय में लागू हुई। अगर आपको कहा गया था कि यह ग्रांट बंद होने वाली है तो आपने इसे आगे राज्य सरकार को क्यों नहीं अवगत करवाया? इस संबंध में प्रोएक्टिव कदम क्यों नहीं उठाए गए? मैं ऐसा समझता हूं कि अगर यह आपकी जानकारी में था और आपने इसको छिपाया तो इससे बड़ा पाप कुछ और नहीं हो सकता है। इसकी वजह से जो समस्या आने वाली है उन्हें हमने नजरअंदाज किया है। दूसरा विषय यह है कि केंद्र सरकार ने राज्यों के मदों में कटौती की है परंतु विदेशी सहायता के प्रावधान जारी रखे हैं। बार-बार यह कहा जाता है कि माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्वगुरु बनने की दिशा में अग्रसर है और उस दृष्टि से विभिन्न देशों को सहायता प्रदान की जा रही है। बजट में भूटान के लिए 2288 करोड़ रुपये, नेपाल के लिए 800 करोड़ रुपये, अफगानिस्तान के लिए 150 करोड़ रुपये, श्रीलंका के लिए 400 करोड़ रुपये, बांग्लादेश के लिए 60 करोड़ रुपये, मालदीव के लिए 550 करोड़ रुपये, म्यांमार के लिए 300 करोड़ रुपये, लैटिन अमेरिकी देशों के लिए 120 करोड़ रुपये तथा अफ्रीकी देशों के लिए 225 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह पूरी तरह अनुचित है। केंद्र सरकार की अपनी प्राथमिकताएं और कूटनीतिक दृष्टि हो सकती है। परंतु हमारा निवेदन मात्र यह है कि जब विदेशी देशों के लिए प्रावधान किए जा रहे हैं तब हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। यह हमारा अधिकार है कि हमें वित्तीय सहयोग मिले। हिमाचल प्रदेश ने

17.02.2026/1530/RKS/डीसी-2

इस देश की तरक्की के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। भले ही आज हम वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं परंतु नेचुरल रिसोर्सिज की दृष्टि से हमारा राज्य अत्यंत समृद्ध है। हमारे यहां पर पांच क्लाइमेटिक जोन हैं। शायद ही ऐसे बहुत कम देश होंगे जहां पर हर तरह के क्लाइमेटिक जोन हैं। यहां हॉट सब ह्यूमिट क्लाइमेटिक जोन, टेम्परेट

जोन, कोल्ड जोन तथा ग्लेशियर जोन आदि हैं और हर जोन की अपना महत्ता है। यद्यपि ग्लेशियर जोन में कोई रहता नहीं है लेकिन हम ग्लेशियर को पिघलने से बचाते हैं तो उससे वर्ष भर जल उपलब्ध होता है। इससे उत्तर भारत और हमारे पड़ोसी देशों को भी पानी मिलता है। यह मानवता के प्रति हमारा योगदान है। आज अगर हम ग्रीन कवर को प्रीजर्व करते हैं तो उसी वजह से हमारे ग्लेशियर पिघलने से बचते हैं। हिमाचल प्रदेश ने हमेशा इस दिशा पर अपना योगदान दिया है और ग्रीन फैलिंग के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है। कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक सिल्वीकल्चर के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा गया था। शायद यह कार्य भाजपा के कार्यकाल में हुआ था और उसमें कुछ पैचिज पर ग्रीन फैलिंग की गई थी। उस पैचिज को इयरमार्कड किया गया और उसमें कंप्लीट फैलिंग की गई। आज उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। वहां पर नेचुरली ट्री बहुत अच्छी तरह ग्रो हुए हैं। हमें इस मैथ्ड को कंट्रोल्ड व साइंटिफिक वे में दूसरी जगह भी अपनाना चाहिए।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

17.02.2026/1535/बी.एस./एच.के.-1

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री जारी...

हमें इसे कंट्रोल्ड वे में दूसरी जगह अपनाना चाहिए क्योंकि हर पेड़ की एक उम्र होती है इसके बाद वह खुद खत्म हो जाता है उसकी बजाय हमें उसका प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहिए। हम अपनी लकड़ी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी लकड़ी इंपोर्ट करते हैं और लकड़ी दुनिया में कहीं भी कटे उसका इंपेक्ट तो एनवायरमेंट पे आएगा ही आएगा बल्कि ज्यादा आएगा। जब हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ट्रांसपोर्ट पर भी हमारा कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है तो हमें उसकी तरफ ही जरूर सोच विचार करना चाहिए।

दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर जो वर्तमान सरकार के ऊपर आपकी तरफ से आरोप लगाए गये। आदरणीय भवानी सिंह पठानिया जी ने यह ठीक कहा कि जब हमारी फर्स्ट सी0एल0पी0 मीटिंग हुई, आप अंदाजा लगाएं कि हमारी सरकार बनने के बाद विधायक दल की पहली मीटिंग में पहला प्रस्ताव क्या पारित हुआ? पहला प्रस्ताव यह पारित हुआ कि हिमाचल भवन और सदन में जो आम हिमाचली रेंट पे करता है, वही रेंट मंत्री हैं, विधायक हैं या फिर मुख्यमंत्री और उप-मुख्य मंत्री और अधिकारी भी उतना ही रेंट पे करेंगे। उससे सरकार की मनसा साफ झलकती है और जो निर्णय आपने लिए थे हालांकि सारे रिव्यू नहीं किये हैं लेकिन सारे मामलों को अक्षरशः लागू कर दिया होता तो आज शायद हमारी स्थिति इससे भी बदतर होती और आज हमें यह सोच विचार करना पड़ेगा। क्योंकि आपकी और हमारी भी मजबूरी है कि जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो जनता ने विकास का एक ही इंडिगेटर मान लिया है और वे बोलते हैं कि दे करके क्या गये। मुख्य मंत्री जी आपके हैं, चाहे हमारे हैं, यही बात होती है कि दे करके क्या गए? फिर विधायक के ऊपर प्रेशर आता है। नये इंस्टीट्यूशन खोलना और नये दफ्तर खोलने हम उसी को ही विकास का एक इंडिगेटर मान रहे हैं और ऐसा करते-करते हमारा इतना ज्यादा गवर्नमेंट का फैलाव हो गया कि अब उसको संभालना मुश्किल है। मुझे आदरणीय मोदी जी की एक बात बड़ी अच्छी लगती है हालांकि उसमें उन्होंने काम नहीं किया परंतु बोला जरूर है। उन्होंने कहा था कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, यह सरकार चलाने का हमारा मूल मंत्र होगा और इसकी जरूरत है और पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे

17.02.2026/1535/बी.एस./एच.के.-2

सीनियर लोग थे उनको धन्यवाद देते हैं जिन्होंने संविधान में संशोधन किया और अपने ऊपर कट लगाया। कई बार नेताओं की बड़ी निंदा होती है और कहा जाता है कि इन्होंने पैसा बर्बाद कर दिया। यह जो एक लाख करोड़ रुपये लोन की बात करते हैं, आपसी दोषारोपण में हम यह प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि इसको नेता अपने ऊपर ही खर्च गए, लेकिन यह वास्तविकता से बहुत दूर है। यह भारत की संसद के अंदर ही निर्णय लिया गया था कि हमने मंत्रिमंडल का आकार जो है उसको 15 प्रतिशत तक

लिमिट कर दिया था और छोटे राज्यों को 12 की संख्या तक लिमिट कर दिया था, लेकिन वह वहीं पर रुक गया। यह फरदर डाउन द लाइन पर्कुलेट होना चाहिए था। जब इंटरनेट नहीं था कंप्यूटराइजेशन नहीं थी तब हम कम दफ्तरों में कम स्कूलों में कम अस्पतालों में गुजारा कर रहे थे। हमारे पास सड़कें कम थी, यातायात के साधन कम थे तो हमारे पास सारा सेटअप कम था। आज हमारे पास इंटरनेट की सुविधा है हमारे पास कम्युनिकेशन के बहुत अच्छे टूल्स हैं। सड़कों का फैलाव लगातार बढ़ रहा है। आज हमें सोचना पड़ेगा कि हर गांव में डिस्पेंसरी खोलने की बजाय जो 10 डॉक्टर्ज, 10 जगह लगाने हैं उन्हें एक जगह लगा करके हर गांव को संड़कों से जोड़ा जाए। अच्छी एंबुलेंस दे करके मरीज को उस जगह पहुंचाया जाए। यदि हमारी पंचायत के अंदर भी बड़ा अस्पताल है लेकिन गांव तक सड़क नहीं है तो शायद वहां पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा। यदि सड़क होगी तो 40 किलोमीटर दूर अस्पताल में भी लोग पहुंच जाएंगे। आज जगह-जगह स्कूल खुले हैं लेकिन गुणवत्ता पर ध्यान दें तो गुणवत्ता में हम कहां खड़े हैं? वर्ल्ड रैंकिंग में इंडिया का नाम बहुत कम है केवल दो-तीन इंस्टीट्यूशन से ज्यादा नहीं बढ़ता है और नेशनल रैंकिंग में हिमाचल का नाम नहीं आता है।

सभापति : माननीय मंत्री जी, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

17.02.2026/1535/बी.एस./एच.के.-3

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री : कुलमिलाकर मेरा बोलने का मकसद यही है कि ये जो आर0डी0जी0 बंद करने की बात कही है इसको एकदम से बंद न करें, धीरे-धीरे स्टेट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर ध्यान दें। हम यह भारत सरकार से आग्रह करेंगे और आप भी इसमें हमारा साथ दें और हिमाचल प्रदेश ने अपने संसाधनों को बढ़ाने की तरफ कदम उठाए हैं तभी तो

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

17.02.2026/1540/डीटी/एच0के0-1

नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री जारी...

हमारी सरकार में 3800 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राजस्व की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन हमें खर्चें भी कम करने पड़ेंगे। हम सिर्फ राजस्व बढ़ाने की बात करेंगे लेकिन अगर खर्चे कम नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। हम एक लाख की बजाय एक करोड़ रुपये कमा लें और हमारा खर्चा सवा करोड़ रुपये या एक करोड़ रुपये होगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। हमारी आमदनी अगर कम भी है तो हमारे खर्चे भी सीमित हों तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि हम भविष्य के लिए एक अच्छी लेगेसी छोड़ कर जाएं। हम अपने परिवार के स्तर पर सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए एक बेहतर लेगेसी छोड़ जाएं। इसलिए हमें कलेक्टिवली, सरकार के तौर पर और एक राज्य के तौर पर, यह सोचना पड़ेगा कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए हम क्या छोड़ जाएंगे? हम उनके लिए एक बेहतर हिमाचल बना कर जाएं, बेहतर व्यवस्था बना कर जाएं और इसके लिए जरूरी है कि हम जितना हो सके उतने अपने खर्च कम करें। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि एक श्वेत पत्र जारी किया जाए ताकि जनता को भी पता लगे कि जो लोन लिया गया, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी के समय लिया गया या हमारे समय में लिया गया, उसको किन-किन कम्पोनेंटस पर खर्च किया गया उसका भी जनता को पता लगना चाहिए।

दूसरा, मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो इस सदन में बैठे हैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप अगर हमारे साथ केंद्र सरकार के पास नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम आपकी मजबूरी समझते हैं, इसलिए आप अपना संकल्प अपने स्तर पर पारित करके अपने केंद्र के नेताओं को दो। कुल मिलाकर हम सब की यही अपेक्षा है कि आर0डी0जी0 प्रदेश को मिलनी चाहिए क्योंकि यह हिमाचल के भविष्य की बात है इसलिए आप हमारी इसमें मदद करें। इसमें एक दम से कट लगेगा तो ठीक नहीं है। यह कट किसके ऊपर लगेगा? यह भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कट उन लोगों पर लगेगा जो प्रदेश के अति गरीब लोग हैं, जो अति असहाय लोग हैं, जो अपने हकों की लड़ाई लड़ना न तो जानते हैं और न ही वह संगठित

होकर वह लड़ाई लड़ सकते हैं। इसलिए उनके हित के लिए भी यही सही है कि हम सब लोग मिलकर अपने-अपने

17.02.2026/1540/डीटी/एच0के0-2

स्तर पर, यानी सरकार अपने स्तर पर और विपक्ष अपने स्तर पर केंद्र सरकार से बात करे। लेकिन हमारा मकसद एक होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की जो आर0डी0जी0 बंद हुई है उस आर0डी0जी0 को हम रिस्टोर करवाएं। जैसे टेपरिंग फोरम में था वैसे हो-बेशक ज्यादा नहीं दे सकते तो थोड़ा कम दे दें-लेकिन दें जरूर। हमें टाइम-बाउंड कर दें कि इस टाइम पर आप इसे वापिस दें नहीं तो इस पीरियड के बाद आर0डी0जी0 परमानेंट बंद कर दी जायेगी। अगर ऐसा होता तो हम अपने आप को आत्म निर्भरता की ओर ले जा सकें।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इस लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

17.02.2026/1540/ डीटी/एच0के0/3

सभापति : अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह जी।

श्री बिक्रम सिंह : सभापति महोदय, नियम-102 के अंतर्गत श्री हर्षवर्धन चौहान जी द्वारा यह जो सरकारी संकल्प प्रस्तुत किया गया है, आपने इसपर मुझे बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

काफी लंबी चर्चा इस विषय में हो चुकी है और हमारे सत्ता पक्ष के साथी अलग-अलग प्रकार के तर्क देकर यह सिद्ध करना चाहते हैं कि आप सब हिमाचल प्रदेश के हितेशी है और जो विपक्ष में बैठे हैं वे हिमाचल प्रदेश के विरोधी हैं। बड़े ही अच्छे शब्दों में हमारे जोग्रिन्द्रनगर विधान सभा के सम्मानीय विधायक ने बोला है कि गलती आप करें, कसूर

आप करें और आज आप को यह लग रहा है कि आपसे ऐसा हुआ है तो आज आप यह संकल्प लेकर आए हैं। अच्छा होता आप विधान सभा के अंदर उस समय भी संकल्प लेकर आते कि हमनें प्रदेश की महिलाओं को 1500-1500 रुपये देने की बात कही है- हमारी गांरटी है लेकिन हम उस राशि को देने में असमर्थ है क्योंकि पैसा कम हो रहा है। उसके ऊपर भी कोई संकल्प इस माननीय सदन में लेकर आते। उसके ऊपर भी चर्चा होती। जब आपने प्रदेश की जनता को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात अपनी गांरटी में की तो उस समय आप को ख्याल नहीं आया कि प्रदेश की वित्तीय हालत कितनी खराब है। आप हर बात पर यह अहसास करवाने की कोशिश करते हैं कि जो केंद्र सरकार है उस केंद्र सरकार ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिय, हमारा सब कुछ बंद कर दिया। आज माननीय उप-मुख्य मंत्री जी संविधान लेकर आ गये और उन्होंने कहा कि यह तो इसमें लिखा हुआ है उसमें जो लिखा है वह हम कर तो रहे हैं। सभी ने यहां पर बताया कि 15वें वित्त आयोग में हिमाचल प्रदेश को 435 करोड़ रुपये मिला है, 16वें वित्त आयोग में हिमाचल प्रदेश में अर्बन बॉडीज को 855 करोड़ रुपये मिला है। इसी प्रकार से Additional Central Assistance for External Aided Projects के लिए वित्तीय वर्ष 2020-2021 से वित्तीय वर्ष 2025-2026 तक 6064 करोड़ रुपये मिले हैं। अगर मोटी-मोटी नजर दौड़ाई जाए

श्री एन0जी0द्वारा जारी...

17.02.2026/1545/वाई.के.-एन.जी./1

श्री बिक्रम सिंह.......... जारी

वर्ष 2020-21 से वर्ष 2025-26 तक 6064 करोड़ रुपये मिले हैं। केन्द्र सरकार की ओर से मोटे-मोटे कामों को देखा जाए तो एम्ज बिलासपुर के लिए 1471 करोड़ रुपये, केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए 500 करोड़ रुपये, आई0आई0एम0 सिरमौर के लिए 531 करोड़ रुपये, आई0आई0आई0टी0 ऊना के लिए 64 करोड़ रुपये और मैडिकल कॉलेज

हमीरपुर-चम्बा-नाहन के लिए 180-180 करोड़ रुपये मिले हैं।...(व्यवधान) आप (संसदीय कार्य मंत्री, श्री हर्षवर्धन चौहान के लिए कहा) कह रहे थे कि केन्द्र सरकार आपको कुछ नहीं दे रही है तो मैं उस विषय में आपको बता रहा हूं।...(व्यवधान) मैं वर्ष 2026-27 की बता कर लेता हूं। वर्ष 2026-27 में रेलवे विस्तार के लिए 2911 करोड़ रुपये मिले हैं। यह धनराशि कॉंग्रेस पार्टी के शासन की तुलना में लगभग 27 गुणा अधिक है। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में 17711 करोड़ रुपये की रेल परियोजनाएं प्रगति पर हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के चार स्टेशनों को शामिल किया गया है जिन पर लगभग 46 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सभी स्टेशन्ज़ व रेल लाइनों को विद्युतिकरण हो चुका है। इसके अलावा स्पेशल असिस्टेंट के तहत हिमाचल प्रदेश को 50 वर्ष के लिए ब्याजमुक्त ऋण दिया जाएगा जिससे प्रदेश को बहुत बड़ा लाभ होगा। इसके अलावा पर्यटन के विषय पर भी काफी कुछ बोला गया है और मैं उन बातों को बार-बार नहीं दोहराना चाहता।

सभापति महोदय, माननीय मंत्री, श्री राजेश धर्माणी जी बोल रहे थे कि ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि जब सत्तापक्ष के लोग अपने विषय को रखते हैं तो यह नहीं देखते कि आज आप लोगों की ऐसी हालत क्यों हुई है? हिमाचल प्रदेश में आज जो हालात बने हैं, उसका क्या कारण है? मैं बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश को आर0डी0जी0 के रूप में वर्ष 2022-23 में 9377 करोड़ रुपये, वर्ष 2023-24 में 8057 करोड़ रुपये, वर्ष 2024-25 में 6249 करोड़ रुपये और वर्ष 2025-26 में 3257 करोड़

17.02.2026/1545/वाई.के.-एन.जी./2

रुपये मिले हैं। माननीय मंत्री, श्री राजेश धर्माणी जी कह रहे थे कि यदि हमें कोई चिट्ठी मिल जाती तो हम कुछ ठीक कर सकते थे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपको ये आंकड़े नज़र नहीं आ रहे थे कि ये लगातार कम होते जा रहे हैं?...(व्यवधान) माननीय श्री राजेश धर्माणी जी, मैं आपके समय की ही बात कर रहा हूं। आपकी सरकार में जब यह

आर0डी0जी0 कम हो रही थी तो क्या आपको भाजपा के माननीय विधायकों की याद नहीं आई? क्या आपको चिंता नहीं हुई कि भाजपा के माननीय विधायकों से बात की जाए? यहां पर ठीक बोला गया कि सत्तापक्ष को पहले से ही पता था कि आर0डी0जी0 बंद होने वाली है। यदि प्रदेश सरकार को पता था कि यह बंद होने वाली है तो सरकार ने इसके लिए क्या किया? मुख्य मंत्री जी ने अभी इसका रिप्लाई देना है तो उन्हें बताना चाहिए कि वे क्या-क्या सुधार करना चाहते हैं? मुख्य मंत्री जी के मन में क्या है? मुख्य मंत्री जी एक तरफ तो कहते हैं कि हमारी मदद कीजिए और दूसरी ओर 40-40 चेयरमैनों की फौज खड़ी कर देते हैं। मुख्य मंत्री जी यहां पर खड़े हो कर कहें कि हम उन सभी को हटाएंगे और हम अपने सलाकारों व एडवोकेट जनरलों को कम करेंगे। पिछले कल जब माननीय श्री जय राम ठाकुर जी इसी विषय पर बोल रहे थे तो मुख्य मंत्री जी बार-बार खड़े हो कर कह रहे थे कि आपके जमाने में भी तो इतने लगाए गए थे तो क्या हुआ। भई, हमारा जमाना अच्छा था तो हमने बना दिए थे लेकिन आपका जमाना ठीक नहीं है तो इनकी संख्या को कम या शून्य कीजिए। आपकी जितनी चादर है उतने पैर पसारिए। आपको पता है कि सरकार के पास पैसा कम है तो हवाई जहाज (हैलीकॉप्टर) को साइकल की तरह क्यों भगा रहे हो? आपको सोचना चाहिए कि पैसा कम है और यदि मुझे (मुख्य मंत्री जी के लिए कहा) चण्डीगढ़ जाना है तो हैलीकॉप्टर को छोड़ कर गाड़ी में चले जाते हैं। मुख्य मंत्री जी, आप इन सब चीजों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।...(व्यवधान) सर, बाद में बोल लेना।

17.02.2026/1545/वाई.के.-एन.जी./3

सभापति : माननीय सदस्य, एक मिनट रुकिए। माननीय मुख्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं।

मुख्य मंत्री : सभापति महोदय, माननीय सदस्य हमेशा बहुत जोश में बोलते हैं और जोश में रहना भी चाहिए क्योंकि इनका जोश धीरे-धीरे कम होता है। जब इनका जोश धीरे-धीरे कम होता है तब इनको पता चलता है कि मैं क्या बोल रहा था।

श्री ए0पी0 द्वारा......जारी

17.02.2026/1550/वाई.के./ए.पी./01

मुख्य मंत्री जारी .....

जितना सड़कों पर मैं आपदा के समय घूमा हूं, आप जो बोल रहे हैं उसे बोलने से पहले सोच लिया करें। दूसरी बात, फौज खड़ी कर दी। आर0डी0जी0 कम हो रही थी। आर0डी0जी0 कम कभी नहीं हो रही थी और न बंद हो रही थी। कई बार आपने बोल दिया। एक हमारे सांसद सदस्य बोलते हैं कि 20 साल पहले से पता था कि आर0डी0जी0 ग्रांट बंद हो रही थी। फिर जय राम ठाकुर जी ने बोल दिया कि आर0डी0जी0 ग्रांट खत्म हो रही थी। आपके समय तो 54,000 करोड़ रुपये मिली। क्यों मिली थी? इसलिए मिली थीं कि आप सुधार करो, खर्च कम करो। हमारे चैयरमैन को गिनाया जा रहा है। आपके समय में जितने थें उससे हमारे काम हैं। जब मैं कल लिस्ट निकलूगा तब बताऊंगा कि हमारे चेयरमैन आपसे कम हैं। एक और बात बताऊं मैं आपको जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को 17,000 करोड़ रुपए मिला, तीन गुना पूर्व सरकार के समय, इन्हें मिला। वह वित्तीय अनुशासन है या यह वित्तीय अनुशासन है कि 54,000 करोड़ रुपये जिनको मिल रहा है और 16,000 करोड़ रुपये जिनको मिल रहा है? इसलिए आप बोलने से पहले आंकड़ों का सही आंकलन कर लें। हम मानते है कि आप बोलने में बहुत अच्छे हैं, किसी पर छींटा-कशी में आप बहुत अच्छे हैं। यह अच्छी बात है, आप करो लेकिन आंकड़ों का तो सही आंकलन करो। एक बात मैं कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, मैं बाहर बैठा हूं, लेकिन सुन सारा रहा हूं। एक-एक चीज का जवाब दूंगा। लेकिन कुछ चीजों को आप कह रहे हैं कि ऐसा है, यह मैं फैक्ट्स के साथ बताऊंगा। हम 16वें फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि संसद में वह अभी पास होनी है। दिनांक 17 मार्च, 2026 तक वह पास होनी है। इस संदर्भ में हमें कैसे आगे बढ़ाना है, किस ढंग से उस पर काम करना है, उसी रणनीति के लिए यह विशेष सत्र बुलाया गया है। ताकि आपके सुझावों को भी उसमें लिखा जाए। आपके सुझावों से हमें बहुत कुछ पता लगेगा। हमारे देश के वित्त मंत्री जी ने भी हमारी सरकार की प्रशंसा की है जिस तरह से हमने तीन वर्षों से सुधार किये हैं। हमारे नगर एवं ग्राम योजना मंत्री जी ने ठीक कहा कि जो 54,000 करोड़ रुपये मिला था अगर

उसका सही आंकलन करते और हमारा जो लोन 48,000 करोड़ रुपये था, उससे 20,000 करोड़ रुपये देते तो ऐसी स्थिति आज प्रदेश के अंदर पैदा न होती।

17.02.2026/1550/वाई.के./ए.पी./02

आर0डी0जी0 अधिकार है और जनता का अधिकार है। यह किसी एक का अधिकार नहीं है। यह आपका भी अधिकार है। यह अधिकार है। मैं इसकी सैक्शन और प्रोविजो भी आपको कल बताउंगा। लेकिन थोड़ा सा आप इस मुद्दे पर गंभीरता से बोलें।

सभापति : माननीय सदस्य, श्री बिक्रस सिंह जी।

श्री बिक्रम सिंह : सभापति महोदय, जब कोई व्यक्ति सही बात करता है तो इनको कड़वी लगती है और कड़वी बात पर तुरंत रिएक्शन देने के लिए मुख्यमंत्री जी खड़े हो जाते हैं। भेईया, क्या गलत बोल रहा हूं मैं? हमारी फोज थी, पैसे थे, दे दिए। आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप मत दो। आप फोज को क्यों लगा रहे हो? ...(व्यवधान) अनिरूध जी, आपको इतने प्रेम से देख रहा हूं। क्यों, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने जब बोला की आर0डी0जी0 कम हो रही थी तो आप कहां सोए हुए थे? यह कहते है कि मैं आपका पूरा भाषण सुन रहा हूं। मैंने आंकड़ों के साथ बात की है और मैंने आंकड़े गिनाए हैं कि आर0डी0जी0 ग्रांट लगातार कम हो रही थी। भेईया, आपने उस समय इसके बारे में क्या चिंता की? उस समय आप लोगों ने क्या बात की? उस समय आपको हम नजर नहीं आए और जब आज ग्रांट बंद हो गई है तो इसके ऊपर सब लोग गंभीर हैं। क्या आपको यह लगता है कि आर0डी0जी0 बंद होने से भारतीय जनता पार्टी खुश है? क्या हम खुश हैं? हम खुश नहीं हैं। लेकिन जो आपका दोहरा चरित्र है, उससे हम दुखी हैं। आप एक तरफ कुछ बातें करते हो और जमीनी हकीकत तो कुछ ओर ही है। आपकी चादर छोटी है तो उसी प्रकार से चलिए। माननीय नगर एवं ग्राम योजना मंत्री जी ने बहुत अच्छा कहा कि जो हमारी पहली मीटिंग हुई उसमें हमने निर्णय लिया कि जब कोई हिमाचल भवन और अन्य भवनों में जाएगा तो फीस बढ़ा दी जाएगी। भईया 400 रुपये से 1200 रुपये तो आपने कर दिये, लेकिन आपने वर्तमान चेयरमैन का वेतन 30,000 रुपये से 1,20,000 रुपये कर दिया। अब आप बताए कि कुप्रबंधन कहा है। आपने एक जगह पर तो 800 रुपये इंक्रीज किया कमरे का, लेकिन

दूसरी तरफ आपने चेयरमैन की तनख्वाह बढ़ा रहे हो। ...(व्यवधान) मेरे पड़ोस का चेयरमैन, बोलने में थोड़ा गलत हुआ होगा, आनरेरीअम। लेकिन कैसे गलत बोल रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री ए0टी0 जारी .....

17/02/2026/1555/AT/ AG /01

Chairman : Please, address to the Chair. Don't disturb please.

बार-बार मौका नहीं मिलेगा यह कोई मतलब है? मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। ...(व्यवधान)

सभापति : हाउस के नेता हैं ये।

श्री बिक्रम सिंह : हाउस के नेता का मतलब यह है कि दूसरे बंदे की नहीं सुननी? मैं हर बात को ऐसे ही बोलूंगा। अगर आप ऐसे ही बीच में पंगा करते रहेंगे तो मैं हर बार रिएक्ट करूंगा। अब मैं बोल रहा हूं कि उनके पैसे बढ़े हैं आपने जवाब दे देना, आप बोल देना बिक्रम, आपने गलत बोला है। आप बार-बार मुझे बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं मेरा सारा रीदम तोड़ रहे हैं।

सभापति : प्लीज, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।

मुख्यमंत्री : सभापति महोदय, यह जो बोलते हैं तो इनकी ट्रेन बुलेट ट्रेन से भी फास्ट चलती है थोड़ी छुक-छुक वाली भी देख लिया करो। जो यह बोल रहे हैं कि चेयरमैन की 1,30,000 रुपये कर दी है, यह गलत बोल रहे हैं। यह सोशल मीडिया का एक कागज देख रहे हैं नोटिफिकेशन नहीं देख रहे हैं। आपके पास नोटिफिकेशन है? नहीं है। और आपको मैं बता दूं चेयरमैनों की तनख्वाह जैसा यह कह रहे हैं, 1,30,000 रुपये किसी की भी नहीं है। ...(व्यवधान) हमारी कैबिनेट का स्केल भी हमने कुछ लोग जो आपके समय के जो चेयरमेन रखे थे उससे भी कम पर ही रखा है। आपको कल का आंकड़ा दे देंगे शिशु धर्मा

जी के भी और त्रिलोक जी के भी। ...(व्यवधान) मैं कैबिनेट वाली बात कर रहा हूं, कल कागज देख लेना।

Chairman : Let him complete (Shri Trilok Jamwal ji). Let him complete. ...(Interruption) माननीय सदस्य, let him complete.

17/02/2026/1555/AT/ AG /02

मुख्यमंत्री : माननीय सभापति महोदय, यह ही बता देंगे कि कितने मिलते थे। मैं बैठ जाता हूं फिर उसके बाद कहता हूं आप बता दीजिए, कितने मिलते हैं।

श्री त्रिलोक जम्वाल : सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी मेरा नाम लेकर कहा कि इन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी का स्केल मिलता था 5 साल में। आपने हाउस के अंदर कहा। आप हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं आप हाउस के नेता हैं। एक अधिकारी ने आपको पर्ची पकड़ाई, आपने वही पढ़ दिया। और यही प्रदेश की जो फाइनेंशियल हालत है वह उसी का ही परिणाम है, इन पर्चियों का परिणाम है कि आज हिमाचल प्रदेश की फाइनेंशियल हालत ...(व्यवधान)

सभापति : आप खुद बता दीजिए, आपको कितना मिलता था। काम खत्म हो जाएगा।

श्री त्रिलोक जम्वाल: जहां तक मुझे एक दिन भी, क्योंकि मैं पेशे से वकील था मुझे कभी भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी का स्केल नहीं मिला 5 वर्षों में न ही मुझे सेक्रेटरी का स्केल मिला। लेकिन मुझे जो ऑनरेरियम मिलता था, वह मुझे 1,20,000 रुपये मिलता था। लेकिन जब आपने पॉलिटिकल एडवाइजर बनाया आपने ढाई लाख रुपये दिया। यह मेरे पास नोटिफिकेशन है। ...(व्यवधान) मैं कैबिनेट रैंक पहले दिन से था और मुझे 5 साल 1,20,000 रुपये मिले, लेकिन आपने ढाई लाख रुपये किए ये कुप्रबंधन है? ...(व्यवधान)

सभापति : इन्होंने सिर्फ आपका पूछा, बाकी किसको क्या दिया वह नहीं पूछा। प्लीज।

श्री त्रिलोक जम्वाल : मैं वही बता रहा हूं।

सभापति : इन्होंने यह पूछा कि आपको कितना मिलता था, बस इतनी सी बात थी। ...(व्यवधान)

श्री त्रिलोक जम्वाल : मुझे 1,20,000 रुपये मिलता था। ...(व्यवधान)

सभापति : माननीय मुख्यमंत्री जी ...(व्यवधान) बिक्रम जी, एक मिनट ...(व्यवधान)

17/02/2026/1555/AT/ AG /03

मुख्यमंत्री : आप लगे क्या थे? कैबिनेट रैंक तो नहीं था न आपका? क्या थे, मैं जानना चाहता हूं। अगर पर्ची गलत होगी तो मैं उसको ठीक करूंगा। ...(व्यवधान)

सभापति : माननीय सदस्य बिक्रम सिंह ठाकुर जी।

श्री बिक्रम ठाकुर : मुझे बड़ी तकलीफ है और मुझे दुख है। आप मेरे परम मित्र भी हैं। आज आप यहां बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे ठीक तरीके से अपनी बात रखने दी जाए।

सभापति : अब आप ही बोलेंगे।

श्री बिक्रम ठाकुर : माननीय मुख्यमंत्री जी कन्फ्यूज हैं। वह (त्रिलोक जम्वाल जी) पूछ रहे हैं कि बाकी कितने थे। आप छोले बेचने नहीं आए हैं, आप मुख्यमंत्री हैं। आपको हर बात का पता होना चाहिए। आप मुख्यमंत्री के नाते यहां गलत डाटा दे रहे हैं।

एम0डी0द्वारा जारी ......

17-02-2026/1600/AG/MD/1

श्री बिक्रम सिंह---जारी

मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि जो चेयरमैन की तनख्वाह है वह आपने अपने समय में बढ़ाई है। मेरा तर्क गलत हो सकता है, मेरे नंबर गलत हो सकते हैं लेकिन आपने

बढ़ाई है। क्योंकि आपकी सरकार के पास पैसा बहुत है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बार-बार केंद्र सरकार के सहयोग की बात करते हैं।

Chairman: Please address the Chair.

श्री बिक्रम सिंहः टैक्स डेवोल्यूशन के अंदर आप लोगों को 83 प्रतिशत से 91.4 प्रतिशत हुआ। वर्ष 2026 से लगभग 13,950 करोड़ रुपये का हिस्सा जोकि पिछले वर्ष से 2,450 करोड़ रुपये अधिक है। ग्रामीण और शहरी विकास मद के लिए 4,179 करोड़ रुपये आपको मिल रहे हैं। एस0डी0आर0एफ0 और डी0एम0एफ0 मद के अंदर 2,682 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। चौदहवें वित्त आयोग में जो आपको सहायता 40,624 करोड़ रुपये मिली थी, पंद्रहवें वित्त आयोग में वह लगभग 48,000 करोड़ रुपये के करीब मिली है। उसके अलावा केंद्रीय योजनाएं, सी0एस0एस0, नाबार्ड, विश्व बैंक आदि को मिलाकर अगर सहायता गिनें तो लगभग 2.12 लाख करोड़ रुपये के करीब बनती है। इसी प्रकार रेलवे, सुरंग और फोर-लेन के लिए भी आप लोगों को बहुत बड़ा अमाउंट मिला है। लेकिन आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी उन विषयों की तरफ ध्यान दें। यह तो अभी बंद होनी है अभी इसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। यह 31 मार्च के बाद का विषय है, जो आप बोल रहे हैं। लेकिन यह बताइए यह तो बंद नहीं हुई। तीन वर्ष तक तो आपका सब कुछ ठीक चलता रहा। अगर सारी चीजें इसी पर डिपेंड करती हैं तो क्या कारण है कि कर्मचारियों का 13 प्रतिशत डी0ए0 ड्यू है? अगर सारी चीजें 31 मार्च से पहले ठीक चल रही थीं और केवल आर0डी0जी0 के कारण गड़बड़ हो रही है तो इन तीन वर्षों में आपने 13 प्रतिशत डी0ए0 क्यों नहीं दिया? एच0आर0टी0सी0 की पेंशन है, वह समय पर क्यों नहीं मिलती? मार्च 2024 के बाद जो सेवा निवृत्त हुए हैं, उनको आज तक किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला। फिर भी आप अपने हर भाषण में कहते हैं कि 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर हो जाएगा। अब जहां भी जाते हैं, वहां जाकर बोलते हैं कि इस योजना का पैसा हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल से मिलेगा, यह योजना 1 अप्रैल से

17-02-2026/1600/AG/MD/2

लागू होगी। आप हिमाचल प्रदेश के लोगों को अप्रैल फूल बना रहे हो। आप हर किसी को 1 अप्रैल की तारीख बताते हो और फिर लोगों को मूर्ख बनाते हो। इसी प्रकार आप बोलते हो

कि वर्ष 2032 में यह देश का सबसे अमीर प्रदेश होगा। आपकी यह सारी बातें केंद्र भी सुनता है, आम जनमानस भी सुनता है, एजेंसियां भी सुनती हैं। जब वे सुनती हैं कि प्रदेश वर्ष 2027 में अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा और वर्ष 2032 तक हिंदुस्तान का सबसे अमीर प्रदेश होगा तो उनको लगता है कि इन्हें ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है। इनके बिना भी काम अच्छा चल रहा है। जिस प्रकार की बातें आप करते हैं क्या कारण है? यही कारण है। अच्छा मान लीजिए, आर0डी0जी0 बंद होने के कारण स्थिति सीरियस हो गई। मुझे बताइए मुख्य मंत्री जी, आर0डी0जी0 बंद होने के बाद अगर इतना बड़ा दुख और परेशानी हो गई तो चेयरमैन बनाने की क्या जरूरत थी? आर0डी0जी0 बंद होने के अगले दिन आपने मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन बनाए। इसका कारण बताएंगे? उसके बाद गाड़ियां जो पहले किसी को नहीं मिलती थी ए0पी0एम0सी0 में नौ नई स्कॉर्पियो दी गई। इससे आपकी हालत का पता कैसे चलेगा कि आप दुखी हैं? अगर आप हमें कन्वेंस करना चाहते हैं कि आप दुखी हैं, वैसे आप सुखी हैं। लेकिन आपका जो सिस्टम है जीने का, रहने का, ऐश करने का उसमें तो किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जहां आपको जवाब देना है वहां स्पष्ट और स्पेसिफिक जवाब होना चाहिए कि यह चीज बंद हुई है इसके कारण प्रदेश को यह नुकसान हो रहा है और मैं इसकी भरपाई के लिए यह कदम उठा रहा हूं। जब आपकी बातें तर्क के साथ होंगी जब आपकी बातों में दम होगा, तो निश्चित तौर पर हम आपके साथ खड़े हैं। हम प्रदेश के लिए खड़े हैं। आप कोई स्पेशल कैटेगरी के हिमाचली नहीं हैं। हम भी वही हिमाचली हैं जो आप हैं। यहां कोई कह रहा है कि मुख्य मंत्री जी हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं,

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी---

17.02.2026/1605/केएस/एजी/1

श्री बिक्रम सिंह जारी ---

ताकि ऊपर से कोई इनकी फोटो खींच लें और बताए कि इनसे बड़ा हिमाचली कोई नहीं है। मुख्य मंत्री जी, हम भी सनातनी है, आप भी सनातनी हैं लेकिन आदरणीय जय राम ठाकुर जी ने जिस समय शपथ ली थी, इन्होंने पंडितों को पूछा और अच्छे मुहुर्त में इनकी

शपथ हुई थी इसलिए पांच साल इनका अच्छा काम चला। आपको हम पहले दिन से बोल रहे हैं, समाचार पत्र भी पहले दिन से बोल रहे हैं कि आपने ठीक मुहुर्त में शपथ नहीं ली जिस कारण भी यह सारी की सारी गड़बड़ हो रही है। आप माता के चरणों में रहते हैं, इन चीजों को माना करो। सभापति महोदय, मैंने केवल दो बातें ही नहीं बताईं, चेयरमैनों और स्कॉर्पियो की ही बात नहीं की, आपने ऑफिसर्ज़ के पैसे भी बढ़ाए हैं क्योंकि उनको नैट की बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये पैसे भी आपने उनके इसके बाद बढ़ाए हैं। आर0डी0जी0 के प्रति आपकी गम्भीरता के ऊपर प्रश्नचिन्ह् लग रहे हैं इसलिए इन सारी चीजों के बारे में चिंतन करिए। आप सच्चे दिल से बोलें कि मैं सारा सिस्टम ठीक करुंगा। सभापति महोदय, कल इनको एडवोकेट जनरल के बारे में बोला तो ये खड़े हो गए और कहने लगे कि आप क्या बोल रहे हैं? आपके जमाने में इतने थे और मेरे जमाने में इतने हैं। सर, आपने जो फौज पाली है, क्या उसने कभी कोई केस भी जीता है? आपने जो फौज पाल रखी है, आप हमेशा दिल्ली और पंजाब के, बाहर के वकील ला कर अपने लोगों के साथ खड़ा करते हो। उसके बाद आप केस लड़ते हो और उसमें भी फेल होते हो। अभी मुख्य संसदीय सचिवों का रिज़ल्ट आने वाला है। उसमें भी आपने फेल होना है। आप यदि यहां पर तर्क के साथ बात रखेंगें, जिस दिन आप सच्चे दिल से यहां पर विषय रखेंगे कि हम इन-इन विषयों को रैक्टिफाई करेंगे तो निश्चित तौर पर हिमाचल के लिए जो लड़ाई आप लड़ेंगे उसमें हम भी शामिल होंगे। सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

17.02.2026/1605/केएस/एजी/2

मुख्य मंत्री : सभापति महोदय, मैंने इनको कई बार समझाया। सदन में भी समझाया और अभी भी समझाया । ये कहते हैं कि गाड़ियां बढ़ा दीं या कुछ और बढ़ा दिया, अब ये हो गया, अब वो हो गया। हमने 17 हजार करोड़ रुपये में अच्छा प्रबन्धन किया। 54 हजार करोड़ रुपये वाला प्रबन्धन नहीं किया। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जब विधायकों की सैलरी बढ़ी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। विधायकों की सैलरी बढ़ी तो बोर्ड/कॉर्पोरेशन्ज़ कई-कई करोड़ रुपये इन्कम टैक्स देते हैं। सरकारी विभाग में जो लोग होते हैं, वह चीज़ हैं, उससे ट्रेज़री में पैसा आता है। बोर्ड/कॉर्पोरेशन में ट्रेज़री से कोई पैसा

नहीं आता। आप तो मंत्री रहे हैं, आपको यह समझना चाहिए। बोर्ड/कॉर्पोरेशन्ज़ के चेयरमैन कौन होते हैं और किनको बनाया जाता है? जिनमें हम हर साल चार और पांच करोड़ रुपये इन्कम टैक्स देते हैं।और जो आप ए0पी0एम0सी0 की गाड़ियों की बात कर रहे हैं, यह नियम है कि कोई गाड़ी अगर 15 साल पुरानी हो जाएगी उसके बाद उसको बदला जाएगा। जो आप इंटरनैट की बात कर रहे हैं, जो अधिकारियों/कर्मचारियों को लैंड लाइन टैलिफोन अलाउंस मिलता है उसको खत्म करके अगर इनको इंटरनैट का दे रहे हैं तो गलत बात नहीं है। जिन चीजों को आप राजनीतिक लाभ के लिए कह रहे हैं, आप कंजंप्शन की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है आप कह रहे हैं लेकिन हमने खर्चे कहां कम किए हैं, वह मैं आपको बताता हूं और कल भी बताऊंगा। 3800 करोड़ रुपये ऐसे ही नहीं हुए। इनसे 50 करोड़ रुपये कम होंगे उसका भी हम गौर रखेंगे कि आगे हमने क्या करना है लेकिन जब विधायकों की सैलरी बढ़ती है तो जो और लोग होते हैं जो उस चीज़ में कंट्रीब्यूट करते हैं और हमें लगता है कि सरकार पर इनका दवाब नहीं पड़ेगा, सरकार की ट्रेजरी से उनका पैसा नहीं जाएगा, उनमें अगर चेयरमैन लगते हैं, जैसे मार्किटिंग बोर्ड है, उनके अपने पैसे हैं। वे अपना रेवन्यू जनरेट करते हैं। इसी तरह से जो बोर्ड/कॉर्पोरेशन्ज़ की बात है, बिजली बोर्ड और ट्रांसपोर्ट घाटे के बोर्ड हैं जिनको हम ग्रांट देते हैं और 2000 करोड़ रुपये के करीब उनको ग्रांट जाती है। तो मेरा यह मानना है कि जब बोर्ड/कॉर्पोरेशन्ज़, ए0पी0एम0सी0 आदि काम करते हैं, मार्किटिंग में जाते हैं, देखते हैं, इन चीजों को ध्यान में रखकर आपको बात करनी चाहिए। सरकार की तरफ से कमीशन के मैम्बर बनते हैं। सरकार की तरफ से ओ0एस0डी0 लगते हैं, सरकार की तरफ से आपके एडवाइज़र लगते हैं जो सचिवालय में बैठते हैं। चेयरमैन बोर्ड हमेशा बोर्ड/कॉर्पोरेशन्ज़ के

17.02.2026/1605/केएस/एजी/3

होते हैं जो अपना रेवन्यू जनरेट करते हैं। सरकार की तरफ से उनको कोई पैसा नहीं दिया जाता। आप यह चीज़ समझिए। यह कहना कि इसमें इतना खर्च हो रहा है, उसमें इतना खर्च हो रहा है वह उनकी अपनी सामर्थ्य है। कई बोर्ड/कॉर्पोरेशन्ज़ तो यह कहते हैं कि

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

17.02.2026/1610/av/As/1

मुख्य मंत्री -------- जारी

हम अपना एडवांस डी0ए0 देना चाहते हैं। ...(व्यवधान) मैं आपको (श्री बिक्रम सिंह) अभी बता रहा हूं और आप सुन लीजिए। ...(व्यवधान) आप गौर से नहीं सुनते इसलिए आपकी इस प्रकार की कन्फ्यूजन है। हमारे कई ऐसे बोड्‌र्ज और कॉरपोशन्ज हैं जिन्हें मुझे रोकना पड़ता है। हमारी जैसे फूड एण्ड सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन है, उनका कहना है कि हम अपना पूरा 13 प्रतिशत डी0ए0 देना चाहते हैं क्योंकि हमें बहुत ज्यादा इन्कम टैक्स लग रहा है। इसी तरह से वन निगम का कहना है लेकिन हम कहते हैं कि अभी हमने सरकारी विभागों का डी0ए0 नहीं दिया है इसलिए आप रुक जाइए वरना वे भी इसके लिए मांग करेंगे। ...(व्यवधान) मैं आपको आगे भी बता रहा हूं। कोऑपरेटिव बैंक 54 करोड़ रुपये इन्कम टैक्स दे रहा है। इसी तरह से कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक 20 करोड़ रुपये इन्कम टैक्स दे रहा है। ये लोग अपने बोर्ड से पास करके आगे जाते हैं, बाकी पोलिटिकल सेक्रेटरी या कई लोग मुख्य मंत्री तथा सरकार द्वारा ऑर्गेनाइज करने के लिए लगाने पड़ते हैं। इन पर कितना खर्चा होता है, मैं इस बारे में आपको बजट के दौरान बताऊंगा। हम छोटे सुधारों में तो जाएंगे ही परंतु मैं आपको बजट के दौरान बताऊंगा कि हम अपने यहां कितने बड़े-बड़े सुधार करने जा रहे हैं। लेकिन हमने जो वास्तविक सुधार किए हैं, मैं उसका भी उल्लेख करना चाहूंगा और यही मैं कहना चाहता हूं। मैं माननीय श्री बिक्रम सिंह से यही कहना चाहता हूं कि जब आप जोश के साथ बोलते हैं तो थोड़ा सोच कर बोला कीजिए।

17.02.2026/1610/av/As/2

सभापति : माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह, अब आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री बिक्रम सिंह : सभापति महोदय, यहां पर सुधारों का विषय चल रहा है न कि लुटाने का विषय चल रहा है। बोर्ड और कॉरपोरेशन हिमाचल प्रदेश के हैं। उनमें जो कुछ हो रहा है वह हिमाचल प्रदेश सरकार का है। अगर उसके ऊपर भी किसी प्रकार का कट लगाया जा सकता है तो वह लगाना चाहिए। मेरा यह कहने का मतलब है और वहां पर जितना पैसा

बच सकता है, उसको बचाना चाहिए। आप यहां पर पैसे बचाने की बात कीजिए बजाय इसके कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को डाउन करने की बात करें।

17.02.2026/1610/av/As/3

सभापति : माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप बोलिए।

श्री जय राम ठाकुर : सभापति महोदय, हमारे माननीय सदस्य जो यहां से बोल रहे हैं उसके संदर्भ में मुख्य मंत्री जी ने जवाब देना है और जवाब देते समय सारी बातों का समावेश हो सकता है। इस तरह से हर जगह इंटरवीन करना, मुझे लगता है कि उचित नहीं है।

यहां पर प्रकाश राणा जी बोल रहे थे परंतु उनको कंक्लूड नहीं करने दिया गया। उनका 15 मिनट्स का समय था परंतु वह पूरा नहीं होने दिया और अगले वक्ता का नाम पुकारा गया। यहां पर कई वक्ता 25-25, 30-30 मिनट्स भी बोले हैं।

यहां से मुख्य मंत्री जी और उप-मुख्य मंत्री जी किसी जरूरी बैठक के लिए चले गए थे। लेकिन जब यहां पर उप-मुख्य मंत्री जी बोल रहे थे तो इन्होंने मेरा बहुत ज्यादा जिक्र किया। इन्होंने मेरी सीट का जिक्र भी किया जिस पर वे खुद 5 वर्ष तक विराजमान रह चुके हैं। मैं यहां पर यह जरूर कहना चाहूंगा कि आपके लिए यह एक व्यवस्था बन गई है। आपकी बातचीत से तो यह एक तरह से भड़ास निकल रही है जिससे साफ जाहिर होता है कि अंदर-अंदर कुछ चल रहा है और वही अब बाहर भी निकल रहा है। आप शायद उसको अब रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं परंतु वह नहीं रुक पा रहा है। उसमें चाहे आपकी तीन वर्ष के कार्यकाल की मण्डी की रैली रही है। आपने वहां पर भी कहा कि 'सुक्खू जी' ऐसे नहीं चलेगा, रात के अन्धेरे में निपटा देंगे और मुझे तो लगता है कि अगर ऐसे हालात रहें तो आप सभी निपट जाएंगे जोकि हमारे सामने बैठे हैं।

आप यहां पर संविधान की किताब लेकर आए। संविधान की किताब लेकर आपके एक नेता पूरे देशभर में घूमे जिसका परिणाम आप सबके सामने है। उन्होंने उसको कितना पढ़ा है; मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि हमें तथ्यों

को समझना पड़ेगा। आपने अगर अन्याय की बात की है तो मैं उस बारे में एक ही बात कहना चाहता हूं कि देश के बहुत बड़े अर्थ शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बनें।

टी सी द्वारा जारी

17.02.2026/1615/टी0सी0वी0/डी0सी0-1

श्री जय राम ठाकुर...... जारी

वे 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे। उनके कार्यकाल में 12वां और 13वां फाइनेंस कमीशन आया और हिमाचल को 18000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस की सरकार के समय में जहां हिमाचल प्रदेश को 18000 करोड़ रुपये आर0डी0जी0 के रूप में मिले वहीं एन0डी0ए0 सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 14वें और 15वें वित्तायोग के दौरान हिमाचल प्रदेश को 78000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। यह 60000 करोड़ रुपये का अंतर है यानी 60000 करोड़ रुपये अधिक प्राप्त हुए जिसका आप जिक्र तक नहीं करते हैं। मैं यह तथ्य इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि विषय एकतरफा जा रहा है और दूसरी ओर की बात सुनी नहीं जा रही है।

सभापति महोदय, मैं बार-बार यह कह रहा हूं कि इंडिकेशन बिल्कुल स्पष्ट थी। राजनीतिक लोगों को इसका आभास हो जाता है। आप तो छात्र जीवन से राजनीति में हैं, आपको इस बात का आभास क्यों नहीं हुआ कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो प्रेजेंटेशन में बताया था कि टेपरिंग हो रही है और यह आगे उस दिशा में जा रही है जहां आर0डी0जी0 समाप्त होनी है। जब आर0डी0जी0 मिलती थी तब भी आप मोदी जी और जय राम ठाकुर को गाली देते थे और जब आर0डी0जी0 बंद हो रही है तब भी उन्हें ही दोष दे रहे हैं। आखिरकार आपकी भूमिका क्या है।

सभापति महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। आप हमसे पूछते हैं कि आपके समय में जो 94000 करोड़ रुपये आर0डी0जी0 का मिला, उसका हमने क्या किया। सभी सरकारों ने ऋण लिया है और ऋण का पुनर्भुगतान तथा ब्याज चुकाना आवश्यक होता है। हमने वर्ष 2018 में 113 प्रतिशत पे-आउट किया है यानी ऋण चुकाने में 6485 करोड़ रुपये दिए। वर्ष 2019 में 7499 करोड़ रुपये का ऋण चुकाया गया जो 149.6 प्रतिशत पे-आउट

रेट था और अब तक का सबसे अधिक था। ...(व्यवधान) Let me speak please. आप अपनी बात बाद में रख लेना। कोविड के दौर में वर्ष 2020 में 7438 करोड़ रुपये चुकाए गए जो 61.34 प्रतिशत रहा। इसके बाद वर्ष 2021 में 7764 करोड़ रुपये ऋण के रूप में चुकाए गए जो 93.4 प्रतिशत था। वर्ष 2022 में 9090 करोड़ रुपये वापस किए गए जिसका पे-आउट रेट 91 प्रतिशत रहा। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के 5 वर्ष के

17.02.2026/1615/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

कार्यकाल में ऋण और ब्याज का औसत पे-आउट रेट 95 प्रतिशत रहा। जबकि आपकी सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल में पे-आउट रेट केवल 60 प्रतिशत रहा। अब आप स्वयं गणना कर सकते हैं कि किस का कार्यकाल बेहतर रहा। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय, यदि हम ऋण की बात करें तो वर्ष 2012 से वर्ष 2017 तक 5 वर्षों में लिया गया ऋण 66 प्रतिशत था। हमारी सरकार में वर्ष 2017 से वर्ष 2022 तक यह 41 प्रतिशत रहा। इसके बाद वर्ष 2022 से वर्ष 2024 तक जब से आपकी सरकार आई है, 2 वर्षों में यह ऋण 140 प्रतिशत तक पहुंच गया जिसने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह पूरा रिकॉर्ड आपके नाम दर्ज हुआ है। आपने यहां पर

श्रीमती एन0एस0 द्वारा जारी ...

17-2-2026/1620/एन0एस0-डी0सी0/1

श्री जय राम ठाकुर ----जारी

एक नोटिफिकेशन का जिक्र किया है। एक नोटिफिकेशन दिनांक 15 मार्च, 2024 की है और इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने कल भी कहा कि 30,000 रुपये से सीधा 1.30 लाख रुपये कर दिए और इसको हम रिकॉर्ड पर लाए हैं। आपने 30,000 रुपये से 1.30 लाख रुपये बढ़ाए हैं। हम इसको गलत बोलें या ठीक बोलें तो वह बात अलग है लेकिन आपने बढ़ाया तो है। ये इफैक्टस भी आपके रिकॉर्ड में जाने चाहिएं। मैं यही कहना चाहता हूं क्योंकि गलत बातें रिकॉर्ड का हिस्सा बनें तो उचित नहीं होगा। दूसरा, with due apologies मैं इतना कहना चाहता हूं कि एक माननीय सदस्य ने यहां पर कहा है और

शायद वे अपने आपको काफी विद्वान मानते हैं तथा उन्होंने मेरे एक सदस्य के प्रति एक शब्द का इस्तेमाल किया है कि 'अधजल गगरी छलकत जाए' that should not be part of the record. यह मुहावरा है लेकिन यह अच्छे प्रसंग में नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि मुहावरा है लेकिन यह अच्छे अभिप्राय में नहीं है। यह किसी के लिए व्यक्तिगत रूप से आक्षेप है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति सारी दुनिया का विद्वान है और वही जानता है तथा दूसरा कोई कुछ नहीं जानता है। ...(व्यवधान) This is part of the record. आप इसको चैक कर लें, यह रिकॉर्ड का पार्ट है। ...(व्यवधान) अगर जनरल बोला है तो किसके लिए बोला है?

सभापति : जनरल बोला है तो इसको देख लेंगे और अगर व्यक्तिगत बोला होगा तो इसको रिमूव कर देंगे।

श्री जय राम ठाकुर : जिसके लिए भी बोला है यह अपमानजनक है। यह शब्द चुने हुए विधायक की गरिमा के खिलाफ है। किसी को जानकारी ज्यादा हो सकती है और किसी को कम हो सकती है लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर इसे रिकॉर्ड में नहीं रखना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं, धन्यवाद।

सभापति : मुख्य मंत्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं?

17-2-2026/1620/एन0एस0-डी0सी0/2

मुख्य मंत्री : सभापति महोदय, आजकल पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी गणित बहुत करने लग गए हैं। ये आजकल परसेंटेज निकाल कर लाने लग पड़ हैं। जब अमाउंट नहीं बताते तो परसेंटेज बताते हैं। ...(व्यवधान) इन्होंने कहा कि 14वें वित्तायोग में इतने हजार करोड़ रुपये ज्यादा मिल गए हैं और 15वें वित्तायोग में 48,000 करोड़ रुपये ज्यादा मिल गए लेकिन आपको तो 54,000 करोड़ रुपये ज्यादा मिले हैं। आप उसके लिए बात नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आपको क्यों मिला था? आपको इसका पता है। माननीय उप-मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि इस संविधान के अनुसार आपको यह अधिकार दिया गया है कि जो आपके घाटे, आय और व्यय में अंतर है आपने उसको पाटना है इसलिए ज्यादा

मिला था और आपने उसको नहीं किया। मैं इनके सामने कुछ तथ्य कल लाऊंगा और मैं उसके बारे में अभी नहीं बोलना चाहता हूं। इनको इसलिए दिया गया था और उसको कोई मोदी जी ने नहीं दिया था। ...(व्यवधान) हमारा जो राजस्व घाटा ज्यादा हुआ उसकी पूर्ति के लिए 14वें व 15वें वित्तायोग से आर0डी0जी0 मिली। उस समय घाटा इतना ज्यादा था कि उसकी पूर्ति के लिए मिलता था। संविधान की बात जो यहां पर कही गई है तो इस संविधान में यही लिखा है। इसलिए आपको भी संविधान के अनुसार जानकारी रखनी चाहिए। माननीय उप-मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि आर0डी0जी0 हमारा हक है। मैं बार-बार कह रहा हूं कि यह कोई खैरात नहीं है, यह हमारा हक है और इसको संविधान में लिखा है। ...(व्यवधान) यह ग्रांट ही है और मैं हक बोल रहा हूं। उसी हक की बात आपको कल बताएंगे कि किस सेक्शन के तहत हक है। हम वह भी बताएंगे। इसलिए तो बोल रहे हैं। श्री जय राम ठाकुर जी ने कहा कि किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप किया गया है तो यह एक मुहावरा है जो भवानी सिंह पठानिया जी ने कहा है कि 'अधजल गगरी छलकत जाए।'

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

17.02.2026/1625/RKS/एचके-1

मुख्य मंत्री जारी...

जब आपके पास आधी-अधूरी जानकारी होगी तो स्वाभाविक रूप से तथ्यों की प्रस्तुति भी अधूरी रह जाएगी। हमने किसी व्यक्ति के लिए टिप्पणी नहीं की है। जो चीज सही है हमने वही कहा है। माननीय नेता प्रतिपक्ष यहां आंकड़े प्रस्तुत कर रहे थे कि वर्ष 2007; वर्ष 2017-18 में 6 हजार करोड़ रुपये, 7 हजार करोड़ रुपये, 8 हजार करोड़ रुपये और वर्ष 2022-23 में 9 हजार करोड़ रुपये वापिस किये। आपको पता होना चाहिए कि वर्ष 2023 के अंतिम तीन महीने हमारी सरकार के थे और उस अवधि का लोन हमने ही वापिस करना है। आप भी मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री रहे हैं और यह आंकड़ा आपने परसेंटेज के हिसाब से बताया है। जब 76 हजार करोड़ रुपये के ऋण पर परसेंटेज के आधार पर गणना की जाती

है तो आंकड़े उसी तरह सामने आते हैं। हमने आपके कार्यकाल के 26 हजार करोड़ रुपये अभी तक वापिस किये हैं जबकि हमने 23 हजार करोड़ रुपये का ऋण लिया है। हम बाकी आंकड़े आपको कल बताएंगे। आपने जो लोन लिया है वह अलग है। आप उसके बारे में नहीं बता रहे हैं कि हमने इतना लोन लिया है। आपने 45 हजार करोड़ रुपये लोन लिया और 36 हजार करोड़ रुपये चुकाया। आपने लोन लिया और वापिस भी किया। उसके बावजूद भी आपके पास 70 हजार करोड़ रुपये शेष था। आपके पास 54 हजार करोड़ रुपये आर0डी0जी0 और 16 हजार करोड़ रुपये जी0एस0टी0 कंपनसेशन के रूप में उपलब्ध थे। यदि उस समय वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित किया होता तो जब आप 48 हजार करोड़ रुपये के लोन के साथ आगे बढ़े तो आप उस लोन को 48 हजार रुपये से कम करके 20 हजार करोड़ रुपये तक ला सकते थे। आप 54 हजार करोड़ रुपये की आर0डी0जी0 से 28 हजार करोड़ रुपये दे सकते थे और 16 सौ करोड़ रुपये और लोन ले सकते थे। आपको एडिशनल बोरिंग मिलती रही। हमने अच्छा प्रशासनिक व्यवस्था इसलिए की क्योंकि हमने आर्थिक हालात पहले ही भांप लिये थे। आप उस समय का वीडियो निकालना मैंने पहले ही बोला था कि प्रदेश की हालत ठीक नहीं है। उस समय श्रीलंका में बहुत बड़ा क्राइसिज चल रहा था अैर मैंने कहा था कि हमारे प्रदेश की हालत भी श्रीलंका जैसी होने वाली है। हमने इस परिस्थिति को संभाला और फालतू के शिक्षा संस्थानों

17.02.2026/1625/RKS/एचके-2

को बंद करवाया। आज उसी एजुकेशन, टूरिज्म और हैल्थ पॉलिसी में हमारी पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही है और हम 17 हजार करोड़ रुपये की वित्तीय सीमा में आगे भी बढ़ रहे हैं। मैं आप पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। आप महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर तो बोल रहे हैं लेकिन आप आर0डी0जी0 पर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। आर0डी0जी0 हमारा अधिकार है और इस अधिकार की लड़ाई के लिए कांग्रेस की सरकार पीछे नहीं हटेगी। आप नेता प्रतिपक्ष है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। आप लोगों को इस संबंध में प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी से स्पष्ट बात करनी होगी। अगर हम 17 तारीख से पहले प्रधान मंत्री

जी से बात करते हैं तो आर0डी0जी0 को पुनः बहाल किया जा सकता है। इसलिए हम आपसे यह बात कर रहे हैं। हम आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं। जहां तक चेयरमैनों की तनख्वाह की बात है यह उनका बोर्ड तय करता है। अगर बोर्ड 5 करोड़ रुपये इंकम टैक्स दे रहा है तो वह उसे अपने खर्चों में शो करेगा और उसके अनुसार अपने निर्णय ले सकता है। बोर्ड ऑटोनोमस बोडी है। ...(व्यवधान) यह डिसिजन बोर्ड करता है। हमारे पास तो वे फाइल को अनुमोदन के लिए भेजते हैं। अगर बोर्ड इंकम टैक्स ज्यादा दे रहा होगा तो ज्यादा तनख्वाह बढ़ा देता है। अगर बोर्ड घाटे में है तो उन चेयरमैनों की सैलरी भी 15 या 30 हजार रुपये ही है। जब आप किसी विषय पर चर्चा करते हैं तो हमें उसका उत्तर स्पष्टता से देना पड़ता है। ठाकुर साहब आपने जो परसेंटेज बताई है उसे मैं पूरे आंकड़े के साथ कल सदन में बताउंगा। आपने अमाउंट क्यों कम बताया? आपने जितना पैसा वापिस किया है उतना पैसा लिया भी है। आपने ज्यादा लोन लिया है। ...(व्यवधान) आप अभी बैठ जाइए। आप मुझे बोलने दीजिए। ...(व्यवधान) मैं भी तो यही कह रहा हूं।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

17.02.2026/1630/बी.एस./एच.के.-1

मुख्य मंत्री जारी..

(...व्यवधान...)

आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने बहुत अच्छी बात बोली, आपने इनको बोलने का मौका नहीं दिया परंतु ये आजकल बोल लेते है। आप बगैर अनुमति के ही बोल लेते हैं। आपने अच्छी बात की कि हमने 40 हजार करोड़ रुपये लिया और उस में से 38 हजार करोड़ रुपये वापस किया। इन्होंने यह तो स्वीकार किया। परंतु आपने आर0डी0जी0 का क्या किया? जी0एस0टी0 कंपनसेशन का क्या किया? उसका हिसाब आप दे दीजिए। सभापति महोदय, इन्हें आर0डी0जी0 और कंपनसेशन सैस का भी बताइए, उसके लिए इन्हें बोलने का स्पेशल मौका दीजिए, धन्यवाद।

सभापति : अब इस चर्चा में लोक निर्माण मंत्री जी भाग लेंगे।

श्री जय राम ठाकुर : सभापति महोदय, मुझे कुछ कहना है और बहुत संक्षिप्त कहना है।

सभापति : ठाकुर साहब, ये यहां से बोलेंगे आप वहां से बोलेंगे ऐसे दोनों तरफ से चलता रहेगा। कल आपको बोलने के लिए स्पेशल समय दे दिया जाएगा। आप अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री जय राम ठाकुर : सभापति महोदय, पिछले तीन सालों से हिमाचल प्रदेश में विकास पर पूर्ण विराम लगा है, खुले हुए और चले हुए संस्थान बंद किए गए हैं और हमारे 5 साल में हिमाचल प्रदेश में सड़के बनी, पुल बने, पानी की स्कीमें बनी। हमारी कितनी योजनएं हैं परंतु आपकी तरफ से आपके ही यहां जो माननीय सदस्य बैठे हैं ये 3 साल में तीन योजनाओं का जिक्र नहीं कर सकते हैं। हमारी योजनाएं जुबान पर भी है और लोगों के जहन पर भी हैं।

सभापति : ठाकुर साहब, यह तो बजट भाषण में भी आ जाएगा।

श्री जय राम ठाकुर : इन्होंने पूछा कि आपने उस पैसे का क्या किया?उस पैसे से हमने लगभग 4,000 किलोमीटर सड़कें बनाई, पेयजल योजनाएं बनाई, हर घर में पानी का नल दिया और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में सहारा योजना, हिमकेयर योजना, जनमंच उसके बाद गृहिणी सुविधा योजना, शगुन योजना और मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना लोगों को दी। आप दो योजना को जिक्र तो करिए।

17.02.2026/1630/बी.एस./एच.के.-2

माननीय सभापति महोदय, हमने काम किया है और लोग उस काम को याद कर रहे हैं। आप हर बार मत पूछा करिए नहीं तो हमें फिर से बोलना पड़ेगा।

सभापति : अब लोक निर्माण मंत्री जी चर्चा में भाग लेंगे।

लोक निर्माण मंत्री : सभापति महोदय, आज हम एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर सदन में चर्चा हो रही है और अभी हम 2026 में हैं मगर मैं 2037 की परिकल्पना कर रहा हूं और जब मेरी उम्र तकरीबन 50 वर्ष की होगी उस समय की परिकल्पना करते हुए मैं आज के संदर्भ में यह बात कर रहा हूं कि आज जो नियम-102 के

तहत प्रस्ताव लाया गया है, रिवेन्यू डिफिसिट ग्रांट के ऊपर उस पर सरकार की ओर से पक्ष रखा गया है और विपक्ष उसमें अपनी सोच आगे रख रहा है। यह विषय आने वाले समय में, जिसको हम कह सकते हैं कि they will have larger and more impactful consequences on the development trajectory of Himachal Pradesh in the times to come.यह कोई आम चर्चा नहीं है, इससे हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों का भविष्य इस चर्चा के ऊपर टिका हुआ है। हमें इसकी गंभीरता को समझना है और मैं जानता हूं की गंभीरता को सब समझते भी हैं। सब अपनी-अपनी बात से परिपेक्ष हैं, सब अपनी-अपनी बात से परिपक्व भी हैं और समझते भी हैं कि हमें इस विषय पर गंभीरता से चर्चा करनी है। मैं इस पर बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि सबने अपनी बातें यहां पर रख दी है सभी आंकड़े भी यहां पर रख दिए हैं कि किस तरीके से हिमाचल जब अस्तित्व में आया या अस्तित्व में जब नहीं भी था जब हिमाचल प्रदेश एक "पार्ट-सी" स्टेट था उसके बाद एक यूनियन टेरिटरी बना। उसके बाद हिमाचल प्रदेश को हमारे प्रथम मुख्य मंत्री डॉ0 यशवंत सिंह परमार जी की वजह से हिमाचल प्रदेश पूरे अस्तित्व में 1971 में आया और उसके बाद जो यह आर0डी0जी0 का सिलसिला शुरू हुआ है

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

17.02.2026/1635/डीटी/एच0के0-1

लोक निर्माण मंत्री जारी...

उसके बारे में सभी प्रबुद्ध माननीय सदस्यों ने अपनी बात को रखा है तो मैं उस पर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता। मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें आज से अगले 20 साल बाद इस माननीय सदन के अंदर उस समय के मुख्य मंत्री जो होंगे, उस समय के जो विधायक होंगे, उस समय का जो विपक्ष होगा, जब वो इसके ऊपर चर्चा करेगा और कहेगा कि एक दौर था जब हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2026 में आर0डी0जी0 बंद हुई थी और आर0डी0जी0 के बारे में जो चर्चा हुई थी उसमें उस समय के मुख्य मंत्री, उस समय के नेता प्रतिपक्ष, उस समय के मंत्री, उस समय के संत्री उनकी क्या बातें इस सदन के अंदर हुई थी, वे बातें उस समय गुंजेगी। वह बातें हिमाचल प्रदेश के राजनीति में गुंजेगी। यहां पर

एक बात माननीय उप-मुख्य मंत्री ने बिल्कुल ठीक कही कि हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया और आज भी उसकी चर्चा हो रही है। उसी तरह यह तो एक ऐसा गंभीर विषय है जिसकी आने वाली पीड़ियां चर्चा करेगी। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इसमें केवल एक विषय नहीं यहां पर तो सभी आर0डी0जी0 के बारे में चर्चा कर रहे हैं मगर इसके साथ-साथ GST Compensation Cess में भी हिमाचल के अधिकारों का हनन हो रहा है और आने वाले समय में उसका नुकसान हमें देखने को मिलेगा, इसलिए उसके बारे में भी हमें चर्चा करनी चाहिए। एक ओर तो बात होती है कि हमें अपने परिवार को छोटा करना है, एक ओर बात होती है कि प्रदेश की जनसंख्या कम होनी चाहिए। इसका रिवार्ड कहां तो हिमाचल प्रदेश मिलना चाहिए और इसके लिए तो केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश को सहायोग मिलना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश ने अपनी जनसंख्या में पहले से ही कंट्रोल किया है। हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर पहले से ही हाई है, इसलिए हमारी जनसंख्या सिमित है। उसका केंद्र सरकार से हमे स्पोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन इसको कंज्यूमर बेस्ड करके हिमाचल को इसका नुकसान हो रहा है। इसके आंकड़े पहले से ही हमारे माननीय सदस्यगण रख चुके है कि जो GST Compensation Cess हमको मिला वह एक समय तक ही मिला मगर अब उसे बंद कर दिया गया है उससे लगातार हिमाचल प्रदेश को

17.02.2026/1635/डीटी/एच0के0-2

नुकसान हो रहा है। हिमाचल प्रदेश को जो आर0डी0जी0 की ग्रांट मिलती है वह प्रदेश के लिए एक मुख्य फांउडेशन है जिसे हम बेडरॉक कहते। क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पर्वतीय राज्य था और एक बार्डर का राज्य भी था उस समय प्रदेश का बार्डर तिब्बत के सा लगता था अब वह अब जो चीन के साथ लगता है। हिमाचल प्रदेश एक आपदा प्रभावित प्रदेश है। पहले भी हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है। प्रदेश के प्रथम मुख्य मंत्री स्वर्गीय डॉ0 यशवंत सिंह परमार जी अखबारों में कई बार आर्टिकल लिखते थे। उस समय के ट्रिब्यून में उनके आर्टिकल छपते थे, उस समय इंडियन एक्सप्रैस अखबार तो था नहीं मगर हिंदी के अखबारों में भी हर दो महिनों में आर्टिकल के द्वारा वे चर्चाएं करते थे कि प्रदेश में

क्या समस्या देख रहे हैं और कैसे हम इन समस्या से कैसे बाहर निकलना है। उस समय भी यह चर्चाएं हुई। उस समय भी उन्होंने जनता का ध्यान इस ओर आकृषित किया और कहा कि किस तरह से हमे इन चीजों से बाहर निकलना है। आज हमें भी उसी परिपेक्ष्य में इन चीजों को देखने की आवश्यकता है। जैसा मैंने कहा कि जो स्पैशल कैटेगरी का दर्जा हमारे प्रदेश को मिला वह यहां कि आर्थिक गतिविधियों पर अधिक लागत और पावती कम हुई है उसी कारण मिला। इसके साथ जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण मंहगा हुआ है। हम सभी जानते हैं कि राजस्व की क्षमता यहां पर सिमित है । हमारे इंकम के रिसार्सिज बहुत लिमिटेड हैं। हमारा जो औद्योगिक सैक्शन है हम सब जानते हैं कि it is merely confined to only few districts of Himachal Pradesh. जो हमारे ऊना जिले का क्षेत्र है या जो बद्दी का क्षेत्र या जो कालाअंब का क्षेत्र है या कोई अन्य क्षेत्र उससे ज्यादा because of the non-availability of land हम अपनी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को नहीं बढ़ा सकते। इन सब चीजों की पूर्ति करने के लिए हिमाचल को यह सहयोग केंद्र सरकार की ओर से एक संवैधानिक स्वरूप में संविधान के अनुछेद 275(1) के अंतर्गत और वित्त आयोग की अनुशंसा के माध्यम से हम लगातार राजस्व घाटा अनुदान मिल रहा है ताकि हमारा राज्य अपने न्यूनतम राजकोषिय दायित्व वेतन, पेंशन, बयाज समाजिक सुरक्षा और बुनियादी

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

17.02.2026/1640/वाई.के.-एन.जी./1

लोक निर्माण मंत्री.......... जारी

सेवाओं को पूरा कर सके। मैं इसमें अडिशनल करना चाहूंगा कि this is not only which is limited to paying of salaries and giving arrears or DA to the employees but this is also expanding into the arena of capital expenditure. आज हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हम बार-बार इस बात का जिक्र करते हैं कि जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था तब यहां पर केवल 200 किलोमीटर सड़कें थीं लेकिन आज लगभग 46 हज़ार

किलोमीटर सड़कें हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी हुई हैं। एक पहाड़ी राज्य होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश में सड़कों का एक बहुत बड़ा जाल बना हुआ है। This is the capital expenditure which have incurred on the developmental trajectory of Himachal Pradesh. यह किसी एक व्यक्ति या किसी एक सरकार का इतिहास नहीं है बल्कि इसके लिए हिमाचल प्रदेश में समय-समय पर बनी सरकारों व नेताओं ने अपना-अपना योगदान दिया है।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात की है। इन परिपेक्ष को देखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि 16वें वित्तायोग की सिफ़ारिशों और केन्द्र सरकार के फैसले के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2026 के बाद राजस्व घाटा अनुदान को बंद कर दिया गया है। सभापति महोदय, यह एक चिंता का विषय है कि जिस तरीके से एक-एक करके जितने भी हमारे देश में constitutional or statutory bodies हैं, उनकी गरिमा को घटाया जा रहा है। जब हम छोटे थे और स्कूल-कॉलेज में पढ़ते थे, तब देखते थे कि जब भी कोई वित्तायोग अपनी सिफ़ारिशें लोकसभा में ले करता था तो उससे पहले महामहीम राष्ट्रपति जी को मिलने जाते थे। वहां जाकर राष्ट्रपति जी को रिपोर्ट दी जाती थी और उसके बाद संसद में ले की जाती थी। आज मुझे एक भी तस्वीर दिखा दीजिए जिसमें 16वें वित्तायोग का प्रतिनिधि मण्डल महामहीम राष्ट्रपति जी को मिलने गया हो। अभी तो यह सिफ़ारिशें केवल लोकसभा के अंदर ले की गई हैं और हमारी केन्द्रीय वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सितारमण जी ने इस रिपोर्ट को अपने बजट भाषण के दौरान पढ़ा है।

17.02.2026/1640/वाई.के.-एन.जी./2

मुख्य मंत्री जी ने सही कहा है कि अभी भी हमारे पास समय है और यदि हम सभी एक आवाज़ में कहें क्योंकि यहां पर हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, कि हमें हमारे हक की लड़ाई लड़नी है। मैंने अपने भाषण की शुरूआत में कहा था कि वर्ष 2037 की परिकल्पना में जो भी लोग इस माननीय सदन में बैठे होंगे, हो सकता है हमारे में

से कुछ होंगे या नहीं होंगे क्योंकि इसे तो जनता निर्धारित करती है, लेकिन इतिहास इसे याद रखेगा कि किन-किन लोगों ने हिमाचल प्रदेश के हक की लड़ाई को लड़ा था और किस-किस ने नहीं लड़ा था।

सभापति महोदय, यहां पर आर्टिकल 275 (1) और आर्टिकल 280 की बात की गई है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार हर पांच वर्ष में एक वित्तायोग का गठन होता है, जिसका मूल दायित्व केंद्र और राज्यों के बीच में करों (राजस्व) के बंटवारे और वित्तीय संबंधों की सिफारिश करना है। मैं केवल हिमाचल प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि पूरे देश में “cooperative federalism” जैसे शब्द भाजपा की सरकार में है ही नहीं और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। This is a very unfortunate event that has occurred in the history of the country और उसका नुकसान हिमाचल प्रदेश को मिल रहा है। हम बार-बार इस बात का जिक्र करते हैं कि हिमाचल प्रदेश भी इसी देश का अंग है। हिमाचल प्रदेश “cooperative federalism” में Union of State का एक अभिन्न अंग है। हमारे अधिकार और देश व प्रदेश की परिकल्पना के विपरीत लगातार कार्य किया जा रहा है।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

अध्यक्ष महोदय, मैं आज चुनाव आयोग की बात नहीं करना चाहूंगा। देश के अंदर जो भी अन्य संस्थान हैं, आज उनको जिस प्रकार से रेडिकेट किया जा रहा है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। यू0जी0सी0 की बात अभी पूरे देश में उठी थी। जिस प्रकार से हमारी statuary bodies को सिस्टेमेटिक तरीके से खत्तम किया जा रहा है

17.02.2026/1640/वाई.के.-एन.जी./3

that is a different debate altogether. आज यदि हम इसके बारे में बात करना शुरू करेंगे तो वह बात कहीं-से-कहीं जाएगी। आज की बात तो केवल हिमाचल प्रदेश के परिपेक्ष में है। इसमें अनुच्छेद 275(1) स्पष्ट रूप से कहता है कि जिन राज्यों के आय

श्री ए0पी0 द्वारा......जारी

17.02.2026/1645/ए.जी./ए.पी/01

लोक निर्माण मंत्री जारी .....

उनके व्यय को पूरा नहीं कर सकती है, उन्हें संसद द्वारा निर्धारित अनुदान देकर इस अंतर को भरा जाएगा। यही राजस्व घाटा का प्रारूप है और आज उसी की अनुपालना इस सदन और देश के अंदर हो रही है और इसमें हम सबको अपनी आवाज उठाने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि 16वें वित्त आयोग का जो basis of analysis है, वह स्पष्ट नहीं है। मैं बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हूं, हालांकि में इकोनॉमिक्स का छात्र जरूर रहा हूं। फिर भी मैं कह सकता हूं कि जिस आधार पर इसको बनाया गया है कि क्यों आर0डी0जी0 ग्रांट हिमाचल प्रदेश को नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि 15वें वित्त आयोग ने भी स्वीकार किया था कि हिमाचल जैसे छोटे राज्यों में स्ट्रक्चरल राजस्व घाटा है और इस कमी को पाटने के लिए आर0डी0जी0 हिमाचल के लिए जरूरी है। लेकिन 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में न तो अलग-अलग राज्यों की आय और व्यय का विस्तृत आंकलन दिया और न ही किसी राज्य-विशिष्ट राजस्व घाटा की गणना दिखाई। बल्कि सभी राज्यों के संयुक्त आंकड़ों के आधार पर एक नाप की टोपी सब प्रदेशों पर, चाहे वह पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो या कर्नाटक हो सभी के ऊपर एक ही फॉर्मूला चला दिया और आज इसी वजह से हिमाचल को नुकसान हो रहा है। माननीय उप-मुख्य मंत्री जी पहले ही कह चुके हैं कि हिमाचल का राजनीतिक जन्म, उसकी भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं। हिमाचल में कितना वन क्षेत्र है, यह सबके सामने है। उस समय क्या हमारी जी0डी0पी0 उतनी नहीं थी जितनी बड़े राज्यों की थी। अगर हम तुलना करें मद्रास प्रेसीडेंसी जिससे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य बने या मुंबई प्रेसीडेंसी जिससे सौराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य बने, तो यह हिमाचल के साथ अन्याय होगा। हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, भाजपा और कांग्रेस को पीछे रखते हुए, हिमाचल प्रदेश की आवाज को, हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों की आवाज को केन्द्र सरकार के समक्ष उठाना की आवश्यकता है और हिमाचल के

हक्कों को वापिस लाने की आवश्यकता है, यह मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, स्टेट शेयर इन सेंट्रल

17.02.2026/1645/ए.जी./ए.पी/02

टैक्स की बात बार-बार हो रही है। हमारा हिस्सा केंद्रीय करों में 15वें वित्त आयोग में 0.830 था, जिसे 16वें वित्त आयोग ने थोड़ा बढ़ाकर 0.914 किया है। वर्ष 2025-26 में 11,500 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित 13,950 करोड़ रुपए, यानी लगभग 2,450 करोड़ रुपए की वृद्धि केवल अनुमानित संग्रह पर निर्धारित करती है। कलेक्शन होगी या नहीं होगी that is in the garb of future.उसके बारे में अभी अनुमान लगाना मैं समझता हूं ठीक नहीं होगा। लेकिन जो 6,000 करोड़ का हमारा घाटा है, इसको हम कैसे पूरा कर सकते है, इस पर हमें चिन्ता करने की आवश्यकता है। अंत में, अध्यक्ष महोदय, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता। हालांकि यहां पर सभी माननीय सदस्यों में लगभग एक-एक घंटे, तीस-तीस मिनट तक अपनी बात रखी है, मगर मैं कुछ ही मिनटों में अपनी बात खत्म करूंगा। इसमें जो मैन आब्जैक्शन 16वें वित्त आयोजग को लेकर आई है, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं। राज्यों की अलग-अलग आय-व्यय का आंकलन जिसके बारे में मैंने जिक्र भी किया है कि 15वें वित्त आयोग ने हिमाचल सहित हर राज्यों के लिए वर्षवार आय-व्यय का विस्तृत अनुमान प्रस्तुत किया था, जबकि 16वें वित्त आयोग ने सभी राज्यों पर एक ही फार्मूला लागू कर दिया। जैसे मैंने आपको कहा कि एक ही टोपी सबके सिर पर लगा दी। वैसे ही आयोग ने यह तर्क दिया कि राज्यों का सम्लित राजस्व घाटा जी0डी0पी0 के 7.8 प्रतिशत से घटकर 6.9 प्रतिशत और आगे 0.3 प्रतिशत तक आ गया है और प्रतिबद्ध व्यय का अनुमान भी कुछ कम हुआ है। इसलिए आर0डी0जी0 की आवश्यकता हिमाचल प्रदेश को नहीं है। लेकिन क्या यह निष्कर्ष और राजस्व घाटे वाले पहाड़ी और आपदा प्रवण राज्य पर भी उतना ही लागू हो सकता है, जैसे किसी बड़े सम्पन्न राज्यों पर हो रहा है।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

17/02/2026/1650/AT/AG/01

लोक निर्माण मंत्री जारी....

मैंने अभी जिक्र किया even in the history if we go वही चीज है। आज अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हम उसी चौराहे पर खड़े हैं। यह मैं एक बात कराना चाहता हूं।

दूसरी बात ignoring of structural weakness, 15वें वित्त आयोग ने स्वीकार किया था कि कुछ राज्यों में स्ट्रक्चरल राजस्व घाटा है जो केवल सब्सिडी या कैश ट्रांसफर से नहीं, बल्कि भौगोलिक और आर्थिक वास्तविकताओं से पैदा होता है। 16वें वित्त आयोग ने इस बात को पर्याप्त महत्व नहीं दिया और न ही ग्रीन बोनस दिया। मुख्यमंत्री जी बार-बार इसका जिक्र करते हैं। क्या यह हमारा कसूर है कि हमारी जनसंख्या कम है? क्या यह हमारा कसूर है कि हिमाचल प्रदेश का फॉरेस्ट कवर आज नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा है? क्या यह हमारा कसूर है कि चाहे बाण के पेड़ है, देवदार के पेड़ हैं या यहां की नदियां, अगर पूरे उत्तर भारत में सबसे ज्यादा पवित्र और साफ जगह है तो वह हिमाचल है? तो हमें इसका सहयोग मिलना चाहिए, समर्थन मिलना चाहिए। लेकिन उल्टा इसकी पेनलाइजेशन हमको करवाई जा रही है यह अतिशयोक्ति है। इसकी लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी है। जो हमारे सात सांसद दिल्ली में बैठे हैं जो वहां तर्क दे रहे हैं कि हम आपको बताएंगे कि पैसा कैसे कम खर्च करना है वह हम निर्णय ले लेंगे। मगर आप हमें यह बताइए कि केंद्र सरकार से अपने अधिकारों की बात हम कैसे रखें। मैं इसे लड़ाई नहीं कहूंगा, बल्कि हिमाचल प्रदेश के अधिकारों के लिए अपनी बात उठाने की बात कहूंगा। इसमें हिमाचल को सही अधिकार के साथ सहयोग मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट भी हैं। शॉर्ट टर्म इंपैक्ट के लिए तो हम सब यहां होंगे, मगर वर्ष 2037 तक जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हिमाचल को मिलेंगे उस समय कौन यहां होगा और कौन नहीं होगा यह भविष्य के गर्भ में है। लेकिन लॉन्ग टर्म इंपैक्ट भी हिमाचल प्रदेश को देखने होंगे।

अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, आज डी0ए0 की बात की जा रही है, वेतन और पेंशन की बात की जा रही है, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन की बात की जा रही है, आज अगर हम किसानों को सोलर पर सब्सिडी दे रहे हैं या गाड़ियां खरीदने पर सब्सिडी दे

17/02/2026/1650/AT/AG/02

रहे हैं मुख्यमंत्री जी ने इसमें पूरा विश्वास जताया है कि as a leader, he has stated that we will try our best to commit to everything that we have done, but still it is a financial implication from which we have to come out. ये हमारे शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स हैं जिनसे हमें आने वाले समय में लड़ना है।

हमारी सी0सी0एस0 स्कीम्स जो केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की बात करना चाहता हूं। विपक्ष बार-बार कहता है कि हिमाचल प्रदेश को एम्स के लिए लगातार पैसा आ रहा है पी0एम0जी0एस0वाई0 के लिए पैसा आ रहा है या पी0एम0 आवास योजना के लिए पैसा आ रहा है। लेकिन यह कोई सौगात नहीं है। जैसा यहां कहा गया, Consolidated Fund of India और अन्य स्कीम्स में, as a federal structure के तहत यह हिमाचल प्रदेश का अधिकार है कि हिमाचल प्रदेश को यह पैसा सड़कों, बिजली और अस्पतालों के लिए आ रहा है। We also must realise that we are also paying 10 per cent contribution in the Centrally Sponsored Schemes.लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि सी0सी0एस0 स्कीम्स में 10 प्रतिशत कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश भी देता है। हम भी इसमें अपना हिस्सा देते हैं। अगर हम आर0डी0जी0 की लड़ाई सही रूप से नहीं लड़ेंगे तो हमारा जो स्टेट शेयर इसमें जा रहा है उसके लिए भी हमें चिंतन करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि ऐसा दिन न आए कि हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो। यह चिंता केवल एक मंत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक 35 वर्षीय युवा के रूप में भी है कि आने वाले 50 वर्षों में, 37 साल में हिमाचल प्रदेश किस दिशा में आगे बढ़े रहा है। यह मैं आपको अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूं। उसके साथ -साथ लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स की बात करें तो प्रदेश में कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने, सड़कों के निर्माण और आय के नए स्रोत बढ़ाने पर हमें किस नजरिये से आगे बड़ाना है यह भी मैं समझता हूं कि एक ट्रेप है, एक विडंबना है कि एक

ओर कहा जाता है कि फॉरेस्ट लैंड की वजह से हिमाचल में ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते that is a problem that we are regularly facing. हिमाचल प्रदेश में इतना पानी और नदियां होने के बावजूद अगर हम अपनी आय बढ़ाने के लिए कदम उठाते हैं तो केन्द्र सरकार ही हमारे खिलाफ उच्च न्यायालय मैं खड़ी हो जाती है। क्या इसके ऊपर आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि इन्हीं विषयों के ऊपर आप हमारी आवाज को उठांए। (**एम.डी. द्वारा जारी**)

17-02-2026/1655/AS/MD/1

लोक निर्माण मंत्री---जारी

हिमाचल प्रदेश में इतना पानी होने के बावजूद, नदियां होने के बावजूद अगर हम अपनी आय बढ़ाने के लिए कदम उठाते हैं तो उसमें केंद्र सरकार ही हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हो जाती है। क्या इसके ऊपर आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप इन विषयों पर हमारी आवाज उठाएं कि हिमाचल प्रदेश की आय को हमने कैसे बढ़ाना है? ये छोटे-छोटे कदम तो हम लेंगे, मगर बड़े कदमों के साथ हम कैसे आगे बढ़ें? हिमाचल प्रदेश में हम अपने आय के स्रोतों को आने वाले समय में कैसे मजबूत कर सकते हैं? इसके ऊपर भी विकासात्मक चर्चा और गंभीर चिंतन होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर ज्यादा बात नहीं कहना चाहता। मैं यही कहना चाहूंगा कि हम सबको इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से, अपनी आत्मा को साक्षी मानते हुए, अपने संविधान को साक्षी मानते हुए पास करना चाहिए ताकि यह आवाज केंद्र सरकार तक जाए कि जब-जब हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ कोई अन्याय होगा तब-तब हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोग और उनके नुमाइंदे एक स्वर में प्रदेश की आवाज को आगे उठाएंगे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उस समय केंद्र में बार-बार यह बात कही जा रही है कि आपके ऊपर दबाव है, आपके ऊपर दबाव है। मगर आप यह सोचिए कि आपकी आने वाली पीढ़ियां क्या इसके लिए आपको माफ करेंगी? क्योंकि उस समय आप दबाव में थे इसलिए आपने हिमाचल की आवाज नहीं उठाई यह बात मैं समझता हूं कि सही नहीं है। उस परिप्रेक्ष्य से हमें इसे समझने की आवश्यकता है। अंत में अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि :-

वक्त की ठंडी हवाओं से डगमगाएंगे नहीं, वक्त की ठंडी हवाओं से डगमगाएंगे नहीं

किसी फैसले से अपने सपनों को मिटाएंगे नहीं

जो हक है हिमाचल का वह लेकर ही दम लेंगे, हम साथ हैं

इसलिए किसी भी संकट से हम कभी डरेंगे नहीं

जय हिंद जय हिमाचल।

17-02-2026/1655/AS/MD/2

अध्यक्ष : इससे पहले कि मैं अगले पार्टिसिपेंट को बुलाऊं अभी 2 मिनट बचे हैं और मेरे पास अभी 17 माननीय सदस्यों की सूची है। हमारे प्रयास करने के बावजूद भी 10 से 12 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट, यहां तक कि 20-22 मिनट तक माननीय सदस्यों के उद्बोधन हुए हैं, फिर भी मुझे संतुष्टि का माहौल नजर नहीं आता। 20 मिनट, 22 मिनट, 30 मिनट बोलने के बाद भी संतुष्टि नहीं है, तो यह मेरा तो कसूर नहीं है। लेकिन 5 to 10 minutes are enough for this debate for each Member. Anyway आप 17 सदस्य हैं मल्टिप्लाई बाय 10 या 12 मिनट तो 170 मिनट बनते हैं और अगर 12 मिनट से ऊपर हुए तो और ज्यादा मिनट हो जाएंगे। इसलिए माननीय सदन की बैठक 3 घंटे बढ़ाई जाती है। अब माननीय सदन रात 8:00 बजे तक चलेगा। otherwise बताओ if you will limitize yourself in your viewpoint certainly I will ...(Interruption) अब बताइए, माननीय हर्षवर्धन चौहान जी।

संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री) : सर, हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो। जैसे आपने कहा कि विधायक लिमिट में बोलें 10-15 मिनट पर्याप्त हैं। अभी थोड़ा रिपीटेशन भी हो रहा है अध्यक्ष महोदय। अगर आप इसे 7 बजे तक कर दें तो वह भी पर्याप्त है। 8 बजे तक कर दें मुझे कोई एतराज नहीं है

अध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक का रात 8:00 बजे तक बढ़ाई जाती है। अब मैं आग्रह करूंगा माननीय सदस्य डॉ0 हंस राज and I hope you will carry the words of Shri Vikramaditya Singh.

डॉ0 हंस राज : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है जो यह नियम-102 के तहत विषय माननीय सदन में लाया गया है, माननीय हर्षवर्धन जी खुद विषय लगाकर बाहर चले जाते हैं। वे मुझे बहुत सीरियस दिखते हैं। जिस तरह की डिबेट यहां चली है उसमें आपने ठीक कहा वैसे जब हम लोग यहां कल चर्चा कर रहे थे तो आप ही ने कहा था कि माननीय राज्यपाल साहब का जो अभिभाषण हुआ, जो पढ़ा गया और समझा गया, उसमें आपने कहा था कि आर0डी0जी0 एक महत्वपूर्ण विषय है। तो इसमें खुलकर बोलो और अपने विषय स्पष्ट रूप से रखो तो मुझे नहीं लगता आपको इसमें समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए--

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी---

17.02.2026/1700/केएस/एस/1

डॉ0 हंस राज जारी ---

उसमें आपने कहा कि आर0डी0जी0 महत्वपूर्ण विषय है तो इसमें खुलकर बोलो और विषय रखो। मुझे नहीं लगता कि इसमें टाइम बाउंड करना चाहिए। अगर रात के 12.00 भी बजते हैं तो बजाने चाहिए, क्या दिक्कत है? क्योंकि प्रदेश के हितों का विषय है और अगर हम गम्भीर हैं तो समय नहीं देखना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, जो आर0डी0जी0 का विषय यहां पर लाया गया है इसमें सभी माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। किसी ने आर्टिकल-275 का ज़िक्र किया। आर्टिकल-280 का भी इसमें ज़िक्र आता है लेकिन जब हम लोग अनुदानों की बात करते हैं तो अनुदान कभी भी बंद हो सकते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं। हम बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स नहीं समझते। आट्‌र्स में भी हमने समाजशास्त्र पढ़ा है। उसी में ही हमारी डॉक्टरेट है। परंतु मैं अपने घर से ही बता देता हूं कि अगर घर की इकोनॉमिक्स खराब हो रही हो तो कैसे ठीक की जाती है। हम लोग चार भाई और एक बहन हैं। मेरे पिताजी छोटी सी नौकरी में थे। वे आई0पी0एच0 में पाइप फीटर होते थे। जब मैंने होश संभाला, जब मैं छठी या 7वीं क्लास में था तो पिताजी 1100 या 1200 तनख्वाह लेते थे। उस समय यह फ्री फीस वाला सिस्टम नहीं होता था। ना कोई फ्री की किताब मिलती थी, ना मिड-डे-मील मिलता था, ना बैग या वर्दी फ्री के मिलते थे। पिताजी पूरा संघर्ष करते थे और

कोशिश करते थे और आजकल जो एक शब्द चला है, चैक-इन बैलेंस का सिस्टम है, मतलब क्रेडिट और डैबिट को कैसे बराबरी पर लाया जाए, वह शायद उनकी अपनी इकोनॉमिक्स काम करती रही होगी लेकिन 1100 रुपये में घर का गुज़ारा नहीं होता था तो उनको एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स करने पड़ते थे। कई बार वे अपनी खेती-बाड़ी में एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स करते थे। कई बार उनको लगता था कि शनिवार या रविवार का दिन छुट्टी का है तो वे पहाड़ में हमारे यहां कौड़, पतीश, शमाख है और उस समय धूप का काम होता था या उन्होंने पोर्टर का काम भी किया है, यह मैं अपने घर की बात बता रहा हूं। वे उन चीजों को मीटअप कर देते थे कि बैलेंस हो जाए और मेरे चार बच्चे पढ़ भी जाएं। हम सभी लोगों ने पिताजी की वजह से अच्छी क्वालिफिकेशन ली। मेरे एक भाई साहब लैक्चरर हैं। बाकी भी अच्छी-अच्छी जगह नौकरी कर रहे हैं। मैं अब जा कर यह सोचता हूं कि वे जब वर्कचार्ज

17.02.2026/1700/केएस/एस/2

बने तो 4200 के लगभग उनकी आय हुई और मैं सीनियर सैकंडरी तक पहुंच पाया। मेरे बड़े भाई कॉलेज में इसलिए नहीं पढ़ पाए क्योंकि उनके पास क्वार्टर के पैसे देने या अन्य व्यवस्था करने के पैसे नहीं थे। भाई साहब ने कहा कि मैं प्राइवेट पढ़ाई कर लूंगा। फिर भी उन्होंने दो पक्के कमरे भी बनाए और जब जे0ई0 और एस0डी0ओ0 आते थे, उस समय रैस्ट हाउस तो होते ही नहीं थे, वे पैदल आते थे तो वे अच्छा भोजन करें, सारा कुछ मेंटेन रहे, तो ये सारा एनवायरनमेंट एक व्यक्ति इतना मेंटेन करता था कि समाज में भी अपनी पूरी हाज़री, किसी तरह का कोई कर्ज भी नहीं और साथ ही साथ पूरा संघर्ष भी। अब यहां जो प्रदेश की विडंबना है, किसी ने कहा कि हमारे समय में 17 हजार करोड़ रुपये मिले, अब हमने 30 हज़ार करोड़ रुपये का कर्जा ले लिया और हमने अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए या जो हमने चुनावों में भाषण दिए थे, उनको पूरा करने के लिए कर्जा लिया तो इसमें किसी का दोष नहीं है। माननीय प्रधान मंत्री जी का बड़ा सिम्पल सा फंडा है कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र होना है, उसके लिए क्या करना है, यह उनको पता है कि कहां रेल पहुंचनी चाहिए, कहां एम्स खुलना चाहिए, कहां फोर लेन या सिक्स लेन बननी है, कहां एक्सप्रैस-वे बनना है या कहां पर क्या करना है। अब इसमें हम लोगों को जो हम प्रदेशों में बैठे हुए हैं, हमें खुद ही सोचना पड़ेगा। हमारी विधायक निधि मुख्य

मंत्री जी ने बंद कर दी। लोग यहां पर जोर से नहीं बोल पा रहे हैं लेकिन मैं यह ज़रूर कहना चाहता हूं कि हमारे पूर्व मुख्य मंत्री नेता प्रतिपक्ष और अन्य साथियों ने भी कहा कि आप हमारे दर्द को नहीं समझ सकते। हम जब गांव में जाते हैं तो लोग हमसे उम्मीद करते हैं। वे भी सोचते हैं कि बरसात में मेरा डंगा गिरा था, तुम्हारी सरकार है नहीं, डी0सी0 के पास फंड नहीं है, ना बैकवर्ड एरिया सब प्लान का पैसा आ रहा है, ना एस0सी0एस0पी0 का पैसा आ रहा है। थोड़ा बहुत आ रहा होगा तो जो तथाकथित प्रभावशाली लोग हैं, वे ले रहे हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

17.02.2026/1705/av/dc/1

डॉ0 हंस राज-------- जारी

इसलिए वे लोग कहां जाएं और कहां पर जाकर अपनी फरियाद करें। आपने ऊपर से जो आई0आर0डी0पी0 और बी0पी0एल0 का सर्वे शुरू किया है, इसके बारे में मैंने विधायक प्राथमिकता की बैठक में भी कहा था। लोग इन्कम का सर्टिफिकेट बनाने के लिए 80 रुपये खर्च कर रहे हैं। मान लो कोई व्यक्ति मेरे निर्वाचन क्षेत्र के टैपा, झजा कोठी या सनवाल से इन्कम सर्टिफिकेट बनाने के लिए चलता है तो उसका 1000 रुपया और खर्च हो जाता है। मैं आपको यह उदाहरण देकर एक छोटी-सी इकोनॉमिक्स समझा रहा हूं। आपने अब एक और नया सिस्टम खड़ा कर दिया है। अब कहा जा रहा है कि फूड एण्ड सप्लाई डिपार्टमैंट में अब ओ0टी0पी0 नहीं जाएगा। उसमें भी अब फेस डिटेक्शन करेंगे, आप अब कोई इस प्रकार की मशीन लाए हैं। आप झोल देखिए कि कितनी ज्यादा मशीन्ज खरीदी जा रही हैं। आप होस्पिटल्ज में देख लीजिए। यहां पर जैसे माननीय लोक निर्माण मंत्री कह रहे थे। मैं आपके साथ हूं और हमारा पूरा दल आपके साथ है। आप 28-28 लाख रुपये, 1-1 करोड़ रुपये और 14-14 करोड़ रुपये की मशीन्ज खरीद रहे हैं जबकि आपके पास उनको ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है। उसमें बीच के झोल के बारे में क्या दुनिया को पता नहीं चलता कि बीच में क्या हो रहा है? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि या तो हम अपनी 'कथनी और करनी' पर डटे नहीं हैं या फिर लोग यहां पर सच्चाई और तथ्यों के साथ

अपनी बात क्लीयर नहीं कर पा रहे हैं। We are performing role according to the need and situation right now. यहां पर हम बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं, हमारे विपक्ष की तरफ से भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन ज्यादा उम्मीद सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति से होती है कि आप काम शुरू करेंगे। अब अगर आर0डी0जी0 नहीं मिलेगी तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तीन वर्षों से मेरा तो कोई पत्थर ही नहीं लगा इसलिए मुझे आर0डी0जी0 से कोई मतलब नहीं है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को तनख्वाह मिल रही है। हमने दो-अढ़ाई लाख लोगों के लिए प्रदेश के 75 लाख लोगों का बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया है। हमने इस विषय पर तो चर्चा की ही नहीं है। सोचने का विषय तो यह है, परंतु आप उस पर नहीं बोलते क्योंकि फिर आपको वोट बैंक नज़र आता है। हमें तो इससे कोई

17.02.2026/1705/av/dc/2

फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम यहां पर जनता की सेवा के लिए ही आए हैं। जिस दिन बी0पी0एल0 वाले सफर हुए हमने उस दिन भी कहा। आपने जो सी0बी0एस0ई0 का झुनझुना पकड़ाया है इससे आपका एच0पी0 बोर्ड भी खत्म हो जाएगा। सी0बी0एस0ई0 में क्या है? इससे अच्छा तो आप अपना करिकुलम ठीक कर लेते। आप अपनी इक्वीवेलैंसी करवा लेते, 25 करोड़ रुपये का नुकसान तो एच0पी0 बोर्ड का इस बार ही हो गया। फिर आप कह रहे हैं कि हम चीजें ठीक कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर में 27,000 मेगावाट का पोटेंशियल आंका गया है। जिसमें से चार प्रोजैक्ट्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी करके गए हैं। अभी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइको-i और साइको-ii का शिलान्यास माननीय मुख्य मंत्री भी करके गए। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपसे अगर लैण्ड एक्वायर नहीं हो रही तो उसमें हमें इंवॉल्व कीजिए। आप हमें इसलिए नहीं करते कि मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं और उसमें पता नहीं मेरा क्या इन्टरस्ट होगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मेरा उसमें कोई इन्टरस्ट नहीं है। हमारा क्या इन्टरस्ट होना, हमारा केवल इतना इन्टरस्ट है कि वहां पर यदि 10, 15, 33 या 50 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट लग जाता है तो उसमें हमारे सौ, दो सौ या चार सौ बच्चे एडजस्ट हो जाते हैं।

अगर आपका फोरलेन द्रमण-चुवाड़ी-जोत-तीसा से होता हुआ पांगी निकल जाता है तो उसमें भी हमारे बच्चे एंगेज हो जाएंगे और टूरिज्म को नये पंख लग जाएंगे। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोग भाषणों के लिए भाषण दे सकते हैं। मैं यहां पर सभी को सुन रहा था और किसी को इंगित नहीं करना चाहता। परंतु श्री भवानी सिंह पठानिया जी पर मैं जरूर कटाक्ष करूंगा। इन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी और बहुत बेहतर तरीके से पढ़ी होगी। लेकिन जिसका विरोध हमारे कुछ साथियों ने किया कि किसी व्यक्ति पर इस प्रकार से कमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहां पर अंग्रेजी कौन नहीं बोल सकता। वे लोग अंग्रेजी जरूर बोलेंगे जिन्होंने पढ़ी हुई है। यहां पर हिन्दी कौन शुद्ध नहीं बोल सकता, यहां पर शुद्धता का परिचय भी दिया जा सकता है। लेकिन जिसके माध्यम से हम अपने हिमाचलियों को समझा सकते हैं, हमें वही भाषा बोलनी चाहिए। अब यहां पर हमारे कई ब्यूरोक्रेट्स हैं जोकि आपके ऊपर बिना बात की लायबिलिटी बने हुए हैं। इसीलिए 58 और

17.02.2026/1705/av/dc/3

60 वर्ष की आयु के बाद बंदे को रिटायर कर दिया जाता है। मैं किसी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूं और चाचा जी, आप (कृषि मंत्री) इस बात को अन्यथा न लें। परंतु मेरा दिमाग जब काम करना बंद कर दे और जब वास्तव में सीट पर बैठकर मैं कुछ नहीं कर पाया तो फिर मैं रिटायर होने के बाद कैसे परफॉर्म कर सकता हूं। यह कैसे सम्भव हो सकता है और आप उनको तनख्वाहें तथा पेंशन भी दे रहे हैं। यह तो इस प्रदेश के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। हमें आर0डी0जी0 के लिए भिखारियों की तरह कटोरा खड़ा नहीं करना चाहिए अगर हम यहां पर डॉ0 वाई0 एस0 परमार जी की दुहाई दे रहे हैं। उसके बाद आदरणीय श्री राम लाल ठाकुर मुख्य मंत्री हुए, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी, श्री शांता कुमार जी, प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी और श्री जय राम ठाकुर जी हुए तथा अब श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू हैं।

टी सी द्वारा जारी

17.02.2026/1710/टी0सी0वी0/डी0सी0-1

डॉ0 हंस राज .. जारी

इतिहास सबको याद करता है और सबको याद करेगा। एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी जी पांगी गई। पांगी हमारा बहुत रिमोट एरिया है। इस बात को कुमारी अनुराधा राणा और डॉ0 जनक राज जी अच्छी तरह से समझते हैं। वहां के लोग आज भी भारतीय जनता पार्टी की ओर ज्यादा झुकाव नहीं रखते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें पहले ऐसी सुविधाएं मिलती थीं जिनकी व्यक्ति आज कल्पना भी नहीं कर सकता। लोगों में गुण होते हैं और हिमाचल एक छोटी-सी स्टेट है। जब राणा जी बोल रहे थे तो वे बड़ी ऑथेंटिक बात कह रहे थे। मैंने आपसे आग्रह भी किया था कि उन्हें अपना भाषण पूरा देने दिया जाए। यहां कई लोग खामख्वाह भी बोल रहे थे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता।

मेरा निवेदन है कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में आज भी बहुत पोटेंशियल है। आज भी लोग सिंगल विंडो के नाम पर एक-डेढ़ साल से वेटिंग में हैं कि उनकी क्लीयरेंस आज होगी या कल होगी। कई लोग कहते हैं कि आपने फ्लां से फोन नहीं करवाया। हम स्वयं इसके गवाह है। कई लोग हमारे पास आए और कहा कि यहां इंडस्ट्री के लिए 2.50 से 6 रुपये बिजली दी जा रही है जबकि जम्मू-कश्मीर में 2.50 से 3 रुपये में इंडस्ट्री के लिए बिजली दी जा रही है और वहां जमीन भी अधिक उपलब्ध है। फिर लोग आपके पास क्यों आएंगे? हम हाइड्रो में काम नहीं करना चाहते, इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहते, टूरिज्म में काम नहीं करना चाहते जबकि एजुकेशन में भी यहां बहुत पोटेंशियल है। यहां भी अच्छी यूनिवर्सिटी स्थापित कर कोटा जैसा मॉडल विकसित किया जा सकता है।

आयुर्वेद के क्षेत्र में भी स्थिति अच्छी नहीं है। इस विभाग से संबंधित मंत्री को खामख्वाह की मिनिस्ट्री दी गई है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी स्थिति बहुत खराब है। मैं अगर सही बताऊं जब से वे मंत्री बने हैं, वे हमारे मित्र है। जब से वे मंत्री बने हैं हमें भी लग रहा था कि एक-आध खेल का ग्राउंड हमें भी मिलेगा। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है क्योंकि हमारी यह प्रदेश के प्रति कुंठा है। जब दूसरे लोग हिमाचलियों पर टिप्पणी करते हैं कि प्रदेश दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच गया है, स्टेटहुड पर भी खतरा हो सकता है क्योंकि आज हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं इसलिए वे लोग ऐसा कहते हैं।

17.02.2026/1710/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी और यहां बैठे सभी माननीय मंत्रियों/सदस्यों से कहना चाहता हूं कि स्टेट इंटरेस्ट में हम कहीं भी साथ चलने को तैयार हैं लेकिन केवल आर0डी0जी0 के लिए नहीं। हम उनसे मांग करेंगे जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आर0जी0डी0 के स्थान पर किसी अन्य मद के लिए अनुशंसा करें। इसलिए हमें भारत सरकार के सामने वास्तविक तथ्य रखने होंगे और यह अनुशंसा करनी होगी कि किसी अन्य मद या योजना के माध्यम से प्रदेश को सहायता दी जाए। हिमाचल में छोटे-छोटे कर्मचारी, जैसे एस0पी0ओ0 का विषय है, वे लोग 25-25 वर्षों से यहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन नए अधिकारियों द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। जिनकी आय 6000 से 7000 रुपये है, यदि उनका 5000 या 6000 रुपये किराए में ही खर्च हो जाएंगे तो वे अपने परिवार का पालन-पोषण कैसे करेंगे। इसी प्रकार सी0बी0एस0ई0 लागू करने के लिए जिन-जिन स्कूलों को अडॉप्ट किया गया वहां के शिक्षकों का अनुभव भी खत्म हो जाएगा और एस0एम0सी0 के अंतर्गत कार्यरत लोगों के लिए कोई पॉलिसी ही नहीं है। जब भी कोई नई पॉलिसी अपनाई जाए तो उसके सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। यह जो मैं सी0बी0एस0ई0 के विषय का जिक्र कर रहा हूं यह कोई छोटी बात नहीं है। कोई सिलेबस बड़ा या छोटा नहीं होता, पढ़ने और पढ़ाने वाला बड़ा होता है। हमने कई जिलाधीशों, बड़े अधिकारियों को भी परीक्षाओं में असफल होते देखा है। हमने यह अपने जीवन में देखा है। हिमाचल प्रदेश अच्छी एजुकेशन इंपार्ट कर सकता है तो हम दूसरों पर क्यों निर्भर रह रहे हैं।

अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आर0डी0जी0 को लेकर अनावश्यक हो-हल्ला न किया जाए। पंचायती राज चुनावों में देरी हुई तो उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है। यदि फंड की कमी थी तो वह स्थिति पहले से ही ज्ञात थी। हम भारत सरकार से यह मांग कर सकते हैं कि विभिन्न योजनाओं और मदों में हिमाचल प्रदेश को आवश्यक धनराशि प्रदान की जाए जिससे प्रदेश की स्थिति स्वतः सुधर जाएगी। साथ ही यहां जो मंत्रीगण बैठें हैं वे मुख्य मंत्री जी से आग्रह करें कि फाइलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। धन्यवाद।

अध्यक्ष श्रीमती एन0एस0 द्वारा शुरू ...

17-2-2026/1715/एन0एस0-एच0के0/1

अध्यक्ष : अब कुमारी अनुराधा राणा चर्चा में भाग लेंगी।

कुमारी अनुराधा राणा : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमाति से नियम-102 के अंतर्गत जो सरकारी संकल्प संसदीय कार्य मंत्री जी के द्वारा लाया गया है, मैं भी उसमें अपने आपको शामिल करती हूं और अपने विचार इस पर रखना चाहूंगी।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, पिछले कल से आर0डी0जी0 पर चर्चा जारी है। इसे 16वें वित्तायोग की रिकोमेंडेशन पर खत्म किया गया है और उसके लिए ही यह विशेष बैठक की जा रही है तथा जो हमारा बजट सत्र आरम्भ हुआ है इस पर इसके लिए की विशेष चर्चा जा रही है। सभी वरिष्ठ माननीय सदस्यों ने इस बारे में अपनी बातें रखी हैं। संविधान के अनुच्छेद 275 क्लॉज (1) की जब हम बात करते हैं तो इसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि ऐसे राज्यों को केंद्र सरकार पूरी मदद करेगी जहां पर भौगोलिक परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं, हमारे रेवेन्यू जनरेशन के साधन बिल्कुल सीमित हैं तो ऐसे राज्यों को विशेष ग्रांट दी जाएगी। उसमें आर0डी0जी0 का नाम स्पष्ट नहीं लिखा है परन्तु उसमें जो अनुदान की बात की गई है तो वह एक तरह से आर0डी0जी0 के तौर पर ही इतने लंबे समय से हिमाचल प्रदेश या अन्य राज्यों को दी जा रही है। जब हम आर्टिकल 280 की बात करते हैं या वित्तायोग की बात करते हैं तो वर्ष 1952 में हमारा पहला वित्तायोग गठित हुआ। वर्ष 1952 से लेकर विभिन्न राज्यों को आर0डी0जी0 के अंतर्गत राशि दी जा रही है। जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया तो वर्ष 1952 के बाद हांलांकि, आर0डी0जी0 इसका स्पेस्फिक नाम नहीं था। उस समय एन0डी0सी0 (National Development Councill) के जरिए एक राष्ट्रीय अस्स्टिेंट के तौर पर राशि राज्यों को दी जाती थी। जब हिमाचल प्रदेश वर्ष 1971 में अस्तित्व में आया और हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो उसके बाद लगातार यह राशि हिमाचल प्रदेश को मिलती आ रही है। जब हम विशेष श्रेणी की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त है और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के 10-11 अन्य राज्यों को भी विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त है तथा ये भी कांग्रेस सरकार की देन है। वर्ष

1969 में 5वां वित्तायोग आया था तो उसकी रिकोमेंडेशन यह थी कि कुछ राज्य जिनके संसाधन सीमित हैं, जिनकी भौगोलिक परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत

17-2-2026/1715/एन0एस0-एच0के0/2

हैं तो उन राज्यों को विशेष दर्जा दिया जाए। जिसमें शुरू में जम्मू-कश्मीर, नागालैंड जैसे राज्यों को शामिल किया गया। वर्ष 1971 में जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो वर्ष 1974 में हिमाचल प्रदेश को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया। यह कांग्रेस सरकार की बहुत बड़ी देन है जो हिमाचल प्रदेश को मिली है। हमें इसका सबसे बड़ा फायदा यह मिला कि जो भी केंद्र सरकार की स्कीम्ज हैं या जो भी ग्रांट आती है उसकी रेशो 90:10 की है। जिसमें 10 प्रतिशत राज्य सरकार कंट्रीब्यूट करती है और 90 प्रतिशत केंद्र सरकार देती है। आज हम देख रहे हैं कि आर0डी0जी0 से जितने भी राज्य प्रभावित हैं तो उनमें सबसे ज्यादा प्रभावित विशेष दर्जा प्राप्त राज्य हैं। उसमें अगर हम परसेंटेजवाइज देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश one of the affected State है। नागालैंड के बाद दूसरे नम्बर पर हम हैं और 12.7 प्रतिशत हमारे बजट पर इसका डायरेक्टली प्रभाव पड़ेगा। यदि मैं हिमाचल प्रदेश के बजट का 100 रुपये की राशि से उदाहरण प्रस्तुत करूं तो उसमें हमारा 45 प्रतिशत बजट सैलरी व पेंशन में जाता है, 22 प्रतिशत बजट लोन का इंटरस्ट चुकाने में जाता है, 9 प्रतिशत हम ऑटोनॉमस बॉडीज को ग्रांट के तौर पर देते हैं और 24 प्रतिशत बजट कैपिटल एक्सपेंडिचर व अन्य वैल्फेयर स्कीम्ज जो हम अपने प्रदेश के लोगों को देते हैं उसमें यूज करते हैं। अब यह बहुत चिंता का विषय है कि 24 प्रतिशत में से 12.7 प्रतिशत की जब कटौती होगी तो कितना बड़ा प्रभाव हमारे विकास कार्यों में पड़ेगा। विपक्ष के सभी वरिष्ठ माननीय सदस्य यही कह रहे हैं कि हमें विधायक क्षेत्रीय विकास निधि और एच्छिक निधि नहीं मिल रही है तो इसका यही सबसे बड़ा परिणाम हमें सामने दिख रहा है कि कितना बड़ा आर्थिक संकट हमारे सामने है और हम एक क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं कि विधायक क्षेत्रीय विकास निधि पर कट लगाना पड़ रहा है। यह संकट आगे न बढ़े

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

17.02.2026/1720/RKS/एचके-1

कुमारी अनुराधा राणा... जारी

क्योंकि आने वाले समय में यह संकट बहुत बड़ा हो सकता है। इसीलिए इस पर चर्चा करने के लिए यह सभा एकत्रित हुई है। जैसा हमारे मंत्रीगणों और सम्मानित सदस्यों ने कहा कि आर0डी0जी0 हमारा अधिकार है। यह कोई खैरात नहीं है, यह हमारा अधिकार है। हिमाचल प्रदेश को 1971 के बाद और बाकी राज्यों को वर्ष 1952 से मार्च, 2026 तक जो ग्रांट मिली है उसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है। अगर हम 13वें वित्तायोग की बात करें तो उस समय जरूर कुछ कटौती हुई थी। परंतु समय के साथ यह देखा गया कि हमारा राजस्व घाटा बढ़ रहा है इसलिए इसको कंपनसेट करने के लिए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की राशि बढ़ती गई। 15वें वित्तायोग और कांग्रेस सरकार के पिछले तीन वर्षों के कार्यकाल में राज्य सरकार को सिर्फ 17000 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है।

(माननीय सभापति श्री संजय रत्न पदासीन हुए।)

इसके विपरीत पूर्व सरकार को 54 हजार करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी। जी0एस0टी0 लागू करने से हिमाचल प्रदेश को नुकसान हुआ है क्योंकि हमारी जनसंख्या कम है और यहां पर बात भी की गई कि यह कंज्यूमर बेस्ड टैक्स है और इसका फायदा उन राज्यों को होगा जिनकी आबादी ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश की आबादी 75 लाख है और हमें जी0एस0टी0 के रूप में ज्यादा नुकसान होगा। जिन राज्यों की जनसंख्या ज्यादा है उन राज्यों को ज्यादा जी0एस0टी0 मिलेगा। यह एक चिंता का विषय है। हम केंद्र को जो अपना कॉन्ट्रिब्यूशन दे रहे हैं, चाहे जंगलों को बचाने की बात हो या नॉर्दन स्टेट के तौर उनको स्वच्छ पानी देने की मदद कर रहे हो परंतु हमें इसके बदले में क्या मिल रहा है? इस बार जो केंद्रीय बजट 2026 पेश हुआ है उसमें उसमें हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य का कहीं जिक्र नहीं है। इस बजट में हिमाचल राज्य को क्या मिला है? माउंटेन ट्रेल की बात जरूर की गई है लेकिन उसके लिए कितना बजट एलोकेट किया जाएगा उसका कोई

जिक्र नहीं किया गया है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने की बात कर रहे हैं लेकिन इस पर भी कोई

17.02.2026/1720/RKS/एचके-2

स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। बौद्ध सर्किट की बात हुई है लेकिन यह हिमाचल प्रदेश के लिए बड़े अफसोस की बात है क्योंकि बुद्धिस्ट तो हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल एरिया में रहते हैं। हिमाचल प्रदेश को जो स्पेशल स्टेटस मिला है उसमें कहीं-न- कहीं ट्राइबल क्षेत्र का भी बहुत बड़ा योगदान हैक्योंकि इसके क्राइटेरिया में कई तरह की कंडीशंस लगाई थी। उसमें ट्राइबल की स्पेसिफिक जनसंख्या की भी कंडीशंज हैं। जो लाहौल-स्पिति, पांगी, भरमौर और किन्नौर के एरिया शेड्यूल- 5 में आते हैं, उस वजह से भी हिमाचल प्रदेश को स्पेशल स्टेटस मिला है। परंतु जब हम केंद्रीय बजट की बात करते हैं तो इसमें नॉर्दन स्टेट के लिए कोई खास प्रोग्राम प्रस्तावित नहीं हैं। हम यह देखते हैं कि southern स्टेट के तौर पर काफी राहत मिली है। जिन 12 स्टेटों में आर0डी0जी0 मिलती है उनमें कई ऐसे प्रदेश हैं जो बड़े राज्य हैं। उनका अपना राजस्व संग्रह काफी है और उन्हें एक या दो प्रतिशत के तौर पर जो आर0डी0जी0 मिलती थी उसके न मिलने से उन राज्यों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम यह कल्पना कर सकते हैं कि यदि हमारे बजट का 12.7 प्रतिशत आर0डी0जी0 पर निर्भर था तो आने वाले समय में हम कितने संकट की स्थिति से गुजरेंगे? जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो मुख्य मंत्री जी ने अपने नेतृत्व में कई ऐसे रिफॉर्म्स किए हैं जो सराहनीय है। मैं आप सभी से काफी कनिष्ठ हूं और मैं यह कहना चाहूंगी कि रातों-रात कोई बदलाव नहीं होता। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कई ऐसे कड़े कदम उठाए हैं जिससे हमारे राजस्व में काफी वृद्धि हुई है। लेकिन यह सब रातों-रात नहीं हुआ है। जो राजस्व करों में 3800 करोड़ रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हुई है वह मुख्य मंत्री जी की दूरदर्शिता का ही परिणाम है। हालांकि हम देखते हैं कि ट्रेजरी बंद रहने के कई इश्यूज हैंलेकिन हम इसका परिणाम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। हमारी लोगों के प्रति जवाबदेही है इसलिए मुझे लगता है कि आर0डी0जी0 को बहाल करना अत्यंत आवश्यक

है। हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक प्लेटफॉर्म में आगे आकर अपनी मांग को मनवाना पड़ेगा। यदि फिर भी बात नहीं बनती तो हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा या फिर सड़कों पर उतरना पड़ेगा। अगर यह ग्रांट बंद हो गई तो हम आने वाले समय में हिमाचल के लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे।

17.02.2026/1720/RKS/एचके-3

हम देखते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग गरीब और किसान लोग हैं। सारी कल्याणकारी योजनाएं गरीब व्यक्तियों के लिए चलाई जाती हैं या जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका रेवेन्यू जनरेशन स्टेट के लिए आता है। यदि हमारे बजट में इतना बड़ा कट लगेगा तो हमारा राज्य कैसे आत्मनिर्भर बनेगा? हम अपने लोन को कैसे कम कर पाएंगे? यह राशि एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है और यह दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। हम इस राशि को किस तरीके से टैकल कर पाएंगे? हमें इस पर राजनीति न करते हुए एक मंच पर आकर माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री के समक्ष अपनी बात रखनी होगी कि हमारी आर0डी0जी0 को बहाल किया जाए। हालांकि हम देख रहे थे कि इसमें टेपरिंग होनी थी।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

17.02.2026/1725/बी.एस./.वाई. के.-1

कुमारी अनुराधा राणा जारी...

परंतु बिल्कुल शून्य कर देना यह बहुत बड़ा कुठाराघात हिमाचल के लोगों के साथ किया गया है और अपने खर्चे को कैसे काम करना है? इसके लिए भी सरकार कदम उठा रही हैं, मुख्य मंत्री जी ने कई ऐसे कदम उठाए हैं, चाहे वह रेस्ट हाउसिज में आम आदमी से लेकर मुख्य मंत्री तक एक दर्जे में सबको शामिल करना, यह सभी एक कड़े कदम की ओर इशारा करते हैं परंतु मुख्य मंत्री जी से यह भी निवेदन करते हैं कि आने वाले समय में मुझे लगता है कि सरकार कड़े कदम उठाने के लिए तैयार भी है कि जो भी फिजूल खर्ची है,

---

चाहे वह विधायक से जुड़ी है, चाहे मंत्री से या किसी से भी जुड़ी है उसको भी कम करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि उसके भी सरकार को आगे आना पड़ेगा और सरकार इस तरह के कड़े जो फैसला हैं वह जरूर लेगी।

मैं ज्यादा नहीं कहते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आर0डी0जी0 हमारा अधिकार है और इससे डायरेक्टली प्रभाव हमारे लोगों को पड़ेगा, चाहे वह वेलफेयर स्कीम्स के माध्यम से पड़े, हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में बहुत बड़ा कट लग रहा है। हम देखते थे कि पहले जनजाति क्षेत्र में बजट की कोई कमी नहीं रहती थी, करोड़ों का फंड सरेंडर होता था या ऐस0सी0डी0पी0 के बजट की जब हम बात करते हैं परंतु आज परिस्थितियां बिल्कुल उलट हो गई है, बहुत क्राइसिस से हमें गुजरना पड़ रहा है और आने वाले समय में स्थिति और बिगड़ेगी इसके लिए तैयार होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए सभी को एक पटल पर एक होकर अपनी आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचानी होगी क्योंकि यह सिर्फ एक सरकार की बात नहीं है, सरकारें आती जाती रहती है परंतु इसका जो प्रभाव है वह आम जनता को यहां हिमाचल के लोगों को भुगतना पड़ेगा। इसके लिए किस तरीके से हम अपने राज्य को आत्मनिर्भर बन पाएंगे यदि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में कुछ खर्च नहीं कर पा रहे हैं और एक बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल के लिए होगा। जब हम आर0डी0जी0 की बात करते हैं, हमारे प्रतिपक्ष के नेता जी ने भी कहा कि वर्ष 2021 में जो कोविड का वर्ष था तो आर0डी0जी0 ग्रांट वन ऑफ द हाईएस्ट मिली है। कांग्रेस सरकार

17.02.2026/1725/बी.एस./.वाई. के.-2

बनने के बाद हम दो भयानक आपदाओं से गुजरे हैं वर्ष 2023 की आपदा हो, चाहे वर्ष 2025 की आपदा हो। यह भी तो एक आपदा है, जिसने हजारों करोड़ रुपये का नुकसान यहां पर किया। 10 हजार करोड़ रुपये का आकलन केंद्र की टीम ने वर्ष 2023 की आपदा में किया और वर्ष 2025 की आपदा का नुकसान भी केंद्र की सरकार की टीम ने यहां आ करके किया परंतु बदले में हमें अभी तक क्या मिला है? 1500 करोड़ रुपये की घोषणा प्रधानमंत्री, मोदी जी के द्वारा की गई थी परंतु यह राशि भी अभी तक हमारी

सरकार को प्राप्त नहीं हुई है और आर0डी0जी0 क्यों महत्वपूर्ण है? हम देखते हैं कि बाकी जितनी भी ग्रांट हमें केंद्र सरकार से मिलती हैं, वह एक टाइट ग्रांट के तहत मिलती है जिसको आपने पार्टिकुलर, स्पेसिफिक स्कीम्स में खर्च करना है, पंरतु हमें अनटाइड ग्रांट के तौर पर जो आर0डी0जी0 मिलती थी उसका उपयोग सैलरी पेंशन के अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर भी किया जाता था। हमारे को कोविड वर्ष में सबसे ज्यादा वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रांट मिली है तो वर्ष 2023 और 2025 की आपदा में क्यों नहीं केंद्र सरकार द्वारा आकलन किया गया? इतनी भयानक आपदा आने के बावजूद केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया उसमें कहीं भी स्पेशल पैकेज की अनाउंसमेंट आपदा प्रभावित राज्यों के लिए नहीं की गई है। जो बिल्कुल एक भेदभाव को दर्शाता है और सभी सरकारों से मेरा निवेदन रहेगा कि हम चाहे फ्रीबीज की बात करते हैं या अन्य घोषणाओं की बात करते हैं वह चुनाव के दृष्टिकोण से करते हैं। इससे हमें बाहर निकलना होगा। आने वाले भविष्य को हम क्या दे करके जा रहे हैं? हमारे आने वाली पीढ़ियां हमसे क्या लेकर जा रही है। इस पर हमें आज से ही सोचना और विचार विमर्श करना अत्यंत आवश्यक है। हम प्रीबीज की घोषणाएं करते हैं, बेशक परंतु मुझे लगता है कि उनको भी सीमित करना होगा। जिस इंसान को जरूरत है, जिस गरीब को जरूरत है जिस गांव के अंतिम व्यक्ति को आवश्यकता है, जैसा महात्मा गांधी जी कहते थे यदि उसकी जरूरत है तो उसे करना चाहिए। सब के लिए मुझे लगता है कि एक तराजू में तोलने की आवश्यकता नहीं और उससे हमें बचना चाहिए। केंद्र सरकार भी सभी राज्यों को एक ही तराजू में तोलने का प्रयास करती है। जबकि हमारे देश में जहां समुद्र भी हैं, पहाड़ भी हैं और

17.02.2026/1725/बी.एस./.वाई. के.-3

रेगिस्तान भी हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, जब हम भारत देश की बात करते हैं, यदि जियोग्राफिक बात की जाए, चाहे भाषा है हर चीज के लिहाज से हमारे पास ट्राइबल क्षेत्र भी हैं, शेड्यूल एरियाज भी हैं। सबको एक तराजू में नहीं तोला जा सकता है। वैसे ही जब हम हिमाचल की बात करते हैं तो यहां 12 जिलों को भी हम एक तराजू में नहीं तोल सकते हैं। ट्राइबल जिलों के जो चैलेंजिज हैं वह बिल्कुल अलग प्रकार के चैलेंजिज हैं।

इतना भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता है वहां -25 - 30 तक आजकल टेंपरेचर जाता है। इस तरह की विपरीत परिस्थितियों में लोग सरवाइव करते हैं। जब केंद्र सरकार इस तरह की दुहाई देती है तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार के लेवल पर भी हमें सभी राज्यों को एक तराजू में नहीं तोलना चाहिए क्योंकि हर जिला की अपनी-अपनी चैलेंजिज हैं। हर जिला की अपनी परेशानियां हैं और अपनी परिस्थितियों हैं परंतु हम धन्यवाद करते हैं सरकार का, सरकार ऐसे कड़े कदम उठाए हैं कि ट्राइबल जनजाति जिलों में भी आज हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जहां एक डॉक्टर नहीं होता था आज वहां पांच स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेरे कैलांग अस्पताल में हैं। काजा में आज मेरे पास सर्जन है जहां कुछ भी नहीं होता था। यह सब एक बदलाव की किरण है और आज आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि मुख्य मंत्री जी के प्रयास से और बेहतर इस दिशा में आगे बढ़ा जाए। हमेशा से कांग्रेस सरकार का आशीर्वाद जनजाति जिलों के साथ रहा है परंतु हम देखते हैं कि इस तरह के क्राइसिस में जब हाथ पूरी तरह से जकड़ लिए जाएं, पूरी कमर तोड़ने की कोशिश की जाए तो सरकार इसमें क्या करेगी। फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर करने की कोशिश कहीं-न-कहीं देख रहे हैं। quasi फेडरल स्ट्रक्चर, जो हम इंडिया स्टेट की बात करते हैं कि हमारा जो देश है वह क्या है

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

17.02.2026/1730/डीटी/वाई0के0-1

कुमारी अनुराधा राणा जारी...

हमारा जो देश है वह क्या है? हमारा देश क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है। सभी राज्यों से मिलकर हमारा देश बनता है। अगर हमारे राज्य मजबूत होंगे तभी हमारा देश भी मजबूत होगा। तभी हम विश्व गुरू बनेंगे। हम जो विकसित भारत की बात करते हैं हम तभी वह बात कर पाएंगे जब हमारे राज्य मजबूत बनेंगे। मैं बार-बार यह कह रही हूं कि सभी राज्यों एक तराजु में तोलना सही बात नहीं है। इसके लिए जो भी हमारे सुझाव हैं, हमारा राज्य चाहे एक छोटा राज्य है, हमारे पास केवल 7 सांसद है इसलिए शायद यह भी एक कारण

हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश को हमेशा भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। जहां पर ज्यादा सांसद है, जैसे किन्ही-किन्ही राज्यों में 200 या 300 सांसद हैं उन राज्यों को ज्यादा तरजीह दी जाती है। कहीं न कहीं मुझे यह लगता है कि यह भी एक प्रकार का भेदभाव का कारण हो सकता है। इसके लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है और आज भी यदि हम आवाज नहीं उठा पाते तो इसके गंभीर परिणाम भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतने पड़ेंगे। इसलिए मेरा इस माननीय सदन से निवेदन रहेगा कि इसके लिए हम सभी को आगे आना पड़ेगा और अपने हक के लिए दिल्ली तक कूच करना पड़ेगा तभी हम हिमाचल प्रदेश के हक को बरकरार रख पाएंगे।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

17.02.2026/1730/डीटी/वाई0के0-2

सभापति : अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री बलवीर सिंह वर्मा जी।

श्री बलवीर सिंह वर्मा : माननीय सभापति महोदय, नियम-102 के अंतर्गत माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो संकल्प इस माननीय सदन में लाया है। मैं भी उस संकल्प पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, वैसे तो यह संकल्प माननीय मुख्य मंत्री महोदय को लाना चाहिए था क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी के पास वित्त विभाग भी है। पर यह संकल्प माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा जाया गया है और जिस तरह से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह संकल्प लाया है, ऐसा लग रहा है कि राजनैतिक दृष्टि से कि इस संकल्प के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को गुमराह करके कांग्रेस के नेता और कांग्रेसी पार्टी हिमाचल प्रदेश में फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह से केंद्र सरकार से विभिन्न योजनाओं में पैसे आ रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्ष 1993-1994 में हिमाचल प्रदेश के ऊपर बिल्कुल भी कर्जा नहीं था। यह जो कर्जा की वजह से हिमाचल प्रदेश आज फाइनेनशयली बहुत ही टाइट स्थिति में आ गया है। वर्ष 1993-1994 के बाद

इस पर प्रोपरली खर्चों को कंट्रोल नहीं किया गया और साथ-ही-साथ कुछ ऐसी योजनाएं लाई गई जिन योजनाओं की जरूरत नहीं थी। सिर्फ वोटस प्राप्त करने के लिए ऐसी योजनाएं लाई गई। मैं रेवन्यू डेफिसिट ग्रांट जो वर्ष 2005 से 2010 व 2010 और 2015 जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, स्वर्गीय डॉ0 मनमोहन सिंह जी देश के प्रधान मंत्री थे। उनके समय में वित्त कमीशन के द्वारा जो हिमाचल प्रदेश को पैसा मिला वह बहुत ही कम मिला है। वर्ष 2005 से 2010 व वर्ष 2010 स 2015 के बीच में पैसा बहुत कम मिला जिसकी वजह से 18000 करोड़ रुपया सिर्फ वर्ष 2005 से 2010 व वर्ष 2010 से 2015 के बीच मिला है। देश में जब आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनी और हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2015 से 2020 के बीच में और वर्ष 2020 से 2025 के बीच में

श्री एन0जी0 द्वारा जारी....

17.02.2026/1735/ए.जी.-एन.जी./1

श्री बलबीर सिंह वर्मा.......... जारी

वर्ष 2020 से वर्ष 2025 के बीच में मिला है।

सभापति महोदय, वर्ष 2012 में प्रदेश में काँग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। उस समय प्रदेश पर लगभग 28 हज़ार करोड़ रुपये का लोन था। उसके बाद जब वर्ष 2017 में प्रदेश से काँग्रेस पार्टी की सरकार चली गई तब प्रदेश पर लगभग 48 हज़ार करोड़ रुपये का लोन चढ़ चुका था। वर्ष 2022 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता से गई तब प्रदेश पर लगभग 69 हज़ार करोड़ रुपये का लोन था। लेकिन वर्तमान सरकार के तीन वर्ष के कार्यकाल में ही लगभग 40 हज़ार करोड़ रुपये का लोन ले लिया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 1993 से लेकर वर्ष 2022 तक जितना लोन लिया गया था उसका लगभग

60 प्रतिशत लोन केवल वर्ष 2022 से वर्ष 2026 के बीच लिया गया है। आज हिमाचल प्रदेश की जनता पर लगभग 1 लाख 10 हज़ार करोड़ रुपये का लोन चढ़ चुका है।

सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश में काँग्रेस पार्टी द्वारा दी गई 10 झूठी गारंटियों की वजह से ही प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब हुई है। उसके बाद भी आज उन गारंटियों को भी पूरा नहीं किया गया है। चुनाव से पहले काँग्रेस पार्टी ने कहा था कि सभी महिलाओं को 1500-1500 रुपये देंगे। काँग्रेस पार्टी ने यह भी कहा था कि हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे लेकिन आज हिमाचल प्रदेश में बिजली की स्थिति यह हो गई है कि प्रदेश के हर गांव के गरीब किसान/बागवान को 2000-2500 रुपये का बिल आ रहा है। आज पूरे प्रदेश के किसान/बागवान काँग्रेस की सरकार को इतनी ज्यादा गालियां दे रहे हैं कि मैं उन्हें यहां पर बोल भी नहीं सकता। काँग्रेस पार्टी ने युवाओं को 5 लाख नौकरियां देने की भी गारंटी दी थी। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश का युवा बेरोजगार घूम रहा है और दो टाइम की रोटी के लिए जूझ रहा है।

17.02.2026/1735/ए.जी.-एन.जी./2

सभापति महोदय, यहां पर काँग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों के दौरान यह दर्शाया कि केन्द्र सरकार से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है और हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह सब कुछ प्रदेश के अपने राजस्व को जनरेट करके कर रहे हैं। मैं सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों को थोड़ा-सा आइना दिखाना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार से हिमाचल प्रदेश की जनता को क्या-क्या मिला है। हिमाचल प्रदेश के स्पेशल स्टेट के दर्जे को केन्द्र की मोदी सरकार ने ही बहाल किया है। केन्द्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्व के आठ राज्यों को 90-10 के अनुपात में डाला गया है जिसके तहत 90 प्रतिशत धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है। इसके अलावा अन्य सभी राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा 60-40 के अनुपात में डाला गया है जिसके तहत 60 प्रतिशत धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है। मैं बताना चाहता हूं कि काँग्रेस की केन्द्र सरकार

ने हिमाचल प्रदेश का यह अधिकार भी छीन लिया था और श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में देश के प्रधान मंत्री बनने के बाद हिमाचल प्रदेश को स्पेशल स्टेट का दर्जा वापिस दिया था। हिमाचल प्रदेश में आज केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की 196 योजनाएं चल रही हैं और उन सभी योजनाओं में केन्द्र सरकार द्वारा 90-10 के अनुपात में पैसा दिया जा रहा है।

सभापति महोदय, सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में किए जा रहे कार्यों को बहुत ध्यान से सुनें। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में लगभग 3000 करोड़ रुपये की लागत से एम्ज़ बनाया गया है। उसे देख कर ऐसा लगता है कि युरोप, अमेरिका

श्री ए0पी0 द्वारा......जारी

17.02.2026/1740/ए.जी./ए.पी./01

श्री बलवीर सिंह वर्मा जारी .....

और आस्ट्रेलिया जैसे किसी देश में पहुंच गये है। बिलासपुर में एम्स का ऐसा हॉस्पिटल बना है जिसे देखने के लिए दूसरे राज्यों के लोग आते हैं। यह 3,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय जे.पी. नड्डा जी और तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने इतना सुंदर अस्पताल बनाया है कि आज पूरा हिंदुस्तान उसे देखने आता है। अटल टनल जोकि माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, जिसे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। 3200 करोड़ रुपये से बनी यह अटल टनल आज विश्व की सबसे ऊंची टनल है और विश्व में नंबर वन मानी जाती है। सभापति महोदय, पिछले 3 सालों में हिमाचल प्रदेश को एस0डी0आर0एफ और एन0डी0आर0एफ0 से करीब 6,000 करोड़ रुपये मिले हैं। इससे सड़कों की मरम्मत हुई है। हिमाचल प्रदेश सरकार बताए कि अपने बजट से कितना पैसा सड़कों पर लगाया, क्योंकि यह पैसा केंद्र ने नेशनल डिजास्टर रिलीफ फण्ड से दिया है। सभापति महोदय, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश को ‟प्रधानमंत्री आवास योजना" से, जो घर डिजास्टर से पिछले साल गिरे थे, उसके लिए

9300 घर नए दिये थे और इस साल 18,000 घर इस योजना के तहत दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त च्प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाछ से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के तीन वर्ष के अंदर ही 5200 करोड़ रुपये दिया जा चुका है। आज हिमाचल प्रदेश में अगर 40,000 किलोमीटर सड़कें हैं, जिनमें से 22,000 किलोमीटर च्प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाछ से बनी हैं। यह स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी जी की देन है। अभी हाल ही में इस स्कीम के अंतर्गत 2200 करोड़ रुपये हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत हुए हैं, जिसमें मेरे चुनाव क्षेत्र के लिए भी लगभग 200 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। इसके लिए मैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। हिमाचल प्रदेश सरकार से हमारी विनती है कि जो 5200 करोड़ रुपये आए हैं, उनका सही से उपयोग किया जाए। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपये का रेल बजट भी मिला है। हिमाचल प्रदेश में च्वंदे भारत ट्रेनछ भी चलाई गई, जिसमें हिमाचल प्रदेश को चार च्वंदे भारत ट्रेन मिली। अब में कांग्रेस

17.02.2026/1740/ए.जी./ए.पी./02

सरकार से पूछना चाहता हूं कि बताईये की आपकी सरकार ने कितनी ट्रेन चलाई। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क भी दिये गये। सभापति महोदय, बिलासपुर में 152 करोड़ रुपये से हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जा रहा है, केन्द्र सरकार इसके लिए बजट का प्रावधान भी कर रही है। आई0आई0आई0टी0 ऊना के लिए 1,300 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। आई0आई0एम0 मण्डी के लिए 500 करोड़ रुपए, मेडिकल कॉलेज के लिए 800 करोड़ रुपए और ऊना में पी0जी0आई0 सैटेलाइट सेंटर के लिए 450 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यह सब केवल स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र की गिनती है। सभापति महोदय, मैं कांग्रेस सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार 60 साल रही, लेकिन वर्ष 2014 से पहले परवाणु से ऊपर फोर-लाइन सड़क पर एक गैंती भी नहीं लगी थी। हम धन्यवाद करते हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और गडकरी जी का, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को स्विट्जरलैंड जैसा बना दिया।

जब आप परवाणु से ऊपर आते हैं और किरतपुर-से-मनाली जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम यूरोप में जा रहे हो। इस फोर-लाइन सड़क के लिए 52,000 करोड़ रुपये दिये गये है। सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार को यह आंकड़ा जरूर सुनना चाहिए। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि 52,000 करोड़ रुपये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रदेश के विकास के लिए दिया है। इस बजट से शिमला-से-मटौर और

श्री ए.टी. द्वारा जारी .....

17/02/2026/1745/AT/ AS /01

श्री बलबीर सिंह वर्मा जारी ....

पठानकोट से मंडी और पिंजौर से नालागढ़-बद्दी तक फोर-लेन के सारे कार्य चल रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश में यह फोर-लेन न बनती तो प्रदेश की स्थिति बहुत दयनीय होती। इसी फोर-लेन के कारण हिमाचल प्रदेश स्विट्जरलैंड की ओर बढ़ रहा है, जिसमें केंद्र सरकार का पूरा सहयोग है।

Chairman : Please wind-up.

श्री बलबीर सिंह वर्मा : सभापति महोदय, अभी तो सिर्फ 25 प्रतिशत हुआ है बस थोड़ा ओर समय लेना चाहता हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में 12 करोड़ से अधिक टॉयलेट बनाए गए। हिमाचल प्रदेश में लगभग 2 लाख टॉयलेट बने। कांग्रेस ने 60 साल राज किया लेकिन हिमाचल में दो टॉयलेट नहीं बना पाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दो लाख टॉयलेट बनाए । ...(व्यवधान)

सभापतिः माननीय सदस्य आर0डी0जी0 पर बोलें।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : सभापति महोदय, इन्होंने सारी बातें केंद्र सरकार पर कही, लेकिन प्रदेश की बात नहीं की केंद्र ने यह नहीं किया, केंद्र ने वह नहीं किया। हम यह कहना चाहते हैं कि केंद्र ने कितना किया है यह सब इनके सामने है। जल जीवन मिशन के तहत

हिमाचल प्रदेश को 4,500 करोड़ रुपये दिए गए। उप-मुख्यमंत्री जी इस आंकड़े को और स्पष्ट करेंगे। इससे लगभग 10 लाख घरों को नल से जल की सुविधा मिली है।

Chairman : Please wind-up.

श्री बलबीर सिंह वर्मा : सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश में दुर-दराज के किसान, बागवान और गरीब लोगों के पास चूल्हा-सिलेंडर नहीं था। 4,63,000 गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। "जन धन योजना" के तहत 17,53,000 बैंक खाते खोले गए। कांग्रेस पार्टी गरीबों के खाते नहीं खुलने देती थी, लेकिन हमारी सरकार ने योजना लाई कि हर गरीब का बैंक में खाता खुले और सीधे पैसे उसके

17/02/2026/1745/AT/ AS /02

खाते में जाएं। इसका लाभ यह हुआ कि लगभग 10 लाख हिमाचल के गरीब किसानों के खातों में पैसा आ रहा है। जो "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना" के तहत मिल रहा है।

सभापति महोदय, चंबा, नाहन और मण्डी मेडिकल कॉलेज के लिए आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की देन है। प्रदेश में तीन आधुनिक आई0सी0यू0 ब्लॉक इस साल के अंत तक बन जाएंगे। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना और आई0जी0एम0सी0 में कैंसर अस्पताल का नया ब्लॉक भी हिमाचल को मिला है। यह भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नडा जी के सहयोग से सिर्फ शिमला शहर के लिए ही 800 करोड़ रुपये स्वास्थ्य क्षेत्र में दिए गए हैं। ...(व्यवधान)

Chairman : Please wind-up. माननीय सदस्य 17 मिनट समय हो गया है।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस बताए किस गरीब परिवार का इलाज उन्होंने किया? आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 80 करोड़ गरीब परिवारों के इलाज के लिए "आयुष्मान भारत योजना" शुरू की, जिसके

तहत हिमाचल प्रदेश के लगभग 11 लाख गरीब लोगों का 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज हो रहा है। ...(व्यवधान)

Chairman : Hon'ble Member, please wind-up.

श्री बलबीर सिंह वर्मा : आपने सिर्फ यह कहा कि हिमाचल को कुछ नहीं दिया गया। मैंने वह आयना दिखाया है कि हिमाचल को क्या दिया है? ...(व्यवधान)

Chairman : Hon'ble Member, please wind-up. ...(Interruption) Hon'ble Member, please address to the Chair.

श्री बलबीर सिंह वर्मा : सभापति महोदय, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपए होता था। केंद्र सरकार ने 12 लाख 20 हजार करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा गया है, जिसका लाभ हिमाचल प्रदेश को भी इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा।

17/02/2026/1745/AT/ AS /03

यदि कांग्रेस के विधायक चाहते हैं तो हम सब मिलकर आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे और विकास के लिए स्कीम-वाइज पैसा देने का अनुरोध करेंगे। अगर कांग्रेस कोई विधायक यह चाहते हैं तो हम मोदी जी से प्रार्थना करेंगे कि इनके खाते में डालें पर विकास के लिए नहीं , विकास के लिए स्कीम-वाइज हिमाचल प्रदेश को मिले जिससे हिमाचल प्रदेश का विकास हो और हिमाचल प्रदेश का विकास दिखे। यह हम सभापति महोदय, कहना चाहते हैं। ...(व्यवधान)

Chairman : Hon'ble Member, please wind-up.

श्री बलबीर सिंह वर्मा : सभापति महोदय, अब मैं काम की बात करता हूं।

एम0डी0द्वारा जारी ......

17-02-2026/1750/AS/MD/1

श्री बलबीर सिंह वर्मा---जारी

2500 करोड़ रूपया आप हर 50 वर्ष के लिए लोन ले सकते हैं without any interest.

सभापति : आपको बोलते हुए 19 मिनट हो चुके हैं। माननीय सदस्य बाकी सदस्यों ने भी बोलना है। आप अपने बाकी सदस्यों का समय ले रहे हैं। आपके बाकी सदस्यों पर कट लगेगा।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : यह भी हिमाचल प्रदेश को हमेशा फायदा देने वाला है। 2,500 करोड़ रुपये 50 साल के लिए हैं और 50 वर्ष के बाद रिफंड करना है। 50 वर्ष के बाद न हम रहेंगे, न आप रहेंगे जो भी रहेंगे वह बिना इंटरेस्ट के इसे लौटाएंगे। यह सबसे बड़ा बेनिफिट है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि 15वें फाइनेंस कमीशन में हिमाचल को 11,000 कुछ करोड़ रुपये मिलते थे। अब 16वें फाइनेंस कमीशन में हिमाचल को 13,000 कुछ करोड़ रुपये मिलने हैं, जिसमें 2,300 करोड़ रुपये अतिरिक्त हर साल हिमाचल प्रदेश को मिलेंगे। इसका भी हिमाचल प्रदेश को फायदा होना है। सभापति महोदय, बातें तो बहुत सारी थी।

Chairman : Please wind-up. Otherwise मैं अब जल्द ही अगले मेंबर को बुलाऊंगा आपको बोलते हुए 20 मिनट हो गए। बाकी सदस्य रह जाएंगे फिर समय सबका कंज्यूम हो जाएगा। माननीय सदस्य please wind-up.

श्री बलबीर सिंह वर्मा : सभापति महोदय, मैं थोड़ा सा माननीय संसदीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यहां पर माननीय सदस्य ने 40-45 मिनट बोला है, और मुझे तो अभी 20 मिनट भी नहीं हुए हैं, सर। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और फॉरेन एडेड स्कीम है, फॉरेन एडेड स्कीम से 1,500 करोड़ रुपये हिमाचल को मिल रहे हैं जिसकी गारंटी केंद्र सरकार दे रही है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 196 हैं। सभापति महोदय मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि अगर खर्चा कम करना चाहते हैं, तो खर्चे कम करने का काम पहले सरकार को करना पड़ेगा, फिर विधायकों को, फिर

17-02-2026/1750/AS/MD/2

अधिकारियों को, फिर कर्मचारियों को ऊपर से नीचे तक लाना पड़ेगा। पहले मंत्रालय को अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, फिर विधायक, फिर अधिकारी, फिर कर्मचारी, और फिर पूरे प्रदेश में। आप एक और स्कीम लाइए हिमाचल प्रदेश की हर जनता 1,35,000 रुपये के कर्ज में है। कोई कर्ज मुक्ति स्कीम लाइए, ताकि जो लोग हिमाचल में कर्ज मुक्त होना चाहते हैं, वे अपने पैसे जमा करवा सकें। इससे रेवेन्यू भी जनरेट होगा। बहुत से लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट भी इसमें आगे आएंगे। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि वर्ष 1992 से पहले हिमाचल प्रदेश के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और समाजसेवी कर्जामुक्त इस दुनिया से गए हैं। लेकिन हम सब कर्ज लेकर इस दुनिया से जाएंगे।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

17-02-2026/1750/AS/MD/3

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री हरीश जनारथा जी भाग लेंगे।

श्री हरीश जनारथा : सभापति महोदय, मैं सिर्फ एक सैकेंड़ लूंगा। मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि शिमला शहर में जो 800 करोड़ रुपये आए हैं, वह किस हॉस्पिटल के लिए आए हैं? यह एक बात है। दूसरी बात, कौन सा हॉस्पिटल है हमें तो विधायक होने के नाते इसकी जानकारी नहीं है। Thank you very much अगर आया है, तो उसकी नोटिफिकेशन भी हमें दे दीजिए। और जो इन्होंने आंकड़े गिनाए हैं, प्लीज उन्हें जरा सोच-समझकर टेबल पर रखा जाए। क्योंकि अभी इन्होंने 15-17 मिनट बोला है। अगर यह पूरा आधा घंटा बोल देते, तो शायद पाकिस्तान और बांग्लादेश का बजट भी यहीं ले आते। तो अब वे कागजात टेबल पर लाए जाएं और उसके साथ हम उन्हें टैली करेंगे और जो 800 करोड़ रुपये आए हैं प्लीज उसके कागजात मुझे भी दे दिए जाएं।

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी भाग लेंगे।

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी---

17.02.2026/1755/केएस/डीसी/1

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर : सभापति महोदय, जो यूनियन बजट 1 फरवरी, 2026 को माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया, हिमाचल के इतिहास में वह काला दिन

कहलाएगा क्योंकि हिमाचल के साथ कुठाराघात हुआ है। हिमाचल के साथ फरेब हुआ है और हिमाचल को बहुत हलके में लिया गया है। हिमाचलियत को और हिमाचल की देवभूमि में एक साजिश के तहत फाइनेंशियल क्राइसिज़ पैदा करने की कोशिश की है। यह वही विचारधारा है जिसका हम स्मरण करवाना चाहेंगे कि जब हिमाचल का गठन हो रहा था तो कहते थे कि स्टेट हुड मारो ठुड, उन्होंने अपने इरादे फिर से दिखाए हैं। राजस्व घाटा अनुदान बंद करके यह नारा भी हमेशा याद रहेगा जिस तरह से वह नारा याद रहता है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। आज यही स्थिति हमारे विपक्ष के साथियों की भी है कि हिमाचल के साथ कुठाराघात हुआ है और आपको सिर्फ इस बात की पड़ी है कि आप ऑप्रेशन लोटस में विफल हुए और आप उसके बाद हिमाचल को फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ धकेलना चाहते हैं। आपके मन में मात्र एक बात है और उप-मुख्य मंत्री जी ने आज सुबह बिल्कुल सही कहा कि जब आर0डी0जी0 बंद हुई तो नेता प्रतिपक्ष ने कहना शुरू कर दिया कि चुनावों के लिए तैयार हो जाएं। बहुत सारी बातें हैं लेकिन जैसा संवेदनशील रवैया आपका पिछले दो दिनों में देखने को मिल रहा है, शायद यहां पर पत्रकार दीर्घा के लोगों के माध्यम से यह आवाज हिमाचल के कोने-कोने तक पहुंच रही है। लोग देख रहे हैं कि राजनीति आपकी प्राथमिकता पर है या हिमाचल का हित प्राथमिकता पर है। बात हिमाचल की है, हिमाचलियत की है, 75 लाख जनता की है, किसानों/बागवानों, कर्मचारियों और पैंशनधारकों की है। This issue of Revenu Deficit Grant (RDG) is not merely about number or account entries but about the financial survival, development and future of our beloved State. आज जो आर0डी0जी0 जिसको आप कह रहे हैं कि this is not a favour or charity but a constitutional mechanism designed to support structurally weak hilly State of Himachal Pradesh. आंकड़े काफी आ गए हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा but is this the model of co-operative federalism which was promised? क्या हम संघीय ढांचे का हिस्सा नहीं हैं? मुख्य मंत्री जी कितनी बार अध्यक्ष, वित्तायोग को मिले, कितनी बार निर्मला सीतारमण जी को मिले और कहीं भी हमें यह एहसास नहीं था, ना रिकमेंडेशन है कि आर0डी0जी0 को बंद किया जाए। मैं एक

17.02.2026/1755/केएस/डीसी/2

बात और कहना चाहूंगा कि हिल रीज़न के structural disadvantages हैं। क्या हमारे पहाड़ समतल हो गए हैं? क्या हमारी ऊंची-ऊंची चोटियां समतल हो गई हैं या हमारे पहाड़ वैनिश हो गए हैं? Hill states must not be punished for structural realities which are beyond their control. जो हम ज्योग्राफिकल कंडिशन्ज़ झेल रहे हैं, वह हमारे कंट्रोल में नहीं है। कंफ्रंटेशन की बात नहीं है यह constitutional assertion की बात है कि हम कैसे अपनी बात को संवैधानिक तौर पर आगे रख सकते हैं। एक लाइन में उत्तर होना चाहिए था कि हिमाचल की आ0डी0जी0 जो हमारा एक संवैधानिक अधिकार था, उसके बंद होने पर आपकी अगुवाई हो।

(श्री आशीष बुटेल, सभापति महोदय पदासीन हुए)

किसी की भी अगुवाई में हो । अपने मुद्दों को रखने के लिए आप हिमाचल के हित के साथ हैं या नहीं हैं?

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

17.02.2026/1800/av/dc/1

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर-------- जारी

यह एक प्रश्न है और उसके साथ में आपने कहा कि बहुत सारा मिसमैनेजमैंट हो रहा है। कोरोना का युग था और आपने उसमें भी अवसर ढूंढे। आपके अपने लोग उसमें सम्मिलित पाए गए। कोरोना के बाद वर्ष 2022 में आपने 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' पर सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया। आपको वह भी याद करना चाहिए।

यहां पर अभी श्री सतपाल सिंह सत्ती जी नहीं बैठे हैं। यहां पर श्री सुख राम चौधरी जी बैठे हैं। वर्ष 2009 से 2012 तक तो आप भी सी0पी0एस0 रहे हैं और आपने भी झण्डी-डण्डी का पूरा लुत्फ उठाया है, आप इस बात को क्यों भूल जाते हैं? श्री वीरेन्द्र कंवर जी इस बार

सदन में नहीं हैं परंतु वे भी सी0पी0एस0 रहे। लेकिन आपने विधायकों की संस्था को चुनौती दी क्योंकि आप अपने दुःख से इतने दुःखी नहीं हैं जितने कि हमारे सुख से दुःखी हैं। आपको यह तकलीफ बहुत अरसे से चली हुई है जिसके लिए आपने बहुत प्रयास कर लिए हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष के अहंकार की बातें ऑपरेशन लॉट्स के वक्त सामने आई। उन्होंने उस वक्त भगवान को भी नहीं माना और कहा कि आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। परंतु देव भूमि के देवी-देवताओं की वजह से हम उस कड़ी में आगे बढ़े हैं। मगर अब तो वे भविष्य वक्ता भी बन गए हैं। वे कुछ दिन पहले कुल्लू आकर बोल रहे थे कि यहां के विधायक महोदय यह सपना पाले बैठे हैं कि वे मंत्री बनेंगे। शायद इस जन्म में उनका यह सपना पूरा नहीं होगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी यह सपना लिया था कि आप कभी प्रदेश के मुख्य मंत्री बनेंगे? आप भी तो (***) बने हैं। उसके बाद आपको बहुत सारा ज्ञान आ गया। लेकिन उस वक्त क्या हालात थे? आपने कुल्लू की अनदेखी किस प्रकार की थी, उस समय कुल्लू के अस्पतालों के क्या हालात थे? उस वक्त कुल्लू के टूरिज्म की क्या हालत थी, उसके बारे में कुल्लू की जनता बखूबी जानती है।

यहां पर जो हमारे भाई लोग जीते हैं वे भी त्रिकोणीय प्रकार से जीते हैं। अगर सीधे तौर पर हमारे लोग एकत्रित हो जाते तो वोट प्रतिशतता हमारी ज्यादा है। ...(व्यवधान) अच्छी बात है, मैं कहता हूं कि आप जीतिए। परंतु कम-से-कम अपनी संस्था को तो चैलेंज मत कीजिए। प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ कि विधायक की संस्था को विधायक ही चैलेंज कर रहे हैं। आप यहां पर मण्डी की बात करते हैं। पंडित

(***) **अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।**

17.02.2026/1800/av/dc/2

सुख राम जी के समय में भी मण्डी एकजुट रहती थी। मण्डी विकास के लिए एकजुट हो जाता है और उसमें कुल्लू भी साथ होता है। श्री जय राम ठाकुर जी की तरह आप पूरे विकास को केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र सिराज़ तक ही सीमित मत कीजिए। मैं आज एक

बात कहना चाहता हूं कि सिराज़ में जो नुकसान हुआ है वह वहां पर अनप्लान्ड रोड निकालने तथा हेलीपैड व हैलीपोर्ट बनाने की वजह से हुआ जिनका मलवा हर कहीं डम्प कर दिया गया तथा पेड़ों को डम्पिंग के नीचे दबा दिया गया। उसी वजह से ...(व्यवधान) श्री इन्द्र सिंह जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। कुल्लू में वर्ष 2023 में भारी नुकसान हुआ था। परंतु आपने उस वक्त उस नुकसान को नुकसान नहीं माना था। ...(व्यवधान) यहां पर जब उस बारे में चर्चा हुई थी तो आपने उस नुकसान को नुकसान नहीं माना था। आज जब अपने ऊपर पड़ती है तब आपको नुकसान का पता चलता है। वर्ष 2023 में हम बोलते रह गए कि माननीय प्रधानमंत्री का कुल्लू का दौरा करवाइए क्योंकि वे सेपू-बड़ी की बातें करते हैं। वर्ष 2023 में जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा हमें वर्ष 2025 और वर्ष 2026 में मिल रहा है और वह भी पूरा नहीं मिल रहा है। उस समय 12-12 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और उसकी एवज में हमें वर्ष 2025 में 400 करोड़ रुपये की राशि मिल रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर समय रहते राहत न मिले then 'justice delayed is justice denied'. मैं यह कहना चाहता हूं।

टी सी द्वारा जारी

17.02.2026/1805/टी0सी0वी0/एच0के0-1

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर .. जारी

कि सी0पी0एस0 पहले भी रहे और आज भी इनकी लड़ाई जारी है। श्री विक्रम ठाकुर जी कह रहे थे कि अभी भी समय है और अभी भी कुछ हो सकता है लेकिन जो भी होगा वह भविष्य के गर्भ में है। अब यह केवल हिमाचल की बात नहीं है, पूरे भारतवर्ष का विषय है। इसलिए भविष्यवक्ता बनने की आवश्यकता नहीं है। आप कह रहे हैं कि तैयार हो जाइए, सत्ता आने वाली है। अभी 21 महीने हैं लेकिन सरकार में 20 दिन भी बहुत होते हैं। 20 दिन में हवा बदलती है और हवा बदलने के उदाहरण लाहौल और मनाली में भी सामने आए हैं।...(व्यवधान) वह भी सब होगा। आप चिंता न करें। मित्रों, 1500 करोड़ रुपये का क्या हुआ? 1500 करोड़ रुपये तो मिले ही नहीं। 1500 करोड़ रुपये की मांग को किए हुए 6

महीने हो गए लेकिन वह राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी ने यह सबके सामने कहा है इसलिए 1500 करोड़ रुपये मांग लीजिए।

मैं मुख्य मंत्री जी, उप मुख्य मंत्री जी और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं, किसको क्या मिला और किसको क्या नहीं मिला, यह मुख्य विषय नहीं है। मुख्य विषय यह है कि हम सबको एकजुट होकर एक संदेश देना है। मुख्य मंत्री जी ने जो संदेश दिया है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ओ0पी0एस0 को बंद नहीं होने दिया जाएगा। पेंशनधारकों, किसानों और बागवानों के लिए 10 गारंटी पर कार्य चलता रहेगा। यह बहुत उत्साहवर्धक बात है और इसके लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं। कहा जाता है कि "The darkest hour of the night is the harbinger of the day." जब घनघोर अंधेरा होता है उसके बाद ही सुबह होती है। इस समय मुख्य मंत्री जी ने जो बातें कही हैं उससे हम पूर्ण रूप से आशावादी हैं कि यह कठिन समय भी निकल जाएगा और आगे अच्छे दिन भी आएंगे लेकिन इस बात को भी याद रखा जाएगा कि जब प्रदेश आर्थिक तंगहाली से जूझ रहा था, उस समय विपक्ष ने साथ नहीं दिया। ओ0पी0एस0 के कारण एन0पी0एस0 की जो राशि आनी चाहिए थी, वह नहीं आ रही है और उस पर अन्य वित्तीय सीमाएं भी लगाई गई हैं। जैसे मुख्य मंत्री जी ने बताया कि आपके समय में 70000 करोड़ रुपये मिले और यहां 17000 करोड़ रुपये मिले। आपके समय में यदि 01 रुपया मिला, तो हम 0.25 रुपये में भी काम चला रहे हैं और बेहतर ढंग से कार्य कर रहे हैं। इसमें आगे और सुधार होगा। 21 महीनों में स्थिति और बेहतर होगी।

17.02.2026/1805/टी0सी0वी0/एच0के0-2

मेरा आपसे अनुरोध है कि इस समय राजनीति छोड़कर सदन को एकजुटता दिखाने का वक्त है। अपने अधिकारों की लड़ाई मिलकर लड़ने का समय है। राजनीति के लिए आगे भी बहुत अवसर मिलेंगे। अभी पंचायत चुनाव होंगे लेकिन वे चुनाव चिन्ह पर नहीं होते हैं। पिछली बार हमने कुल्लू और शिमला में जिला परिष्द् की सीटें जीती थी लेकिन बाकी जगह नहीं जीत पाए। इस समय आवश्यक है कि पूरा सदन एकजुट होकर हिमाचल और हिमाचल के हित की बात करे। मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी या आपके (विपक्ष) के साथ पूरा सदन आगे बढ़ने के लिए तैयार है।

अंत में, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि केदारनाथ त्रासदी के समय तत्कालीन यू0पी0ए0 सरकार द्वारा जो राहत पैकेज दिया गया था, उस संबंध में मैंने पहले भी चर्चा की थी। उस समय आपने कहा था कि ये तथ्य गलत हैं लेकिन उससे संबंधित दस्तावेज आज भी सदन में प्रस्तुत किए गए हैं। उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उस समय केन्द्र सरकार ने पहाड़ी राज्यों को किस प्रकार से लाभ पहुंचाया था।

एन0एस0 द्वारा जारी ....

17-2-2026/1810/एन0एस0-एच0के0/1

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर -----जारी

मैं मुख्य मंत्री जी व संसदीय कार्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि वे इस सदन में यह प्रस्ताव लेकर आए और जिस प्रकार से सभी माननीय सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया है, हम आपसी मतभेद भूल कर एकजुटता दिखाएं तो बहुत बेहतर होगा जिससे हिमाचल प्रदेश में एक अच्छा संदेश जाएगा।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

17-2-2026/1810/एन0एस0-एच0के0/2

सभापति : श्री विपिन सिंह परमार जी आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री विपिन सिंह परमार : सभापति महोदय, आर0डी0जी0 के ऊपर चर्चा हो रही है और विधायक जी ने बहुत ज्ञान दिया है तथा नेता प्रतिपक्ष उस समय यहां पर नहीं थे। इस माननीय सदन में जो भी विधायक चुन कर आए हैं वे लोगों के आशीर्वाद से आए हैं। श्री जय राम ठाकुर जी को सिराज की जनता ने 6 बार जीता कर यहां भेजा है। पार्टी के निर्णय के बाद ये उस समय नेता बने थे और हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री बने थे। इसलिए आपने जिस शब्द का प्रयोग किया है कि (***) मुख्य मंत्री हैं। एक तो इन शब्दों को एक्सपंज किया जाए और कार्यवाही से निकाला जाए ...(व्यवधान) यह बिल्कुल गलत है। एक

प्रतिनिधि को इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना और वह भी चुने हुए प्रतिनिधि और 6 बारे के विधायक के बारे में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है। ...(व्यवधान) सभापति महोदय, जो भी यहां पर जीत कर आते हैं वे अपने विधान सभा क्षेत्र के विकास के लिए कोशिश करते हैं। ये मंत्री बनने के चक्र में मुख्य मंत्री जी को खुश करना चाहते हैं। ...(व्यवधान) इसलिए कोई यह कहे कि वहां पर अगर स्टेट हैड, नाबार्ड, सी0आर0एफ0 या पी0एम0जी0एस0वाई0 से रोड कनैक्टिविटी गांव-गांव में पहुंची तो वह हर विधायक का प्रयास होता है। लेकिन इन शब्दों का प्रयोग करना कि वहां पर मलबा और पेड़ों को कटिंग के बाद नीचे फैंके गए और उसके बाद उसके ऊपर मलबा डाल दिया गया तथा जब बरसात हुई तो उसके कारण यह आपदा आई। सभापति महोदय, इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण करना और एक तरफ ये कह रहे हैं कि विधायक संस्था मजबूत होनी चाहिए, सी0पी0एस0 के बारे में टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए।

17-2-2026/1810/एन0एस0-एच0के0/3

सभापति : माननीय परमार जी, आप अपना प्वाइंट रखें।

श्री विपिन सिंह परमार : मैं यही कह रहा हूं कि इन शब्दों को एक्सपंज किया जाए और मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि मिल करके दिल्ली चलते हैं तो क्या आपकी भावना साथ में चलने की है? यहां से आप किसी को खुश करने के लिए किसी भी प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं और यह आचरण ठीक नहीं है। इसलिए हम इनके शब्दों से हर्ट हुए हैं और उनको विड्रॉ किया जाए तथा जो (***)जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है और जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है तो ये असंसदीय हैं। मैं यही कहना चाहता हूं। विधायक महोदय मुख्य मंत्री जी को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और मैं यही बोलने के लिए खड़ा हुआ था।

आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

सभापति : संसदीय कार्य मंत्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री : सभापति महोदय, श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी ने जो वक्तव्य दिया है तो इन्होंने बहुत पॉजिटिव बोला है और इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बोली है जो हमारे माननीय विपिन सिंह परमार जी बोल रहे हैं। अब (***) शब्द असंसदीय शब्द नहीं है। अब जो भी हुआ है तो वह सबको पता है कि बी0जे0पी0 के जो डिक्लेयर्ड चीफ मिनिस्टर थे तो वे प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी थे। ...(व्यवधान) वे चुनाव हार गए। ...(व्यवधान) माननीय धूमल साहब

(***) **अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।**

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

17.02.2026/1815/RKS/वाईके-1

संसदीय कार्य मंत्री जारी

वह चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद भाजपा विधायक दल ने श्री जय राम ठाकुर जी को मुख्य मंत्री बनाया। श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी ने बड़ी पोजिटिव बात कही है। इन्होंने कहा कि कुल्लू भी मण्डी लोकसभा संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। इन्होंने पिछले पांच साल के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि सिराज विधान सभा क्षेत्र में सबसे ज्याद विकास हुआ है। ...(व्यवधान) जो बातें हुई उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड का सही आबंटन न होने के कारण सिराज में ज्यादा विकास हुआ है। हम राजनीतिक लोग हैं और हम ऐसी बातें करते हैं लेकिन आप इसको पर्सनली क्यों ले रहे हैं? आपने सी0पी0एस0 की बात की। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या सी0पी0एस0 कांग्रेस के राज में ही बनाए गए हैं? हमने वर्ष 2005 में सी0पी0एस0 बनाए। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने हमारे खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की और हमारे सदस्यों को हाई कोर्ट ने अनशीट कर दिया। फिर इन्होंने इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अनशीट करने के लिए याचिका दायर की मगर

इलैक्शन कमीशन ने अनशीट नहीं किया। वर्ष 2007 में भाजपा की सरकार आ गई। वर्ष 2007 में श्री सुख राम चौधरी, श्री विरेन्द्र कंवर और श्री सतपाल सिंह सत्ती जी सी0पी0एस0 थे। वर्ष 2005 में आपका नजरिया कुछ और था लेकिन जब आपकी बारी आई तो आपका पैमाना कुछ और हो गया। आपकी पार्टी के तीन सी0पी0एस0 वर्ष 2007 से वर्ष 2012 तक रहे। कांग्रेस पार्टी ने इसका कोई एतराज नहीं किया और न ही कभी मीडिया में इसके बारे में चर्चा की। हमने माननीय उच्च न्यायालय में भी इसके विरुद्ध कोई याचिका दायर नहीं की। ...(व्यवधान) फिर भाजपा की सरकार आई और इन्होंने मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक की पोस्ट किएट की। आपके दो माननीय सदस्य मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक बने। हमने इसका कोई एतराज नहीं किया। हमने कहा कि पोलिटिकल लोग हैं इसलिए हमने इसका न तो विरोध किया और न ही समर्थन। आपके दो माननीय विधायकों ने इस पोस्ट में बैठकर पांच साल तक सत्ता का सुख भोगा। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने यह किया तो आपने फिर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। यह भारतीय जनता पार्टी का दोहरा मापदंड है। कहते हैं कि 'हाथी के दांत खाने के और,

17.02.2026/1815/RKS/वाईके-2

दिखाने के और'। श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी ने ऐसी कोई बात नहीं की जो इन्हें गलत लग रही है। अगर श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी मंत्री बनेंगे तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी या श्री जय राम ठाकुर जी की कृपा से बनेंगे? यह ठीक है कि बाहर इस तरह की टिप्पणियां की जा सकती हैं। मगर हमें पर्सनल लैवल पर इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

सभापति : माननीय नेता प्रतिपक्ष जी।

श्री जय राम ठाकुर : माननीय सभापति महोदय, मैं तो सदन में उपस्थित नहीं था लेकिन चलते-चलते मैं इन सब बातों को सुन रहा था। मेरी गैर-मौजूदगी में कुछ टिप्पणियां की गईं जिनका जिक्र श्री विपिन सिंह परमार जी ने किया। ...(व्यवधान) जब आप बोल रहे थे तो हम आपकी बात सुन रहे थे। अब आप बैठ जाइए। हमने कभी भी किसी को अपमानित

करने के लिए शब्दों का चयन नहीं किया है। सभापति जी वे अभी भी बैठकर बोल रहे हैं। आप उनकी बात को सुनिये। ...(व्यवधान) (***)...(व्यवधान) मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आज यह शब्द बोल रहा हूं।

सभापति : माननीय श्री जय राम ठाकुर जी आप अपना प्वाइंट रखिए। आप बताइए कि आपका क्या प्वाइंट है? ...(व्यवधान)

श्री जय राम ठाकुर: मैं यहां पर बोलूं कि मैंने क्या बोला है?

(***) **अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।**

श्री बी0एस0द्वारा जारी

17.02.2026/1820/बी.एस./.वाई. के.-1

श्री जय राम ठाकुर जारी..

... (व्यवधान)

मैं यहां पर बोलू कि मैंने क्या बोला है? मैंने यह बोला है कि हमारे पार्टी के सार्थियों ने यह बोला है कि दशहरे के लिए जय राम ठाकुर को भी बुला लेते हैं और यह परंपरा रही है और हम बुलाते रहते हैं। कभी मण्डी में बुलाते हैं, शिवरात्रि का पर्व होता है। न, न उनको मत बुलाइए। मेरी तो मंत्रिमंडल की मेंबरशिप, ... (व्यवधान)

Chairman : Shri Jai Ram Thakur Ji, that is not a discussion that we have to take here. Sorry. This is not a discussion.

श्री जय राम ठाकुर : सभापति महोदय, इनको आपने आधा घंटा बोलने दिया।

सभापति : माननीय सदस्य आधा घंटा नहीं बोले हैं। He is well within the time. ...(Interruption)

श्री जय राम ठाकुर : उसके बाद लाइटर मूड में जब पार्टी के साथियों के साथ हमारी मीटिंग हो रही थी तो मैंने इतना ही कहा कि भई कोई बात नहीं हम नहीं आए लेकिन उसके बावजूद वे बने नहीं और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में भी उनकी बनने की संभावना होगी क्योंकि मुख्य मंत्री बनाना नहीं चाह रहे हैं।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर: ऐसा बोला गया है कि इस जन्म में नहीं बनेंगे।

श्री जय राम ठाकुर : नहीं, मैंने (***)शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। आप एक लिमिट में रहिए। आपकी बात करने का तौर-तरीका कैसा है?

Chairman : You please make your point. ...(Interruption) आदरणीय सुन्दर सिंह ठाकुर जी। ... (व्यवधान)

श्री जय राम ठाकुर : एक सीमा तक आपको बोलना चाहिए। आप बोलते हैं (***)मैं व्यवस्था के अनुसार मुख्य मंत्री बना हूं।

सभापति : यह बात चर्चा के दौरान आ गई है।

(***) **अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।**

17.02.2026/1820/बी.एस./.वाई. के.-2

श्री जय राम ठाकुर : एक व्यवस्था के अनुसार में मुख्य मंत्री बना हूं। मैं आपकी कृपा से नहीं बना हूं। यहां आदरणीय मुकेश जी विपक्ष के नेता थे, यहां विपक्ष के नाते मुकेश जी लड़ाई लड़ते रहे हमारी लड़ाई आमने-सामने होती थी लेकिन भाग्य को मंजूर था कि मुख्य मंत्री आदरणीय सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी बने। आदरणीय कौल सिंह ठाकुर जी हार गए और आदरणीय आशा कुमारी जी भी हार गई।

सभापति : ठाकुर साहब, वह बात आ गई है। आदरणीय विपिन सिंह परमार जी ने बोल दिया।

श्री जय राम ठाकुर : आप गलत बातों को जस्टिफाई कर रहे हैं। (***)

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर : हम डरने वाले नहीं हैं।

श्री जय राम ठाकुर : ऐसा नहीं होता किसी भी चीज की एक लिमिट होती है, सीमा होती है।

सभापति : कृपया, बैठ जाइए।

श्री जय राम ठाकुर : (***)

सभापति : ठाकुर साहब, आपका यह विषय आ गया है।

श्री जय राम ठाकुर : (***)

Shri Sunder Singh Thakur : (***)

Shri Jai Ram Thakur : (***)

सभापति : माननीय सदस्य कृपया शांत रहें और विधान सभा में शांत महौल बनाएं और जो सार्थक चर्चा यहां पर हो रही है उसे हम कंटीन्यू करें। मुख्य मंत्री महोदय कुछ कहना चाह रहे हैं।

मुख्य मंत्री : सभापति महोदय, ... (व्यवधान)

(***) **अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।**

17.02.2026/1820/बी.एस./.वाई. के.-3

Chairman : Please let him speak. Hon'ble Chief Minister is speaking, please let him speak. ...(Interruption)

मुख्य मंत्री : सभापति महोदय, मैं यह चाहूंगा कि हमारे पूर्व मुख्य मंत्री इस सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और जब बातचीत होती है और तकरार होती है तो आपको किसी चीज को व्यक्तिगत तौर पर लेने की जरूरत नहीं है।

श्री जय राम ठाकुर : इन्होंने व्यक्तिगत तौर पर ही बोला है।

मुख्य मंत्री : कृपया मुझे बोलने दीजिए। मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री होता है उसमें कोई दो राय नहीं है। ... (व्यवधान)

सभापति : आदरणीय सुन्दर सिंह ठाकुर जी, आदरणीय विनोद जी कृपया बैठ जाइए।

मुख्य मंत्री जी आप अपनी बात कहिए।

श्री जय राम ठाकुर : इन्होंने गलत बोला है।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

17.02.2026/1825/डीटी/ए0जी0-1

सभापति : माननीय सदस्य श्री सुंदर सिंह जी प्लीज। ...(व्यवधान) Please be quiet. ...(व्यवधान) श्री विनोद जी कृपया बैठ जाइए। ...(व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्री जी।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

मुख्य मंत्री : माननीय सभापति महोदय, मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा शांत रहे गुस्सा न करें। सदन के अंदर पक्ष और विपक्ष के बीच में कई बार ऐसा होता है इसलिए नेता प्रतिपक्ष को भी इतना गुस्सा आना ठीक नहीं है। मुख्य मंत्री-मुख्य मंत्री होता है और अगर कोई ऐसी बात है तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम इन शब्दों को विड्रा कर लेंगे। लेकिन एक बात इन्होंने भी कही है जो मैंने भी सुनी है। इन्होंने कहा कि आप इस जन्म में कभी भी मंत्री नहीं बनेंगे। ...(व्यवधान) आप ने बोला मैं आपको देखूंगा-यह आपने अभी बोला। मैं इसको देखूंगा यह शब्द आपने बोला। ...(व्यवधान) मैं यह कहना

चाहता हूं कि सुंदर सिंह जी भी सम्मानित सदस्य हैं। सुंदर जी की तरफ से आपको जल्द ही लोकभवन आने का इनविटेशन मिल जाएगा कि यह मंत्री बनने जा रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूर्व मुख्य मंत्री जी को यह कहना चाहता हूं ...(व्यवधान) जब माननीय सदस्य श्री सुंदर सिंह जी जब पूर्व में विपक्ष में थे उस समय मैं भी इनके साथ ही था कुछ चीजों का आपको भी ध्यान रखना चाहिए जब आप मुख्य मंत्री की कुर्सी पर थे। इनके कुल्लू शोभला होटल का मेन गेट तोड़कर रख दिया। यह मेरे पास आए इन्होंने यह बात मुझे यह बात बताइ। ...(व्यवधान) मैं आपको यह बात बता रहा हूं----(व्यवधान) आप थोड़ा सा शांत रहिए ठाकुर साहब----(व्यवधान)

Speaker: No personal references, please.

17.02.2026/1825/डीटी/ए0जी0-2

मुख्य मंत्री : नेता प्रतिपक्ष आप थोड़ा शांत रहिए। (व्यवधान) मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि सदन में कई बार तर्क-वितर्क होते हैं जब आप किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं तो दूसरा आदमी भी पीछे नहीं रहता। जब इस प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणियां होती हैं तो कई बार इस प्रकार का आपसी विवाद पैदा हो जाता है। अगर माननीय सदस्य श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी को मंत्री बनाना है तो वह कांग्रेस पार्टी ने तय करना है, संसद में हमारे विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी ने और हमने तय करना है। अब आपने बोल दिया कि आप कभी भी मंत्री नहीं बनेंगे, इसको समझाओ यह बात आपने अभी मेरे सामने कही है। अगर कोई (***) शब्द इन्होंने बोला है तो हम कह रहे हैं कि उसे कार्यवाही से निकाल दीजिए। लेकिन कार्यवाहीं से वे शब्द भी निकालने पड़ेगे जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने माननीय सदस्य श्री सुंदर सिं के विरूद्ध कहे हैं। ...(व्यवधान) अभी मेरे सामने बोला कि इसको देखो। ...(व्यवधान) मेरे सामने बोला है और आप मेरी बात भी ...(व्यवधान) मेरे कहने का अर्थ है कि माननीय सदस्य श्री सुंदर सिंह के विरूद्ध जो भी व्यक्तिगत टिप्पणी

हुई हैं उसको भी सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए और नेता प्रतिपक्ष के विरूद्ध जो व्यक्तिगत टिप्पणियां की गई हैं वे भी कार्यवाही से निकाल दी जाएं। मैं नेता प्रतिपक्ष को इनविटेशन देने चाहूंगा जब हमारे माननीय सदस्य श्री सुंदर सिंह जी मंत्री बनेंगे तो लोक भवन से आपको इंविटेशन भेज जरूर भेज दिया जायेगा। ...(व्यवधान)

(***) **अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।**

Speaker: Please, please. No personal remarks, please. Some personal remarks have come on the record. I will peruse the whole record vis-à-vis Thakur Sunder Singh ji and Thakur Jai Ram ji and will see that all those personal remarks will be removed from the record. Thank you. Please don't be personal in debate.

Next Speaker, Hon'ble Shri Trilok Jamwal ji.

श्री त्रिलोक जम्वाल एन0जी0द्वारा जारी..

17.02.2026/1830/ए.जी.-एन.जी./1

अध्यक्ष.......... जारी अंग्रेजी के पश्चात......

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने आप को नियम-102 के तहत प्रस्तुत हुए सरकारी संकल्प की चर्चा में शामिल करता हूं। मुझ से पूर्व के वक्ताओं ने इस विषय के ऊपर विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला है और मैं उन बिंदुओं पर दोबारा से नहीं जाना चाहता। इस विषय की चर्चा के दौरान एक बिंदू पर बार-बार चर्चा की गई और उससे यह प्रतीत होता है कि वर्तमान प्रदेश सरकार के 3.5 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं तथा यह इस सरकार का अंतिम बजट है इसलिए कोई-न-कोई बहाना बनाकर एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें भी जिस नियम का हवाला दिया जा रहा है यानी के आर्टिकल

275(1) का जिक्र किया जा रहा है तो उसमें कहीं पर भी आर0डी0जी0 ग्रांट को मैंडेटरी नहीं लिखा गया है। सत्तापक्ष के सभी वक्ताओं ने कहा है कि यह हमारा अधिकार है, इसका संविधान में प्रावधान है, यह हमें मिलकर रहेगा और यदि केन्द्र सरकार नहीं देगी तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायलय में जाएंगे।...(व्यवधान) मुख्य मंत्री जी, सभी ने कहा है और मुझ से पूर्व वक्ता ने भी अभी-अभी कहा है। मैं उसी के ऊपर बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, आर0डी0जी0 मैंडेटरी नहीं है। केन्द्र और राज्य के बीच में यदि कोई गैप पैदा होता है तो उसके लिए कैसे सहायता की जा सकती है, केवल उसके बारे में लिखा गया है। उस आर्टिकल में आर0डी0जी0 का कोई जिक्र नहीं है। वहां पर जिसका जिक्र किया गया है, वह शब्द है "may"। उसमें भी यह constitutional binding नहीं है। यहां पर आर्टिकल 280 का हवाला दिया जा रहा है और उसके अनुसार वित्तायोग का गठन करते हैं तथा उनकी जो भी सिफ़ारिशें होती हैं तो उसके लिए संसद को अधिकार है कि उन सिफ़ारिशों को मानना है या नहीं। यह कहां से आ गया कि आर0डी0जी0 मैंडेटरी है?

17.02.2026/1830/ए.जी.-एन.जी./2

पहले दिल्ली वाले नेता भी संविधान लेकर घूमते थे और आज माननीय उप-मुख्य मंत्री भी संविधान की बड़ी किताब लेकर आए थे। मैं कहना चाहता हूं कि जब वे संविधान की किताब लेकर आए ही थे तो वे उस शब्द को भी पढ़ लेते।

अध्यक्ष महोदय, आप तो कानूनविद हैं और मैं बताना चाहता हूं कि आर्टिकल 275(1) क्या कहता है? आर्टिकल 275(1) कहता है कि Grants from the Union to certain States.

275(1) - Such sums as Parliament may by law - Speaker, Sir, the word is "may" and "by law". The word is not "should". तो where the State has right?

...(Interruption) - Such sums as Parliament may by law provide shall be charged on the Consolidated Fund of India in each year as grants-in-aid of the revenues of such States as Parliament may determine - जिसको पार्लियामैंट निर्धारित करेगी, केवल उसको मिलेगा। - to be in need of assistance, and different sums may be fixed for different States.

अध्यक्ष महोदय, आपने जो एक कागज सप्लाई किया है उसके तहत केवल वित्तायोग की सिफ़ारिशों के अनुसार 12वें वित्तायोग द्वारा आर0डी0जी0 पर कमेंट किया गया था कि यह धीरे-धीरे समाप्त होनी चाहिए। उसके बाद 13वें वित्तायोग में केवल आठ स्टेट्स थीं। अगर यह संविधान में प्रोवाडिड है

श्री ए0पी0 द्वारा......जारी

17.02.2026/1835/AS/AP-01

श्री त्रिलोक जम्वाल जारी .....

तो पहले दिन से ही स्टेट उस कंटिन्यूटी में रहनी चाहिए थी। पहले 8 स्टेट्स थी और उसके बाद जब 15वां वित्त आयोग आया तो इसमें स्टेट्स की संख्या आठ से बढ़कर 17 हो गई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो हमारे लोग यह कह रहे हैं कि यह मैटर ऑफ राइट है, हमारा अधिकार है, हम लेकर रहेंगे। यह कांस्टीट्यूशनल राइट कैसे कंपल्शन है। यह तो संविधान में एक प्रोविजन है कि 275 (1) या 275 के तहत किन-किन स्टेट्स को कैसे-कैसे और कब-कब, जो सेंटर को लगता है और इसमें फाइनेंस कमीशन कि अगर रिकमेंडेशन है उसके बाद भी पार्लियामेंट may determine. मैं आपको बताता हूं कि प्रोविजन में क्या लिखा है और प्रोविजन में और भी स्पेसिफिक किया है। 'Provided that there shall be paid out of the Consolidated Fund of India as grant-in-aid of the revenue of the State such capital and recurring some as may be necessary to enable that State to meet the cost of such schemes. Schemes of the developments as

may be undertaken by the State with the approval of the Government of India for the purpose of purporting the welfare of the Scheduled Tribe in the State or raising the level of administration Scheduled Tribe therein to that of the determination of the rest of the area of the State.'

अध्यक्ष महोदय, आपकी सारी आर0डी0जी0 की डिस्कशन आर्टिकल 275 (1) पर है। आप जितना कुछ कह रहे है और आपका सिर्फ बजट का और जो कल माहमहीम गवर्नर महोदय का अभिभाषण था उसके दूसरे पेज पर आपने इसी को कोट किया है। जिसको महामहीम गवर्नर महोदय ने पढ़ने से इनकार कर दिया और कहा कि इसमें कनफ्लिक्ट है। यह कांस्टीट्यूशनल, यानी हमारे संघीय ढांचा पर टीका-टिप्पणी है। इसलिए 275 (1) हमें कोई राइट नहीं देता। राइट तो सिर्फ ग्रांट का है, आपका राइट आर0डी0जी0 का नहीं है। उसमें भी इन्होंने आगे स्पेसिफिक किया है कि ग्रांट्स में भी आपको पंचायती राज सिस्टम में कितने ग्रांट मिल रही है। आपको अन्य विभागों में कितनी ग्रांट मिल रही है। अभी प्रदेश में जो आपदा हुई तो आपने क्या मांगा। केंद्र सरकार को जब लगेगा कि किसको कितनी ग्रांट

17.02.2026/1835/AS/AP-2

देनी है और किस मद के लिए देनी है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो इस माननीय सदन में कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आए थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा पढ़ा ही नहीं। मैंने बार-बार रिपीट किया कि शब्द may है शब्द should नहीं है। It should be binding upon the Central Government. उन्होंने कहा कि Parliament may determine और जहां तक अध्यक्ष महोदय आर0डी0जी0 का इशू है और कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के साथ बहुत भेदभाव हो रहा है। अगर हिमाचल प्रदेश के साथ बड़ा भेदभाव है तो जब हमें छठे फाइनेंस कमीशन से लेकर 11वें फाइनेंस कमीशन तक हिमाचल प्रदेश को केवल 3,865 करोड़ रुपये की आर0डी0जी0 मिली थी। हालांकि कांग्रेस जब यह क्लेम करती की उन्होंने 55 सालों तक राज किया, तो उस समय तो ज्यादातर आपकी ही सरकार रही है। कहा जा रहा था कि अर्थशास्त्री आए माननीय स्वर्गीय डॉ मनमोहन सिंह जी तो हिमाचल प्रदेश को केवल 18 हजार 91 करोड़ रुपये मिले। केवल

पिछले 10 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को 90 हजार करोड़ करोड़ रुपये के आसपास आर0डी0जी0 मिली। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अगर उसमें 90 हजार करोड़ के आस-पास आर0डी0जी0 मिलती है तो सबसे हिमाचल प्रदेश का सबसे ज्यादा हित किसने देखा? हिमाचल प्रदेश के हित के बारे में किसने सोचा?

अध्यक्ष : आप yield करेंगे, माननीय मुख्य मंत्री महोदय wants to speak.

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

17/02/2026/1840/AT/ AS/01

मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य वकील हैं वे लॉ की इंटरप्रिटेशन आपके सामने कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इन सारी चीजों की विस्तृत जानकारी सबको पता होता है कि "मे" और "शैल" में क्या अंतर है और किस तरह इंट्रोड्यूस करना होता है। लेकिन मैं इस विषय पर कल आपसे बात नहीं करना चाह रहा था। आर0डी0जी0 को ग्रांट कहा जाता है, आर0डी0जी0 का मतलब ही Revenue Deficit Grant है। यह किन राज्यों को दी जाती है? जहां आय कम होती है और व्यय ज्यादा होता है उसके बीच के घाटे को पूरा करने के लिए आर0डी0जी0 का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत यह प्रावधान किया गया है।

दूसरी बात 10 साल में 90 हजार करोड़ रुपए आर0डी0जी0 मिली। अगर 10 साल में 90 हजार करोड़ रुपए आर0डी0जी0 मिली तो आप उसकी डिटेल बताइए कि किस साल में कितनी मिली। 10 साल में जो आर0डी0जी0 मिली उस समय हमारी आय और व्यय में कितना अंतर था? आर0डी0जी0 ऐसे ही नहीं मिलती इसके पैरामीटर होते हैं। हर चीज का पैरामीटर होता है। आय और व्यय के आधार पर उस समय हमारी स्टेट की स्थिति ठीक नहीं थी। इसलिए 14वें वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग ने भी दी। जैसे-जैसे स्थिति ठीक होती है, आर0डी0जी0 कम किया जा सकती है और उन राज्यों में बंद भी की जा सकती है।

जैसे पंजाब को 14वें वित्त आयोग में आर0डी0जी0 नहीं मिली। लेकिन 15वें वित्त आयोग ने उनकी आय और व्यय के अंतर को देखते हुए 26,000 करोड़ रुपये की आर0डी0जी0 रिकमेंड की है। इससे पहले उन्हें आर0डी0जी0 नहीं मिलती थी। उन्होंने कहा आय और व्यय के बीच के घाटे को पूरा करने के लिए आर0डी0जी0 का प्रावधान संविधान में दिया गया है। आप इस एक्ट को अपने तरीके से एलेबोरेट कर रहे हैं आप वकील हैं, तो थोड़ा अपने तरीके से तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आर0डी0जी0 हिमाचल प्रदेश का अधिकार है। कल मैं इसके सेक्शन प्रावधानों और प्रोविज़ो को भी बताउंगा, प्रोविज़ो पढ़कर यह कह रहे हैं कि एस0टी0 को भी ग्रांट देना चाहिए, जिनको देना चाहिए वह तो अलग है। इसलिए आप इस चीज़ को सही ढंग से एलेबोरेट करें। आप कहिए कि आर0डी0जी0 हमारा अधिकार है। हमारी आय और व्यय

17/02/2026/1840/AT/ AS/02

में अंतर रहेगा क्योंकि हमारी संपदा पानी है, उस संपदा से धन तो केंद्र सरकार कमा रही है लेकिन पानी की एवज में हमें कुछ नहीं दे रहे हैं। यह सब आर0डी0जी0 के रूप में आ रहा था। आप पढ़े-लिखे हैं, तो सही तरीके से इसे प्रस्तुत करें। आप वकील हैं इसको तोड़-मरोड़ कर न पेश करें, ठीक तरह से पेश करें।

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री कह रहे हैं कि प्रोविज़ो अलग है, आप तो वकील हैं।

Speaker : Without going into the details of proviso or sub-article, leave them aside. The issue is the deficit, how to meet the deficit.

श्री त्रिलोक जम्वालः अध्यक्ष महोदय, जो हमें 90 हजार करोड़ रुपये पिछले 10 वर्षों में मिले, वह भी हिमाचल प्रदेश को ध्यान में रखते हुए मिले हैं।

अध्यक्ष : ये भी यही बोल रहे हैं।

श्री त्रिलोक जम्वालः मैंने कहा कि जब लंबे समय से कांग्रेस की सरकार प्रदेश में रही तो केवल 3,819 करोड़ रुपए ही मिला, तब तो कोई नहीं बोला। पिछले 10 वर्षों में केवल 1,70,000 करोड़ रुपये ही मिले हैं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आर0डी0जी0 बंद हुई है तभी ये बोल रहे हैं, अगर इस ग्रांट को कम किया जाता तो इन्होंने नहीं बोलना था। यह तो पूरी तरह बंद हो गई है, तब इस सदन में यह प्रस्ताव लाया गया है।

श्री त्रिलोक जम्वालः तो इसका मतलब यह है कि जो हमारे वकील केन्द्र सरकार के समक्ष गए थे, उन्होंने हमारा केस सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं किया। यह मैं इस सदन में कहना चाहता हूं।

अध्यक्षः यह आपकी ऑब्ज़र्वेशन हो सकती है।

17/02/2026/1840/AT/ AS/03

श्री त्रिलोक जम्वालः हां, यह मेरी ऑब्ज़र्वेशन है। इसका मतलब भी यही है। जब हमारी प्रदेश की आर0डी0जी0 बंद हुई तो उसके साथ-साथ 17 स्टेट्स की भी बंद हुई है लेकिन हमें अपने रिसोर्सेज़ और चीज़ों पर भी काम करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जब हमारी आर0डी0जी0 बंद हुई, तो हमारा टैक्स रिवैल्यूएशन लगभग ढाई हजार करोड़ रुपये बढ़ा है। उसे भी अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारा रूरल डेवलपमेंट और अर्बन डेवलपमेंट के लिए हमें लगभग 2,450 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। मैं यह कह रहा हूं कि वे स्कीम-ओरिएंटेड होती हैं जैसे माननीय सदस्य बलबीर सिंह वर्मा जी कह रहे थे कि अगर 12,000 करोड़ रुपये का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रखा गया है तो ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट बनाए जाएं, ज्यादा प्रोजेक्ट बनेंगे तो उससे ज्यादा पैसा आएगा। प्रदेश में जो सेंटर के प्रोजेक्ट चले हुए हैं, वे तो आपसे ठीक ढंग से चल नहीं रहे और जो चल रहे हैं वह रूक-रूक कर चले हैं। मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरे बिलासपुर में रेल है .....

के0एस0द्वारा जारी ......

17.02.2026/1845/केएस/डीसी/1

श्री त्रिलोक जम्वाल जारी ---

मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं। मेरे बिलासपुर में रेल है और जहां तक वर्ष 2022 में हमने लैंड एक्वायर की थी,उससे आगे एक इंच भी लैंड इस सरकार ने एक्वायर नहीं की। आज हम जहां खड़े हैं, पिछले 10 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में जो चेंज हुआ है, पहले बिलासपुर से चंडीगढ़ पहुंचने के लिए पांच घंटे का समय लगता था अब हम वहां दो घंटे में पहुंचते हैं। यह चेंज है और यह वर्ष 2014 से पहले क्यों नहीं हुआ? मेरे बिलासपुर में एम्स बन गया। हिमाचल प्रदेश में पहले एक भी एम्स नहीं था। यह सैंटर गवर्नमैंट के आशीर्वाद से ही हुआ है। आप एक तरफ सैंटर गवर्नमैंट को कोसेंगे और दूसरी तरफ मांगने जाएंगे, ऐसा कैसे होगा? आप संघीय ढांचा गाते रहेंगे इसलिए आज यहां खड़े हैं। मेरे बिलासपुर से धर्मशाला जाना हो, अगर थोड़ा सा बीच का पैच छोड़ दें तो दो-ढाई घंटे में हम वहां पहुंच जाते हैं जबकि पहले पांच-छः घंटे लगते थे। यह इन्फ्रास्ट्रक्चर कहां से आया? हम बिलासपुर से मनाली दो-ढाई घंटे में पहुंच जाते हैं। आप कल्पना कीजिए कि कितना बदलाव है, कितना पैसा है और यह सैंटर का पैसा है इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतनी बड़ी स्कीम्ज़ आ रही हैं, एम्स आ रहे हैं, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज आ रहे हैं। हमें सैंटर गवर्नमैंट का थैंक्स करना चाहिए। मेरे से पूर्व माननीय लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य जी कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में पहले 200 किलोमीटर सड़कें थीं और अब 46,000 किलोमीटर सड़कें हो गई हैं। 46,000 किलोमीटर में लगभग 24,000 किलोमीटर सड़कें प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी हैं जिसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ले कर आए थे। आज प्रदेश कैसे बदल रहा है? सरकार कहती है कि यह भी ठीक नहीं है, वह भी ठीक नहीं है, हम बिजनैस के हिसाब से देखेंगे। आपने चार हाइड्रो प्रोजेक्ट के एम0ओ0यू0 कैंसिल कर दिए। आपने बल्क ड्रग फार्मा प्रोजेक्ट पर क्वैश्चन मार्क लगा दिया। बड़े प्रोजैक्ट्स के ऊपर क्वैश्चन मार्क लगाएंगे तो काम कहां से होगा? हिमाचल के युवाओं को रोज़गार कैसे मिलेगा। हिमाचल के बेरोज़गार युवाओं को कहां से रोज़गार मिलेगा, कहां से इंवेस्टमैंट आएगी? अगर इन बड़े प्रोजैक्टों के ऊपर भी प्रदेश सरकार ध्यान दे तो हमारे पास डवलपमैंट के बहुत ज्यादा ऐसे बिंदु हैं जिनको हम आगे बढ़ा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, जो इनका बार-बार एक थ्रस्ट

रहता है कि हमें ग्रांट्स मिलनी चाहिए उसके लिए प्रयास करें लेकिन एक शब्द के ऊपर एक वातावरण बनाने

17.02.2026/1845/केएस/डीसी/2

का प्रयास ना करें कि आर0डी0जी0 नहीं मिली इसलिए हम 10 गारंटियां पूरी नहीं कर पाएंगे। हाउस के अंदर तो कह रहे हैं कि सात गारंटियां पूरी हो गईं लेकिन पब्लिक का मूड क्या है, ज़रा उसको भी भांप लें। पब्लिक क्या देख रही है उसको भी भांप लें। साढ़े तीन साल हो गए जो साढ़े तीन सालों में नहीं कर पाए वह अगले एक साल में क्या कर लेंगे? मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कई बार कहा कि हिमाचल का हित देखिए, हिमाचलियत का हित देखिए। हम हिमाचल हैं और हिमाचल रहना चाहिए और माननीय उद्योग मंत्री हर्षवर्धन जी ने भी और उप-मुख्य मंत्री ने भी यही कहा। मैं कहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, हिमाचल भी रहेगा, हिमाचलियत भी रहेगी लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं रहेगी, यह चंद दिनों की ही मेहमान है।

अध्यक्ष महोदय, रेलवे में हमें इस बार 2,911 करोड़ रुपये मिले। इतनी बड़ी सौगात के लिए कहां तो इनको धन्यवाद करना चाहिए था, धन्यवाद का प्रस्ताव लाना चाहिए था।

अध्यक्ष : यही तो ये बोल रहे हैं। आप एडमिट करते जा रहे हो सारी बातें कि this is the effort to strangulate the elected Government and you are admitting it.

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने साढ़े तीन साल नहीं कुछ किया वे अगले एक साल में क्या करेंगे?

अध्यक्ष : चलो, वह तो बाद की बात है but you are admitting what they are saying. …(Interruption).

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, एक साल बच गया उसके बाद तो जाना ही है।

Speaker : They are saying that the Union Government is trying to strangulating the State Government and you are supporting that contention. …(Interruption). Anyway, this is your decision.

17.02.2026/1845/केएस/डीसी/3

श्री त्रिलोक जम्वाल : नहीं, मैं यह कह रहा हूं कि एक साल बाद वर्ष 2027 में जाना ही जाना है । बिलासपुर में एक कहावत है मुझे पता नहीं कि वह कितनी रिलेवेंट है लेकिन उसका मतलब (***)साढ़े तीन साल हो गए,

अध्यक्ष : यह ना समझ आया और ना ही यह पार्ट ऑफ रिकॉर्ड है। This will not be part of the record.चलो, छोड़ो अब एक्सप्लेन ना करें।

श्री त्रिलोक जमवाल : मैंने यही कहा कि साढ़े तीन साल भी नही कर पाए तो एक साल में क्या कर लेंगे। अब तो ये केवल रोना रो रहे हैं कि जैसे-तैसे आर0डी0जी0 का रोना रो कर पब्लिक के बीच में हम खड़े होने लायक रह जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा। आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

अगले वक्ता श्रीमती अ0व0 की बारी में---

17.02.2026/1850/av/dc/1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा नियम-102 के तहत रेवन्यू डेफिसिट ग्रांट के बारे में सरकारी संकल्प चर्चा में लाया गया है, आपने मुझे उस पर बोलने का समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

वैसे तो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने चाहे पक्ष है या विपक्ष; मेरे बहुत से साथियों ने इस बारे में बातें की हैं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो कहा है, मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा कि आर0डी0जी0 क्या है या आर्टिकल 275 या आर्टिकल 280 क्या है; क्योंकि इस बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है। इस बारे में बहुत सारी बातें आ चुकी हैं। यहां पर श्री त्रिलोक जम्वाल जी

ने बहुत अच्छी बात की है, शायद ये अच्छे वक्ता रहे होंगे। वैसे तो मैंने भी अच्छी प्रैक्टिस की है क्योंकि मैं भी क्रीमिनल लॉयर रहा हूं परंतु हमारा कभी आमना-सामना नहीं हुआ। मैं हाई कोर्ट भी आता था। ...(व्यवधान) नहीं, कोर्ट में नहीं हुआ। आप अच्छे वक्ता हैं और आपने अच्छी बातें कीं परंतु आपने यहां आज मन की बात भी बोल ही दी। आपकी आर0डी0जी0 रोकने की जो मन्शा है, आपने वह मन्शा भी बता दी। ...(व्यवधान) राजनीति के बारे में आप लोगों ने ठीक बात कही परंतु राजनीति के लिए और भी बहुत सारे मंच होते हैं। अभी केवल प्रदेश की लगभग 75 लाख जनता की बात है। यह कोई काँग्रेस पार्टी या बी0जे0पी0 की बात नहीं है। हमारे मुख्य मंत्री सच बोलते हैं कि सरकारें आती-जाती रहती हैं। मुख्य मंत्री और मंत्री बदलते रहते हैं। किसके भाग्य में क्या है, उसको वही मिलेगा। यहां पर पहले भी भाग्य वाली बात हो चुकी है परंतु मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि और काँट्रोवर्सी हो जाएगी। परंतु अभी हमें केवल प्रदेश हित देखना है। यहां पर सत्ता पक्ष यानी सरकार की ओर से तो संकल्प लाया ही गया है परंतु मेरा माननीय नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के सभी साथियों से इण्डिविजुअल अनुरोध है कि हमें इस संकल्प को लेकर माननीय प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए। साथ में, हमारे चार लोक सभा के सदस्य, तीन राज्य सभा तथा आठवें हमारे श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हैं क्योंकि वे भी तो हिमाचल प्रदेश से ही ताल्लुक रखते हैं। ठीक है कि यहां पर बहुत सारी बातें हुईं। यहां पर श्री जय राम ठाकुर जी ने भी कहा कि ये तो बंद होनी ही थी और हमें यह पहले से पता था। यह बात आपको पहले से पता थी, यह जानकारी तो हमें आपसे ही मिली है। यहां पर जो दूसरे 17 प्रदेशों की बात की गई है उनकी अलग-अलग परिस्थितियां हैं। हमारी परिस्थिति कुछ और है क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है। हमारी 18,000 करोड़ रुपये के करीब इन्कम है तथा

17.02.2026/1850/av/dc/2

लगभग 42,000 करोड़ रुपये के करीब खर्चा है। हम जी0एस0टी0 की वजह से टैक्स नहीं लगा सकते। पहले वैट था फिर वह भी खत्म कर दिया गया। मैं तो माननीय मुख्य मंत्री और पूरे मंत्रिमण्डल को बधाई देना चाहता हूं। यहां पर जैसे श्री जय राम ठाकुर जी कह रहे थे कि जब मैं मुख्य मंत्री बना तो उस समय 48,000 करोड़ रुपये का कर्ज था और आप जाते-जाते लगभग 75,000 करोड़ रुपये का कर्जा छोड़कर गए। ...(व्यवधान) उसमें 15,000

करोड़ रुपये से ज्यादा कर्मचारियों की देनदारियां थीं। जब माननीय श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने मुख्य मंत्री की शपथ ली तो मेरे ख्याल में उस समय खजाने में एक रुपया भी नहीं था। परंतु इन्होंने फिर भी सरकार चलाई। आपके द्वारा इतना ज्यादा कर्जा छोड़ने के बावजूद सरकार चलाई और फिर वर्ष 2023 की त्रासदी आई। वर्ष 2023 में कितना नुकसान हुआ और फिर वर्ष 2025 में त्रासदी आई। आप यहां जैसे कह रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं है,

टी सी द्वारा जारी

17.02.2026/1855/टी0सी0वी0/एच0के0-1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा... जारी

तो मैं कहना चाहता हूं कि इसकी आवश्यकता है। आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमारे प्रदेश में त्रासदी आई है। प्रदेश में वर्ष 2023 और 2025 में बहुत नुकसान हुआ है। कोविड के समय आप सफल हुए, उस समय आपने अधिक संसाधन लाए, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं लेकिन हमें अभी भी वर्ष 2023 और वर्ष 2025 की तरह सहायता चाहिए।

इसके अलावा मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कई सोर्सिज मोबिलाइज किए हैं, इनकम बढ़ाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। हमारी सरकार कार्य कर रही है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक दिन में हो जाएगा या आज ही सोर्स बढ़ जाएंगे। पहले के मुख्य मंत्री ने भी प्रयास किए होंगे यानी सभी ने अपने स्तर पर कोशिश की होगी। यदि आज यह ग्रांट हमें नहीं मिलती है तो इससे प्रदेश को बहुत नुकसान होगा। इसमें हम सबको नुकसान होगा। चुनाव अलग विषय है। जम्वाल साहब, चुनाव का इससे कोई संबंध नहीं है। जनता सब जानती है कि किसका क्या कसूर है। यह भी आवश्यक नहीं है कि अगली बार हम सभी यहां इस माननीय सदन में होंगे। जनता का मूड बदलता रहता है। आप सोच रहे होंगे कि हिमाचल प्रदेश में परिवर्तन की परंपरा रही है लेकिन ऐसा होना अनिवार्य नहीं है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण चर्चा लाई गई है और यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। हम सबको एकजुट होकर राजनीति को छोड़कर इस विषय पर विचार करना चाहिए। यह न भारतीय जनता पार्टी का विषय है, न कांग्रेस पार्टी और न

सरकार का विषय है। सरकारें आती-जाती रहती हैं लेकिन प्रदेश और 75 लाख जनता का हित सर्वोपरि है। यदि हम यह ग्रांट लाने में सफल नहीं हुए तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। आप सभी जानते हैं कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में विकास कार्य रुक जाएंगे। ओ0पी0एस0 के विषय में भी चर्चा नहीं की जा रही है। कर्मचारियों की बात है, यूथ की बात है, किसान और बागवान की बात है, आज बागवानों के साथ भी षड्यंत्र की आशंका है, जिस पर मैं बजट सैशन में विस्तार से चर्चा करूंगा। आज बागवानी से संबंधित लगभग 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं और लगभग 5000 करोड़ रुपये की आर्थिकी इससे जुड़ी

17.02.2026/1855/टी0सी0वी0/एच0के0-2

है। इसमें केवल बागवानी ही नहीं, बल्कि बागवान, आढ़ती, लेबर, ट्रांसपोर्ट और बहुत-सारे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। हजारों लोगों की आजीविका इससे प्रभावित होती है, इसलिए यह चिंता का विषय है।

इस विषय पर हम सबको एकजुट होना चाहिए। हो सकता है कि किसी की राजनीतिक मजबूरी हो, वह अलग बात है। अब तक विपक्ष के जितने भी विधायकों और माननीय सदस्यों ने बात रखी है उनमें डॉ0 हंस राज जी ने खुलकर समर्थन की बात कही, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। बाकी जम्वाल साहब ने भी अपनी बात रखी और चाह रहे हैं कि सरकार को गिराना है लेकिन सरकार को छोड़कर पहले जनता की बात की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। 75 लाख जनता, रोजगार, बेरोजगार, किसान और बागवान की हम बात ही नहीं कर रहे, बल्कि हम अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं सी0पी0एस0 के बारे में अधिक नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि मैं स्वयं भी सी0पी0एस0 रहा हूं। पहले भी कई सी0पी0एस0 रहे हैं, श्री सत्ती जी आप भी रहे हैं। आप तो शायद हमारे खिलाफ पटीशनर हैं। आपके समय में 9 सी0पी0एस0 रहे, हमारे समय में 6 रहे और इससे पहले भी कई सी0पी0एस0 के पद पर रहे हैं। चेयरमैन बनना और गाड़ियां खरीदना भी नई बात नहीं है। हां, यह सही है कि खर्चों को कम करना पड़ेगा। जहां कटौती संभव है, वहां कटौती करना आवश्यक है। जो आवश्यक खर्चे हैं, उन्हें करना ही

पड़ेगा। गाड़ी की आवश्यकता थी, इसलिए उपलब्ध कराई गई। गाड़ी तो नेता प्रतिपक्ष को भी मिली है। आपने भी कहा कि पुरानी गाड़ी चलने की स्थिति में नहीं है।

एन0एस0 द्वारा जारी ....

17-2-2026/1900/एन0एस0-एच0के0/1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा -----जारी

हमारी कल कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग थी तो वहां पर बात चली कि खाने का रेट भी बढ़ाना चाहिए। मुझे माननीय सुरेश कुमार जी की बात अच्छी लगी कि हम अब भोजन करना भी छोड़ देते हैं। मेरे कहने का अर्थ है कि जरूरी चीज तो करनी ही पड़ेगी। जीने के लिए जो आवश्यक है वह हमें करना पड़ेगा। यह बात ठीक है कि हमें अपने खर्चे भी कम करने पड़ेंगे और रिसोर्सिज भी पैदा करने पड़ेंगे लेकिन ये सब एक दिन, एक महीने या डेढ़-दो सालों में नहीं होगा। हमें जो आर0डी0जी0 मिलती थी वह इसलिए जरूरी है। ठीक है, हम भविष्य में नीति बनाएंगे। यहां पर विपक्ष के साथी बोल रहे थे कि आपने पिछले तीन सालों में क्या किया? अगर हम ऐसे कोसने लगे कि ठाकुर साहब आप भी पांच साल मुख्य मंत्री रहे तो आपने क्या किया? अगर हम एक-दूसरे को कोसते रहेंगे तो विकास कार्य कैसे होंगे? इसलिए प्रदेश को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो यह एक-दो आदमियों का काम नहीं है, एक-दो दिन, एक-दो महीने का काम नहीं है और इसमें समय लगेगा। यह सबके कोलैक्टिव एफर्टस से होगा। इसलिए इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। आप हमारे साथ आर0डी0जी0 के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना और उनसे कहना कि हमें ये ग्रांट दें। दूसरी और स्कीमें भी हैं जैसै यहां पर कहा जा रहा था कि पी0एम0जी0एस0वाई0 या अन्य और स्कीमें जो केंद्र सरकार से स्पॉंसर्ड हैं तो ये स्कीमें अभी नहीं आई हैं बल्कि बहुत पहले से हैं। कई स्कीमें आती हैं। विपक्ष के भाषण का करक्स तो यही होता है कि हिंदुस्तान वर्ष 2014 में आजाद हुआ है और सब कुछ वर्ष 2014 में हुआ है लेकिन ऐसा नहीं है। वर्ष 2014 से पहले भी कई महान प्रधानमंत्री रहे हैं। आप तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी भूल गए थे। आप उनका नाम ही भूल गए थे। इससे पहले भी कइयों ने

काम किया है। ठीक बात है कि कई प्रधानमंत्रियों, मुख्य मंत्रियों और मंत्रियों ने कम या ज्यादा काम किया होगा। लेकिन आपको इतना भी नहीं कहना चाहिए अन्यथा यह बेईमानी होगी कि हिंदुस्तान वर्ष 2014 में आजाद हुआ और पिछले 10 सालों में हमें इतनी ग्रांट मिली। उसका भी कारण रहा होगा कि हमें ग्रांट क्यों मिलती है? उसका संविधान में उल्लेख है और मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं। मैं भी पेशे से वकील हूं। जैसे मैंने पहले कहा कि हमें प्रदेश को आत्मनिर्भर करने के लिए रिसोर्सिज को मोबिलाइज करने की आवश्यकता है। लेकिन निर्भर कैसे होना है तो यह एक दिन, एक महीने या एक साल

17-2-2026/1900/एन0एस0-एच0के0/2

का काम नहीं है। इसके लिए समय लगेगा। मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को काफी पटरी पर लाया है, चाहे वाइल्ड फ्लॉवर हॉल वाले केस की बात हो या अन्य और बातें हों। इसके बाद भी और कदम उठाने की आवश्यकता है। इसलिए मेरा माननीय जय राम ठाकुर जी व विपक्ष के सभी साथियों से अनुरोध है कि आप हमारे साथ केंद्र सरकार के पास चलें और आर0डी0जी0 बहाल करवाएं। आप इस बात को दिमाग से निकाल दें कि इस ग्रांट की वजह से अगर सरकार गिरी तो हमें फायदा होगा। आप इस गलतफ़हमी में मत रहना। जनता समझदार है और सब जानती है कि किसने क्या किया और कौन क्या करेगा? हम तो यही चाहते हैं कि हम अगली बारी 68 के 68 विधायक इसी माननीय सदन में हों। यहां पर विपक्ष के मित्र कह रहे थे कि श्री जय राम ठाकुर जी ने 5 वर्षों में इतना काम किया। मैं सोच रहा था कि सब ठाकुर साहब की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं तो ये विपक्ष में क्यों गए होंगे तब तो इनको सत्ता में होना चाहिए था। ये सब सदस्यों के सोचने का विषय है इसलिए इस संकल्प को मत ओपोज करें और इसमें सब साथ दें तथा प्रदेश-हित में काम करें। हमारा प्रदेश शांत प्रदेश है और हम देवी-देवताओं को मानने वाले हैं तथा हमारा प्रदेश देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए इसके ऊपर राजनीति करना छोड़ दें। अब यह हो सकता है कि आपकी कोई राजनीतिक मजबूरी होगी तो उसका आपको ही पता होगा कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो टिकट कटेगी, यह अलग बात है। लेकिन प्रदेश-हित में हम सबको इकट्ठे मिल कर चलना है, मैं यही कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब श्री इन्द्र सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

आगे …….आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

17.02.2026/1905/RKS/वाई के-1

श्री इन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान द्वारा जो नियम-102 के तहत प्रस्ताव लाया गया है, मैं इस पर अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। मंडयाली में एक पुरानी कहावत है अगर इजाजत हो तो मैं उसे सुना सकता हूं।

'सुथणू सियाणा हो ता नाड़े जो जगह चाहिए'।

कहने का मतलब है कि पजामा सियाणा हो तो नाड़े को जगह चाहिए। आप उस नाड़े को भूल गए जो पजामे में होना चाहिए था। आप लोगों को गुमराह करके सत्ता में आ गए लेकिन आज आपको आर0डी0जी0 नजर आ रही है। श्री हर्षवर्धन चौहान जी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में भाजपा नेता श्री जय राम ठाकुर और डॉ0 राजीव बिन्दल जी ने भाग लिया। यह ठीक हुआ कि हमारे नेता उस बैठक में गए और आपको सद्बुद्धि आ गई। आपने 70 साल तक राज किया लेकिन आपको आज तक सद्बुद्धि नहीं आई। जब आर0डी0जी0 बंद होने की बात कही जा रही है तो आपको सद्बुद्धि आ गई। मुख्य मंत्री जी इस संबंध में अपना पक्ष रखने में विफल रहे हैं। आपने जिस तरह से 89 वकील रखे हैं अगर आप उनमें से एक-दो वकील अपने साथ ले जाते तो वे वहां अपनी बात रखते। लेकिन मुख्य मंत्री जी अपनी बात रखने मे असफल रहे हैं। आप इसके लिए भाजपा को दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? सरकार आपकी है और आप अपना पक्ष मजबूती से रखिए। हम भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। कुछ वक्ताओं ने कहा कि पूर्व मुख्य मंत्री एक्सिडेंटल हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आपके मुख्य मंत्री भी एक्सिडेंटल हैं। आपने कौन-सा चुनाव से पहले इनको मुख्य मंत्री

घोषित किया था? आपने किसकी अध्यक्षता में चुनाव लड़े? श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी को ऐसी बातें करना शोभा नहीं देती। इनका नाम तो सुन्दर है लेकिन इनकी बातें बड़ी (***) हैं। मैं सरेआम कह रहा हूं कि वे अपनी डिबेट में भी ऐसा ही कहते हैं।

Speaker : (***) word will not be part of the record.

(***) **अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।**

17.02.2026/1905/RKS/वाई के-2

श्री इन्द्र सिंह : प्रधानमंत्री जी को गाली देना घटिया बात है। यह बात तो मैं मंडियाली भाषा में बोल रहा था। शायद आपको यह बात समझ आई होगी।

अध्यक्ष : मुझे यह बात समझ नहीं आई तभी मैंने इसे रिकॉर्ड से निकालने के आदेश दिए। कृपया आप किसी के ऊपर पर्सनली न कहें।

श्री इन्द्र सिंह : सर, मैं अपने शब्द वापिस लेता हूं। कोरोना काल के समय जब संकट आया तो सदन को स्थगित करने का प्रस्ताव पारित हुआ। आर0डी0जी0 बंद होना तो पहले से ही निश्चित थी। मैं पढ़ रहा था कि आर0डी0जी0 धीरे-धीरे कम होती जा रही है। जब आपको पहले ही आभास था तो वर्ष 2023 में आपके कान क्यों नहीं खड़े हुए? तब आपको विपक्ष की याद क्यों नहीं आई? वर्ष 2024 व वर्ष 2025 में फिर आर0डी0जी0 कम हुई तो उस समय भी आपने अपनी बात नहीं कही। जब हिमाचल प्रदेश के साथ 17 राज्यों की आर0डी0जी0 बंद हुई तो आपको विपक्ष की याद आई। हिमाचल प्रदेश में अभी आर0डी0जी0 बंद नहीं हुई है लेकिन आपके लोग कह रहे हैं कि आर0डी0जी0बंद हो गई है।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

17.02.2026/1910/बी.एस./वाई.के.-1

श्री इन्द्र सिंह जारी ...

यह भी सत्य नहीं है, यह असत्य बात है क्योंकि अभी तो 31 मार्च, 2026 आने वाला है और केन्द्र का बजट पास होने वाला है। उसके बाद इसे कहा जाएगा कि आर0डी0जी0 बंद हो रही है। अध्यक्ष महोदय, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए भाजपा को कोसा जा रहा है या केन्द्र सरकार को कोसा जा रहा है। मैं चाहता हूं कि उद्योग मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, मुख्य मंत्री जी तो यहां पर नहीं बैठे हैं लेकिन आप लोगों ने वाटर में सैस लगा दिया। आदरणीय अनिल शर्मा जी यहां पर बैठे हैं। इनको 82,400 रुपये का पानी का बिल आया है। जिस आवास में मैं रहता नहीं हूं उसमें भी 1200 रुपये का बिल आ गया है और यह एक महीने का बिल है पानी वहां पर आता नहीं है। मैंने इसके लिए एक इंटरव्यू भी दिया था।

अध्यक्ष महोदय, यह दशा इस सरकार की है। अगर विधायकों को पानी नहीं मिलेगा तो आम जनता को कहां से मिलेगा। मैं आज की बात नहीं कह रहा हूं ये सभी लोग विधायक यहां पर बैठे हैं मेरे पड़ोसी आदरणीय विनोद कुमार जी यहां पर हैं। मैं सच्चाई बोल रहा हूं कि मेरे आवास में पानी नहीं था। आज तीन महीने के बाद पानी आया और आज ही 1200 का बिल भी आ गया। वह मीटर कैसा मीटर है? जब वहां पर पानी ही नहीं आया तो मीटर कैसे घूम गया और बिल कैसे आ गया? यह इस सरकार के हालात है। आप मुझे आई0पी0एच0 के बारे में मत बताइए कि किस तरह से काम होता है। मैं 27 वर्ष 8 महीने इस विभाग में रहा हूं। (***)

Speaker: Undesireable will not go on record.

श्री इन्द्र सिंह : (***)आदरणीय सुन्दर सिंह को मंत्री बना दिया है आपको लालच दे दिया और आप पीछे-पीछे कानाफूसी कर रहे थे। परंतु आप नहीं बन पाएंगे, (***)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया, आर0डी0जी0 जी बोलिए।

श्री इन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार खनन पर आती उससे रेवेन्यू जनरेट करती तो मैं कहता कि सरकार आज इस स्थिति में नहीं होती और सरकार के जो

(***) **अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।**

17.02.2026/1910/बी.एस./वाई.के.-2

नुमाइंदे हैं वे अपने चेहतों से रात को खनन करवाते हैं। मेरे बल्ह में यह काम रात को हो रहा है। करोड़ों रुपये का जो नुकसान हुआ है, वहां पर खेतों और घरों को जो नुकसान हुआ है आज उसकी कोई भरपाई नहीं कर रहे हैं।

मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं हमने 8 लाख रुपये घरों को बनाने के लिए दिया मेरे विधान सभा की बात कीजिए, आपने किसे यह पैसा दिया? यह पैसा किसे दिया गया मैं बताना चाहता हूं। आप इस विधान सभा में झूठ बोल कर कभी इसका श्रेय नहीं मिलेगा। वह पैसे किसे दिए गए जिसका कोई भी नुकसान नहीं हुआ था उसे ये पैसा दिया गया। अगर सड़कों की हालत ठीक की होती उस पर आपने पैसा खर्च किया होता तब भी मानते परंतु आपकी संकट की घड़ी आ चुकी है। आज मेरी सड़कों में फुट-फुट गड्ढे पड़े हुए हैं। एक कवाड-डडोर सड़क राधा स्वामी सत्संग को जाती है और गौसदन को जाती है परंतु आज तक वह सड़क वर्ष 2023 की त्रासदी के बाद नहीं बनी है। जो गौशाला के लिए तुड़ी जाती है वह भी नदी से हो करके जाती है जब बरसात होती है तो कंधे में उठा करके उसे वहां के लोग ले करके जाते हैं। यह हालात आप लोगों के हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ये बातें बजट में बोल लेना अभी आर0डी0जी0 पर बोलिए।

श्री इन्द्र सिंह : अगर मैं पानी की बात करूंग, आप लोगों ने कुछ राहत दी होती तो संकट की बात करते जब आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं तो संकट की बात क्यों कर रहे है। जैसा कि डॉ0 हंस राज जी ने बोल कि यदि आप घर से ठीक चलते तो एक की कमाई से पांच लोगों का खाना-पीना होता था। आज पूरी फौज यहां पर है मंत्रीगण यहां है, सी0पी0एस0 तो हटा दिए गए हैं। मैंने पहले भी इस मंच के माध्यम से कहा था कि आप अपनी सैलरी मत बढ़ाइए,संकट आने वाला है। लेकिन आप लोगों ने मेज थपथपाया कि सैलरी बढ़ रही है। मैंने कहा था कि कर्मचारियों को भी दो और अधिकारियों को भी दो।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

17.02.2026/1915/डीटी/Ag-1

श्री इन्द्र सिंह ... जारी

मैंने कहा था कि कर्मचारियों और अधिकारियों को भी उनका एरियर दिया जाए। ...(व्यवधान) मेरे कोई दस्तखत नहीं है। मैं मानता हूं कि आय बढ़नी चाहिए थी लेकिन जब संकट दिख रहा था तो ये चीजें नहीं आनी चाहिए थी। आज कर्मचारियों की ओ0पी0एस0 के ऊपर बादल मंडरा रहे हैं। आपने कर्मचारियों का एरियर नहीं दिया। वर्ष 2016 के बाद किसी को एरियर नहीं मिला है। अगर आपने एरियर दिया होता तब मैं मानता कि यह संकट आता। अगर अपने डी0ए0 दिया होता तब भी संकट आता। लेकिन साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह संकट ऐसे ही चलता रहेगा। आप इसके लिए कुछ सुझाव दें और आप जो तय करेंगे हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। पूर्व मुख्य मंत्री जी को कोसना मुझे लगता है अच्छा नहीं है। हमारे नेता श्री जय राम ठाकुर जी हैं अगर ये बोलेंगे दिल्ली चलना है तो हम दिल्ली चल पड़ेंगे। आपके नेता बोलेंगे तो हम आपके साथ चल पड़ेंगे लेकिन आप अपने खर्चे को कम कीजिए। जो आपने सी0पी0एस0 बनाए थे इनके पद को बचाने के लिए आपने करोड़ों रुपये की राशि कोर्ट में लगा दी। आपने नई गाड़ियों ली और सरकारी बंगलों की रेनोवेशन करवाई। आपने करोड़ो रुपये की राशि रेनोवेशन में लगा दी। आज वो कोठियां वैसे की वैसे पड़ी हैं। आप केरला में जाइए वहां किस तरह की विधान सभा है। (***)मैं चाहता हूं कि जो आपने पैसा खर्च किया है यह चीज आपको पहले सोचकर करनी चाहिए थी। आप अपने खर्चे कम कीजिए तब आपको आर0डी0जी0 की जरूरत नहीं पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद।

Speaker: (***) will not be part of the record. All those references, which the Hon'ble Member has made, and which are undesirable, will not be part of the record.

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

17.02.2026/1915/डीटी/Ag-1

अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री आर0एस0बाली जी भाग लेंगे।

श्री आर0एस0बाली0 : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज माननीय मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी ने नियम- 102 के तहत जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हूं। आज का विषय बड़ा गंभीर विषय है। यह विषय हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों से जुड़ा हुआ है। इस विषय पर बड़ी संवेदनशीलता, बड़ी गहराई और एकजुट होकर सोचने की जरूरत है। हिंदुस्तान का जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, जब देश का संविधान बना, उस संविधान में फेडरल कंट्री बनाने के लिए यानी देश में जो केंद्र और राज्य की सरकार होगी वे एकजुट होकर काम करेगी। फेडरल कंट्री उसे कहा जाता है जब केंद्र और प्रदेश की सरकार हर चीज में मिलकर काम करती है। जब इसको फेडरल कंट्री बनाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को जोड़ा गया तो संविधान ने कुछ हक छोटे प्रदेशों के लिए निश्चित किए गए। वह हक यह थे कि प्रदेशों को आगे कैसे बढ़ाया जाए और वहां रोजमर्रा की जिंदगी किस तरह चलाई जाए। आज जो हमारी 75 लाख की आबादी है उस वक्त यह आबादी कम हुआ करती थी। लेकिन आज भी उसी की तुलना में यह आबादी ज्यादा है। जो संसाधन उस वक्त थे उसकी तुलना में आज ये संसाधन बढ़े हैं। क्योंकि इसमें वे प्रदेश चुने गए जिन प्रदेशों की अपनी कमाई से ज्यादा खर्चा था। जब पहला फाइनेंस कमीशन बना तो उन्होंने विचार विमर्श करके और

श्री एन0जी0द्वारा जारी

17.02.2026/1920/ए.जी.-एन.जी./1

श्री आर0 एस0 बाली.......... जारी

एक लम्बी एक्सर्साइज़ करके तथा एक लम्बी सोच के साथ संविधान के तहत एक व्यवस्था बनाई। उस व्यवस्था में आर0डी0जी0 का प्रावधान किया गया। आर0डी0जी0 उन प्रदेशों को देने का प्रावधान किया गया जिन प्रदेशों के पास आय के साधन बहुत कम थे। उन प्रदेशों में हिमाचल प्रदेश को भी जोड़ा गया क्योंकि हिमाचल प्रदेश के पास कमाई कम और खर्चे ज्यादा थे तथा बकायदा संविधान में इस प्रावधान को रखा गया था। माननीय सदस्य, श्री त्रिलोक जम्वाल जब इसके बारे में कह रहे थे तब उन्होंने बार-बार इस विषय को घूमाने की कोशिश की है। माननीय सदस्य बहुत बुद्धिजीवी हैं और उम्र के हिसाब से मुझ से वरिष्ठ भी हैं। जब वे अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने कहा कि यह हक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, जब हिन्दूस्तान का संविधान बना उसके बाद पहले वित्तायोग ने यह फैसला किया था। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री श्री आर0के0 शनमुखम चेट्टी जी ने पहले वित्तायोग कि सिफ़ारिशों को रखा था। उसके बाद देश के अनेकों वित्त मंत्री हुए जिनमें श्री मोरारजी देसाई जी, श्री वी0पी0 सिंह जी, श्री यशवंत सिन्हा जी, श्री मनमोहन सिंह जी, श्री प्रणब मुखर्जी जी, श्री अरुण जेटली जी आदि शामिल हैं। इसके अलावा अनेकों प्रधान मंत्रियों ने जोकि अलग-अलग पार्टियों से थे, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, श्री मोरारजी देसाई जी, श्री पी0 वी0 नरसिम्हा राव जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री मनमोहन सिंह जी शामिल हैं और उनके बाद अब श्री नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधान मंत्री हैं। वर्ष 1952 से लेकर वर्तमान तक जब हर पांच वर्ष के बाद एक वित्तायोग गठित हुआ यानी के पहले वित्तायोग से लेकर 15वें वित्तायोग तक हर प्रधान मंत्री, हर वित्त मंत्री और हर वित्तायोग ने आर0डी0जी0 को हक बताते हुए हिमाचल प्रदेश को उसका हक दिया। क्या वे सभी गलत थे? क्या उनकी सोच गलत थी? क्या हमारे सभी प्रधान मंत्री गलत थे? क्या हमारे सभी वित्त मंत्री गलत थे?

17.02.2026/1920/ए.जी.-एन.जी./2

क्या हमारे सभी वित्त मंत्रियों ने गलत सोचा? क्या सभी वित्तायोग ने गलत सोचा? क्या यह सोच अभी आई है? आज से पहले भी हमारी पार्टी के सभी प्रधान मंत्रियों के लिए विपक्ष के माननीय सदस्य टिका-टिप्पणी करते रहते हैं। लेकिन हमने कभी भी इनकी पार्टी या अन्य किसी भी पार्टी के प्रधान मंत्री के लिए गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। हमारी एक सोच है और हमें ऐसे संस्कार मिले हुए हैं कि किसी के लिए भी बुरा नहीं कहना है। एक कहावत है कि "जो तन लागे-सो तन जाने"। यह प्रदेश हमारा घर है और प्रदेशवासी हमारा परिवार है तथा हमें इसे मिलकर चलाना है। आज उसी को तोड़ा जा रहा है जिसे बनाना है। आज समय आ गया है कि हम सभी को एक-दूसरे के साथ मिलकर इस घर को चलाना है। इस घर को चलाना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा तथा इसके लिए हम सभी को इक्कठे होना पड़ेगा। मैं विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी पार्टी के पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी गलत थे? क्या जनता पार्टी के श्री मोरारजी देसाई जी गलत थे? क्या पूर्व केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी व श्री यशवंत सिन्हा जी गलत थे? इनमें से कोई भी गलत नहीं था। इन सभी ने विभिन्न प्रदेशों व हिमाचल प्रदेश को उसका हक दिया और वह हक हर वर्ष निरंतर मिलता रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज उस हक को क्यों छीना जा रहा है? इसके पीछे के क्या कारण हैं? कारण यह है कि हमें देश में ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। कारण यह है कि अमेरिका में बैठकर ट्रम्प महोदय निर्णय लेंगे कि भारत कैसे चलेगा और हिमाचल प्रदेश का क्या होगा। क्या ऐसा होगा कि व्हाइट हाउस डिसाइड करेगा कि भारत देश में राज्यों को कैसे चलना है? क्या एक फैडरल देश का केन्द्रीकरण कर दिया जाएगा? दिल्ली में बैठकर यह सोचना कि प्रदेश को किस प्रकार चलाना है

श्री ए0पी0 द्वारा......जारी

17.02.2026/1925/ए.एस./ए.पी./01

श्री आर0एस0 बाली जारी .....

यह बहुत जरूरी है। क्योंकि भारत एक फेडरल कंट्री है। प्रदेश का ज्यादातर टैक्स दिल्ली जाता है। प्रदेश का टैक्स चाहे वह राशन, कपड़े, मोबाइल, पेट्रोल-डीज़ल या कोई भी सामान हो, उसका टैक्स केंद्र को जाता है। फिर उस टैक्स का एक हिस्सा प्रदेश को मिलता है और उसी से प्रदेश को चलाया जाता है। आज प्रदेश को वित्त आयोग टैक्स का पैसा किस तरह से आबंटन होना है उसका निर्णय लेती है। उसके बाद प्रदेश में टैक्सों का आवंटन किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपनी कमाई से जो प्रदेश नहीं चला पाते, उन्हें राजस्व घाटा अनुदान दिया जाता है। हमारा प्रदेश भी उन्हीं में से एक है। आज जब विपक्ष के वरिष्ठ सदस्य बोल रहे थे, उन्होंने बहुत सी बातें कहीं। मैं माननीय बलबीर जी का बहुत सम्मान करता हूं, वे वरिष्ठ है और उनको हमसे ज्यादा अनुभव हैं। लेकिन जिस तरह से आज वे पैसे गिनवा रहे थे और लगभग सभी ग्रांट्स को उन्होंने गिनवाया। चाहे वे सड़क की ग्रांट हों, मेडिकल की ग्रांट हों, पर्यटन की ग्रांट हों चाहे वह कोई भी ग्रांट हो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वे ग्रांट्स पहले नहीं आती थीं? क्या वे ग्रांट्स अभी आनी शुरू हुई हैं? मुझे लगता है कि सरकार को कोसना तो आसान है। लेकिन विपक्ष की सकारात्मक भूमिका केवल आलोचना नहीं है। हम यहां इनसे सीखने के लिए आते हैं। पक्ष और विपक्ष के सीनियर नेताओं से हम सिखते हैं। जब पहली हम बार सदन में आते हैं, तो वरिष्ठ नेताओं से सीखते हैं और हम सीखकर वापस जाते हैं। लेकिन जिस दिन से यह सरकार आई और पहला सत्र हुआ, विपक्ष ने कहा कि मुख्य मंत्री नायक नहीं, खलनायक हैं। आज कहा गया कि आपने जब से सरकार को संभाला है तब से प्रदेश के दिन अच्छे नहीं हैं। लेकिन वही मुख्य मंत्री जिन्होंने रात-दिन मेहनत करके एक कर दिया। ऐसे मुख्य मंत्री जिन्होंने संसाधन अपने आप जुटाए हैं। प्रदेश में रिकॉर्ड है कि संसाधनों को जुटाया गया, इन्हें बढ़ाया गया, रात-दिन एक करके मेहनत की गई, कई चोर दरवाजे बंद किए गए और उनसे संसाधनों में बढ़ोतरी की गई और प्रदेश को चलाया गया। जो हमें टैक्स मिलते थें चाहे जी0एस0टी0 हो जिसके कारण पिछली सरकार को हजारों करोड़ रुपए मिले, लेकिन आज वह जी0एस0टी0 भी हमें नहीं मिल पाया। आज जो आर0डी0जी0 (राजस्व घाटा अनुदान) आपको पिछली सरकार के समय मिली, उससे कई गुना कम हमें मिली।

17.02.2026/1925/ए.एस./ए.पी./02

यह सब आपके सामने है, आप जानते हैं, पहचानते हैं और दिल से मानते भी हैं लेकिन बोलने से परहेज है। आप 1,500 की बात करते हैं, कहते है कि महिलाओं को 1500 रुपये नहीं मिले। आप देखिए आर0डी0जी0 के साथ क्या हो रहा है। सरकार बनते ही मुख्य मंत्री और मंत्रिमंडल के साथ सारे एम0एल0एज0 के साथ क्या हुआ, मिशन लोटस हुआ। उसके बाद हम आपदा से लड़े, ग्राउंड जीरो पर जाकर लड़ाई लड़ी। माननीय मुख्य मंत्री और मंत्री महोदय लड़े। मुख्य मंत्री जी ने अपने जीवन की कमाई भी दे दी। आपदा आई हम सबको इसका दुःख है। लेकिन आपदा जैसी स्थिति से लड़ने के लिए प्रदेश किस तरह से तैयार होगा उसके लिए हमें मिलकर सोचना पड़ेगा। यहां तक कहा गया कि आर0डी0जी0 सिर्फ वेतन देने के लिए है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा हमारे एक माननीय सदस्य द्वारा कहा गया और बहुत-सी बातें उनके कहते हुए हुई। लेकिन आर0डी0जी0 ग्रांट ऐसी नहीं है। आर0डी0जी0 की कैपिंग इस तरह से नहीं की गई। आर0डी0जी0 सरकार की कमाई और खर्चों के गैप को पूरा करने के लिए दी जाती है। आज मुझे लगता है कि आर0डी0जी0 को एक विषय माना जाए। इसको कोई मुद्दा न माना जाए।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

17/02/2026/1930/AT/ DC/01

श्री आर0एस0बाली जारी....

आज सरकार और विपक्ष को एकजुट होने की आवश्यकता है। यह कल की बात है 75 लाख लोगों का कल कैसा होगा इसकी बात है आज हम आज यहां बैठें है और यह मौका सबको मिलता है। आगे जाकर प्रदेश कैसा देखेगा यह उस की बात है। सिर्फ ग्रांट के सहारे प्रदेश नहीं चल सकता। स्कूल-कॉलेज और विकास की चीजें केवल ग्रांट से नहीं चल सकतीं। ग्रांट एक विशेष उद्देश्य के लिए आती है, एक महकमे के लिए आती है। पर जब आपको खुला पैसा मिलता है, तो आप उसे किसी भी जगह लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि सकारात्मक सोच की जरूरत है और उसके ऊपर काम करने की जरूरत है।

अब तक जितने भी वित्त आयोग बने हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी ने आर0डी0जी0 की रिकमेंडेशन की है। आज तक लगभग 15 वित्त आयोगों ने इसका मतलव

पांच साल का एक वित्त आयोग होता है, यानी 50 साल में 10 वित्त आयोग, और अब तक तकरीबन 15 वित्त आयोग हो चुके हैं। जब से भारत बना है, हिंदुस्तान बना है, तब से सभी वित्त आयोगों ने आर0डी0जी0 प्रदेशों को देने की रिकमेंडेशन की है। मैं माननीय पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री विक्रमादित्य जी को सुन रहा था। उन्होंने भी आप सबसे गुहार लगाई। नौजवान मंत्री हैं, उन्होंने भी आपसब से कहा। पक्ष के सभी नेताओं ने कहा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा कि आज इकट्ठा होकर प्रदेश की बात करने की जरूरत है। आज 1500 और 15 लाख देने की बात नहीं है पूछा जाए कि काला धन कब आएगा? पूछा जाए कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष कब मिलेंगे? पूछा जाए पिछले 10 साल में 20 करोड़ रोजगार और 12-13 साल के अंदर तकरीबन 24 करोड़ लोगों को रोजगार देना था। इसका मतलब एक भी बेरोजगार पूरे देश में नहीं बचना था। पूछा जाए कि वर्ष 2022 तक सभी कच्चे घर पक्के कर दिए जाने थे क्या आज हिंदुस्तान के सभी कच्चे घर पक्के हो गए हैं?

जब आप एक उंगली किसी की ओर करते हैं तो चार उंगलियां अपनी ओर होती हैं। मेरे चाचा जी विपिन परमार जी यहां बैठे हैं। हम आप सभी बड़े लोगों से सीखते हैं श्री सतपाल सिंह सत्ती पक्ष और विपक्ष के उन नेताओं से जिन्होंने लंबा समय काम किया है।

17/02/2026/1930/AT/ DC/02

आप दिल से जानते हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं। आप जानते हैं कि स्थिति क्या है पर बोल नहीं पा रहे हैं। आज माननीय विक्रमादित्य जी ने भी कहा, माननीय धर्माणी जी ने भी कहा कि बोलने का वक्त आ गया है। जब प्राकृतिक आपदा आई तो यहीं बैठकर वोट हुआ। कहा गया कि दिल्ली चलिए। प्रदेश के लोगों ने जान गंवाई है। आज गुहार लगाने की जरूरत है, पैसा लाने की जरूरत है। यहां पर वोटिंग हुई पर आप लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। इस बात का दुख है और आज आर0डी0जी0 की बात हो रही है तो उसको भी घुमाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कम बोलता हूं, संक्षिप्त में बोलता हूं। पर चाहता हूं कि आप उदार दिल मेरी ओर भी रखेंगे, मुझे पता है इन्होंने बोलना है, मैं सिर्फ दो मिनट में कन्क्लूड करूंगा। मुझे पता है कि यहां सभी सीनियर लोग बैठे हैं, तो मैं दो मिन्ट में कन्क्लूड करूंगा। आपने हमेशा बड़ी उदारता दिखाई है। सभी विपक्ष के सदस्यों

का धन्यवाद करूंगा मेरे सभी चाचा जो यहां बैठे हैं जिन्होंने मेरे पिताजी विकास पुरुष स्वर्गीय जी0एस0 बाली जी के साथ लंबा समय काम किया। आप लोगों का आशीर्वाद रहा है।

आप सभी सीखतें हैं। पक्ष के सभी नेता सिखाते हैं। माननीय हर्षवर्धन जी एक सीनियर मंत्री हैं। जब वे बोल रहे थे तो उनकी बात को संवेदनशीलता से सुनने की जरूरत थी। मुझे लगता है कि आज यह वक्त आ गया है। अगर संविधान ने यह व्यवस्था बनाई है तो उसे गलत कैसे कहा जा सकता है? अगर संविधान में लिखा है कि आर0डी0जी0 का हक इन राज्यों को मिलेगा और उसमें हिमाचल प्रदेश भी एक है, तो वह गलत कैसे हो सकता है? यह सहयोग छोटे राज्यों को इसलिए दिया गया क्योंकि हम एक छोटा पहाड़ी राज्य हैं। हमारी भौगोलिक स्थिति अलग है। हमारे यहां एक मकान बनाने में ज्यादा पैसा लगता है। हमारे यहां हर चीज बाहर से आती है। अगर शहर में 2,00,000 रुपये में कोई चीज बनती है तो हमारे हिमाचल प्रदेश में वही चीज 5,00,000 रुपये की पड़ती है। हर चीज महंगी है, बाहर से लानी पड़ती है।

एम0डी0द्वारा जारी ......

17.02.2026/1935/केएस/डीसी/1

श्री आर0एस0 बाली जारी ---

आर0डी0जी0 की ज़रूरत आज हमें ज्यादा है। मुझे लगता है कि आज आर0डी0जी0 को मुद्दा ना समझ कर इस विषय पर हमें इकट्ठा होना चाहिए। आज हिमाचल को दबाव की नहीं, दबाने की नहीं, सहयोग की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है, आपके नेताओं की ज़रूरत है, केंद्र की ज़रूरत है और मुझे पता है कि केंद्र हमेशा बड़े भाई की तरह काम करेगा। आज भी संवेदनशीलता से सोचेगा। अभी तक हमें वह चीज़ नहीं मिल पाई जो आपको मिली परंतु तब भी आज प्रत्येक काम हो रहे हैं। कौन बोलता है कि डवलपमैंट नहीं हो रही है? आप आ कर देखिए कि किस तरह के डवलपमैंट के काम हो रहे हैं। आप नगरोटा बगवां में आ कर देखिए कि मुख्य मंत्री जी के आशीर्वाद से किस तरह के डवलपमैंट के काम वहां पर हो रहे हैं। प्रत्येक महकमें के रात-दिन काम चले हुए हैं। आप

कभी भी आएं मैं स्वागत करुंगा। आज हिमाचल को दबाव की नहीं, सहयोग और आशीर्वाद की ज़रूरत है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं हमेशा की तरह बड़ी उदारता दिखाई। बोलने को बहुत कुछ था लेकिन कंस्टिट्यूशन के तहत फेडरल कंट्री जो बनाया गया, केंद्र को हिमाचल प्रदेश का, राज्यों का सहयोग करना चाहिए और फेडरल कंट्री के तहत हमारा संवैधानिक अधिकार देना चाहिए, यही गुहार है, यही आपसे कामना है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री आशीष बुटेल, माननीय सभापति पदासीन हुए)

17.02.2026/1935/केएस/डीसी/2

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री जीत राम कटवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान जी द्वारा लाया गया नियम-102 के अंतर्गत प्रस्ताव जो कि आर0डी0जी0 से सम्बन्धित है, उसके ऊपर आपने मुझे चर्चा के लिए आमंत्रित किया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि जो 16वें वित्तायोग की रिपोर्ट का ज़िक्र है, जिसके बारे में चर्चा हो रही है, मैं ज्यादा पोलिटिकल तो नहीं बोलूंगा परंतु इस मामले से सम्बन्धित पोलिटिकल-वे में भी मैं बात करुंगा। वित्तायोग का गठन आर्टिकल-280 के अंतर्गत होता है और सरकार ने अपना जो गवर्नर महोदय का अभिभाषण जारी किया, उसमें 275(1) में इसका हवाला दे कर जो शुरू किया, मैं दोहराता हूं कि यह गलत है। 275 (1) में केंद्र और राज्यों के बीच में धन के आबंटन, टैक्सिज़ के आबंटन, रिसोर्सिज़ के आबंटन का कोई वित्तायोग का हवाला नहीं है। वित्तायोग एक रिकमेंडेटरी बॉडी है और वित्तायोग रिकमेंडेशन देता है और उसको सरकार माने या ना माने या किस रूप में मानें या किस अमेंडमेंट के साथ मानें, वह पार्लियामेंट का प्राधिकार है। यह सिफारिशों के तौर पर है ना कि पार्लियामेंट ने इनको माना है। अभी इस दफा जो बजट पेश हुआ तो ये जो कहना है कि 275 (1) में, उसमें मैं स्पैसिफाई कर देता हूं कि 'Grants-in-aid to States after considering their development needs; the only reference to the Finance

Commission is in proviso Clause(ii) of the Article -275'.उसका मतलब यह है कि कोई एक दफा फाइनेंस कमीशन नोटिफाई हो गया तो उसको टर्मज़ एण्ड कंडिशन या कोई ऑर्डर प्रेसिडेंट नहीं कर सकते हैं और अगर जो कोई भी उसकी टर्म्ज़ एण्ड कंडिशन में चेंज होती है तो वह पार्लियामेंट के माध्यम से होती है और differentiating higher grants are available given to Centre. हिमाचल जो है, यह जो Differential Rate System है, 90:10 के अनुपात में हमारे प्रदेश का एक आर्थिक रिकगनेशन है, एक economic status है जो हमारा यह पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण जितनी भी हमारी जो कमियां हैं या जितने भी हमारे शॉर्ट फॉल्ज़ हैं, उसको 90:10 के अंतर्गत आंका गया है और

17.02.2026/1935/केएस/डीसी/3

यही बात है कि सैंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम्ज़ इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, 90:10 की रेशो में है। एक्सटर्नली एडिड प्रोजेक्ट जो बाकी जनरल कैटेगरी स्टेट्स को लोन के रूप में आते हैं, हमें 80:20 के रूप में देते हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

17.02.2026/1940/av/DC/1

श्री जीत राम कटवाल-------- जारी

एक्सटरनली एडिड प्रोजैक्ट जो बाकी जनरल केटेगरी स्टेट्स को लोन के रूप में आते हैं, वह हमें 80:20 के रूप में देते हैं और यही आर्टिकल 275 का प्रावधान है। आर्टिकल 275 का जो मेन्डेट है यानी जो डिविजिबल पूल है, उसके बारे में संसद को पावर है न कि वित्तायोग को है। इसलिए मैं अपनी इस बात को दोहराता हूं कि ओपनिंग पैराज ऑफ गवर्नर्ज अड्रैस आर्टिकल 275 के अधिकार क्षेत्र या जिसके बारे में लिखा गया है कि हमारी आर0डी0जी0 बंद हो गई है, यह बिल्कुल ही तथ्यों से परे है। यह आर्टिकल 280 का मामला है और 280 में ही डील होता है। मेरे से पहले बहुत सारे वक्ताओं ने आर्टिकल 280 पर पूरी तरह से चर्चा कर ली है। अब मैं यह बताना चाहूंगा कि जनरल केटेगरी स्टेट्स एक्सटरनली एडिड प्रोजैक्ट में जो फण्ड या लोन है या फिर जो सेंटरली स्पोंसर्ड स्कीम्ज हैं, इसमें जनरल

केटेगरी स्टेट्स को 60:40 के हिसाब से मिलता है। यह 50:50 में भी दी जाती है जबकि हिमाचल को which as per Article-275 is getting grants -in-aid in the ratio of 90:10. यह सबसे महत्वपूर्ण बात है और इसमें डिविजिबल पूल भी आएगा। रिकॉमेंडेशन्ज के बारे में जो आप बोल रहे हैं कि हमारा हक है, ऐसा नहीं है। यह बात अलग है कि हमें वर्ष 1952 से लगातार मिलता रहा और यह भी पता है कि पिछले वित्तायोग में अगर 13 राज्यों को मिलता था तो 15वें वित्तायोग में 17 स्टेट्स को मिला परंतु अब बंद हो गया। यह बंद क्यों हुआ? इसके बंद होने के कुछ कारण होंगे, डिविजिबल पूल बढ़ा और हमारा जो टैक्स शेयर था, वह 32 प्रतिशत था यानी वर्टिकल डिवीजन को केंद्र सरकार ने 32 प्रतिशत से 41 प्रतिशत किया। जी0एस0टी0 में बैटर कलैक्शन और जो एकदम बढ़ोतरी हुई, उसके कारण यह एक मैकेनिज्म है। आप जो आर0जी0डी0 के बारे में बातें कर रहे हैं, इसका मुख्य कारण है merger of plan and non-plan expenditure. वित्त विभाग वित्तीय स्थिति के बारे में मुख्य मंत्री और मंत्री मण्डल को परामर्श देता है। परंतु कुछेक बातें ऐसी हैं जोकि मिक्स नहीं होनी चाहिएं, उनका कोई फायदा नहीं होगा। आप उसके बारे में जो मर्जी डिसकस कीजिए। यहां पर डिसक्शन के बाद जो भी कागज कहीं जाएगा या दिल्ली जाएगा यानी गवर्नमैंट ए, बी या सी कोई भी हो। मैं इसके साथ यह भी कहूंगा कि 14वें वित्तायोग ने 32 से 41 प्रतिशत किया था और plan and non-plan expenditure को

17.02.2026/1940/av/DC/2

इकट्ठा करने के बाद यह व्यवस्था क्रिएट हुई। माना राज्य के सामने अभी यह एक बहुत बड़ा इश्यू है। नॉन पार्टिशिन यानी आप जिस शेप में ले जाना चाहते हैं उस शेप में आपको अपोजिशन या हमारे सपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती। हम आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। आपके लिए भारत सरकार द्वारा कई रिमाइंडर और दूसरी बहुत सारी बातें कही गई हैं कि लोन कंट्रोल कीजिए। आपका लोन 42.08 प्रतिशत है यानी जितना आपका सकल घरेलू उत्पाद है उसका 42.08 प्रतिशत कर्जा है। So viability of State is at stake और उसके साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अनप्रोडक्टिव एक्सपैंडिचर पर भी कर्व

लगने चाहिएं यानी 'सर्व जन हिताय, सर्व जन सुखाय', कहने का मतलब यह है कि काम या पॉलिसी वही लाओ जो सभी तक पहुंच सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ से हम खींच कर उधर चले जाएं और दूसरी तरफ से खाली हो जाएं। इसलिए यह भी सरकार का ही दायित्व बनता है और इसको मौके की सरकार को देखना चाहिए। केंद्र सरकार क्यों अच्छी चल रही है। मैं आपको बताऊं कि आज जो आपके हर घर में जल से नल है, आयुषमान भारत, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन, वन रैंक-वन पेंशन, एल0पी0जी0, 23 करोड़ लोगों को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय बनें, 5 करोड़ लोंगों के लिए घर बनें, किसान सम्मान निधि दिनांक 23 मार्च, 2019 से लगातार 6,000 रुपये मिल रही है। वह पैसा किसको जाता है?

टी सी द्वारा जारी

17.02.2026/1945/टी0सी0वी0/एच0के0-1

श्री जीत राम कटवाल... जारी

वह पैसा किसको जाता है? वह पैसा सबसे गरीब व्यक्ति को जाता है और एक ही सेकंड में पूरे भारतवर्ष में क्लिक करके खाते में पहुंच जाता है। यह पॉलिसी है, यह मेकैनिज्म है और यह एफिशिएंसी है। डवलपमेंट को एन्श्योर करना या विकसित भारत का जो एक मॉडल है, यदि हमें उसे लागू करना है या उसका हिस्सा बनना है तो हमें भी इन चीजों में प्रो-एफिशिएंसी और एक किस्म की प्रोपराइटी लानी चाहिए। जो चीजें हमें सूट नहीं कर रही हैं, उन पर भी हमें विचार करना होगा। अब कर्ज बढ़ता जा रहा है। आपका 58000 करोड़ रुपये का बजट था उसमें से 10 प्रतिशत प्रति वर्ष उसका प्रिंसिपल वापिस जाता था यानी वह 1 लाख करोड़ रुपये का 10000 करोड़ रुपये जाता था। 7 से 8 प्रतिशत उसका इंटरेस्ट रेट भी होगा तो लगभग 18000 करोड़ रुपये हो गया। 30000 करोड़ रुपये पेंशन और सैलरीज में चले गए यानी कुल 48000 करोड़ रुपये हो गए। 3000 से 4000 करोड़ रुपये कमिटेड एक्सपेंडिचर हो गया जिसमें सब्सिडी, सोशल सिक्योरिटी पेंशन जैसे खर्च भी शामिल हैं। इन खर्चों को आप नहीं काट सकते क्योंकि ये वर्षों से चले आ रहे हैं और यह केवल प्रेसिडेंट ही नहीं बल्कि सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। यह डिबेटेबल नहीं है। यदि

इन सभी को जोड़ दें तो 52-53 हजार करोड़ रुपये हो जाता है। ऐसे में डवलपमैंट के लिए पैसा बचा ही कहां है। पिछले वर्ष बजट पर जो डिबेट हुई थी उसमें 9800 करोड़ रुपये के अगेंस्ट लगभग 5125 करोड़ रुपये एक्सपेंडिचर का था। इस बार तो अप्रैल से ट्रेजरी ही बंद है। Treasury shifted to Shimla. यहां से वही बिल पास होते हैं जिनके बारे में वित्त विभाग से आदेश होते हैं। यह सरकार की अच्छी स्थिति नहीं मानी जा सकती। सरकार की एफिशिएंसी और सरकार की वर्किंग को भी एक तरीके से रिव्यू करने की आवश्यकता है। कहां हम बचत कर सकते हैं, कहां हम एफिशिएंसी ला सकते हैं, यह सभी बातें देखने योग्य हैं। आर0डी0जी0 के विषय में कहा जा रहा है कि इसका पैसा कम हुआ। 15वें वित्तायोग की 37199 करोड़ रुपये की रिकमेंडेशन थी। (घण्टी) सर, मेरे से पहले भी कई माननीय सदस्य मुझसे ज्यादा समय तक बोलकर गए हैं। it is not irrelevant. It is relevant.

Chairman : Hon'ble Member, of course it is relevant but there is a time limit fixed by the Hon'ble Speaker.

17.02.2026/1945/टी0सी0वी0/एच0के0-2

Shri Jeet Ram Katwal : Hon'ble Chairman, Sir, time limitation is for everybody not for me only.

Chairman : Shri Jeet Ram Katwal Ji, it is not only for you it for all the speakers.

श्री जीत राम कटवाल :: मेरा आपसे आग्रह है, मेरे से पूर्व वक्ता 20 मिनट बोलकर गए हैं।

सभापति : प्लीज थोड़ा जल्दी वाइंडअप कीजिए।

Shri Jeet Ram Katwal : Hon'ble Chairman, Sir, I am very clear in my averments. आप चीजें नोट करें। यह स्थिति केवल यहां के लिए यूनिक नहीं है। आर0डी0जी0 की जो रिकमेंडेशन है it is for whole of the country not only for the Himachal हमें यह बात भी स्वीकार करनी चाहिए। यहां कहा गया कि यह हमारे हक की बात है, हक तो सभी के होते है लेकिन नियम भी सभी के लिए होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन भी सभी का होता है और उसका पालन भी सभी को समान रूप से करना होता है। एक और बात यह है कि अभी

बेहतर कलेक्शन हुई है और लगभग 14000 करोड़ रुपये तो जी0एस0टी0 कलेक्शन के रूप में आने का आकलन है। पहले यह केवल 3000 से 4000 करोड़ रुपये होता था। इस डवलपमैंटल मॉडल में हमें भी अपनी भागीदारी और इसे कोऑपरेटिव तरीके से समझना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कई राज्यों ने इसको अपोज किया, कोई बात नहीं लेकिन हिमाचल की अपनी विशेषताएं है। हमें सेंटर गवर्नमेंट की ओर से सिर्फ आर0डी0जी0 नहीं दी जाती है बल्कि there are hundreds of channels and there are hundreds facilities and schemes which we are getting from the Govt. of India. हमें इन सभी बातों को हॉलिस्टिक तरीके से देखना चाहिए और यदि अन्य रिकमेंडेशन्ज हैं तो उन पर भी ध्यान देना चाहिए। यह विकसित भारत का मॉडल है और हमें भी इसमें अपना योगदान देना चाहिए। वर्ष 2026-27 के लिए भारत सरकार का जो बजट डॉक्यूमैंट है इसमें पहले 11806 करोड़ रुपये टैक्स कलेक्शन थी जो हिमाचल प्रदेश को शेयर के रूप में मिला था। अब इसमें लगभग 14000 करोड़ रुपये मिलने का आकलन है और यह पहले से ज्यादा होगा।

एन0एस0 द्वारा जारी ...

17-2-2026/1950/एन0एस0-एच0के0/1

श्री जीत राम कटवाल-----जारी

यह एफिशिएंसी है, ट्रांसपेरेंसी है और सिस्टम में एक अच्छे तरीके से हम उसको ला रहे हैं। आप सबसे बड़ी बात कॉंस्टिच्यूशन के वायोलेशन की कर रहे हैं। आप पंचायतों के इलैक्शन टाल रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको यह एक ओर दिक्कत आएगी। आप मेरी बात सुन लीजिए। पंचायतों को जो ग्रांट, सब्सिडी या डायरेक्ट स्कीम्ज आती हैं the word is duly elected bodies उनको है या डैफर होंगी या पोस्टपोन होंगी। कहीं कल को ऐसा न हो क्योंकि कानून तो संविधान का हिस्सा है। वे पंचायतों को या duly elected bodies को देंगे। आप पंचायतों के चुनावों को बिना मतलब के ही टाले जा रहे हैं। संविधान का वायोलेशन तो आप खुद ही समझ लीजिए कौन कर रहा है? केंद्र सरकार हमारी कोई दुश्मन नहीं है। केंद्र सरकार हर तरीके से मदद करती है। मैंने आपको इतनी

स्कीमें गिनाई हैं। केंद्र सरकार के इतने प्रावधान हैं और केंद्र सरकार के जो हाइवेज या सड़कें हैं, जितने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के डवल्पमैंट की बातें हैं या बजट एलोकेशन्ज की जो बातें हुईं तो मैं उन पर ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं because that is a budgetary debate. मैं आर0डी0जी0 के प्वाइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं तो इन चीजों के ऊपर गौर करना आवश्यक है। सरकार को भी यह सोचना चाहिए। 16वें वित्तायोग की रिपोर्ट कोई इतनी बड़ी रिपोर्ट नहीं है। इसको आप बैठ कर अच्छे तरीके से अध्ययन करें। दूसरी जो सेंट्रल स्पाँसर्ड स्कीम्ज या 90:10 की जो स्कीम्ज हैं तो उनमें हमें ज्यादा हिस्सा मिले इसके लिए प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज-3 में 2683 करोड़ रुपये मिले और 2240 करोड़ रुपये अभी पी0एम0जी0एस0वाई-4 में मिले तथा एक किस्त और आने को तैयार है। हमें सी0आर0आई0एफ0 में पैसा मिला। पी0एम0आवास योजना में पैसा आ रहा है तो ये डवल्पमैंट मॉडल है और प्रदेश को भी उसका उतना ही लाभ मिल रहा है। अगर हम एफिशिएंटली इसको करेंगे तो हमारी डवल्पमैंट होगी। ऐसा नहीं है कि केंद्र की डवल्पमैंट अलग है और हिमाचल की डवल्पमैंट अलग है। इन बातों को भी आप समझें और मात्र इसके ऊपर न चलें तथा मात्र आर0डी0जी0 की बात न करें। There are other hundred ways जहां हम अच्छे तरीके से अपने केस को चला सकते हैं जहां स्कीमों के रेग्युलर चैनल्ज हैं जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास, हॉर्टिकल्चर की योजनाएं, इरिगेशन की

17-2-2026/1950/एन0एस0-एच0के0/2

योजनाएं और ए0डी0बी0 की योजनाएं आदि शामिल हैं। कई एक्सटर्नल ऐडिड प्रोजैक्ट्स हैं और उनमें भी बड़ी-बड़ी योजनाएं आती हैं तथा हमें 80:20 की रेशो में मिलती हैं। 100 रुपये में 20 रुपये हमें देने हैं बाकी भारत सरकार देती है जबकि जनरल कैटेगरी स्टेटस को कोई सब्सिडी नहीं है। मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूं तो आप इनके ऊपर भी विशेष ध्यान दें। वर्ष 2004 से वर्ष 2014 के बीच का जो दस वर्षों का पीरियड था तो प्रदेशों को केंद्र सरकार से 18 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर हुए हैं। इसी पीरियड में 84 लाख करोड़ रुपये सेंट्रल गवर्नमैंट से स्टेटस को डिवॉल्व हुआ तो ये दर्शाता है कि इकोनॉमी में

buoyancy है और इकोनॉमी इम्प्रूव हो रही है। हम भी उस इम्प्रूवमैंट में को-ऑपरेट करें और सहयोग करें तथा हम भी उसमें कम-से-कम उस लैवल तक जाएं ताकि हम हर बार यह न कहें कि हम गरीब हैं और हमें यह चाहिए। मैं इसके साथ ही यह कहना चाहूंगा कि अभी जो करंट फाइनैंशियल ईयर में 15 लाख करोड़ रुपये डेवोल्यूशन की प्रोजैक्शन्ज आई हैं और पिछले पांच सालों में ये 100 लाख करोड़ रुपये एन0डी0ए0 गवर्नमैंट के दौरान आए थे। मैं यह नहीं कहता कि यह एन0डी0ए0 गवर्नमैंट ने अकेले किया बल्कि ये सारी स्टेटस के Cooperative Federalism की बात है। सभी ने काम किया। सभी प्रदेशों ने काम किया और बैटर कोलैक्शन हुई और यहां कंन्यूमर कल्चर है। आप बोल रहे हैं कि हिमाचल को शेयर नहीं मिलता। मैं आपको सीधी बात बताऊं कि जी0एस0टी0 का मतलब है कि अगर आपके कंज्यूम होगा तो प्रोडक्ट वहीं बिकेगा और वही शेयर आपको मिलेगा। आपकी कोई ऐसी बात नहीं है। आपकी जनसंख्या के लिहाज से अच्छा कंज्यूमर है, अच्छी सोसायटी है और लोगों के एफिशिएंट लाइफ स्टैंडर्ड हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इसलिए हमें थोड़ा अपने को स्ट्रीमलाइन करने की आवश्यकता है। अगर हम इन सारी चीजों को देखें और अगर हम इसको मानते हैं तो हमें इसे राइट अर्नेस्ट में

आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

17.02.2026/1955/RKS/वाइके-1

श्री जीत राम कटवाल जारी...

अगर हम इसको मानते हैं तो हमें इसको राइट अर्नेस्ट और नॉन पार्टिशन एटीट्यूड में लेना चाहिए। आर0डी0जी0 एक अलग विषय है लेकिन अन्य योजनाएं हर डिपार्टमेंट में निंतर चलती रहती हैं। उनके लिए हमारा कोओपरेशन हमेशा प्रदेश हित में रहा है। हमारी जनता हमारे लिए न केवल मार्गदर्शक हैं बल्कि जनार्दन भी हैं। श्री आर0एस0 बाली जी कह रहे थे कि प्रदेश में काफी विकास हुआ है। मैंन प्लानिंग की मीटिंग में भी कहा था कि मेरे चुनाव क्षेत्र में जो 9 पुल बन हैं उनमें से 4 पुल बिना अप्रोचिज के ही हैं। जिनके चुनाव

क्षेत्र में विकास हुआ है उनको बधाई हो परंतु हमें इस बात का दुःख है कि हमारे क्षेत्रों से भारी पक्षपात हुआ। विधायक क्षेत्र विकास निधि, ऐच्छिक निधि और हमारे दूसरे जो काम हैं उनके लिए हमारे सदस्यों ने बार-बार कहा। ठीक है कि विपक्ष वालों के साथ थोड़ा भेदभाव हो क्योंकि रूलिंग पार्टी को administrative access अधिक रहती है, आप उसे इंजॉय कीजिए। लेकिन आप हमें इतना भी डिप्राइव न करें कि लोग आपको इयरमार्कड कर लें। हमारे लोग इसके लिए चुप बैठने वाले नहीं हैं। जनता हर बात को सही तरीके से समझती है।

अध्यक्ष महोदय आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका आभार। धन्यवाद।

अब इस माननीय सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 18 फरवरी, 2026 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

दिनांकः 17 फरवरी, 2026 **यशपाल शर्मा**
शिमला-171004. **सचिव।**